



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222301
CG-DL-E-08102020-222301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]
No. 405]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ ASVINA 8, 1942

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2020

परिषद् की रिपोर्ट

फा. संख्या 104/40/लेखा.1 प्रस्तावना.—भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद्, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18 की उप-धारा (5बी) की अपेक्षाओं के अनुरूप 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में संस्थान के कामकाज से संबंधित अपनी 40वीं वार्षिक रिपोर्ट और इसके साथ समेकित लेखों का लेखापरीक्षित लेखा-विवरण एवं इन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में उपर्युक्त अवधि के बाद से लेकर आज तक के कार्यक्रमों और संगठित गतिविधियों तथा की गई पहलों को भी शामिल किया गया है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: परिषद् द्वारा 19 जनवरी, 2020 से सीएस आशिष गर्ग को अध्यक्ष और सीएसनागेन्द्र डी. राव को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

परिषद् की बैठकें: वित्तीयवर्ष के दौरान परिषद् द्वारा 9 बैठकें आयोजित की गईं।

समितियों का गठन: परिषद् द्वारा गठित विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों, विशेषज्ञ समूहों, सलाहकार बोर्डों, और बाहरी समितियों का विवरण इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-क** में दिया गया है। आयोजित बैठकों और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट-ख** में दिया गया है।

क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं: निरंतर नई जानकारी उपलब्ध कराना और अपने सदस्यों का क्षमता निर्माण करना संस्थान के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। पूरे देश में क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने परिषद को अपना मूल्यवान सहयोग और सहायता देना जारी रखा और संस्थान ने पूरे वर्ष बड़े उत्साह एवं जोश से अपनी गतिविधियों और कामकाज तथा उत्तरदायित्वों को निभाया है। इस प्रक्रिया में, इसने व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रबंधन कौशल दिशानिर्देश कार्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्टडी सर्कल की बैठकें, क्षेत्रीय और राज्य सम्मेलनों, कैरियर जागरूकता कार्यक्रमों और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया। इसके अलावा, उन्होंने पुस्तकालय प्रणाली का उन्नतीकरण, समाचार-बुलेटिन प्रकाशित करने, कैपस प्लेसमेंट का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक सदस्यों की सहायता करने और मानव संसाधन बैठकों जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

शाखाएं: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के 72 शाखाएं, जिनकी क्षेत्र-वार स्थिति नीचे दी गई है: संस्थान की नई शाखाओं सहित बेलगावी, गोरखपुर, पटियाला और करनाल

आंकड़ों पर एक नजर:

सदस्यों एवं छात्रों का क्षेत्र-वार आंकड़ा निम्नानुसार है:

सदस्यों की संख्या					
	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	कुल
15.09.2020 को	6344	22412	11926	21910	62592
31.03.2020को	6275	22684	11071	21160	61190
31.03.2019को	5989	21391	10409	19757	57546

रेगुलर प्रोग्राम के लिए छात्रों की संख्या					
	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	कुल
15.09.2020 को	20764	60070	45421	63877	190132
31.03.2020को	22820	66433	50432	70760	210445
31.03.2019को	24911	74365	53175	77686	230137

फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए छात्रों की संख्या					
	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	कुल
15.09.2020 को	4113	9591	7046	9556	30406
31.03.2020को	5104	11745	8699	11705	37257
31.03.2019को	6110	14955	10021	16997	48083

कैलेण्डर वर्ष 2018 के लिए सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषद और शाखाएं पुरस्कार

क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा प्रदत्त योगदान को मान्यता देने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा करने के लिए, संस्थान की परिषद् ने सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषद् और शाखाएं पुरस्कार शुरू किए।

वर्ष 2018 के सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषद्, सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शाखा तथा ग्रेड स्तरीय सर्वोत्कृष्ट चैप्टर पुरस्कार यहां दिए गए विवरण के अनुसार निम्न है:

सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद: दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद		
सर्वश्रेष्ठ शाखाओं		
क्र.सं.	श्रेणी	शाखा के नाम
1.	सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा	भुवनेश्वर
2.	ग्रेड ए +	बैंगलुरु,
3.	ग्रेड ए	इंदौर
4.	ग्रेड बी	कोयम्बटूर
5.	ग्रेड सी	भुवनेश्वर
6.	ग्रेड डी	अमरावती

अध्याय को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान ने वर्ष 2018 में पुरस्कारों की नई श्रेणियों की शुरुआत की। इसके लिए प्राप्तकर्ता निम्नानुसार थे :

क्र.सं.	पुरस्कार श्रेणी	मापन श्रेणी	प्राप्ति
1	बेस्ट स्टडी सेंटर अवार्ड	अधिकतम संख्या में विद्यार्थी पंजीकृत	डीएम कालेज आफ कॉमर्स, डीएम कालेज कैम्पस, इफाल, मणिपुर 795001
2	कैरियर जागरूकता कार्यक्रम (CAP) गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्याय पुरस्कार	कैप की अधिकतम संख्या आयोजित की गई	बैंगलुरु,
3	कक्षा कक्ष शिक्षण गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्याय पुरस्कार	कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए अधिकतम छात्र पंजीकृत हैं	कोयम्बटूर
4	उमरता हुआ अध्याय पुरस्कार	अध्याय जो पहले ही महीने में सक्रिय हो गया	बेलागवी
5	प्लेसमेंट सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्याय	अध्याय जो प्लेसमेंट सेवाओं के लिए संचालन गतिविधियों का संचालन करता है	चंडीगढ़
6	छात्र पंजीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्याय	अध्याय जो छात्र पंजीकरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त किया	गोवाहटी (NE)

उपर्युक्त सभी अवार्ड जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, जयपुर में 14 वें से 16 वें सत्र, 2019 तक आयोजित कंपनी सचिवों के 47वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए।

2. बुनियादी ढांचा

I) वर्तमान में अपने परिसर:

क) मुख्यालय

लोधी रोड, नई दिल्ली और नोएडा

ख) सीसीजीआरटी/सीओई कार्यालय

नवी मुंबई में सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग

आईसीएसआई-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आईसीएसआई-सीओई) हैदराबाद में

ग) क्षेत्रीय कार्यालय:

ईआईआरओ-कोलकाता, एनआईआरओ-नई दिल्ली, डब्ल्यूआईआरओ-मुंबई, एसआईआरओ-चेन्नई।

घ) शाखाएँ

अहमदाबाद, बैंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, भीलवाड़ा, डोम्बीवली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गोवा, एनई-गुवाहाटी, हैदराबाद, हुगली, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, मदुरई, मंगलौर, मैसूर, नागपुर, पटना, पुणे, सूरत, थाणे, उदयपुर, वड़ोदरा।

II) बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए की गई पहलें :

क) मुख्यालय

i) आईसीएसआई सीओई-कोलकाता-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना के लिए संस्थान ने न्यू टाउन, कोलकाता में डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ से 1.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति (अकादमिक ब्लॉक और हॉस्टल ब्लॉक) से संबंधित गतिविधियाँ जैसे वास्तुकार की नियुक्ति, इसकी मंजूरी के लिए स्थानीय प्राधिकरण को भवन योजना प्रस्तुत करना, संबंधित प्राधिकरण को भवन योजना अनुमोदन शुल्क जमा करना, मृदा परीक्षण, स्वीकार्य के विस्तार के लिए डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ की स्वीकृति प्राप्त करना। निर्माण अवधि, प्री-क्वालिफिकेशन प्रेस नोटिस के माध्यम से सीमा की दीवार का निर्माण और ठेकेदारों की छोटी सूची का निर्माण पूरा हो गया है। लघु सूचीबद्ध ठेकेदारों को जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेजों (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) को अंतिम रूप देना प्रक्रिया में है।

ii) आईसीएसआई सीआईआरटी-मानेसर- संस्थान ने 1567.5 वर्गमीटर का एक प्लॉट खरीदा था। एमटीआर। सेक्टर-2 में, HSIIDC से IMT मानेसर। यह भूमि शुरू में गुडगांव अध्याय कार्यालय के लिए खरीदी गई थी, लेकिन बाद में परिषद द्वारा 4 वीं और 5 मई, 2019 को हुई बैठक में इसे अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित करके मुख्यालय परियोजना बनाने का निर्णय लिया गया। परिसर में गुडगांव अध्याय की गतिविधियों को समायोजित करने के लिए भी। प्रस्तावित परिसर (सिंगल ब्लॉक) शैक्षणिक और आवासीय सुविधाओं को समायोजित करेगा। परिसर के निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ जैसे वास्तुकार की नियुक्ति,, इसकी मंजूरी

के लिए स्थानीय प्राधिकरण को भवन योजना प्रस्तुत करना, मिट्टी परीक्षण और चारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है। प्री-क्वालिफिकेशन प्रेस नोटिस और निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के माध्यम से ठेकेदारों की लघु सूची जारी है।

- (iii) **आईसीएसआई मुख्यालय, सी-37, नोएडा**— सम्पूर्ण इमारत के बाहरी हिस्से की मरम्मत और संरचनात्मक सुदृढीकरण लगभग पूरा हो चुका है तथा पहली और दूसरी मंजिल का नवीनीकरण कार्य पूरा होने वाला है। पहली और दूसरी मंजिल के नवीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद, शेष मंजिलों के नवीकरण का काम शुरू किया जाएगा।
- (iv) **सीसीजीआरटी भवन, नवी-मुंबई**— मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के निष्पादन से पहले भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट नवंबर, 2019 में पूरा हो चुका है। परियोजना के लिए आर्किटेक्ट का चयन प्रक्रियाधीन है।
- (v) **सीओईई—हैदराबाद**— सम्पूर्ण परिसर (संस्थागत खंड एवं छात्रावास खंड) के ढांचे का निर्माण पूर्ण हो चुका है और पहले चरण में सम्पूर्ण छात्रावास खंड, स्वागत-कक्ष, भूतल (ऑडिटोरियम को छोड़कर) और संस्थागत खंड की पहली मंजिल को अगस्त, 2018 में प्रारम्भ कर दिया गया था। अब, दूसरे स्थान चरण में, फर्निशिंग कार्य अर्थात् एक कक्षा, कंप्यूटरलैब, पुस्तकालय, टॉयलेट्स का आंतरिक कार्य और दूसरी मंजिल के सम्पूर्ण क्षेत्र का पेंटिंग कार्य पूर्ण किया जाएगा।
- (vi) **सीओई अजमेर**— अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने 23 सितंबर, 2013 के संशोधित पत्र के माध्यम से, महाराणा प्रताप नगर, अजमेर में गुणवत्ता और नैतिकता के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए तीन व्यावसायिक संस्थानों (आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीओआई) को संयुक्त रूप से 24000 वर्ग गज का एक भूखंड आवंटित किया गया। उक्त भूमि के लिए कुल भुगतान शेयर के अनुसार किया गया और 28 सितंबर, 2013 को संयुक्त रूप से भूखंड पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। लीज डीड का निष्पादन अभी होना शेष है। आईसीएआई और आईसीओआई दोनों ने आईसीएसआई को अपना भूखंड देने की पेशकश की। आईसीएसआई ने उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। तत्पश्चात्, एडीए से भूमि के हस्तांतरण अर्थात् आईसीएसआई के पक्ष में अन्य दो व्यावसायिक संस्थानों के भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है। उक्त विषय एडीए के विचाराधीन है।
- (vii) **सौर परियोजना**— लोधी रोड स्थित मुख्यालय के भवन में 20 किलोवाट की क्षमता वाले ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम को स्थापित और परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। सी-36, सेक्टर-62, नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट के भवन में 30 किलोवाट की क्षमता वाले ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना और परिचालन के लिए आदेश पहले ही दिया जा चुका है और इसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।

ख) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

- (i) **आईसीएसआई—एनआईआरसी** —
- रूफ-टॉप सोलर प्रोजेक्ट— 25 किलोवाट क्षमता वाले ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है और उसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।
 - वर्षा जल संचयन— व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है। निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
 - लिफ्ट—नए के साथ मौजूदा पुराने लिफ्ट का प्रतिस्थापन किया जाना है। निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- (ii) **भोपाल शाखा**— भोपाल शाखा के कार्यालय के उपयोग के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) से निर्मित परिसर का अधिग्रहण किया गया। परिसर के फर्निशिंग से संबंधित गतिविधियों को पूरा किया गया है। परियोजना के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति। नवीनीकरण / फर्निशिंग के लिए ठेकेदार को आशय पत्र 1 सितंबर, 2020 को जारी किया गया है।
- (iii) **कोयम्बटूर शाखा**—13068 स्कायर फिट भूमि खरीदी गई है। परिसर के निर्माण से संबंधित गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। बिक्री विलेख के निष्पादन सुधार। परियोजना के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति। मंजूरी हेतु स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा करने के लिए भवन योजना को अंतिम रूप देना। मिट्टी परीक्षण, भवन योजना को अनुमोदन हेतु स्थानीय प्राधिकरण को अभी प्रस्तुत किया जाना है।
- (iv) **कोच्चि शाखा**— मौजूदा भवन को ध्वस्त करके नए भवन के निर्माण से संबंधित गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है: परियोजना के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति। अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकरण को भवन योजना प्रस्तुत करना। न्यायालय से भूमि उपयोग के संबंध में संस्थान के पक्ष में निर्णय प्राप्त करना। स्थानीय प्राधिकरण से निर्माण के लिए भवन अनुमतिपत्र की प्राप्ति।
- (v) **जयपुर शाखा**—
- ऑडिटोरियम— शाखा में ऑडिटोरियम के निर्माण की व्यवहार्यता के लिए अग्रिम चरण में स्ट्रक्चरल ऑडिट का कार्य पूरा हुआ।
 - सोलर पैनल—12 किलोवाट क्षमता वाली ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम स्थापित और चालू हो गया है।

(vi) भीलवाड़ा शाखा —

- गार्ड रूम —गार्ड रूम का निर्माण पूरा किया गया।
- सोलर पैनल —12 किलोवाट क्षमता वाली ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम स्थापित और चालू हो गया है।

(vii) फरीदाबाद शाखा—

- इमारत —फरीदाबाद शाखा के निर्माण से संबंधित शेष कार्य पूरा हो चुका है।
- सोलर पैनल —12 किलोवाट की क्षमता वाले ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग के लिए आदेश पहले ही दिया जा चुका है और उसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।

(viii) पुणे शाखा—

- कक्षाओं के साउंड प्रूफ बनाने से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।
- नए फर्नीचर के साथ कार्य पूरा किया गया और उपयोग के लिए तैयार है।

(ix) रायपुर शाखा—इस शाखा परिसर के निर्माण के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) से 3229 वर्ग फुट प्लॉट पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

III) परिषद की स्वीकृति के अनुसार शाखाओं के लिए भूमि / निर्मित संपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्राथमिकता निर्धारण।

- मैंगलोर शाखा** —परिसर के अधिग्रहण के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित किया गया था और प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन जारी है।
- अहमदाबाद शाखा** —परिसर के अधिग्रहण के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित किया गया था और प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन जारी है।
- जोधपुर शाखा** —जोधपुर शाखा के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- नागपुर, हुगली, हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, विशाखापट्टनम, शिमला, चंडीगढ़, राजकोट, सूरत, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लुधियाना और नोएडा शाखाओं के लिए भूमि-अधिग्रहण/ निर्मित संपत्ति/भवन-निर्माण के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर अपनी विभिन्न बैठकों में प्राथमिकता निर्धारण को अनुमोदित किया गया।

3. मानव संसाधन—टीम आईसीएआई को मजबूत बनाना

(1) कर्मचारी विकास : हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और सेवाएं प्रदान करने में कर्मचारियों की क्षमताओं, दक्षताओं और प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। 23 कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए 01.04.2019 से 15.09.2020 तक भेजा गया।

(2) भर्ती—टीम : संस्थान के सचिव ने 1 जून 2020 से कार्यभार संभाला। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 2 निदेशकों और 1 संयुक्त निदेशक को संस्थान को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया।

(3) कर्मचारी कल्याण योजनाएँ—वर्ष के दौरान, निम्नलिखित पहल की गई:

- संस्थान द्वारा अपने सभी कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी और बच्चों को “प्रमाणित सीएसआर प्रोफेशनल” पर 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए देय सभी शुल्कों में 75% की छूट दी गई है।
- आईसीएसआई मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन ट्रस्ट नियमों में कुछ बीमारियों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है।
- संस्थान ने फरवरी, 2020 के महीने में मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर आयोजित किए।

4. कर्मचारी संबंध

15.09.2020 को, संस्थान के कर्मचारियों की संख्या 373 थी, जिसमें 103 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, जो कुल कर्मचारी संख्या का 27 प्रतिशत थी। कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बना रहा।

5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

वित्तीय वर्ष 2019 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत फाइल किए गए मामलों और उनके निपटारे की रिपोर्ट

क्र. सं.	विवरण	मुख्यालय	एनआईआरओ और उसके चैप्टर्स	ईआईआरआ और उसके चैप्टर्स	डब्ल्यूआईआर ओ और उसके चैप्टर्स	एसआईआरओ और उसके चैप्टर्स
01	यौन शोषण की प्राप्त शिकायतों की संख्या	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
02	निपटारा की गई शिकायतों की संख्या	01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6) ई-प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस)

संस्थान ने अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों के लिए एक वेब आधारित प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लागू की है। दूसरों के बीच की प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं

1. प्रदर्शन योजना
2. प्रदर्शन का मूल्यांकन
3. असंतोषजनक रेटिंग का विश्लेषण
4. शिकायत निवारण प्रणाली

मानव संसाधन निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए मूल्यांकन के लिए ई-पीएमएस लागू किया गया है

(7) युवा पेशेवरों के साथ अनुबंध

संस्थान अपने विभिन्न निदेशालयों में युवा पेशेवरों को अनुबंध पर लगा रहा है ताकि समयबद्ध तरीके से काम सौंपा जा सके। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत 17 युवा पेशेवर योजना के तहत लगे हुए थे।

4. व्यवसायिक विकास की पहल

(i) वेबिनार

रिपोर्ट के दौरान कुल 51 वेबिनार आयोजित किए गए। उसी का विवरण इस प्रकार है

तिथि	विषय	फैकल्टी
24 मई 2019	फॉर्म डीपीटी 3 और एमएसएमई फॉर्म-I	श्री चंदन कुमार, उप निदेशक, एमसीए श्री शशि राज दारा, संयुक्त निदेशक, एमसीए
17 जून, 2019	कंपनी अधिनियम, 2013 में नवीन घटनाक्रम (फॉर्म डीपीटी -3)	श्री शशि राज दारा, संयुक्त निदेशक, एमसीए श्री भास्कर सुब्रमण्यन, उद्योग प्रधान, इंफोसिस
4 जुलाई, 2019	आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सीएसएएस-1 से सीएसएएस-4	ASB के सदस्य
12 जुलाई, 2019	कंपनी अधिनियम, 2013 (फार्म बेन -2 और एनएफआरए-1) के तहत नवीन विकास	सीएस विनोद कोठारी, कंपनी सचिव का अभ्यास करना
9 अक्टूबर, 2019	eCSIN और UDIN	आईसीएसआई परिषद के सदस्य
25 फरवरी, 2020	कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसपीआईसीई को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा	श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए श्री सूर्या, सहायक निदेशक, एमसीए श्री के.एम.एस. नारायणन, सहायक निदेशक, एमसीए श्री भास्कर सुब्रमण्यन, उद्योग प्रधान, इंफोसिस
16 मार्च, 2020	फेमा पर वेबिनार - एफडीआई और एकदिवसीय अंतर्वेशन और कंपाउंडिंग	सीएस अतुल मित्तल, पार्टनर डेलोइट हार्किन्स और सेल
1 अप्रैल, 2020	कंपनियां फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020	श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए श्री भास्कर सुब्रमण्यन, उद्योग प्रधान, इंफोसिस श्री के.एम. नारायणन, सहायक निदेशक, एमसीए
3 अप्रैल, 2020	संबंधित पार्टी के लेन-देन	सीएस मकरंद जोशी, कंपनी सचिव सचिव

6 अप्रैल, 2020	कंपनियां (संशोधन) विधेयक, 2020	डॉ. के.एस. रविचंद्रन, प्रबंध भागीदार, केएसआर एंड कंपनी एलएलपी
15 अप्रैल, 2020	सीएसआर : द प्रैक्टिकल वे	सीएस विनोद कोठारी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
17 अप्रैल, 2020	COVID-19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बोर्ड मीटिंग और ईजीएम रखने में छूट।	सीएस एस सुधाकर, उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट सचिवीय), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
20 अप्रैल, 2020	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत हाल के संशोधन	सीएस (डॉ.) डी. के. जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
22 अप्रैल, 2020	सचिवीय ऑडिट – लॉकडाउन के दौरान लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग	सीएस के सेथुरमन, समूह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
24 अप्रैल, 2020	सकारात्मकता और विचारों की शक्ति	श्री श्री श्री स्वामी वीरशानंद सरस्वती, राष्ट्रपति रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, कर्नाटक
27 अप्रैल, 2020	जीएसटी में हाल के बदलाव और खुले मुद्दे	सीएस बिमल जैन, कार्यकारी सलाहकार, ए2जेड टैक्स, एलएलपी
29 अप्रैल, 2020	बैलेंसिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल	गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग
30 अप्रैल, 2020	स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन	डॉ. देवी प्रसाद शेटी, अध्यक्ष और संस्थापक नारायण स्वास्थ्य
1 मई, 2020	महामारी के बीच एनसीएलटी	माननीय श्री न्यायमूर्ति ए के सीकरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय श्री बलविंदर सिंह, सदस्य, एनसीएलटी माननीय श्री जिनान केआर, सदस्य एनसीएलटी कोलकाता बेंच
7 मई, 2020	काम की कला को संतुलित करना जीवन संतुलन	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल, सदस्य, अपीलीय प्राधिकारी और अतीत अध्यक्ष, आईसीएसआई
9 मई, 2020	ड्रीम, डेयर, डिलीवर	सुश्री प्रिया कुमार, प्रेरक अध्यक्ष
11 मई, 2020	भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव अवसर और खतरा	श्री इंजेती श्रीनिवास, पूर्व सचिव, एमसीए
13 मई, 2020	निर्धारण और यूपीएसआई का प्रकटीकरण – केस स्टडीज	श्री वी. सुंदरेशन कार्यकारी निदेशक, सेबी
14 मई, 2020	योग : तनाव को दूर करने के तरीके	स्वामी रामदेव, योग गुरु डॉ. गिरीश आहूजा, पूर्व परिषद सदस्य, आईसीएसआई सीएस सतविंदर सिंह, पूर्व परिषद सदस्य, आईसीएसआई
16 मई, 2020	अवसर में परिवर्तन की चुनौतियाँ	श्री अमोघ लीला प्रभु, उपाध्यक्ष, इस्कॉन मंदिर द्वारका
18 मई, 2020	आत्मनिर्भर भारत एक नए भारत की सुबह	श्री सुरेश प्रभु, संसद के माननीय सदस्य, राज्यसभा श्री के जे अल्फोंस, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा श्री आशुतोष शर्मा, भारत सरकार के सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग श्री अतुल सोबती, महानिदेशक, SCOPE श्री नारायणन सदानंदन, एमडी और सीईओ, एसबीआई पेंशन फंड्स लिमिटेड श्री निक्सन जोसेफ, अध्यक्ष और सीओओ, एसबीआई फाउंडेशन श्री अमित गोयनका, निदेशक, विनब्रिड प्राइवेट लिमिटेड और कार्यकारी संपादक सीएसआर टाइम्स
21 मई, 2020	सोशल मीडिया और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका	श्री प्रियांक कानोंगो, अध्यक्ष, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग श्री सुनील कुमार, निदेशक (एचआर और ईबी),

		एमटीएनएल प्रो मुक्ति कांता मिश्रा, सह-संस्थापक और अध्यक्ष, संचुरियन विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन श्री वेंकट के नारायण, सीईओ प्रेस्टिज ग्रुप, श्री राकेश माहेश्वरी, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, मीटी, जीओआई श्री डी के अग्रवाल, अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई
22मई, 2020	सेबी LODR – ए जर्नी सो फार	श्री खुशरू बुलसारा, सीजीएम लिस्टिंग, बीएसई लिमिटेड श्री नीरज कुलश्रेष्ठ, मुख्य नियामक अधिकारी, बीएसई लिमिटेड सीएस बी. रंगनाथन, कार्यकारी उपाध्यक्ष एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सुश्री इशिता शर्मा, प्रबंधक, कॉर्पोरेट वित्त विभाग, सेबी
23मई, 2020	निवेशक शिक्षा और संरक्षण में IEPFA की भूमिका	श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय डॉ. कामाख्या नृ सिंह IEPF, चेयर, प्रोफेसर, IICA डॉ. नवीन जे सिरौही हेड, स्कूल ऑफ फाइनेंस, IICA
25मई, 2020	संकट प्रबंधन: नए युग के रणनीतिक व्यावसायिकता	श्री संदीप एम. तमगडगे, आईपीएस एडल. डीजीपी, नागालैंड
29मई, 2020	स्वास्थ्य जीवन का एक तरीका	श्री किरन रिजिजू, युवा मामलों और खेल मंत्री (आई/टी) श्री गगन नारंग, ओलंपिक पदक विजेता श्री मनीष बटाविया, खेल टीकाकार श्री संदीप प्रधान, आईआरएस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सुश्री एकता विश्वा (आईआरएस), मिशन डायरेक्ट
5 जून, 2020	विश्व पर्यावरण दिवसरू प्रकृति के लिए समय	सुश्री सुमैरा अब्दुलाली, पर्यावरणविद् और संस्थापक, आवाज फाउंडेशन सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई और संपादक, डाउन टू अर्थ सीएस (डॉ।) पी वी एसजेगन मोहन राव, पूर्व राष्ट्रपति द आईसीएसआई
8 जून, 2020	डैडमैरु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नया युग उत्प्रेरक	श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार श्री राजीव चावला, अध्यक्ष, इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया
10 जून, 2020	यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग	डॉ. किरण बेदी, पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल श्री अनिल गुप्ता, परिषद सदस्य (सरकार नामित), आईसीएसआई
13 जून, 2020	साइबर सुरक्षा धमकी और चुनौतियां	डॉ. वरुण कपूर, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस निदेशक, मध्य प्रदेश
16 जून, 2020	साधारण चेहरे, अतिरिक्त साधारण कार्य लोगों के जीवन में अंतर लाना	पदम श्री डॉ। प्रकाश आमटे और डॉ। मंदाकिनी आमटे, (मैगसेसे पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता संस्थापक, लोक बिरादरी प्रचारक)
17 जून, 2020	कॉर्पोरेट लीडर के लिए आईटी सशक्तीकरण	श्री अजय पांडे, महाप्रबंधक – आईटी सेवा सॉफ्टेल सॉल्यूशंस प्राइवेट। लिमिटेड श्री रुषम शाह, वीपी (मार्केटिंग एंड सेल्स), स्वर्णिमटच सॉल्यूशंस प्रा। लिमिटेड
21 जून, 2020	योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस : कल्याण और प्रतिरक्षा	सीएस प्रीति मल्होत्रा, निवारक हेल्थकेयर क्रूसेडर, अध्यक्ष, स्मार्ट भारत समूह, भारत

	तथा घर घर में योग	डॉ नम्रता बागोरिया, हेल्थ इवेंजलिस्ट और पॉडकास्टर फॉर हेल्थ 4.0, कनाडा, डॉ पामेला स्मिथ, एंटी-एजिंग एंड फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यूएसए डॉ। शबनम दास कर, फंक्शनल एंड मेटाबोलिक मेडिसिन, कनाडा में विशेषज्ञ सीए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पूर्व सीसीएम, सरकार नामित सीए अनिल गुप्ता, सीसीएम सरकार नामित प्रोफेसर डॉ। तनुजा मनोज केसरी, निदेशक एआईआईए सीएस सुधीर जैन, योग ट्रेनर
27 जून, 2020	ग्रासरूट्स से ग्लोबल शासन	श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा प्रो. रमेश अरोड़ा, अध्यक्ष, विकास अकादमी और पूर्व प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल, सदस्य, अपीलीय प्राधिकारी और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई
3 जुलाई, 2020	जीवन प्रबंधन कौशल सफलता के लिए	स्वामी अक्वेशनन्द गिरि जी महाराज, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, इंदौर के पूर्व मेयर और विधान सभा सदस्य, म.प्र
24 जुलाई, 2020	कंपनी सचिव का सशक्तीकरण पेशा: अंतर्राष्ट्रीय दृश्य	सीएस नितिन बी कोटक, रणनीतिक वित्त और आर्थिक सलाहकार सीए कुणाल सिंघानिया, बाइस राष्ट्रपति बाहरी रिपोर्टिंग, अमेरिकन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क शहर सीएस लक्ष्मी कांत गर्ग, अध्यक्ष आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए सीएस रेणुका रमन, उपाध्यक्ष, आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए
11 अगस्त, 2020	कॉर्पोरेट प्रशासन और नेतृत्व सिनर्जिस्टिक नेक्सस बनाना	प्रोफेसर बी एस सहाय, निदेशक, आईआईएम जम्मू श्री राजीव भदौरिया, सह-संस्थापक, माई ट्रांसफॉर्म डॉ. जाबिर अली, प्रोफेसर अर्थशास्त्र और व्यावसायिक पर्यावरण, आईआईएम जम्मू डॉ. मुकबिल बुरहान, अध्यक्ष कार्यकारी शिक्षा, पंड जम्मू सीए रजत जैन, मुख्य लेखा अधिकारी, आईआईएम जम्मू
22 अगस्त, 2020	कोविड-19 और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के दौरान सेबी द्वारा छूट	श्री प्रदीप रामकृष्णन, महाप्रबंधक, सेबी सुश्री रोशन सारा चेरियन, एजीएम, सेबी
27 अगस्त, 2020	निधी कंपनियों के लिए नियामक नियम	श्री राजेश वर्मा, आईएस, सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री एस के वशिष्ठ, उप सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सीएस वी श्रीधरन, विगत परिषद सदस्य, आईसीएसआई
1 सितंबर, 2020	राष्ट्रीय व्यापार के राष्ट्रीय लाइव वेबिनार	श्री राजेश वर्मा, आईएस, सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

		श्री के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
4 सितंबर, 2020	वीसी और ओएवीएम बैठकें का नून, प्रौद्योगिकी और लोग	सीएस सुधाकर सारस्वतुला, उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट सचिवीय), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
7 सितंबर, 2020	निवेशक शिक्षा और जागरूकता	श्री राजेश वर्मा, आईएस, सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री के पी कृष्णन, आईएस, पूर्व सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और IEPFA अध्यक्ष श्री नवनीत चौहान, महाप्रबंधक, IEPFA
8 सितंबर, 2020	2020 निवेशक सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता पर एसोचैम के साथ संयुक्त वेबिनार	श्री मनोज पांडे, आईआरएस संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री जे. एन. गुप्ता, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सेबी श्री एस के जिंदल, अध्यक्ष, कमोडिटी मार्केट्स पर राष्ट्रीय परिषद, एसोचैम श्री लव चतुर्वेदी, सह अध्यक्ष, पूंजी बाजार और निवेशक सुरक्षा परिषद, एसोचैम सुश्री मोना मिडे, प्रबंध भागीदार, डेव और गिरीश एंड कंपनी श्री के सुकुमारन, पूर्व डीन, एनआईएसएम श्री खुशरू बुलसारा, प्रमुख – आईपीएफ, बीएसई लिमिटेड श्री ऋषि नाथनी, प्रमुख बीडी और मार्केटिंग, एमसीएक्स सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई
10 सितंबर, 2020	को भारत सरकार के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडशिप पर संयुक्त शिखर सम्मेलन एसोचैम के साथ संयुक्त रूप से	श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों और वित्त मंत्रालय डॉ एम एस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई सीएस प्रीति मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष द आईसीएसआई डॉ निरंजन हीरानंदानी, अध्यक्ष, एसोचैम और संस्थापक और प्रबंध निदेशक, हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई श्री विनीत अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोचैम और प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम लिमिटेड श्री आशीषकुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड। श्री दीपक सूद, महासचिव, एसोचैम सुश्री केरी वार्निंग, सीईओ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क (U.K.) और जापान वित्तीय सेवा एजेंसी के सदस्य विशेषज्ञ
12 सितंबर, 2020	ई-फॉर्म पीएस-6 दाखिल करने में जटिलताओं पर वेबिनार	सीएस मकरंद जोशी, प्रैक्टिसिंग सचिव
16 सितंबर, 2020	निवेश के अवसरों और चुनौतियों पर वेबिनार 2020	श्री खुसरो बुलसारा, प्रमुख – आईपीएफ बीएसई लिमिटेड श्री राजीव गर्ग, क्षेत्रीय प्रमुख, बीएसई – उत्तर श्री प्रतीक मोहन, सीडीएसएल, दिल्ली श्री हरबिंदर सिंह सोखी, बीएसई आईपीएफ

(ii) पीसीएस दिवस (15 जून)

यह तिथि विश्वास के प्रदर्शन की याद दिलाने, विश्वास को सौंपने और इस पेशे के ब्रिगेड में अधिक से अधिक जिम्मेदारी के अंकन का एक उदाहरण है, अर्थात्, नियामक अधिकारियों द्वारा कंपनी सचिवों में प्रैक्टिस और राष्ट्र भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

पीसीएस दिवस, 2019

इस भावना को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2019 में पीसीएस दिवस को एक पूरे सप्ताह तक फैला दिया गया, जिसके तहत 15-22 जून, 2019 के दौरान क्षेत्रीय परिषदों और अध्यायों में पैन इंडिया पीसीएस इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीसीएस दिवस, 2020

15 जून, 2020 को सरकार और भारत इंक के गणमान्य व्यक्तियों के साथ आईसीएसआई पीसीएस दिवस के समारोह का आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और द्वारा की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों और उनके पते ने सदस्यों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक नया उत्साह प्रदान किया।

(iii) राष्ट्रीय पीसीएस सम्मेलन

व्यावसायिक कंपनी सचिवों का 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन 5 एवं 6 जुलाई 2019 को बेंगलुरु में “पेशेवर उत्कृष्टता का गतिशील विस्तार (Expanding Dynamics of professional Excellence)” विषय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद और सर्वश्रेष्ठ शाखाओं के पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम ने आईसीएसआई की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के शुभारम्भ को रेखांकित किया जो इस प्रकार हैं :

- (i) विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (UDIN) पोर्टल
- (iii) कर्मचारी कंपनी सचिव पहचान संख्या (eCSin) दिशानिर्देश
- (iii) व्यावसायिक कंपनी सचिव – रेडी रेकनर
- (iv) सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार
- (v) आईसीएसआई वेबसाइट को नया रूप
- (vi) पीसीएस पोर्टल

(iv) पूँजी बाजार सप्ताह-भारतीय पूँजी बाजार-विजन 2022 को पुनः परिभाषित करना

आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु पूँजी बाजार में सुशासन की संरचना को मजबूत करने के लिए, संस्थान पुरे देश में मेगा इवेंट्स के रूप में एक कार्यक्रम वार्षिक पूँजी बाजार सप्ताह मना रहा है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, “आईसीएसआई पूँजी बाजार सप्ताह –2019” का आयोजन 9-17, 2019 के दौरान भारतीय पूँजी बाजार-विजन 2022 को फिर से परिभाषित करने के थीम पर किया गया। मेगा कार्यक्रम कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किए गए।

पूँजी बाजार सप्ताह के दौरान मुंबई में ‘एम्प्लिफाइंग प्रोफेशनल होराइजन्स – गैनिंग नेशनल ग्रोथ’ विषय पर एक मेगा कार्यक्रम 10 अगस्त 2019 को श्री जी. महालिंगम, पूर्णकालिक सदस्य, सेबी, मुख्य अतिथि के रूप में और श्री आशीष कुमार चौहान, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बीएसई लिमिटेड, सम्मानित अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में मनाया गया।

(v) कंपनी सचिवों का 47वां राष्ट्रीय अधिवेशन

राष्ट्रीय अधिवेशन “न्यू इंडिया – रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म” विषय के तहत आयोजित किया गया, कंपनी सचिवों का 47वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, जयपुर, राजस्थान में 14 नवंबर, 2019 –16 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया। तीन दिवसीय कार्यक्रम को कई तकनीकी और विशेष सत्रों में विभाजित किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संसद सदस्य श्री रामचरण बोहरा ने की। अधिवेशन के समापन सत्र के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, डॉ. सतीश पूनिया और श्री आशीष चौहान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीएसई लिमिटेड की गरिमामयी उपस्थिति रही। कंपनी सचिवों द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों और आईसीएसआई को उनके प्रेरक शब्दों के साथ मार्गदर्शन प्रदान किया।

(vi) कॉर्पोरेट सीएस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

कॉर्पोरेट सीएस का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 4-5 जनवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के कर-कमलों से हुआ। पेशेवरों की बदलती भूमिका और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन का विषय “अनुपालन से परे शासन : कंपनी सचिवों के लिए क्षितिज का विस्तार करना” पर केंद्रित किया गया था। इसमें पूरे देश से लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यावसायिक हित के क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रेरक तथा विशेष सत्रों के तीन तकनीकी सत्र शामिल थे। दो विशेष सत्र बोर्ड की अपेक्षाओं : सीएस को कैटलिस्ट टू बोर्ड फंक्शनिंग और साइबर थ्रेफ्ट को समर्पित थे।

(vii) 71वां गणतंत्र दिवस— 2020 का उत्सव

संस्थान ने 26 जनवरी, 2020 को मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और देश भर की शाखाओं में ध्वजारोहण के माध्यम से 71वाँ गणतंत्र दिवस, 2020 मनाया। कई अन्य कार्यक्रम शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में आयोजित किए गए।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस—2020 का उत्सव

आईसीएसआई ने 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया, इंदौर शाखा द्वारा एक पूरे दिन का सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अध्यक्षता सुश्री आर्यमा सान्याल, विमानपत्तन निदेशक ने की। महिला दिवस को विभिन्न अन्य आईसीएसआई शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में बहुत धूमधाम से मनाया गया।

(ix) फिट इंडिया—फिट आईसीएसआई वॉकथॉन

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने हाल ही में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ 4 अक्टूबर, 2019 को अपना स्थापना दिवस मनाया। आईसीएसआई ने संस्थान के सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखा कार्यालयों में अखिल भारतीय फिट “इंडिया फिट आईसीएसआई” वॉकथॉन का आयोजन किया। सदस्यों और छात्रों ने अपने साथियों के साथ वॉकथॉन में भाग लिया, जिसे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए फिटनेस शपथ का भी संचालन किया गया। इस कार्यक्रम को भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भी सराहना की।

(x) आईसीएसआई का 51वां स्थापना दिवस

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का 51वां स्थापना दिवस 5 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की सौम्य और गरिमामयी उपस्थिति में मनाया गया। अपने संबोधन के दौरान, माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि “कंपनी सचिवों ने भारत के विकास और वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम वास्तव में, आपके योगदान, कड़ी मेहनत और सफलता पर गर्व करते हैं। देश के प्रथम नागरिक के आलावा, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय य श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री इंजेलि श्रीनिवास ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कंपनी सचिवों द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों और आईसीएसआई का अपने प्रेरक शब्दों के साथ मार्गदर्शन किया।

(xi) संकल्प से सिद्धि – एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त आईसीएसआई

आईसीएसआई के स्थापना दिवस का उत्सव अपने इच्छित लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दुहराने और एक स्थायी राष्ट्र निर्माण और समाज एवं हितधारकों की अभूतपूर्व तरीके से सेवा करने का दिन था। इस दृष्टि के अनुसरण में और भारत @ 75 – संकल्प से सिद्धि को दृष्टि की थीम को ध्यान में रखते हुए, आईसीएसआई ने उत्तरदायित्व के प्रति कदम बढ़ाया है और ‘एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त आईसीएसआई’ की पहल शुरू करके ‘एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत’ के राष्ट्रीय मिशन में योगदान करने का मंतव्य प्रकट किया है।

(xii) प्रतिभूति कानून और पूंजी बाजार पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला

संस्थान ने 5-7 जून, 2020 के दौरान प्रतिभूति कानून और पूंजी बाजार पर 3 दिनों की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। माननीय न्यायमूर्ति जोग सिंह, पूर्व न्यायिक सदस्य, सैट उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। कैपिटल मार्केट्स, सेबी (एलओडीआर)(LODR) रेगुलेशन, सेबी अधिनियम, 1992, शासन चुनौतियाँ, आंतरिक व्यापार, आदि से संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

(Xiii) स्वतंत्र निदेशकों के परिचय के लिए कार्यक्रम

एमसीए (MCA) एवं आईआईसीए (IICA) ने स्वतंत्र निदेशकों के संस्थान को मजबूत करने के उद्देश्य से कंपनी निदेशक अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक का डेटाबैंक लॉन्च किया। भारत इंक के शासन ढांचे को मजबूत करने में आईडी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आईसीएसआई ने आईआईसीए के साथ मिलकर स्वतंत्र निदेशकों के परिचय के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। 20 जून, 2020 को 3 घंटे के ऑनलाइन कौंउज आयोजित किया गया जिसमें स्वतंत्र निदेशक के लिए संभूति और स्वतंत्र निदेशक एवं आचार संहिता तथा आचार संहिता और देयता में अपरिहार्य सम्यक् तत्परता से संबंधित पहलुओं को कवर किया गया।

(xiv) नया दौर नए अवसर(New Dynamics New Opportunities) पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला

संस्थान ने 23-24 मई, 2020 के दौरान नए डायनेमिक्स न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज विषय पर अपनी तरह के दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। दो दिवसीय कार्यशाला में संस्थान के सदस्यों और छात्रों सहित 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। दो दिनों के विचार-विमर्श के दौरान समकालीन विषयों जैसे आरईआरए, मध्यस्थता, सचिवीय ऑडिट—स्कोप, योजना और रणनीतियाँ, एनजीओ, सोसायटी, निधि कंपनी, निर्माता कंपनियों, सीएसआर, फेमा, एमएसएमई को कवर किया गया। सफलता और संतुष्टि की ओर एक यात्रा पर एक प्रेरक सत्र भी आयोजित किया गया।

(xv) आईपीएफ प्राधिकरण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2019 को धर्मशाला में आयोजित निवेशक शिक्षा और जागरूकता पर राज्य स्तरीय सम्मेलन

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन और एक मेगा कैरियर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का उद्देश्य

धर्मशाला के युवाओं के बीच कंपनी सचिव के तौर पर उनके पास उपलब्ध विभिन्न निवेश और कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना था ताकि वे कई लोगों के बीच एक सूचित निवेश और कैरियर विकल्प बना सकें। कार्यक्रम में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक जबरदस्त प्रतिक्रिया और प्रशंसा प्राप्त की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

(xvi) पीएचडी चौबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (PHDCCI) और स्कोप (SCOPE) के साथ साझेदारी में कार्यशालाएं और कार्यक्रम संस्थान ने पीएचडी चौबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन द्वारा आयोजित दो कार्यशालाओं में सहायक भगीदार की भूमिका निभाई थी। उसका विवरण इस प्रकार है:

- (i) श्रृंखला का छठा कॉन्क्लेव 7 जून, 2019 को पीएचडी चौबर हाउस, दिल्ली में “जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करना (जीएसटीआर-9) और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट (जीएसटीआर-9सी)– आउटवर्ड सप्लाय और इनपुट टैक्स क्रेडिट–खण्ड दर खंड आने वाले मुद्दों और शिकायतों को समझना” विषय पर आयोजित हुआ।
- (ii) 10 जून, 2019 को एससीओपीई(SCOPE),लोदी रोड, नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी विनियमों के तहत नवीनतम घटनाक्रम।
- (iii) 26 जून, 2019 को पीएचडी चौबर हाउस, दिल्ली में आर्थिक और वाणिज्यिक कानूनों के तहत नवीनतम घटनाक्रम पर संगोष्ठी।
- (iv) पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में “जीएसटी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) के व्यावहारिक पहलुओं और खण्ड दर खंड फॉर्म को कैसे भरें” पर जीएसटी कॉन्क्लेव।
- (v) 19 जुलाई, 2019 को जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा : सुशासन सलाहकार पर सम्मेलन।
- (vi) 24 जुलाई, 2019 को “सीमा शुल्क और जीएसटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन – केंद्रीय बजट 2019 और जीएसटी बाहरी आपूर्ति-प्रासंगिक एडवांस रूलिंग और जीएसटीआर-9 और 9 सी के साथ विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विश्लेषण और चर्चा” पर जीएसटी कॉन्क्लेव।
- (vii) एससीओपीई (स्कोप)कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 3 दिसंबर, 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत हाल के परिवर्तनों पर संवादमूलक सत्र।

(xvii) वर्तमान खंड 2017-20 के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए दिशानिर्देशों में छूट

कोविड-19 और अखिल भारतीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परामर्श के दृष्टि से , 2017-20 के वर्तमान खंड के लिए अनिवार्य पीएचपी प्राप्त करने की समयावधि को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। गया है। पुनः, अनिवार्य पीसीएच (2017-20 के वर्तमान खंड के लिए) प्राप्त करने में सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) वेबिनार के माध्यम से अधिकतम 8 (आठ) पीसीएच की सीमा में ढील दी गई है और सदस्य बिना किसी सीमा के वेबिनार के माध्यम से पीसीएच के हकदार होंगे।
- (ii) सदस्य ऑनलाइन मूल्यांकन मॉड्यूल को अर्हता प्राप्त करके 60 पीसीएच तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल में शामिल होने का शुल्क 1000 रुपये, जीएसटी होगा।
- (iii) सदस्य नामांकन के समय प्रत्येक पीएमव्यू/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए 10 पीसीएच भी प्राप्त कर सकते हैं।
- (iv) ऐसे सदस्यों को 1 अप्रैल, 2020 से वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की अनुमति है, जो 30 सितंबर, 2020 तक पीसीएच की आवश्यकता में कमी को पूरा करने का एक शपथपत्र प्रस्तुत करते हैं।

(xviii) ई-क्रेडिट घंटे की सुविधा

सुविधा की दृष्टि से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के वर्तमान खंड के लिए क्रेडिट घंटे प्राप्त करने हेतु आईसीएसआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सदस्यों को , परिषद ने ई-लर्निंग कार्यक्रमों/वेबिनार, ऑनलाइन परीक्षा और प्रमाणन पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से क्रेडिट घंटे प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(xix) सदस्यों के लिए एक विशेष ऋण योजना का शुभारंभ

संस्थान ने पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संस्थान के सदस्यों के लिए एक अनूठी ऋण योजना की सुविधा प्रदान की। ऋण अपनी व्यावसायिक & व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए दर्जी हैं। वही किसी भी कोलेटरल या पूर्वभुगतान शुल्क के बिना उपलब्ध है और ऋण आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से वदसपदमजीने भौतिक यात्रा की कठिनाइयों को दूर कर रही है।

(xx) आईसीएसआई सतत प्राविधिक शिक्षा: स्व-मूल्यांकन मॉड्यूल

प्रोग्राम क्रेडिट घंटे प्राप्त करने की आवश्यक आवश्यकता को पूरा करने में हमारे सदस्यों की सहायता करने के प्रयास में, संस्थान ने 16 मार्च, 2020 को आईसीएसआई सतत व्यावसायिक शिक्षा: स्व-मूल्यांकन मॉड्यूल के तत्वावधान में एक अनूठी पहल की। तीन मॉड्यूल 2017-20 के ब्लॉक के लिए, पहल के अंतर्गत सदस्य को तीन वर्ष 2017-20 के ब्लॉक के लिए, प्रत्येक मॉड्यूल अर्हता के लिए 10 पीसीएच प्राप्त करने और प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदान किए गए छह मॉड्यूल में से किसी में ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने का एक विकल्प है। सदस्य 30 सितंबर, 2020 तक प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। 31 जुलाई, 2020 को कार्यक्रम के तहत कुल पंजीकरण संख्या 2438 थी।

(xxi) आईसीएसआई (सतत व्यावसायिक शिक्षा) दिशानिर्देश, 2019

सदस्यों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए पूर्व दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं और 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो गए हैं। ये दिशानिर्देश सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होंगे चाहे वे व्यवहार में हों या अन्यथा न हो। संस्थान के सभी सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संरचित और असंरचित शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एक वर्ष में 20 सीपीई क्रेडिट सुरक्षित करें। हालांकि, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में अतिरिक्त कार्यक्रम क्रेडिट घंटे को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xxii) आईसीएसआई ऑनलाइन क्रैश कोर्स

- संगठनों के साथ-साथ पेशेवरों को भी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन स्थिति में भी पेशेवरों को निरंतर और अद्यतन ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। कंपनी सदस्यों के पेशे पर प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में सदस्यों के लिए अद्यतन ज्ञान की आवश्यकता को साकार करते हुए आईसीएसआई ने निम्न विषयों पर ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किए हैं
 - (i) प्रतिभूति कानून की शिकायतें
 - (ii) बौद्धिक संपदा अधिकार
 - (iii) पंचाट से संबंधित कानून और
 - (iv) पेशेवरों के लिए आईटी उपकरण
 - (v) दिवाला और दिवालियापन संहिता
 - (vi) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
 - (vii) कॉर्पोरेट बैठकें
 - (viii) लेखापरीक्षा, रिपोर्ट और प्रमाणपत्र
 - (ix) कॉर्पोरेट पुनर्गठन
 - (x) सीए, 2013 के तहत अपराध और दंड प्रावधान

आईसीएसआई ऑनलाइन क्रैश पाठ्यक्रम का उद्देश्य त्वरित और निर्बाध शिक्षा प्रदान करना है। ये पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव वेबिनार और वीडियो आधारित व्याख्यान के माध्यम से दिए जाते हैं, इसके बाद कुछ पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन और परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर उम्मीदवारों को आईसीएसआई पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान करता है। अप्रैल, 2020 से आगे बढ़ते हुए, पाठ्यक्रमों को 2286 से अधिक सदस्यों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और संचयी पंजीकरण प्राप्त हुआ है।

(xxiii) आईसीएसआई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(i) पेशे पर प्रभाव रखने वाले क्षेत्रों के लिए अद्यतन ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए, आपके संस्थान ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं:

- प्रमाणित सीएसआर पेशेवर
- माल और सेवा कर
- फोरेसिक ऑडिट
- पॉश (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- महिला निर्देशक
- चालू होना
- फेमा
- वाणिज्यिक अनुबंध प्रबंधन
- RERA
- एमएसएमई
- स्वतंत्र निदेशक
- साइबर सुरक्षा

(ii) कुल, 3485 संख्या में उम्मीदवार संचयी रूप से इन प्रमाणिक पाठ्यक्रमों में अपने नित्य विकास और ज्ञान आधार के अपडेशन के लिए पंजीकृत हैं।

(iii) इन पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन मूल्यांकन और परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इंटरैक्टिव वेबिनार और वीडियो आधारित व्याख्यान के माध्यम से दिया जाता है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के सफल समापन पर उम्मीदवारों को आईसीएसआई पुरस्कार प्रमाण पत्र।

(xxiv) आईसीएसआई पीएमक्यू पाठ्यक्रम

(i) आपकी परिषद ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पोस्ट सदस्यता योग्यता पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है:

- i) आंतरिक लेखापरीक्षा पर पीएमक्यू पाठ्यक्रम
- ii) पंचाट पर पीएमक्यू पाठ्यक्रम
- iii) CSR पर PMQ कोर्स
- iv) श्रम कानूनों पर पीएमक्यू पाठ्यक्रम

- (ii) इसके अलावा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पीएमव्यू पाठ्यक्रम को पूरी तरह से संशोधित किया गया है और सभी पीएमव्यू पाठ्यक्रम के लिए संशोधित संशोधित तौर-तरीकों के अनुसार पेश किया जा रहा है।
- (iii) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसे अधिक जीवंत बनाने के लिए पीएमव्यू पाठ्यक्रम को नया रूप दिया गया है। इस विषय पर ऑनलाइन वेब-आधारित कक्षाएं और रिकॉर्डेड व्याख्यान के 25-30 घंटे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, संदर्भ सामग्री 6 अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी। सभी संसाधन आईसीएसआई ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
- (iv) इसके अलावा, मूल्यांकन के तौर-तरीकों को भी संशोधित किया गया है, जिसके तहत MCQ आधारित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, यह प्रतिपादित किया जाएगा कि इसे कहीं से भी लिया जा सकता है और इसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा अर्थात् जून और दिसंबर। आगे की,
- (v) इसके अलावा उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और प्रस्तुति देनी होगी जो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकती है। इनमें से प्रत्येक के लिए पासिंग मार्क्स 50: हैं।
- (vi) ऑनलाइन मोड में वर्ष भर प्रवेश खुला रहेगा। 1 जनवरी से 30 जून के बीच पंजीकृत अभ्यर्थी— एक ही वर्ष दिसंबर में परीक्षा के प्रयास में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच पंजीकृत उम्मीदवार परीक्षा के जून के प्रयास में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।

5. सुविधा और मानक

(i) आईसीएसआई (कंपनी सचिवों की उपस्थिति और आचरण के लिए दिशानिर्देश), 2020

इन दिशानिर्देशों के पीछे का अभिप्राय न्यायालयों, वैधानिक निकायों और अर्ध न्यायिक निकायों जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सेबी, सीसीआई आदि के समक्ष उपस्थिति के लिए शिष्टाचार और सदाचार के नियमों को प्रदान करना, प्राधिकरण के लिए सम्मान सुनिश्चित करना और कंपनी सचिवों के पेशे की गरिमा बनाए रखना, कंपनी सचिवों को न्यायिक अधिकारियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार से रोकने और नियामकों के बीच एक पेशेवर छवि बनाने और कंपनी सचिवों के पेशे के लिए एक ब्रांड का निर्माण करना है।

पुरुष सदस्यों के लिए

ए। नेवी ब्लू सूट (कोट और पतलून), अधिमानतः सीएस लोगो / इसिग्निया या नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ एक शांत रंग के ट्राउजर, इनसिग्निया पर

ख। नेक टाई (आईसीएसआई)

सी। सफेद पूर्ण आस्तीन शर्ट

डी। औपचारिक जूते

महिला सदस्यों के लिए

ए। नेवी ब्लू कॉर्पोरेट सूट (कोट और पतलून), अधिमानतः सीएस लोगो / प्रतीक चिन्ह के साथ अथवा

ख। सीएस लोगो के साथ नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ साड़ी / किसी अन्य पोशाक की पोशाक, इसिग्निया

सी। एक सौम्य जूते / Bellies / वेजेस, आदि

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (प्रोटोकॉल गाइडलाइंस), 2019

“द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (प्रोटोकॉल गाइडलाइंस), 2019 ‘के तत्वावधान में दिशानिर्देशों का एक और सेट, एक योजनाबद्ध और पेशेवर तरीके से संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य औपचारिक घटनाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रदान करता है जिससे प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए एक केंद्रित शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके।

(iii) आईसीएसआई विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड योजना

संस्थान द्वारा गठित 20 सदस्यों वाले विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड, कॉर्पोरेट कानूनों, प्रतिभूति कानूनों, कानूनी सलाहकार, वित्त, मीडिया और समृद्ध उद्योग के अनुभव वाले अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समूह है। बोर्ड कॉर्पोरेट और सुरक्षा कानून से संबंधित विभिन्न मामलों में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

संस्थान की परिषद ने बोर्ड की सेवाओं के प्रतिपादन / लाभ के लिए एक योजना को मंजूरी दी, ऐसी योजना को आईसीएसआई विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड योजना, 2020 के रूप में नामित किया गया है।

(iv) इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम पर मार्गदर्शन नोट

निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल प्रतिभूति बाजार का अस्तित्व किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक अवयवों में से एक है। प्रतिभूति बाजार में विश्वास, विश्वास और अखंडता को स्थापित करने के लिए, सेबी ने निष्पक्ष बाजार आचरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 को पहले के 1992 पीआईटी विनियमों को बदलने के लिए प्रेरित किया है। आईसीएसआई ने अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) पर एक गाइडेंस नोट

निकाला, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम पर गाइडेंस नोट के तत्वाधान में है, जिसका उद्देश्य पीआईटी विनियमों पर आवश्यक मार्गदर्शन और विवरण प्रदान करना है। जहाँ भी आवश्यक हो।

(v) सचिवीय मानकों की प्रयोज्यता पर मार्गदर्शन

देश में प्रचलित कोविड कोविड -19 के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने हितधारकों द्वारा अनुपालन में आसानी के लिए शिथिल कर दिया है।

एमसीए द्वारा दी गई छूटों के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल (SS-1) की बैठक में सचिवीय मानक के अनुपालन पर सदस्यों के प्रश्न और सामान्य बैठक (SS-2) पर सचिवीय मानक उपयुक्त मार्गदर्शन जारी करने के बाद संबोधित किए गए। आईसीएसआई द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन प्रकृति में स्वेच्छिक था और एमसीए द्वारा दी गई छूट के अनुरूप था और एमसीए द्वारा विस्तारित विश्राम की अवधि के लिए ही लागू होगा। SS-1 और SS-1 पर उक्त मार्गदर्शन आईसीएसआई के सभी सदस्यों को प्रसारित किया गया है और सचिवीय मानकों के अनुपालन की सुविधा के लिए आईसीएसआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

(vi) आईसीएसआई ऑडिटिंग मानकों पर मार्गदर्शन नोट

हितधारकों द्वारा मानकों के अनुपालन की सुविधा के लिए और आईसीएसआई ऑडिटिंग मानकों में निहित विभिन्न प्रावधानों के व्यावहारिक पहलुओं की व्याख्या करने के लिए, आईसीएसआई ऑडिटिंग मानकों पर मार्गदर्शन नोट्स आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए थे। ऑडिटिंग मानकों पर इन दिशानिर्देश नोट्स को आईसीएसआई ऑडिटिंग मानकों [सीएसएएस-1 से सीएसएएस-3] में निहित विभिन्न प्रावधानों के स्पष्टीकरण, प्रक्रियाओं और व्यावहारिक पहलुओं को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि हितधारकों द्वारा अनुपालन की सुविधा प्रदान की जा सके।

6. कारपोरेट शासन प्रणाली को सुदृढ़

(i) सीएस विनियम

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद संस्थान ने कंपनी सचिवों के विनियम, 1982 को कंपनी सचिवों (संशोधन) विनियम, 2020 में संशोधन किया है। कंपनी सचिवों (संशोधन) विनियमों की अधिसूचना, 2020 दिनांक 03 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। दिनांक 03 फरवरी, 2020। कंपनी की विनियम, 1982 की संशोधित तिथि तक संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ii) वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट पर मार्गदर्शन नोट

भारतीय कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सेबी में अनुपालन अनुपालन तंत्र की बढ़ती आवश्यकता को महसूस करते हुए, सेबी 08 फरवरी, 2019 को परिपत्र के साथ सामने आया, जिसमें वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट को कंपनी सचिव द्वारा प्रैक्टिस में सूचीबद्ध संस्था को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। वार्षिक आधार, सभी लागू सेबी विनियमों और परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में जारी किए गए। संस्थान ने 3 अप्रैल 2019 को इस दिशानिर्देश नोट को सभी हितधारकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए कार्य को पूरा करने के लिए संस्थान के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए लाया। यह दिशानिर्देश नोट वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट की प्रक्रिया और दायरे पर प्रकाश डालता है और सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य कानूनों के संबंध में विस्तृत जाँच भी प्रदान करता है।

(iii) बोर्ड मूल्यांकन के लिए एक गाइड

बोर्ड की रणनीतिक योजना में उल्लिखित परिणामों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड मूल्यांकन सीधे बंधा हुआ है। उसी के मद्देनजर, यह प्रकाशन बोर्ड मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय रुझानों, भारत में कानूनी ढाँचे, कदम उठाने, मूल्यांकन के बाद की गतिविधियों और बोर्ड मूल्यांकन के लिए बाधाओं की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करता है। बोर्ड मूल्यांकन और भारत में प्रचलित कानूनी ढाँचे, कार्यप्रणाली, मापदंडों और अन्य पहलुओं में अंतरराष्ट्रीय रुझानों और प्रथाओं को शामिल करने वाला संशोधित संस्करण इस गतिविधि को करने में एक सही संदर्भ और मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में प्रकाशन जारी किया गया था।

7. क्षमता निर्माण

(i) बोर्ड की रिपोर्ट पर संदर्भकर्ता

यह तथ्य कि बोर्ड की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इस तथ्य से समझा जा सकता है कि न केवल दस्तावेज को वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, बल्कि इसमें शामिल सामग्री भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित की गई है। बोर्ड की रिपोर्ट पर संदर्भकर्ता एक व्यापक दस्तावेज है जो नमूना प्रारूप, चेक सूचियों आदि का विवरण देता है।

(ii) ई-फॉर्म पीएस-6 पर संदर्भकर्ता

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों के आवंटन) नियम, 2014 के नियम 9ए द्वारा शासित प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को प्रैक्टिस में एक कंपनी सेक्रेटरी या व्यवहार में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रत्येक छमाही के निष्कर्ष से साठ दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को पीएस-6 जमा करना आवश्यक है। पीएस-6 पर यह रेफरेंसर पीएस-6 के प्रमाणन पहलुओं पर पेशेवरों को मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पीएस-6 को प्रमाणित करते समय सामना किए गए व्यावहारिक मुद्दों का समाधान करता है।

(iii) वर्चुअल मीटिंग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महामारी, भारत इंक की कार्यप्रणाली की वजह से दवतउंस नए सामान्य 'की स्थिति को देखते हुए, इसके महत्व को लागू करते हुए लागू कानूनों का पालन आभासी मोड में स्थानांतरित हो गया है। बोर्ड की बैठकें और अन्य बैठकें ऑडियो और वीडियो साधनों के लिए हुई हैं। नियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई ये छूट न केवल प्रौद्योगिकी के साथ बल्कि कानूनों के साथ परिचित करने की आवश्यकता को भी अपने साथ ले आई है ताकि सच्चे पत्र और भावना में उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। संस्थान ने 9 सितंबर, 2020 को इस प्रकाशन को आभासी माध्यमों से बैठकें आयोजित करने के पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के इरादे से निकाला है।

(iv) पीसीएस के लिए अनुपालन सॉफ्टवेयर जारी करना

कॉम्प्लिसिटी कंपनी सचिवों के अभ्यास के लिए एक एकीकृत क्लाउड-आधारित अनुपालन प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो उन्हें अपने अभ्यास संचालन का प्रबंधन करने और अपने ग्राहकों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करता है। उक्त अनुपालन सॉफ्टवेयर अगले 3 वर्षों के लिए संस्थान द्वारा सभी कार्यरत कंपनी सचिवों (पीसीएस) को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। कॉम्प्लिसिटी शासन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और उनके ग्राहकों के अनुपालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में पीसीएस की बहुत मदद करेगी। पीसीएस सचिवीय, कानूनी, अनुपालन, अनुबंध, मुकदमेबाजी, समय पत्रक, कार्य ट्रेकर्स तथा इस जैसे कई अन्य मॉड्यूल के माध्यम से अपने अभ्यास को पूरी तरह से डिजिटलाइज और स्वचालित कर सकता है। पीसीएस आज से ही अपना निःशुल्क खाता बनाने के लिए complinty.icsi.edu पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

(v) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा प्रदान की गई विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं के लिए वेतनमान पर आईसीएसआई मार्गदर्शन

विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के पैमाने पर यह मार्गदर्शन, जिसमें अंतर के साथ मार्गदर्शक सिद्धांत शुल्क के पैमाने को तय करने के लिए ग्राहक और पीसीएस के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और पेशेवरों पर लगाए जाने वाले शुल्क के उचित और उचित पैमाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा उनके अनुभव, विशेषज्ञता, जोखिम, परिचालन लागत, जुड़े जोखिम, गलत प्रमाणीकरण के लिए दंड और बाजार की शक्तियों का आधार।

8. स्वतः शासन**(i) ECSIN पर अक्सर पूछे जाने वाले**

प्रश्न कर्मचारी कंपनी सचिवों की पहचान संख्या एक विशिष्ट संख्या है जो संस्थान के प्रत्येक सदस्य द्वारा उत्पन्न होने के लिए अनिवार्य है जो नियुक्ति के समय और इस्तीफे के समय किसी भी क्षमता में रोजगार में है जब तक कि उसी को छूट नहीं दी जाती है। ECSIN की पीढ़ी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके लिए किसी भी दस्तावेज को सदस्य द्वारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। पेशे के नियमन की दिशा में एक कदम के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की काउंसिल ने आईसीएसआई (कर्मचारी कंपनी सेक्रेटरी आइडेंटिफिकेशन नंबर) गाइडलाइंस, 2019 जारी किया, जो इस यूनिक नंबर की पीढ़ी के लिए प्रदान करता है। इन दिशानिर्देशों को 01 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी किया गया था। ECSIN की पीढ़ी में सदस्यों की सुविधा के प्रयास में, संस्थान 10 जनवरी, 2020 को थाफ के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस पुस्तिका के साथ आया था।

(ii) यूडीआईएन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को जारी। प्रमाणित करते समय संस्थान के प्रत्येक प्रैक्टिसिंग मंबर द्वारा जेनरेट करने के लिए अनिवार्य होता है। यूडीआईएन की पीढ़ी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके लिए किसी भी दस्तावेज को सदस्य द्वारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। पेशे के नियमन की दिशा में एक कदम के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की काउंसिल ने आईसीएसआई यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूडीआईएन) गाइडलाइंस, 2019 जारी किया, जो इस यूनिक नंबर (यूडीआईएन) को जेनरेट करने का प्रावधान करता है। ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी किए गए थे। यूडीआईएन की पीढ़ी में सदस्यों की सुविधा के प्रयास में, संस्थान 10 जनवरी 2020 को थाफ के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस पुस्तिका के साथ आया था।

(iii) यूडीएन एमनेस्टी योजना

एक यूडीएन एमनेस्टी योजना 1 सितंबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक एक पीसीएस हो सकती है :

- (i) पहले किए गए यूडीआईएन उत्पन्न करें
- (ii) पीढ़ी के समय दर्ज किए गए यूडीआईएन विवरणों को सुधारें
- (iii) उपयोग नहीं किए गए यूडीएन को रद्द करें।

वैश्विक महामारी कोविड कोविड -19 के प्रसार के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों को देखते हुए, देशव्यापी तालाबंदी के बाद, योजना को 1 सितंबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक ऑनलाइन अनुरोध विंडो देने की पहल की गई।

(iv) आईसीएसआई पीयर रिव्यू मैकेनिज्म

(i) सहकर्मी समीक्षकों के साम्राज्यीकरण के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में लंबाई और चौड़ाई में आयोजित किए गए थे, जहाँ लगभग 70 सदस्यों को सहकर्मी समीक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(ii) देश में लॉकडाउन के दौरान, 17 मई, 2020 और 22 अगस्त, 2020 को दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

(iii) वर्ष २०१६-२० के दौरान, ४५ सहकर्मी समीक्षकों को सूचीबद्ध किया गया और ६४ सहकर्मी समीक्षकों को ०१.०४.२०२० से १५.०६.२०२० तक के लिए सूचीबद्ध किया गया और आज तक ६१० सहकर्मी समीक्षक हैं।

(iv) वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 153 प्रैक्टिस यूनिटों की समीक्षा की गई थी, जो कंपनी के सचिव द्वारा अभ्यास और पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में पीयर रिव्यू ऑफ अट्रेंक्शन एंड ऑडिट सर्विसेज के दिशानिर्देशों के तहत जारी किए गए थे।

(v) 1 अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक की अवधि के दौरान लगभग 135 प्रैक्टिस यूनिट्स की समीक्षा की गई है और सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। आज तक पीर रिव्यू यूनिट्स की संख्या 784 हैं।

(vi) पीयर रिव्यू मैनुअल का तीसरा संशोधित संस्करण 14-16 नवंबर, 2020 के दौरान जयपुर में आयोजित 47 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जारी किया गया

9. गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड

(i) गुणवत्ता की समीक्षा करते समय अपने कर्तव्यों को पूरा करने में गुणवत्ता की समीक्षा करने वालों की सहायता करने के लिए, 10 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन पुरस्कार, 2019 समारोह में गुणवत्ता की समीक्षा के लिए एक गाइड जारी किया गया था।

(ii) गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का पुनरु गठन

कंपनी सचिवों के नियम 8 (1) के अनुसार (गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, और अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की सेवा और भत्ते की शर्तें) नियम, 2006 अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल की गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड चार साल का होगा।

(iii) तदनुसार, बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के कार्यकाल ने वर्ष २०१६-२० के दौरान अपना कार्यकाल पूरा किया:

- सुश्री किरणबेरोईवसुदेव अध्यक्ष
- श्री आशीष कुशवाहा सदस्य
- श्री विनीत के। चौधरी सदस्य

इसके अलावा, सीएस इलम कांबोज ने वर्ष के दौरान इस्तीफा दे दिया

(iv) संस्थान सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके रखरखाव के लिए उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करता है।

(v) मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या G-S-R-339 (E) और G-S-R-33 (E) दिनांक 1 जून, 2020 और 14 जनवरी, 2020 को क्रमशः गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया।

- सुश्री निशि सिंह, पूर्व सदस्य, सीबीडीटी अध्यक्ष
- श्रीदेवेंद्र कुमार, सलाहकार (कॉस्ट), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सदस्य
- श्री मनीष गुप्ता, काउंसिल मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सदस्य
- श्रीप्रमोद कुमार राय, उप-कंपनी सचिव, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के सदस्य

(vi) गुणवत्ता की समीक्षा की गई

Nifty50 / BSE30 कंपनियों के सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रचलित व्यावसायिक सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा और व्यवहारिक समीक्षा बोर्ड के निर्देशन में जिन सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी

10. संस्थान का विभिन्न सरकारी/नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति

भारत में प्राथमिक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देने के लक्ष्य और उद्देश्य से और प्राथमिक बाजार में प्रणाली और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति (पीएमएसी) गठित की है। संस्थान ने मुंबई के सेबी भवन में आयोजित पीएमएसी की बैठकों में भाग लिया।

(ii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित और आईबीबीआई द्वारा प्रशासित मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने के लिए समिति

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को नियमनों पर सिफारिश करने और कंपनियों और पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा अनुपालन के लिए मूल्य निर्धारण मानकों और नीतियों का निर्धारण करने के लिए 'मूल्यांकन मामलों पर सलाहकार समिति' का गठन किया था। उक्त समिति में अध्यक्ष, आईसीएसआई द्वारा आईसीएसआई-आरवीओ का प्रतिनिधित्व किया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(iii) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन की सिफारिश करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित शोधन अक्षमता कानून समिति

विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और संहिता में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधान विकसित हो रहे हैं। संहिता के कार्यान्वयन में शामिल मुद्दों की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए स्थायी समिति के रूप में शोधन अक्षमता कानून समिति के पुनर्गठन पर विचार किया। अध्यक्ष, आईसीएसआई उक्त समिति के सदस्य हैं।

(iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति

मौजूदा ढांचे की समीक्षा और मार्गदर्शन करने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर एक सुसंगत नीति तैयार करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर उच्च स्तरीय समिति-2018 (एचएलसी-2018) का गठन किया गया। सीएस रंजीत पांडे, निकटतम पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई को सीएसआर के भविष्य पर आईसीएसआई और इसके हितधारकों के विचारों को साझा करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(v) सूचीबद्ध और गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग (बीआरआर) प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए समिति

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मार्च 2018 में जारी किए गए जिम्मेदार एनजीआरबीसी, यानी नेशनल गाइडलाइंस ऑन अपडेटेड एनजीआरबीसी के बीआरआर फ्रेमवर्क के आधार पर सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरआर) प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए 2018 में एक समिति का गठन किया था। श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में। 11 अगस्त, 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, श्री राजेश वर्मा द्वारा हितधारकों के लिए रिपोर्ट औपचारिक रूप से जारी की गई है। अध्यक्ष, आईसीएसआई समिति के सदस्य हैं और आईसीएसआई ने बीआरओ प्रारूप के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(vi) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के लिए जाँच पुस्तिका तैयार करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में एसएफआईओ द्वारा जांच की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जांच मैनुअल तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अध्यक्ष, आईसीएसआई समिति के सदस्य हैं। 16 मार्च, 2020 और 26 मई, 2020 को समिति की बैठकें हुईं और बैठकों के दौरान जाँच पुस्तिका की विषय-वस्तु पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

(vii) बीमा विकास एवं भारतीय नियामक प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर समिति

IRDAI वर्ष 2016 में भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और इसे और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए प्राधिकरण ने, दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। सीआईएसआई समिति में संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 28 मई, 2020 को समिति की बैठक आयोजित की गई और उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए

(viii) जीएसटीएन की परामर्श समिति

माल और सेवा कर नेटवर्क ने जीएसटी में मौजूदा प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और विभिन्न उभरते मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जीएसटीएन की परामर्श समिति का गठन किया है। आईसीएसआई समिति में प्रतिनिधित्व कर रहा है। समिति की बैठक 14 जुलाई, 2020 और 4 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी।

(ix) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का मानकीकरण प्रकोष्ठ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के लिए एक मानकीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में की गई है। मानकीकरण प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञों की पहचान करना शामिल है। आईसीएसआई समिति का एक प्रतिनिधि सदस्य है। सचिव आईसीएसआई इस समिति के सदस्य है।

(x) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की लेखा और वित्त सेवाएँ अनुभागीय समिति

भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, बीआईएस ने सेवा सेक्टर के क्षेत्रों में मानकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए एक समर्पित प्रभाग परिषद (सर्विसेज सेक्टर डिवीजन काउंसिल – एसएसडीसी) की स्थापना की है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष रूप से 12 चौपियन सर्विसेज सेक्टरों के रूप में चिह्नित किया है। इस प्रभाग परिषद के अंतर्गत, अनुभागीय समिति में से एक “लेखा और वित्त सेवा अनुभागीय समिति” है, समिति का कार्यक्षेत्र लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मानकीकरण है। उपाध्यक्ष आईसीएसआई इस समिति का एक प्रतिनिधि सदस्य है।

(xi) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा गठित स्टार्टअप पर समिति

कुछ स्टार्टअप द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श और उसमें स्पष्टता की मांग पर चर्चा करने के लिए एमसीए द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आईसीएसआई समिति का एक सदस्य है। 16 मार्च 2020 को इस समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श किया।

(xii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा गठित कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी (LLP) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अनुपालन की समीक्षा करने के लिए समिति

एमसीए ने संबंधित अधिनियमों की प्रासंगिकता और आवश्यकताओं की जांच करने और संबंधित प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने, कम करने और सरल बनाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 और नियमों के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता एमसीए के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम। एम। जुनेजा द्वारा की जाती है। आईसीएसआई समिति का सदस्य है। समिति की बैठक 20 अगस्त, 2020 को विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन और तर्कसंगत बनाने, कम करने और संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हुई थी।

(xiii) निधि कंपनियों के लिए विनियामक शासन को देखने के लिए समिति

एमसीए ने निधि नियमों के संदर्भ में नियामक शासन की जांच करने और संशोधनों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था, यदि कोई हो। समिति की अध्यक्षता एमसीए के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडेय द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, आईसीएसआई समिति के सदस्य हैं। 15 सितंबर, 2020 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई और जिसमें निधी कंपनियों के लिए निगरानी और अनुपालन तंत्र पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

11. आईसीएसआई कार्य बल

(i) बैंकिंग और वित्त क्षेत्र पर कार्य बल

आईसीएसआई ने उन क्षेत्रों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए बैंकिंग और वित्त क्षेत्र पर एक कार्य बल का गठन किया है जहां कंपनी सचिव बैंकिंग और वित्त उद्योग को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और इन भावी कार्यभार को संभालने के लिए सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए उपाय सुझा सकते हैं। कार्य बल की अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव श्री डीके मित्तल द्वारा की जा रही है।

(ii) श्रम कानूनों पर कार्य बल

संस्थान ने लेबर कोड पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो लेबर कोड पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएसआई से सुझाव और विचार ले रहा है और लेबर लॉ में कंपनी सेक्रेटरी के लिए अवसर तलाश रहा है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्रालय की पूर्व सचिव सुश्री सुधा पिल्लई द्वारा की जा रही है। 22 अक्टूबर, 2019, 26 नवंबर, 2019, 27 जनवरी, 2020 और 4 अगस्त, 2020 को बैठकें चार श्रम संहिता और मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2020 के कोड पर संस्थान के सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गईं।

(iii) आईसीएसआई— एनसीएलटी पर कोर ग्रुप

आईसीएसआई ने एनसीएलटी पर एक कोर ग्रुप का गठन किया है। इस कोर ग्रुप के अंतर-अलिया के गठन का उद्देश्य कंपनी सचिव पेशेवरों के प्रतिनिधित्व और वकालत कौशल को उन्नत करना और विभिन्न एनसीएलटी बेंचों पर पालन की जा रही विविध प्रथाओं के मानकीकरण का सुझाव देना है। कोर ग्रुप की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री एम। एम। कुमार, माननीय अध्यक्ष, एनसीएलटी द्वारा की जा रही है।

टास्क फोर्स की बैठक 22 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी ताकि कंपनी सचिवों के प्रतिनिधित्व कौशल के उन्नतीकरण पर विचार-विमर्श किया जा सके और विभिन्न एनसीएलटी बेंचों पर विभिन्न प्रथाओं का मानकीकरण भी किया जा सके।

(iv) निधियों पर कार्य बल

निधि नियमों के प्रावधानों को फिर से ध्यान में रखते हुए और एमसीए को निगरानी तंत्र का सुझाव देने के लिए, निधि पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। निधि नियमों के प्रावधानों को पुनर्जीवित करने के लिए 6 फरवरी, 2020 को टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई थी।

(v) सचिवीय ऑडिट पर कोर ग्रुप

मौजूदा प्रारूप को फिर से तैयार करने के लिए रोजगार में वरिष्ठ चिकित्सकों, नौकरशाहों और कंपनी सचिवों वाले एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। कोर ग्रुप की रिपोर्ट एमसीए को सौंप दी गई है।

(vi) स्टार्ट अप, एमएसएमई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर टास्क फोर्स

टास्क फोर्स का गठन स्टार्ट अप्स और एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है, जो अपने उद्यमशीलता के क्षेत्र में कंपनी सचिवों की भूमिका के बारे में और देश भर के विभिन्न संस्थानों में इस संबंध में सहायता डेस्क / संपर्क केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। टास्क फोर्स की मितिंग 21 अक्टूबर 2019 को विभिन्न पहलुओं पर हुई।

(vii) कंपनी कानून पर कार्य बल

संस्थान ने मसौदा नियमों पर विचार-विमर्श करने, कंपनी अधिनियम के तहत व्यावहारिक कठिनाइयों और उसी पर आईसीएसआई से सुझाव देने और कंपनी कानून में कंपनी सचिवों के लिए आगे के अवसरों की खोज के लिए कंपनी कानून पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की बैठकें 4 जनवरी, 2020, 22 नवंबर, 2019, 3 अक्टूबर, 2019, 24 सितंबर, 2019, 16 अगस्त, 2019 और 31 जुलाई, 2019 को आयोजित की गईं, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया गया। और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मसौदा नियमों पर आईसीएसआई के सुझाव।

(viii) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) के लिए कोर ग्रुप

आईसीएसआई ने सीआरसी (सीआरसी) के अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने एवं उसे उपलब्ध कराने, और आईसीएसआई एवं एमसीए के बीच हस्ताक्षरित एमओयू (MOU) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए के लिए सीआरसी हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया है। कार्य बल की अध्यक्षता सीएस मनीष गुप्ता, परिषद सदस्य, आईसीएसआई कर रहे हैं।

(ix) एमसीए ई-फॉर्म पर संदर्भकर्ता पर उप-समूह

संस्थान ने एमसीए ई-फॉर्म पर रेफरेंसर पर एक उप-समूह का गठन किया है जिसमें रोजगार और व्यवहार दोनों में कंपनी सचिव शामिल हैं, PCS समिति एमसीए ई-फॉर्म पर रेफरेंसर को अपडेट करने के तरीके से सदस्यों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। यह विनियामक विकास के अनुपालन के लिए उन्हें सुसज्जित करने के लिए सदस्यों के ज्ञान उन्नयन और क्षमता निर्माण का एक प्रयास है। 18 जुलाई, 2020, 20 जुलाई, 2020, 23 जुलाई, 2020 और 31 अगस्त, 2020 को उप समूह की बैठकें एमसीए ई-प्रपत्रों में संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई।

(x) भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए कोर ग्रुप

आईआरडीए ने भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रिया / सुझाव प्रदान करने के लिए आईसीएसआई द्वारा एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। मिति 21 अक्टूबर 2019 को विभिन्न पहलुओं पर हुई। 26 अगस्त 2020 को विभिन्न पहलुओं पर इस समिति की मिति हुई।

12. सुझाव, अभ्यावेदन और मान्यताएँ**(i) मान्यताएँ प्राप्त हुई****• मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019**

व्यवहार में कंपनी सचिवों को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आठवीं अनुसूची में 'जवत योग्यता और अनुभव के मध्यस्थ' में शामिल किया गया है।

• एक्चुरियल प्रोफेशन

- कंपनी सचिवों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया (IAI) से एक्चुरी पेशे में प्रवेश की शर्त में छूट प्रदान की गई है – संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।

• नेट वर्थ सर्टिफिकेट

- कंपनी सचिवों को एनएसडीएल की आवश्यकता के अनुसार डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के समय जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नेट वर्थ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- कंपनी सचिवों को सीडीएसएल की आवश्यकता के अनुसार डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के समय जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नेट वर्थ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

• सचिवीय लेखा परीक्षा

- 8 फरवरी, 2019 को सेबी के परिपत्र की विडियोग्राफी में कंपनी सचिवों को हर सूचीबद्ध इकाई का सचिवीय ऑडिट और इसकी सामग्री को भारत में शामिल असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया है।
- कंपनी सचिवों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत एक सौ करोड़ या उससे अधिक के बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार लेने वाली प्रत्येक कंपनी के सचिवीय ऑडिट का संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

• ई फॉर्म का पूर्व प्रमाणन

- कंपनी के सचिवों को प्रैक्टिस में प्राधिकृत सार्वजनिक कंपनियों के लिए ई-फॉर्म PAS 6 के गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिए नियम 9 के तहत कंपनी का प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट) नियम (2014)

• अधिकृत संग्रह केंद्र

- गुजरात राज्य में प्राधिकृत संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी सचिवों को व्यवहार में प्राधिकरण।

(ii) मान्यता प्राप्त करने या विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन से आराम पाने के लिए प्रस्तुत प्रतिनिधि:**○ सरकारी कार्यालयों का मंत्रालय**

- 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत फॉर्म और कुछ अनुपालन दाखिल करने में छूट के लिए अनुरोध।
- 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बड़ी कंपनियों के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए अनुरोध
- नियम 8 में संशोधन के लिए अनुरोध (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2020 3 जनवरी, 2020 को अधिसूचित
- आईसीएसआई यूडीआईएन और eCSIN unique नंबर को ई-रूपों में शामिल करने के लिए अनुरोध
- ई-फॉर्म पीएस -6 की तैनाती के लिए अनुरोध
- फॉर्म INC & 22A के फाइलिंग के लिए अनुरोध

- परिसमापन के तहत कंपनी के मामले में कंपनी सचिव के इस्तीफे की अनुमति देने का अनुरोध
- DPT-3 दाखिल करने के लिए अनुरोध प्रक्रिया में एकरूपता की आवश्यकता है
- 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ई-फॉर्म के पूर्व-प्रमाणन के लिए अनुरोध
- 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 (1) में संशोधन के लिए अनुरोध, साठ दिनों के भीतर वित्तीय विवरण दाखिल करने में सक्षम
- 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डीआईआर -3 केवाईसी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध
- गंभीर चक्रवात फानी -2019 (Fani - 2019) के कारण ओडिशा राज्य में कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ई-फॉर्म भरने के लिए समय के विस्तार की अनुमति देने का अनुरोध

○ सेबी को:

- सहकर्मी को सेगमेंट के विनियम 7 (2) (ए) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए एक निवेशक द्वारा सगाई के लिए सहकर्मी की समीक्षा की गई कंपनी सचिव (पीसीएस) पर विचार करने का अनुरोध (प्रशासकों की नियुक्ति और निवेशकों के लिए वापसी की प्रक्रिया) विनियम, 2018।
- श्री पी महालिंगम, संपूर्ण समय सदस्य, सेबी को सौंपी गई प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी की फर्म द्वारा एक सेक्रेटरी ऑडिट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से संबंधित प्रतिनिधित्व।

○ श्रम कानून

- द प्रस्तावित 37 ऑक्यूपेशनल सेप्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2019 की धारा 37 के तहत थर्ड पार्टी ऑडिट और सर्टिफिकेशन के संचालन के लिए विशेषज्ञ के रूप में एम्पावरमेंट के लिए कंपनी सचिवों पर विचार करना, श्री भर्तृहरि महताब, माननीय अध्यक्ष, स्थायी के अधीन श्रम पर समिति
- मध्य प्रदेश राज्य में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन/ऑडिट स्कीम के प्रारूप पर विचार करने के लिए और अभ्यास में कंपनी सचिवों को अधिकृत करने के लिए, श्री कमलनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत

○ जीएसटी कानून; सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के ऑडिट यू/एस 35 (5) और विशेष ऑडिट यू/एस 66 का संचालन करने के लिए कंपनी सचिव को अधिकृत करने और सीजीएसटी नियमों के फॉर्म जीएसटीआर-9 सी यू / आर 80 (3) को प्रमाणित करने का अनुरोध करें। 2017- श्री राजीव रंजन, विशेष सचिव और श्री एस.के. रहमान, संयुक्त सचिव जीएसटी परिषद सचिवालय के अधीन। श्री योगेंद्र गर्ग, प्रधान आयुक्त, जीएसटी को भी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया। ऑडिट के संचालन के लिए संबंधित राज्यों को कई प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किए गए हैं।

○ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कंपनी सचिवों को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अनुमति देने के लिए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मध्यस्थ के लिए कंपनी सचिवों की योग्यता पर विचार करें, श्री रावसाहेब पाटिल दानवे उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री, खाद्य को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया था। और सार्वजनिक वितरण

○ ई-स्टॉपिंग के लिए अधिकृत संग्रह केंद्र कंपनी सचिवों को प्राधिकृत संग्रह केंद्र (ACC) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने का अनुरोध प्रमुख सचिव (राजस्व) -सह संभागीय आयुक्त, सरकार को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली के एनसीटी और इक्कीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी पत्र भेजे गए थे

○ PFRDA: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) रेगुलेशन 2018 के तहत PFRDA / 2019/13 / REG&POP&1 दिनांक 17 जून, 17 के साथ पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी को अधिकृत करने का अनुरोध। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल को 2019 प्रस्तुत किया गया।

○ POSH: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियमों के तहत अनिवार्य अनुपालन प्रमाण पत्र पेश करने का अनुरोध

○ IRDA: IRDAI (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियमन 34 (7) के तहत कंपनी सचिवों को मान्यता देने का अनुरोध, IRDA के अध्यक्ष डॉ सुभाष चंद्र खुटिया को प्रस्तुत किया गया।

○ डीआरटी और डीआरएटी:

कंपनी के सचिव को प्रैक्टिस में सचिव को ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) और डेट रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध,

○ विविध:

- गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए गुजरात में उर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) का आंतरिक ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी से विचार करने का अनुरोध।
- श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम) को सौंपे गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वेतन रोल पर सचिव नियुक्त करने का अनुरोध

(iii) प्रस्तुत आईसीएसआई के सुझाव और विचार:

क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए निगम के मंत्रालय के अधिकार

- मसौदा कंपनियों पर टिप्पणियां (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) संशोधन नियम, 2020।
- टिप्पणियां (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) संशोधन नियम, 2019।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर से संबंधित ई-फॉर्म के मसौदे पर प्रस्तुतियाँ।

- (iv) एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत अपराधों के विघटन पर विचार और सुझाव।
- (v) ड्राफ्ट वैलेर्स बिल, 2020 पर विचार और सुझाव।
- (vi) प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार और सुझाव।

ख. सेबी को:

- (i) सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993 पर सेबी परामर्श पत्र पर विचार और सुझाव।
- (ii) सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993 पर सेबी परामर्श पत्र पर विचार और सुझाव।
- (iii) संबंधित पक्ष के लेनदेन पर कार्य समूह की सेबी रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ।
- (iv) सेबी परामर्श पत्र पर आईसीएसआई के सुझाव नस कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर ट्रस्टीज के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
- (v) 'किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रदान की गई गारंटी के संबंध में सेबी कंसल्टेंट पेपर' पर टिप्पणियाँ।
- (vi) सेबी परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ "अधिमान्य मुद्दों के मूल्य निर्धारण और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों वाले कंपनियों में अधिग्रहण के लिए खुले प्रस्ताव से छूट"।
- (vii) निवेश सलाहकारों के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा पर सेबी परामर्श पत्र पर सुझाव (IA) सेबी को प्रस्तुत किए गए।
- (viii) सेबी सोशल स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार और सुझाव।

ग. सलाहकारों के मंत्रालय

- (i) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2019 पर देखें और सुझाव दें
- (ii) उपभोक्ता संरक्षण विभाग पर उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विचार और सुझाव।
- (iii) उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मसौदा नियमों पर देखें और सुझाव

घ. श्रम और रोजगार मंत्रालय

- (i) वेज (सेंट्रल) रूलस, 2019 के ड्राफ्ट कोड पर विचार और सुझाव।
- (ii) सामाजिक सुरक्षा, 2019 पर मसौदा संहिता पर सुझाव।
- (iii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 के तहत संस्थान के विचार और सुझाव।
- (iv) (केंद्रीय) नियम, 2020 पर ड्राफ्ट कोड पर विचार और सुझाव।

इ. अन्य मंत्रालय

- (i) ड्रॉफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 के विचार और सुझाव विधेयक के प्रासंगिक खंडों में कंपनी सचिवों को मान्यता देने के सुझाव सहित विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर आरबीआई चर्चा पत्र पर विचार और सुझाव – भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए।
- (iii) ड्राफ्ट पेंशन फंड (विदेशी निवेश) नियम, 2020 पर विचार और सुझाव – वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन।
- (iv) मसौदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (गैस एक्सचेंज) विनियम, 2020 पर विचार और सुझाव – सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को प्रस्तुत किए गए।
- (v) मसौदा और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2020 पर विचार और सुझाव – केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सचिव को सौंपे गए। अप। वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत जीएसटी कानून के तहत अपराधों के
- (vi) डी-अपराधीकरण पर सुझाव।
- (vii) आरबीआई को प्रस्तुत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की मान्यता के लिए आरबीआई मसौदा ढांचे पर आईसीएसआई के सुझाव।

(iv) कोविड –19 के कारण विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन से छूट मांगने के लिए प्रस्तुत प्रतिनिधि

(i) कॉर्पोरेट मंत्रालय के लिए

- (i) कोविड –19 के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रपत्र और कुछ अनुपालन के दाखिलों में छूट के लिए अनुरोध
- (ii) कंपनियों के नियम 4 में संशोधन के लिए अनुरोध (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 कंपनियों को कंपनियों के नियम 3 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रतिबंधित मामलों पर विचार करने की अनुमति देता है। (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम, 2014
- (iii) वैश्विक महामारी लॉकडाउन के कारण यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रतिबंधित मामलों के लिए अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से बैठक आयोजित करने में छूट का अनुरोध
- (vi) ई फॉर्म एमजीटी 14 दाखिल करने में छूट का अनुरोध

(v) एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, २०२० और कंपनियों के विस्तार के लिए अनुरोध

(vi) कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020 के तहत राहत के लिए अनुरोध

(vii) कोविड -19 के कारण एजीएम रखने के लिए विस्तार का अनुरोध

(viii) कोविड -19 के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रपत्र और कुछ अनुपालन के दाखिलों में छूट के लिए अनुरोध

(ii) सेबी को:

(i) कोविड -19 महामारी के कारण सेबी (LODR) के विनियमन 24। के तहत वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध

(ii) सेबी (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 2018 के विनियमन 76 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट का अनुरोध।

(iii) डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के साथ प्रतिनिधित्व कनेक्शन w-r-t- कोविड -19 महामारी के कारण (लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को किए गए किसी भी फाइलिंग/सबमिशन का प्रमाणीकरण/प्रमाणीकरण।

(iii) एनएसडीएल और सीडीएसएल को

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पूंजी के पुनर्गठन के तिमाही रिटर्न दाखिल करने के लिए समय अवधि में छूट के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए प्रतिनिधित्व।

(iv) आरबीआई को

भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कोविड -19 महामारी के कारण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट का अनुरोध।

(v) जी.एस.टी. को

श्रीमती को प्रस्तुत कोविड -19 के कारण जीएसटी कानून में संशोधन का अनुरोध। निर्मला सीतारमण, अध्यक्ष, जीएसटी परिषद।

13 अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्ह

(i) अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

➤ आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए

आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए का शुभारंभ

आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए को 12 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए के सदस्यों की समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित की गई थी:

(i) सीएस लक्ष्मीकांत गर्ग, अध्यक्ष

(ii) सीएस रेणुका रमन, वाइस चेयरपर्सन

(iii) सीएस चंद्रमौली सुब्रमण्यम, सचिव

(iv) सीएस हिरेन जगदीशभाई मिस्त्री, कोषाध्यक्ष

(v) सीएस प्रफुल्ल कुमार कचोलिया, सदस्य

(vi) सीएस विनीता सीतापति, सदस्य

(vii) सीएस नीना, सदस्य

➤ आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूनाइटेड किंगडम (यूके) का उद्घाटन

आईसीएसआई ने 24 वें अगस्त, 2020 को आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूनाइटेड किंगडम का उद्घाटन किया, जिसमें श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय की सौम्य उपस्थिति थी। पेशे से वैश्विक आउटरीच को मजबूत करने के लिए आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूके की स्थापना का उद्देश्य। आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीएसआई सदस्यों और छात्रों के लिए पेशेवर अवसरों में वृद्धि करेंगे।

ICSI ओवरसीज सेंटर, यूके

निम्नलिखित सदस्यों की समिति के साथ कार्य करेगा :

- (i) इंद्रप्रीत कौर बेदी, चेयरपर्सन
- (ii) मनीष टेमानी, उपाध्यक्ष
- (iii) सोम्या रस्तोगी, सचिव
- (iv) जनक पोपत लाल प्रजापति, कोषाध्यक्ष
- (v) दीपा ग्रेसगौदर, सदस्य
- (vi) श्रीकांत कंकानाला, सदस्य
- (vii) सुखप्रीत कौर मक्कड़,

सदस्य संस्थान अपने स्टेकहोल्डर्स की सुविधा के लिए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ओवरसीज सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

(ii) . एशिया संवहनीयता प्रतिवेदन (Asia Sustainability Reporting) 2019

आईसीएसआई प्रतिनिधियों ने 4–5 सितंबर, 2019 को सिंगापुर में आयोजित संवहनीयता प्रतिवेदन शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की विषयवस्तु “सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग: एज मैन्डटॉरी बेटर” दुनिया में ईएसजी के खुलासे को उजागर करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर परिलक्षित होती है। शिखर सम्मेलन संवहनीयता प्रतिवेदन और उभरते विषयों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित था।

(iii) आईसीएसआई परिषद की बैठक और आईसीएसआई— सीएसआईए (CSIA) सम्मेलन 2019

आईसीएसआई ने 9–10 सितंबर, 2019 को कॉर्पोरेट सेक्रेटरी इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड (CSIA) की काउंसिल की बैठक की मेजबानी की। सीएसआईए हांगकांग स्थित पेशेवर निकायों का एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ है, जो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, हांगकांग, भारत, केन्या, लंडन, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरीका, जिम्बाब्वे से चौदह कॉर्पोरेट सचिव संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है, और लगभग 1,00,000 कॉर्पोरेट सचिवों की सदस्यता वाले समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह कॉर्पोरेट सचिवीय, कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन सेवाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के लिए मंच बनाता है। आईसीएसआई सीएसआईए में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

11 सितंबर, 2019 को आईसीएसआई—सीएसआईए सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में “रीडिफाइनिंग ग्लोबल गवर्नेंस— डॉन ऑफ ए न्यू एरा” विषय पर किया गया था। सम्मेलन की मेजबानी एनआईआरसी (NIRC)—आईसीएसआई द्वारा की गई थी और इसमें भारत और अन्य देशों के 150 से अधिक कंपनी सचिवों और शासन पेशेवरों ने भाग लिया।

(iv) . लिडरशिप रोल आईसीएसआई

सीएस रंजीत पांडे, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई की बैठक के दौरान वर्ष 2020 के लिए कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड (सीएसआईए) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

सीएस आषीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई की बैठक के दौरान वर्ष 2021 के लिए कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड (सीएसआईए) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

(v) . इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नाइजीरिया के अध्यक्ष के साथ बैठक

श्री बोडे अयाकु अध्यक्ष, इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नाइजीरिया ने 26 सितंबर, 2019 को भारत में बोर्ड मूल्यांकन और कॉर्पोरेट प्रशासन मूल्यांकन, जिसे हाल ही में नाइजीरिया में पेश किया गया है और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

(vi) मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (MACS) 2019 का वार्षिक सम्मेलन

मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (MACS) के निमंत्रण पर, आईसीएसआई प्रतिनिधियों ने 18–19 सितंबर, 2019 को वन वर्ल्ड होटल, बंडार उटमा, पेटलिंग जया, मलेशिया में “कंपनी सेक्रेटरीशिप डिजिटल लैंडस्केप— चुनौतियां और परिवर्तन” थीम पर आयोजित एमएसीए (MACS) 2019 के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। सीएस रंजीत पांडे, अध्यक्ष, आईसीएसआई ने “साइबर रिस्क” पर प्लेनरी सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया जिसे प्रतिनिधियों ने बहुत सराहा। एमएसीए ने आईसीएसआई सचिवीय मानक (SS–1) को अपनाते हुए निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय अभ्यास गाइड का शुभारंभ किया।

(vii) एमएसीएस सचिवीय अभ्यास गाइड (एमएसपीजी 2) निजी कंपनियों के सदस्यों की बैठकों पर

मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एमएसीएस) ने निजी कंपनियों के सदस्यों की बैठकों पर दूसरा एमएसीएस सेक्रेटरीयल प्रैक्टिस गाइड (एमएसपीजी 2) पूरा किया। MSPG 2 ने अपने बेंचमार्क के लिए आईसीएसआई की जनरल मीटिंग्स पर सचिवीय मानक (SS–2) को अपनाया।

यह प्रैक्टिस गाइड मलेशियाई कंपनी अधिनियम, 2016 के आधार पर विकसित और तैयार किया गया था

(viii) आईसीएसआई मध्य पूर्व (DIFC) एनपीआईओ (NPIO) का सम्मेलन

आईसीएसआई ने आईसीएसआई मध्य पूर्व एनपीआईओ को गैर-लाभ निगमित संगठन कानून, दुबई के 2012 के डीआईएफसी कानून नंबर 6, 24 सितंबर, 2019 के तहत निम्नलिखित संस्थापक सदस्यों और बोर्ड के साथ एक गैर लाभ निगमित संगठन के रूप में शामिल किया है:

- (i) सुश्री भावना श्रीवास्तव, अध्यक्ष

(ii) श्री लक्ष्मी नरसिम्हा दास न्यापथी, सचिव(क्रो मैक लिमिटेड के प्रतिनिधि)

(iii) श्री विजय कुमार ओझा, सदस्य

(iv) श्री आर. लक्ष्मणन, सदस्य

(v) श्री जी वी एस साई अरविंद, सदस्य

ख. आईसीएसआई मध्य पूर्व (DIFC) NPIO पेशे के वैश्विक फैलाव को मजबूत करेगा और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में रहने वाले छात्रों और सदस्यों को सुविधा प्रदान करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में बैंक की उपस्थिति डमछ। क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन के आयामों के विस्तार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी।

ग. एनपीआईओ का उद्घाटन समारोह 10 तारीख, 2019 को दुबई, यूएई में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह एच.ई. श्री विपुल, भारत के महावाणिज्यदूत, मुख्य अतिथि के रूप में दुबई, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडे, भारत सरकार अतिथि के रूप में और श्री निक नडाल, उपराष्ट्रपति, हक्कामा इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नर मुख्य वक्ता।

घ. आईसीएसआई मध्य पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 28 दिसंबर, 2020 को लॉन्च किया था। पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण के लिए, आईसीएसआई ने अपने पोर्टल सुलभ एथलीट <https://apps.icsi.edu/icsinpio/login.aspx> के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता का विकास किया।

(ix) आईसीपीए (AICPA) और सीआईएमए (CIMA) फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन न्यूयॉर्क

आईसीएसआई के अध्यक्ष, सीएस रंजीत पांडे के नेतृत्व में आईसीएसआई के प्रतिनिधिमंडल ने 15-16 अक्टूबर, 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित एआईसीपीए और सीआईएमए फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन न्यूयॉर्क में भाग लिया।

(x) केन्या एकाउंटेंट्स एंड सेक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित आईसीएसआई मुख्यालय का दौरा किया।

केन्या एकाउंटेंट्स एंड सेक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के प्रतिनिधियों ने आईसीएसआई से अनुरोध किया कि वे प्रमाणित सचिवों की योग्यता के मानदण्डों और शासन पेशेवरों के लिए उभरती हुई क्षमताओं के बारे में चर्चा करने के लिए आईसीएसआई में अध्ययन यात्रा करें। बोर्ड के प्रतिनिधियों ने 6 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आईसीएसआई मुख्यालय का दौरा किया।

(xi) सिडनी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में आईसीएसआई मुख्यालय का दौरा किया।

सिडनी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने संस्थान के साथ पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 21 नवंबर, 2019 को आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

(xii) आईसीजीएन (ICGN) 2019 ग्लोबल स्टूडेंटशिप फोरम

आईसीजीएन प्रतिनिधियों ने 26 नवंबर 2019 को लंदन में आईसीजीएन 2019 ग्लोबल स्टूडेंटशिप फोरम में भाग लिया। कार्यक्रम उद्देश्यपूर्ण अनुबंध के माध्यम से लंबी अवधि के कॉर्पोरेट मूल्य पर प्रबंधन गतिविधियों के प्रभाव पर निवेशक वोटिंग नीतियों, औचित्य और साक्ष्यपरक कंपनी अनुबंध के परिणामों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना था।

(xiii) विदेशी केंद्र के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

परिषद ने "आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर (एस) की स्थापना और कामकाज के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी।

(xiv) सदस्य सत्यापन का ऑनलाइन समर्थन आईसीएसआई-आईसीएसए एमओयू

ICSI&ICSA MoU के तहत सदस्य सत्यापन का ऑनलाइन समर्थन आईसीएसआई-आईसीएसए एमओयू के तहत आईसीएसआई सदस्य सत्यापन फॉर्म के सुचारु और त्वरित प्रसंस्करण के लिए, संस्थान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है और इसे 24 जुलाई, 2020 को आयोजित वेबिनार "कंपनी सचिव के सशक्तीकरण-अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य" के दौरान लॉन्च किया गया था।

(xv) अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

आईसीएसआई के विजन के आगे अर्थात् शुद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में एक वैश्विक नेता होने के लिए और अपने सदस्यों को कभी बदलते वैश्विक परिदृश्य से जुड़े सही कौशल के साथ प्रदान करने के लिए, आईसीएसआई अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित कर रहा है। भारत और विदेश के प्रख्यात वक्ताओं द्वारा संबोधित इन इंटरएक्टिव वेबिनारों ने न केवल आईसीएसआई हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि विश्व स्तर पर सीएस पेशे के मानक और स्थिति को भी बढ़ा रहे हैं।

दिनांक	विषय	वक्ताआ
15 th मई, 2020	ग्लोबल इकोनॉमी पर COVID19 का प्रभावक प्रोफेशनल और वे फॉरवर्ड की भूमिका	सुश्री सुश्री केरन साउथगेट, अध्यक्ष, CSIA सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई सीएस रणजीत पांडे, उपाध्यक्ष, सीएसआई और तत्काल अतीत अध्यक्ष, आईसीएसआई श्री टिम शेही, महानिदेशक, सीजीआई श्री सादमानीर, सीनियर पार्टनर, क्रो मैक लि।

		सीएस लक्ष्मी कांत गर्ग, प्रबंध निदेशक, डेलॉइट और टौच एलएलपी
28 मई, 2020	आर्थिक सहाय विनियम (ईएसआर)	सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई सीएस रंजीत पांडे, उपाध्यक्ष, सीएसआईए और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई श्री एम. हनुमंत कुमार, एमडी, एमसीए ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री नरसिंह दास, एसोसिएट पार्टनर, क्रो मैक लिमिटेड श्री हरिकिशनरनकावत, प्रबंध भागीदार, आरएनजी ऑडिटर सीएस आर लक्ष्मणन, संस्थापक सदस्य, आईसीएसआई मध्य पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ
23 जुलाई, 2020	कोविड -19 समय में कॉरपोरेट गवर्नेंस का डिजिटलीकरण।	i. श्री बेंजामिन विवनलान, सीईओ और प्रबंध भागीदार, विवनलन एंड एसोसिएट्स ii. श्री एलन इवांस, एक्स्को सदस्य, सी.एस.आई.ए.
24 जुलाई, 2020	कंपनी सचिव व्यवसाय का सशक्तिकरण : अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण	1. सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई 2. सीएस रंजीत पांडे, उपाध्यक्ष, सीएसआईए और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई 3. सीएस नितिन वी कोटक, रणनीतिक वित्त और व्यापार सलाहकार 4. सीए कुणाल सिंघानिया, उपाध्यक्ष, बाहरी रिपोर्टिंग, अमेरिकन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क सिटी। 5. सीएस लक्ष्मीकांत गर्ग, अध्यक्ष, आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए 6. सीएस रेणुका रमन, उपाध्यक्ष, आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूएसए
24 अगस्त, 2020	कंपनी सचिवों की भूमिका का विकास—यूके परिप्रेक्ष्य	सीएस अभिजीत मुखोपाध्याय, अध्यक्ष (कानूनी) और जनरल काउंसिल, हिंदुजा समूह सीएस इंद्रप्रीत कौर बेदी, अध्यक्ष, आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूके सीएस मनीष टेमानी, उपाध्यक्ष, आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, यूके

14. कॉर्पोरेट शासन पुरस्कार

कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुति समारोह 10 जनवरी, 2020 को आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सम्मानित अतिथि थे और उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रस्तुति समारोह के दो विशेष सत्रों की अध्यक्षता डॉ. रितेश मलिक, संस्थापक, इनोविन 8 कॉर्किंग और श्री सोनम वांगचुक, संस्थापक, द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) द्वारा की गई।

(i) कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, 2019

• कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत नए पुरस्कार की श्रेणियाँ:

सभी वर्गों में कॉर्पोरेट्स को प्रेरित करने के प्रयास में आईसीएसआई ने कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पुरस्कारों की नई श्रेणियों की शुरुआत की। नई व्यवस्था के तहत, सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनियों के लिए पुरस्कार निम्नानुसार कंपनी के टर्नओवर के अनुरूप सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध श्रेणियों में कंपनियों को और इसके बाद उन्हें बड़ी, मध्यम और उदयमान श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करते हुए पुरस्कार दिए गए।

(क) सूचीबद्ध कंपनियों की श्रेणी (3 पुरस्कार)

सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनियों को तीन पुरस्कार निम्नलिखित सूचीबद्ध श्रेणी में एक-एक पुरस्कार दिए गए :

- o बड़ी : टर्नओवर => रु. 10000 करोड़
- o मध्यम: टर्नओवर <रु. 10000 करोड़ और => रु. 1000 करोड़।
- o उदयमान: टर्नओवर <= रु. 1000 करोड़)

(ख) गैरसूचीबद्ध कंपनियों की श्रेणी (3 पुरस्कार)

सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनियों को तीन पुरस्कार निम्नलिखित गैर सूचीबद्ध श्रेणी में एक-एक पुरस्कार दिए गए:

- o बड़ी : टर्नओवर => रु. 10000 करोड़
- o मध्यम: टर्नओवर <रु. 10000 करोड़ और => रु. 1000 करोड़।
- o उदयीमान: टर्नओवर <= रु. 1000 करोड़)

• **कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए विशेषज्ञ समूह**

पहले और दूसरे प्रश्नावली, मूल्यांकन के तरीके और स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रश्नावली, सचिवीय लेखा परीक्षकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा अंतिम रूप दिया गया। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता सीएस एन हरिहरन, कार्यकारी उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने की। संक्षिप्त सूची के कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के साथ बातचीत भी विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा की गई।

• **कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के पुरस्कार विजेता**

(क) सूचीबद्ध श्रेणी

- o महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी: बड़ी श्रेणी)
- o ब्लू स्टार लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी: मध्यम श्रेणी)
- o टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी: उभरती श्रेणी)

(ख) गैर सूचीबद्ध श्रेणी

- o बीएसई राजधानी पावर लिमिटेड (गैर सूचीबद्ध कंपनी: बड़ी श्रेणी)
- o स्टार यूनियन डार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर सूचीबद्ध कंपनी: मध्यम श्रेणी)
- o रूट मोबाइल लिमिटेड (गैर सूचीबद्ध कंपनी: उभरती श्रेणी)

(ii) **4वां आईसीएसआई उत्कृष्टता पुरस्कार**

• **पुरस्कार की श्रेणियाँ**

1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सीएसआर खर्च करने वाली सभी कंपनियों 4वें आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार में भाग लेने के लिए पात्र थीं। आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत पुरस्कारों की श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं:

सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट – निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के तहत दिया जाने वाला एक पुरस्कार:

- o बड़ी – (वास्तविक सीएसआर खर्च>– रु.25 करोड़)
- o मध्यम – (वास्तविक सीएसआर खर्च>रु.10 करोड़ और ≤ रु.25 करोड़)
- o उभरती – (वास्तविक सीएसआर खर्च> रु.1 करोड़ और ≤ रु.10 करोड़)

• **आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए विशेषज्ञ समूह**

सीएस जे. श्रीधर, कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समूह ने प्रश्नावली, मूल्यांकन पद्धति, क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए मानकों को अंतिम रूप दिया गया था।

पहली बार, लघु सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्षेत्र मूल्यांकन शुरू और कार्यान्वित किया गया। क्षेत्र मूल्यांकन के लिए मानकों को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, कंपनी सचिव पेशेवरों और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

• **4वां आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार के पुरस्कार विजेता**

4वां आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट का पुरस्कार निम्नलिखित को प्रदान किया गया:

- o अपोलो टायर्स लिमिटेड (बड़ी श्रेणी)
- o एसआरएफ लिमिटेड (मध्यम श्रेणी)
- o परसेंट सिस्टम्स लिमिटेड (उभरते श्रेणी)

(iii) **आईसीएसआई सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार**

संस्थान की परिषद ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में शासन की संस्कृति को बढ़ाने और सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्टिंग के महत्व को बढ़ाने में सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में अपनी भूमिकाओं में कंपनी सचिवों के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से एक नई श्रेणी के पुरस्कार अर्थात “सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार” का निर्णय लिया है।

• सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा-परीक्षक रिपोर्ट पुरस्कार के लिए विशिष्ट समूह

स्वर्गीय सीएस संजय ग्रोवर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रश्नावली और मूल्यांकन पद्धति को अंतिम अंतिम रूप दिया गया। विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सचिवीय लेखा-परीक्षक के साथ बातचीत भी की गई।

• सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार के विजेता

आईसीएसआई सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार निम्नलिखित को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया:

- o सीएस अतुल मेहता, न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड के सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट के लिए मेहता एंड मेहता एसोसिएट्स
- o सीएस (डॉ.) सीवी मधुसूदनन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट के लिए केएसआर एंड कंपनी
- o सीएस विनीता नायर, आवास विकास और वित्त निगम लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी।

(iv) कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता को साकार करने के लिए आईसीएसआई जीवनपर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार

प्रतिष्ठित आईसीएसआई जीवनपर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार श्रीमती इंदु जैन, अध्यक्ष, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को कॉर्पोरेट शासन में उत्कृष्टता को साकार करने में प्रदान किया गया।

15. आईसीएसआई- भारत का जीएसटी भगीदार

जीएसटी के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, संस्थान अपने सदस्यों, छात्रों और संबंधित हितधारकों की क्षमता को जीएसटी के बारे में उनकी समझ को आगे बढ़ाने और विभिन्न पहलों के माध्यम से जीएसटी में अपडेट के साथ उन्हें लगातार अवगत कराते हुए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) जीएसटी दिवस, 2019

1 जुलाई, 2019 को जीएसटी दिवस मनाया गया, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्टिफिकेट कोर्स नामक एक समर्पित कोर्स के शुभारंभ के रूप में चिह्नित किया गया, जिसका उद्देश्य जीएसटी के सिद्धांतों के बारे में एक व्यापक अंतर्दृष्टि देने के साथ-साथ उम्मीदवारों को सक्षम करने वाले अप्रत्यक्ष शासन की अन्य बारीकियों को बताना था। जीएसटी की अवधारणा और इसके कार्यान्वयन की समझ हासिल करना और उन्हें जीएसटी के संबंध में वर्तमान विकास के बारे में बताना। इसके अलावा, संस्थान ने अध्याय और क्षेत्रीय कार्यालयों में पैन-इंडिया कार्यक्रम आयोजित किए थे।

(ii) जीएसटी दिवस, 2020

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए, 1 जुलाई 2020 को लाइव वेबिनार मोड के माध्यम से एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर श्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य परिषद सदस्यों के साथ एक विशेष संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया।

जीएसटी न्यूजलेटर और इंफो कैप्सूल के साथ उद्घाटन सत्र के दौरान "आईसीएसआई ने लॉकडाउन में अवसरों को अनलॉक करने" पर एक वीडियो भी जारी किया था।

इनके साथ, तीन तकनीकी सत्र "जीएसटी- द वे फॉरवर्ड", "जीएसटी में स्थायी मुद्दे और व्यावसायिक अवसर" और जीएसटी में लेखन क्षेत्राधिकार में समकालीन मुद्दे पर आयोजित किए गए थे।

(iii) जीएसटी न्यूजलेटर

संस्थान नियमित रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी) को समर्पित एक मासिक समाचार पत्र निकाल रहा है। भारत सरकार की पहल से नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के महत्व और दूरगामी प्रभाव को देखते हुए और भारत सरकार के "वन नेशन वन टैक्स" के आदर्श वाक्य को बरकरार रखते हुए, आईसीएसआई का 37वां अंक – जीएसटी समाचार पत्र अगस्त, 2020 में प्रकाशित किया गया था। सभी मुद्दे जीएसटी न्यूजलेटर संस्थान की वेबसाइट <https://www.icsi.edu/GSTEdicySeries.aspx> पर जीएसटी कॉर्नर पर उपलब्ध हैं।

(iv) जीएसटी शैक्षिक श्रृंखला

जीएसटी के शासन में क्षमता निर्माण की पहल को आगे बढ़ाते हुए, संस्थान ने एक जीएसटी शैक्षिक श्रृंखला विकसित की है। इस श्रृंखला में संस्थान, जो सफल और शैक्षणिक रूप से उपयोगी रहा है, ने 490 से अधिक मुद्दों को सामने लाया है। जीएसटी एजुकेशनल सीरीज के सभी मुद्दे संस्थान की वेबसाइट जीएसटी कॉर्नर पर <https://www.icsi.edu/GSTEducationalSeries.aspx> पर उपलब्ध हैं।

16. शैक्षणिक पहले और विकास

(i) इन्फॉर्मेशन कैप्सूल का परिचय-नए सिरों से निर्मित सदस्यों के लिए एक दैनिक अद्यतन

संस्थान ने सदस्यों के लिए दैनिक अपडेट, ज्ञान के समृद्ध इनपुट के साथ संरचित रूप में 'इंफो कैप्सूल के संशोधित संस्करण को फिर से प्रस्तुत किया है। इंफो कैप्सूल शैक्षणिक कोने के तहत छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाता है।

इन्फो कैप्सूल आईसीएसआई में नवीनतम घटनाओं, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से महत्वपूर्ण नियामक परिपत्रों, सेबी और अन्य नियामकों, पुनर्गठन और दिवाला से संबंधित समाचार मूल्यांकन एनसीएलटी और एनसीएलएटी और अन्य न्यायिक घोषणाओं से विनियामक जानकारी मार्केट वॉच, कॉरपोरेट शासन के घटनाक्रम आदि क्षेत्रों पर केंद्रित है।

(ii) केस डाइजेस्ट सीरीज

संस्थान ने केस डाइजेस्ट सीरीज लाने की एक नई पहल की है, जहाँ कंपनी कानून, दिवालियापन कानून, प्रतिस्पर्धा कानून, सुरक्षा कानून, उपभोक्ता कानून, कॉरपोरेट धोखाधड़ी, धनशोधन, सामान्य कानून, श्रम कानून, प्रत्यक्ष कर कानून, माल और सेवा कर कानून, बैंकिंग कानून, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, यह व्यापार और विनियामक दृष्टिकोण से हाल के मुद्दों पर केस स्टडी को भी कवर करता है। केस डाइजेस्ट श्रृंखला संस्थान के छात्रों और सदस्यों को प्रसारित की जाती है।

(iii) कोविड 19— विनियामक अद्यतन

सरल और नए अनुपालन समय सीमा पर स्वयं को समझने और अद्यतन करने में सदस्यों का समर्थन करने के लिए, संस्थान ने न्यायपालिका, मंत्रालयों और विभिन्न नियामकों की पहल को कवर करते हुए व्यापक बुकलेट कोविड 19— विनियामक अद्यतन के तीन खंड निकाले हैं।

(iv) सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) बुलेटिन— सीएसईईटी छात्रों के लिए एक मासिक ई-पत्रिका प्रारम्भ

यह मासिक बुलेटिन सीएसईईटी पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों को शामिल करता है, जिसमें प्रत्येक विषय से संबंधित नमूना प्रश्न उत्तर के अलावा अर्थशास्त्र, समसामयिकी आदि पर नवीनतम जानकारी शामिल हैं।

(v) छात्रों के लिए एक मासिक ई-पत्रिका—नए रूप में छात्र कंपनी सचिव

संस्थान ने निम्नलिखित विशेषताओं के साथ विषयवार अपडेट ६ केस कानूनों आदि सहित कई नए खंडों को जोड़ते हुए पत्रिका को नया रूप दिया है:

- थीम लेख के साथ थीम आधारित पत्रिका और हाल के घटनाक्रमों पर लेख
- नवीनतम विनियामक/व्यावसायिक विकास पर लेख
- विषयवार विनियामक अद्यतन
- कंपनी कानून कोना
- कानूनी अधिकतम का उपयोग

(vi) विषयवार मासिक अद्यतन

छात्रों को वास्तविक समय के आधार पर शिक्षित करने के लिए आईसीएसआई ने हालिया नियामक घटनाक्रमों को शामिल करते हुए विषयवार और अध्यायवार मासिक अद्यतन पेश किया है।

(vii) छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिका

“प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर” विषय पर एक अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है और परीक्षा की तैयारी में छात्रों की मदद करने के लिए आईसीएसआई वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(viii) विषय विशेषज्ञ समिति का गठन

संस्थान ने 24 विषयों में से प्रत्येक के लिए विषयवार विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है, जिसमें विभिन्न विषयों के अध्ययन सामग्री में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि को शामिल करने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और अभ्यासरत पेशेवरों से सदस्य शामिल हैं। समिति ने बैठकों की और संस्थान ने अध्ययन सामग्री में उनके सुझावों को शामिल किया।

(ix) सीएसईईटी पठन सामग्री

सीएसईईटी के तहत सभी चार विषयों के लिए संदर्भ पठन सामग्री आईसीएसआई की वेबसाइट पर तैयार और अपलोड की गई है।

(x) सीएसईईटी मॉक टेस्ट

सीएसईईटी परीक्षा के भाग-ए के लिए मॉक टेस्ट के पांच सेट आईसीएसआई वेबसाइट पर लॉन्च किए गए हैं।

(xi) आईसीएसआई वेबसाइट पर कार्यकारी और व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री की उपलब्धता।

जून 2020 परीक्षा (अब दिसंबर 2020 की परीक्षाओं के साथ विलय) के लिए प्रासंगिक अध्ययन सामग्री को अद्यतन और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डोमेन के विषय विशेषज्ञों के विचारों पर विचार करने के बाद अध्ययन सामग्री को संशोधित किया गया है।

(xii) शैक्षणिक पोर्टल पर दिशानिर्देश के उत्तर अपलोड करना

जून 2015 से दिसंबर 2019 तक पिछले सत्र के प्रश्नों और समाधानों के वर्षवार और मॉड्यूलवार वाले दिशानिर्देशों के उत्तर आईसीएसआई वेबसाइट पर शैक्षणिक पोर्टल के तहत अपलोड किए गए हैं।

(xiii) निम्नलिखित प्रशिक्षण मॉड्यूलों के पुनरीक्षण, समीक्षा और पुनरीक्षण में प्रशिक्षण का समर्थन निम्न मॉड्यूल अपडेट किए गए और संशोधित किए गए :

- ईडीपी मॉड्यूल 5 दिन की उद्यमिता
- 2 दिन ईडीपी प्रशिक्षण मॉड्यूल – प्रेरण
- 15 दिन का नया ईडीपी मॉड्यूल
- 3 दिन XBRL और ई-मतदान
- 5 दिन का कौशल विकास eMSOP मॉड्यूल

(xiv) ई-लर्निंग के माध्यम से वेबिनारों की वीडियो व्याख्यान /वीडियो रिकॉर्डिंग: पोर्टल

ई-लर्निंग पोर्टल पर छात्रों के लाभ के लिए वेबिनारों, वीडियो व्याख्यान और पुराने और नए विषयों के विभिन्न विषयों से संबंधित क्रेडिट कोर्स के 180 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं।

17. सदस्यगण :

- अप्रैल, 2019 से 15 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, क्रमशः 5109 और 659 सदस्यों को एसोसिएट्स और फेलो के रूप में भर्ती किया गया था। 15 सितंबर, 2020 तक संस्थान में 52409 एसोसिएट और 10183 फेलो सदस्य 62592 सदस्य थे। 1 अप्रैल, 2019 से 15 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, 1726 अभ्यास के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 10918 सदस्य थे, जो 15 सितंबर, 2020 तक अभ्यास के प्रमाण पत्र धारण कर रहे थे। चार क्षेत्रों में द्वि-वार्षिक आईसीएसआई कन्वोकेशन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे।
 - परिषद को 1 अप्रैल, 2019 से 15 वीं तारीख, 2020 तक की अवधि के दौरान 29 सदस्यों के दुःखद निधन की रिपोर्ट पर खेद है, जिनमें से 21 कंपनी सचिवों के जीवन निधि (सीएसबीएफ) के आजीवन सदस्य भी थे।
- 1) **सदस्यों की सूची:** कम्पनी सचिव विनियमन, 1982 के विनियम 161 के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 19(3) के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 को सदस्यों की सूची सीडी में उपलब्ध कराई गई है।
 - 2) **लाइसेंसधारी :** 1 अप्रैल, 2019 से 15 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, संस्थान के 26 अंतिम ६ व्यावसायिक परीक्षा पास छात्रों को लाइसेंस-आईसीएसआई के रूप में भर्ती किया गया था। 15 सितंबर, 2020 तक लाइसेंसधारकों की संख्या 110 थी
 - 3) **कम्पनी सचिव हितलाभ निधि (सीएसबीएफ):**

31 मार्च, 2020 को सीएसबीएफ के आजीवन सदस्यों की क्षेत्रवार ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

क्षेत्र	31 मार्च, 2020 को	15 सितंबर, 2020 को
ईआईआरसी	1033	1043
एनआईआरसी	4648	4693
एसआईआरसी	4057	4105
डब्ल्यूआईआरसी	4181	4225
विदेशी	55	55
कुल आजीवन सदस्यों की संख्या	13974	14121

4) **मानद फेलोशिप:** संस्थान के मानद फेलोशिप को 5 अक्टूबर, 2019 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा श्री अजुन राम मेघवाल, पाली उद्योग मामलों के राज्य मंत्री, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम और श्री इनजेटी श्रीनिवास, सचिवालय, एमसीए द्वारा सम्मानित किया गया। भारत, श। राम नाथ कोविंद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आईसीएसआई के 51 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान।

(18) छात्र प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**(क) प्रशिक्षण देने के लिए कम्पनियों/ पेशेवर कम्पनी सचिवों का पैनल बनाना**

विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान अधिक कम्पनियों/अन्य संस्थाओं के साथ ही पेशेवर कम्पनी सचिवों का पैनल बनाकर अपने प्रशिक्षण आधार का विस्तार करने के निरंतर प्रयास करता रहता है। वर्ष के दौरान 273 कंपनियों और 715 प्रैक्टिसिंग कंपनी के सचिवों को छात्रों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए सम्मानित किया गया।

(ख) एग्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

वर्ष 2019-2020 के दौरान कुल 10 एग्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। 262 विद्यार्थियों ने कक्षा माहौल में सफलतापूर्वक 8 दिन का ईडीपी पूरा किया।

कोविड-19 के कारण, मार्च 2020 के बाद से फिजिकल क्लास रूम मोड में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि, 15 दिवसीय ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दो ई-ईडीपी (3 दिवसीय ई-गवर्नेंस और 5 दिवसीय कौशल विकास) आयोजित किए गए थे।

8 दिवसीय ई-ईडीपी (3 दिन ई-गवर्नेंस और 5 दिन कौशल विकास) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	कुल छात्रों ने भाग लिया
1.	8 दिन ई-ईडीपी (3 दिन ई-गवर्नेंस और 5 दिन कौशल विकास) का पहला बैच 3 दिन ई-गवर्नेंस 5 दिन का कौशल विकास	310 349
2.	8 दिन ई-ईडीपी (3 दिन ई-गवर्नेंस और 5 दिन कौशल विकास) का पहला बैच 3 दिन ई-गवर्नेंस 5 दिन का कौशल विकास	291 285

(ग) प्रबंधन कौशल अनुस्थापन कार्यक्रम (एमएसओपी)

क्र.सं.	एमएसओपी प्रोग्राम	छात्रों की संख्या	01.04.2019 से 31.03.2020 तक प्रोग्राम की संख्या
i	रेगुलर एमएसओपी	2454	64
ii	रेजीडेंसियल एमएसओपी	281	8

कोविड-19 के कारण, मार्च 2020 के बाद से फिजिकल क्लास रूम मोड में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

ई-एमएसओपी (यानी 01.04.2020–15.09.2020 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से)।

क्र.सं.	कार्यक्रम	छात्रों की संख्या
iii	ई-एमएसओपी	2522

(डी) एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ

- क. संस्थान ने पहली बार कार्यकारी और फाउंडेशन प्रोग्राम के छात्रों के लिए एक दिन का एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। अब सीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से अपने पंजीकरण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम से गुजरना होगा।
- ख. 1 जून 2019 को या उसके बाद पंजीकृत फाउंडेशन और कार्यकारी प्रोग्राम के सभी छात्रों के लिए एक दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम लागू होता है।
- ग. एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अध्ययन की योजना, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, कार्यक्रम की अवधि, परीक्षा पैटर्न, प्रशिक्षण संरचना आदि से अवगत कराना है, जिससे छात्रों को सीएस पाठ्यक्रम के बारे में सभी अद्यतन जानकारी मिल सके और यह संस्थान से भी जुड़ सके।
- घ. 15 सितम्बर, 2020 तक, कुल 12415 फाउंडेशन कार्यक्रम के छात्रों और 22460 कार्यकारी कार्यक्रम के छात्रों ने अनिवार्य एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत पंजीकरण किया है।

(ई) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकायों का सूचीकरण ।

- क. आईसीएसआई में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सत्र लेने के लिए शिक्षाविदों, कॉर्पोरेट प्रशिक्षकों, उद्योग के नेताओं और पेशेवरों का एक पूल होने के लिए, संस्थान ने संकायों / प्रशिक्षकों के सशक्तीकरण के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिनके पास पर्याप्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पंजीकरण करने के लिए शिक्षण अनुभव है वे छात्रों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक संकाय के रूप में संस्थान के साथ कराएं।
- ख. आईसीएसआई में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संकायों / प्रशिक्षक के सूचीकरण की घोषणा सीएस सदस्यों, पेशेवरों / शिक्षाविदों, विजिटिंग संकायों / अतिथि संकायों / कॉर्पोरेट प्रशिक्षकों / उद्योग और शिक्षाविदों के नेताओं के बीच सूचीकरण के लिए सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में प्रसारित की गई थी।
- ग. अब तक प्राप्त आवेदनों की समय-समय पर समिति द्वारा विधिवत जांच की जाती है और सूचीकरण के लिए पात्र संकायों का चयन किया जाता है।

(एफ) टीओटी (प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण) कार्यक्रम का शुभारम्भ

(i) संस्थान ने नए शामिल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए टीओटी कार्यक्रम शुरू किया है। टीओटी सीएस छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईसीएसआई के नव पंजीकृत प्रशिक्षकों के लिए एक तरह का प्रेरण कार्यक्रम है। पहला टीओटी कार्यक्रम 19 अक्टूबर, 2019 को अध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति में मुख्यालय में आयोजित किया गया। टीओटी कार्यक्रम में लगभग 30 पंजीकृत प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था:

- प्रशिक्षण कैसे दिया जाए पर मार्गदर्शन करने के लिए
- उन्हें प्रशिक्षण के 4पी(Ps), यानी, उद्देश्य, योजना, प्रस्तुति और प्रदर्शन
- प्रशिक्षण प्रदान करते समय प्रशिक्षक से क्या अपेक्षित है, यह जानने के लिए:
- प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उनकी कमियों को दूर करने के तरीके का सुझाव देना

(ii) पहले टीओटी कार्यक्रम के दौरान टीओटी मैनुअल भी लॉन्च किया गया। टीओटी के संचालन के लिए सभी चार क्षेत्रों और उत्कृष्टता केंद्र को शामिल करने का भी प्रस्ताव था। तदनुसार, दूसरा टीओटी 14 दिसंबर 2019 को सीआई, हैदराबाद में 25 से अधिक प्रशिक्षकों और 11 जनवरी, 2020 को सीसीजीआरटी में आयोजित किया गया था, जिसमें 32 प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

(जी) परियोजना प्रोत्साहन का शुभारम्भ

संस्थान ने प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेवाओं में स्वचालन लाने के लिए 27.02.2020 को ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। ई शासन पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों पर समय पर और तेजी से जवाब देना है। अब छात्र व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजीकरण, एनओसी / पूर्णता प्रमाणपत्र और अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण से छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं।

(एच) कोविड-19 के कारण लॉक डाउन की अवधि के दौरान सभी पात्र छात्रों के लिए ई-एमएसओपी को सुलभ बनाना

संस्थान ने 31.03.2020 और 19.06.2020 के परिपत्र के माध्यम से पेशेवर पास और ई-एमएसओपी पंजीकरण के बीच अस्थायी रूप से दो साल का समय सीमा हटाकर ई-एमएसओपी में प्रवेश लेने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी है। इस छूट को प्रदान करके, संस्थान ने सभी व्यावसायिक कार्यक्रमों में छात्रों को उनके उत्तीर्ण होने के वर्ष भिन्नता होने के बावजूद दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य शर्तों की पूर्ति के लिए ई-एमएसओपी से गुजरने की अनुमति दी। यह छात्रों को क्षेत्रों और शाखाओं में आयोजित कक्षा आधारित एमएसओपी (MSOP) की प्रतीक्षा किए बिना सदस्यता के लिए आवेदन करने की सुविधा के लिए किया गया था। कुल 1986 ई-एमएसओपी एप्लीकेशन अपूर्व हुए आज तक।

(आई) छात्रों के लिए 8 दिन के ई-ईडीपी (3 दिन ई गवर्नेंस और 05 दिन कौशल विकास कार्यक्रम) सहित 15 दिनों के ई-शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान करना।

कोविड 19 के कारण तालाबंदी के दौरान, आरओ और शाखा द्वारा आयोजित सभी अल्पकालिक प्रशिक्षण बंद कर दिए गए थे। कई छात्र इस कारण अपने 15 दिनों के शैक्षणिक कार्यक्रम और ईडीपी को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। लॉक डाउन की अवधि के दौरान छात्रों को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए, संस्थान ने 8 दिनों के ईडीपी (3 दिन ई गवर्नेंस और 5 दिनों के कौशल विकास कार्यक्रम) सहित 15 दिन ई शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रशिक्षण 17 अप्रैल-19 मई 2020 तक का आयोजित किया गया। कुल 3952 छात्रों ने सम्पूर्ण किया।

(जे) कोविड 19 के कारण लॉक डाउन अवधि के दौरान संस्थान के रिकॉर्ड में प्रशिक्षुओं की पहली और दूसरी तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने में छूट।

संस्थान ने लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान 30 जून 2020 तक पहली त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि में ढील दी थी। हालांकि, पूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने त्रैमासिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसे 30 सितंबर 2020 तक पहली और दूसरी तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 19.06.2020 के परिपत्र के माध्यम से पुनः बढ़ा दिया गया था।

(के) सीएस प्रशिक्षुओं और उम्मीदवारों के लिए 05 दिन का ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण (PSDT)

प्रशिक्षुओं के बीच अपने कौशल प्रवृत्ति को बढ़ाकर आत्मविश्वास का निर्माण करने हेतु, और मुख्य एवं उभरते क्षेत्रों में अपनी कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए, संस्थान ने सीएस प्रशिक्षुओं के लिए 05 जून से 6 जून 2020 तक 05 दिनों का पीएसडी एस (PSDT) आयोजित किया। ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य घर से काम करने के दौरान सीएस प्रशिक्षुओं की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षुओं के बीच विश्वास निर्माण और प्रेरणा, उनके व्यावहारिक कौशल, आईटी कौशल और आलेखन कौशल को बढ़ाव देना था। कुल 593 छात्रों ने सम्पूर्ण किया।

(एल) ऑनलाइन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (e PDP)

24 पीडीपी घंटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 31.03.2014 को या उससे पहले कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की सुविधा के लिए, संस्थान ने ऑनलाइन विधि के माध्यम से पीडीपी का आयोजन किया। ईपीडीपी का पहला बैच 06 मई-17 मई 2020 तक आयोजित किया गया। कुल 1290 छात्रों ने 24 घंटे e PDP सम्पूर्ण किया।

(एम) कोविड-19 के कारण लॉक डाउन अवधि को सीएस प्रशिक्षुओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की निरंतरता के रूप में मानना

वैश्विक महामारी ("कोविड-19") के प्रकोप के परिणामस्वरूप पूर्ण लॉक डाउन हो गया, इसलिए, 30 मार्च 2020 के परिपत्र के माध्यम से संस्थान ने सभी प्रशिक्षकों / नियोक्ताओं (कंपनियों, पीसीएस और अन्य संस्थाओं) को सूचित किया कि वे संस्थान के साथ पंजीकृत सीएस प्रशिक्षुओं और चल रहे उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण को उनके प्रशिक्षकों (ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक मोड) के दिशानिर्देश और निगरानी में घर से काम करने के लिए की अनुमति दें।

उपरोक्त के दृष्टिगत, लॉक डाउन अवधि के दौरान घर से काम वाले को (सरकार द्वारा इसमें किसी विस्तार को भी शामिल करें, यदि ऐसा हो) को प्रशिक्षण अवधि के तौर पर माना जाएगा।

(एन) पूर्व परीक्षा टेस्ट की आवश्यकता के अनुपालन और सीएस परीक्षा के दिसंबर 2020 के सत्र में नामांकन के लिए एक दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए छूट (कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में अभूतपूर्व संकट को देखते हुए)

छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा, दिसंबर 2020 सत्र में उपस्थित होने के लिए स्वयं को नामांकित करने के लिए ओडीओपी (ODOP) और पूर्व-परीक्षा परीक्षण की उपरोक्त दो आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। अब छात्रों को अस्थायी रूप से ओडीओपी की आवश्यकता के बिना परीक्षा के लिए खुद को नामांकित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उन्हें 20 नवंबर, 2020 तक उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।

(ओ) 8 दिवसीय ई-ईडीपी (3 दिन के ई-गवर्नेंस और 05 दिन के डेवलपमेंट प्रोग्राम) सहित 15 दिवसीय ई-शैक्षणिक कार्यक्रम का दूसरा बैच

15 दिन के ई शैक्षणिक कार्यक्रम के पहले बैच में छात्रों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और कोविड 19 के कारण वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 8 दिवसीय ई-ईडीपी (3 दिन के ई-गवर्नेंस और 05 दिन के डेवलपमेंट प्रोग्राम) सहित 15 दिवसीय ई-शैक्षणिक कार्यक्रम का दूसरे बैच का आयोजन 25 जून से-31 जुलाई जुलाई 2020 तक किया।

(पी) सीएस प्रशिक्षुओं और उम्मीदवारों के लिए 05 दिनों के ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण (PSDT) का दूसरा बैच

5 दिनों के ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण के पहले बैच में हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 11 जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक ऑनलाइन पीएसडीटी (PSDT) का दूसरा बैच आयोजित किया।

(क्यू) कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी सचिव अधिनियम, 1982 के विनियम (3 फरवरी, 2020 तक संशोधित अनुसार) 46 बीए और 46बीबी से अस्थायी छूट प्रदान करना

परिषद की सिफारिशों के अनुसार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद, विनियमन 46बीए और 46बीबी के तहत अस्थायी छूट दी गई है। कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 के तहत छात्रों को कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 के नियमन 46 BB (Regulation-46BB) में निर्धारित एक महीने की ईडीपी के बजाय ऑनलाइन मोड में 15 दिन की ईडीपी पूरी होने के बाद अपने 21 महीने का अभ्यास शुरू करने की अनुमति है। हालांकि, उन्हें अपने प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के शुरू होने के छह महीने के अंदर कक्षा विधि में ईडीपी के शेष 15 दिनों में पूरा करने की आवश्यकता होगी। कक्षा मोड में उक्त ईडीपी को एक बार इस तरह के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रों और शाखाओं को फिर से खोलने पर पूरा करना होगा।

(आर) सीएस TRAINEE DRIVE – 2019 में आईसीएसआई हाउस, नोएडा में आयोजित किया गया

इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), सीएस प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, 5 सितंबर, 2019 को आईसीएसआई हाउस, नोएडा में एक विशेष CS Trainee Drive (ii) - 2019 का आयोजन किया गया। यह आयोजन सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट्स, फर्मों और आकांक्षी छात्रों के बीच की खाई को पाटने के संदर्भ में आयोजित किया गया था, क्योंकि छात्रों और संगठनों की ओर से इस अभियान की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई थी।

(19) प्लेसमेंट

वर्ष 2019-20 में, आईसीएसआई के सदस्यों के लिए प्लेसमेंट के अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

i. आईसीएसआई की वेबसाइट पर दिसंबर, 2018 आर जून, 2019 के व्यावसायिक परीक्षा में आईसीएसआई के शीर्ष 25 रैंक धारकों की सूची प्रकाशित करना : शीर्ष कॉर्पोरेट्स से प्रशिक्षुओं और सीएस प्रोफेशनलों के सुविधा आवश्यकता के लिए शीर्ष 25 रैंक धारकों का विवरण आईसीएसआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया।

दिसंबर 2018 और जून 2019 की परीक्षा में सफल छात्रों में से प्रत्येक 25 रैंक धारकों की सूची, छात्रों की सहमति लेने के बाद संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

ii. बड़े प्लेसमेंट अभियान : संस्थान ने आईसीएसआई के सभी चार क्षेत्रों में मई, 2019 के महीने में बड़े प्लेसमेंट अभियान 2019 के पहले चरण का आयोजन किया गया। बड़ा प्लेसमेंट अभियान 04 मई, 2019 को डब्ल्यू आई आरसी (WIRC)-मुंबई में आयोजित किया गया। तत्पश्चात, इसे 17 मई, 2019 को एन आई आरसी-दिल्ली, इसके बाद 18 मई, 2019 को ई आई आरसी-कोलकाता में, और 24 मई, 2019 को एस आई आरसी-चेन्नई में संपन्न हुआ।

बड़े प्लेसमेंट अभियान, 2019 का दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर, 2019 के महीने में आयोजित किया गया। यह एस आई आरसी-चेन्नई में 22 नवंबर, 2019 को एन आई आरसी-नई दिल्ली और डब्ल्यू आई आरसी-मुंबई में 30 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया। ई आई आरसी-कोलकाता के लिए अभियान 10 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई।

- iii. **1 जनवरी 2014 से 25 जून 2019 तक युवा कंपनी सचिवों की प्रोफाइल पता लगाना (मैपिंग):** आईसीएसआई ने अपने उन सदस्यों के बीच एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जिन्होंने अपनी रोजगार की स्थिति, विशेषज्ञता के क्षेत्र, विशिष्ट डोमेन ज्ञान और देश भर के उद्योग द्वारा पेश किए गए रोजगार के अवसरों को समझने के लिए 1 जनवरी 2014 से 25 जून, 2019 तक या उसके बाद अपनी सदस्यता प्राप्त कर ली थी।
- iv. **नए सदस्यों और छात्रों के लिए आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल:** सदस्यों को प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, संस्थान ने बाजार में नौकरी के अवसरों की पहचान करने के लिए सदस्यों की सहायता के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। आईसीएसआई वेबसाइट पर प्लेसमेंट के लिए एक टैब नियमित रूप से 0 से 2 साल / 2-5 साल / 5 साल और उससे अधिक के अनुभव के साथ नौकरी के अवसरों के साथ अद्यतन किया गया। उक्त टैब ने आईसीएसआई सदस्यों के लिए मौजूदा नौकरी के अवसरों को खोजना आसान बना दिया, इसने छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी सहयोग दिया है। यह टैब 14 नवंबर, 2019 तक www.icsi.edu पर सक्रिय था।
- 14 नवंबर 2020 से प्रभावी आईसीएसआई प्लेसमेंट, <https://placement.icsi.edu/> सभी सदस्यों और छात्रों के लिए शुरू किया गया। आवेदन करने के लिए सदस्यों और छात्रों के लिए कॉर्पोरेट और अन्य नियोक्ताओं द्वारा नौकरियां और प्रशिक्षण पोर्टल पर पोस्ट किए जाते हैं।
- v. **आईसीएसआई रणनीतिक बैठक:** 29 फरवरी, 2020 को आईसीएसआई, सीसीजीआरटी (CCGR), सीबीटी (CBD) बेलापुर, मुंबई में वरिष्ठ मानव संसाधन पेशेवरों, कॉर्पोरेट समुदाय के अनुभवी सदस्यों, तकनीकी विशेषज्ञों आदि के साथ एक संवादमूलक सत्र आयोजित किया गया।
- vi. **एचआर सम्मेलन :** आईसीएसआई -एसआईआरसी ने 22 अगस्त, 2019 को आईसीएसआई -एसआईआरसी हाउस, चेन्नई के लिए और कॉर्पोरेट्स में एचआर विभाग में एचआर प्रबंधक और कार्यकारी अधिकारियों के लिए एचआर कॉन्वलेव का आयोजन किया। आईसीएसआई - ईआईआरसी ने 9 नवंबर, 2019 को द पीयरलेस इन, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र के लिए एचआर कॉन्वलेव-I, 2019 का आयोजन किया।

vii सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी सचिव की भर्ती में सहायता

- भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- इंडिया लिमिटेड (SC / ST / OBC के लिए आरक्षित श्रेणी) (NCL)
- नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएँ शामिल हैं

विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी सचिव के लिए रिक्ति के बारे में संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए विज्ञापनों के जवाब में, बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे जो संबंधित संगठनों द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांच और फिल्टर किए गए थे। उनके साथ मान्य प्रतिक्रियाएँ साझा की गईं, जिनमें से शीर्ष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया गया था, साक्षात्कार के लिए और पदों के लिए अंतिम चयन किए गए थे।

(viii) **विभिन्न सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए सीएस छात्रों की शॉर्टलिस्टिंग संस्थान को प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए** कंपनी सचिव छात्रों की आवश्यकता के बारे में विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रशिक्षु आवश्यकताओं को संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। इस तरह के संगठनों के लिए प्रदान मानदंडों के आधार पर प्रतिक्रियाओं की जांच और जांच की गईरु

- आधिकारिक परिसमापक का कार्यालय
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सीएल-II अनुभाग
- क्षेत्रीय निदेशक उत्तर (MCA) का कार्यालय
- कंपनियों के रजिस्ट्रार, और अन्य सरकार। संस्थाओं।

(ix) प्रशिक्षु और आईसीएसआई हाउस, नोएडा में अग्रणी संगठनों के सदस्यों के लिए विशेष कैम्पस ड्राइव

संस्थान अपने प्रशिक्षु और नौकरी खोज में संगठनों और छात्रों और सदस्यों की सहायता के लिए एक और मंच प्रदान करने के लिए। संस्थान की प्रशिक्षु और नौकरी की आवश्यकता के लिए संस्थान द्वारा विशेष ड्राइव का आयोजन किया गया है।

(x) विभिन्न बातचीत में प्लेसमेंट कियोस्क की स्थापना

प्लेसमेंट कियोस्क की स्थापना हैदराबाद, चंडीगढ़, रांची और नई दिल्ली में की गई थी, ताकि नियुक्ति से संबंधित सभी सदस्य संबंधित प्रश्नों को सहायता और संबोधित किया जा सके। इसके अलावा, सदस्यों के बारे में सदस्यों को जागरूक करने के लिए एक प्लेसमेंट कियोस्क को कॉर्पोरेट सीएस, मुंबई के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्थापित किया गया था। नया प्लेसमेंट पोर्टल और उन्हें विभिन्न नौकरियों और प्रशिक्षु आवश्यकताओं के लिए पोर्टल पर खुद को और अपने संगठनों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें।

xi. प्लेसमेंट एजेंसियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना: संस्थान के प्लेसमेंट गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए इच्छुक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) मंगाई गई है। यह भी चर्चा की गई कि एक बाहरी एजेंसी को आमंत्रित करने के बजाय संस्थान के प्लेसमेंट अभियान के लिए कॉर्पोरेट्स और ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेंसी, आईसीएसआई के विभिन्न प्लेसमेंट पहलों के लिए और अधिक कॉर्पोरेट्स लाएंगी जिसके पास अधिक शॉर्टलिस्टिंग / चयन, विभिन्न कॉर्पोरेट्स / स्टॉक एक्सचेंजों / आरटीए (RTA) / बैंकिंग और वित्त उद्योग / नियामकों / सरकारी विभाग और अखिल भारतीय आधार पर उद्योग में अन्य श्रेणियों में दैनिक आधार पर नियमित गतिविधि और भारत के दो राज्यों के बीच कम से कम एक कुशल योग्य जनशक्ति को आईसीएसआई पेशे, इसके पाठ्यक्रम और वितरण को समर्पित जनशक्ति होगी।

20 छात्र के लिए क्षमता निर्माण

सीएस नियमित कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2020 तक, 256 छात्र कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकृत हुए और 4606 छात्र व्यावसायिक कार्यक्रम में पंजीकृत हुए। 31 मार्च, 2020 तक, नियमित कार्यक्रम में वैध पंजीकरण के साथ 210445 छात्र थे।

वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2020 से 15 सितंबर 2020 तक, 521 छात्र कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकृत हुए और 541 छात्र व्यावसायिक कार्यक्रम में पंजीकृत हुए। 15 सितंबर, 2020 तक, नियमित कार्यक्रम में वैध पंजीकरण वाले 190132 छात्र थे।

ख) सीएस फाउंडेशन कार्यक्रम

31 मार्च 2020 तक के वर्ष के दौरान, 14373 छात्रों को फाउंडेशन प्रोग्राम में प्रवेश दिया गया। 31 मार्च, 2020 तक, फाउंडेशन प्रोग्राम में वैध पंजीकरण के साथ 37253 छात्र थे।

फाउंडेशन प्रोग्राम को 3 फरवरी 2020 से बंद कर दिया गया है। 15 सितंबर, 2020 तक, फाउंडेशन प्रोग्राम में वैध पंजीकरण के साथ 30406 छात्र थे।

सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी)

कंपनी सचिवों (संशोधन) विनियम, 2020 ने सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) शुरू की है। 3 फरवरी, 2020 से सीएसईईटी की शुरुआत के साथ, फाउंडेशन प्रोग्राम का नया पंजीकरण अस्तित्व में आ गया और 3 फरवरी, 2020, सीएसईईटी सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए एकमात्र योग्यता प्रवेश परीक्षा है। सीएसईईटी को कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के विविध शैक्षणिक मानकों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, ताकि मेधावी छात्रों को आकर्षित किया जा सके और पेशे के लिए उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सके। जो उम्मीदवार 12 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं या पास कर रहे हैं वे सीएसईईटी में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। स्नातक / स्नातकोत्तर सहित कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों को 3 फरवरी, 2020 से सीएसईईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सीएसईईटी के माध्यम से मेधावी उम्मीदवारों का चयन करने की प्रक्रिया उद्योग और नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भविष्य के सदस्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। वर्ष के दौरान, 3 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक, सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) के लिए 4522 छात्रों ने पंजीकरण किया और 01.04.2020 से 15.09.2020 तक, 13489 छात्रों ने सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) के लिए पंजीकरण किया।

(घ) आईसीएसआई विद्यार्थी शिक्षानिधि ट्रस्ट : संस्थान ने आर्थिक तौर पर पिछड़े और अकादमिक रूप से मेधावी दोनों विद्यार्थियों को कंपनी सचिव पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'आईसीएसआई विद्यार्थी शिक्षा निधि ट्रस्ट' की स्थापना की है। एसईएफटी के जरिए, संस्थान राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्यों में योगदान करते हुए आर्थिक तौर पर जरूरतमंद और अकादमिक रूप से मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा देता है।

ट्रस्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र विद्यार्थियों को पंजीकरण/प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और फाउंडेशन/एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में प्रवेश के समय आम तौर पर देय अन्य शुल्कों के भुगतान की वापसी की जाती है। परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर, ऐसे विद्यार्थियों को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम/प्रोफेशनल प्रोग्राम चरणों में लागू सभी शुल्कों का भुगतान वापस किया जाता है।

वर्ष के दौरान, आर्थिक तौर पर पिछड़े और अकादमिक रूप से मेधावी श्रेणी से क्रमशः 99 और 356 विद्यार्थियों को ट्रस्ट की ओर से वित्तीय सहायता दी गई।

वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित 99 छात्रों और शैक्षणिक रूप से उज्ज्वल श्रेणी के तहत 356 छात्रों को ट्रस्ट से वित्तीय सहायता दी गई और 1 अप्रैल, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक आर्थिक रूप से पिछड़े और संबंधित 4 छात्रों ट्रस्ट की ओर से अकादमिक ब्राइट श्रेणी के 23 छात्रों को वित्तीय सहायता दी गई।

(ङ) परीक्षाओं का संचालन : रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, कंपनी सचिव विनियम, 1982 में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए कंपनी सचिव परीक्षाएं, जून और दिसंबर, 2019 सत्र में पूरे भारत भर में क्रमशः 166 और 172 केन्द्रों और विदेश में स्थित दुबई केन्द्र पर आयोजित की गईं। परीक्षाओं के जून और दिसंबर, 2019 सत्रों में उपस्थित होने के लिए क्रमशः 66718 और 70361 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया। इसके अलावा, फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं दुबई में एक विदेशी केन्द्र सहित पूरे भारत में 125 और 127 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गईं जिनमें परीक्षाओं के जून और दिसंबर, 2019 सत्रों में बैठने के लिए क्रमशः 14034 और 12095 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया। वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षाओं के विभिन्न चरण पूरे करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

परीक्षा का चरण	परीक्षा सत्र	
	जून, 2019	दिसम्बर, 2019
फाउंडेशन प्रोग्राम	8450	7557
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पुराना पाठ्यक्रम)	2233	2185
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (नया पाठ्यक्रम)	222	752
प्रोफेशनल प्रोग्राम (पुराना पाठ्यक्रम)	2719	2619
प्रोफेशनल प्रोग्राम (नया पाठ्यक्रम)	39	280

परीक्षाओं के लिए शहरों की सूची और परीक्षा परिणामों से संबंधित आंकड़े क्रमशः **परिशिष्ट—‘ग’** और **परिशिष्ट—‘घ’** में दिए गए हैं।

(च) सदस्यता पश्चात् योग्यता (पीएमक्यू) परीक्षा का संचालन: संस्थान ने जून, 2019 में कॉरपोरेट शासनमेंसदस्यता पश्चात् योग्यता (पीएमक्यू) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित की। 6 विद्यार्थियों ने नामांकन किया 5 ने परीक्षा दी तथा 2 विद्यार्थियों ने पास किया।

(छ) अखिल भारतीय पुरस्कार : कम्पनी सचिव परीक्षाओं में विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और पहचान देने के लिए, संस्थान ने अनेक पुरस्कार स्थापित किए हैं। निम्नलिखित विद्यार्थियों ने जून और दिसंबर, 2019 परीक्षाओं में राष्ट्रपति का अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त किया:

पदक/परीक्षा	जून 2019	सेंटर	दिसम्बर, 2019	सेंटर
प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक	तान्या कथूरिया	कानपुर	श्रुति कल्पेश शाह	मुंबई
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	खुशी अग्रवाल	अजमेर	कल्याणी अश्विन पुंडलिक	पुणे

पंडित नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार **पाली (राजस्थान) के रितेश मेहता** ने जीता। मौजूदा अखिल भारतीय पुरस्कार योजनाओं, क्षेत्रीय और शाखा पुरस्कार योजनाओं सहित अन्य पुरस्कार विजेताओं के विवरण संस्थान की वेबसाइट www.icsi.edu पर दिया गया है।

(ज) मेरिट प्रमाणपत्र/मेरिट छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता: जून, 2019 और दिसंबर, 2019 में आयोजित फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम प्रत्येक में पहले 25 शीर्ष स्थान वाले सफल विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के अनुसरण में, परीक्षाओं के जून, 2019 और दिसंबर, 2019 सत्र में फाउंडेशन प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के सभी प्रश्नपत्र पहले प्रयास में क्वालीफाई करने वाले पहले 25 टॉपर्स को कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम के क्रमशः एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसी प्रकार, प्रतिभा-सह-साधन सहायता योजना के तहत, पात्र अभ्यर्थियों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि और जून, 2019 और दिसंबर, 2019 परीक्षाओं में प्रतिभावान प्रदर्शन पर विचार करते हुए वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

(झ) पुनः-पंजीकरण नीति : संस्थान द्वारा लाई गई पुनः-पंजीकरण नीति के संदर्भ में, जिन विद्यार्थियों ने संस्थान के पहले के किसी भी पाठ्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट प्रोग्राम/एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास कर ली है वो प्रोफेशनल कार्यक्रम चरण के लिए सीधे पंजीकरण/नामांकन करा सकते हैं बशर्ते वे विनियमों के अनुसार डीनोवो पंजीकरण/विस्तार के लिए पात्र नहीं हैं। वर्ष के दौरान पुनः पंजीकरण नीति के अंतर्गत 44 छात्र पंजीकृत किये गये। 1 अप्रैल 2020 से 15 सितम्बर 2020 15 विद्यार्थियों का पुनः पंजीकरण हुआ।

ज) क्लास रूम टीचिंग : संस्थान देश के विभिन्न भागों में परिचालित संस्थान के क्षेत्रीय एवं चैप्टर कार्यालयों में क्लास रूम टीचिंग सेंटरों के माध्यम से अपने छात्रों को विकल्प आधार पर क्लास रूम टीचिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। आईसीएसआई स्टडी सेंटर छात्रों को क्लास रूम टीचिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।

संस्थान ने उन छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू की हैं, जो आईसीएसआई के क्लास रूम टीचिंग सेंटर में कक्षाएं ले रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण, संस्थान ने आभासी कक्षाएं (वर्चुअल क्लासेस) की व्यवस्था की। आभासी कक्षाएं कई संचार और फाइल-साझाकरण उपकरणों से सुसज्जित हैं जो प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों दोनों को वास्तविक समय में विचारों को बातचीत करने, संलग्न करने और आदान-प्रदान करने की अनुमति देती हैं।

इसके अलावा, मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने और उनका समर्थन करने के लिए, आईसीएसआई ने विभिन्न अन्य पहलें जैसे ऑनलाइन क्रैश पाठ्यक्रम, संशोधन कक्षाएं, मॉक टेस्ट आदि भी शुरू की हैं। संस्थान के सभी छात्रों के लिए विषयवार वीडियो व्याख्यान भी उपलब्ध हैं। संस्थान के सभी छात्रों द्वारा संस्थान के ई-लर्निंग पोर्टल, <https://elearning.icsi.in> पर मुफ्त में वीडियो लेक्चर को एक्सेस किया जा सकता है।

फाउंडेशन, कार्यकारी और व्यावसायिक कार्यक्रम चरणों के छात्रों के अलावा, संस्थान ने सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) के लिए पंजीकृत छात्रों को आभासी कक्षाओं की सुविधा भी प्रदान की।

(ट) आईसीएसआई के क्लास रूम टीचिंग के छात्रों और वाणिज्य / प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों के लिए वीडियो लेक्चर सेशन आयोजित किए गए : संस्थान ने अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में कक्षा शिक्षण में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई नई पहल की हैं। संस्थान के प्रख्यात संकायों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान संस्थान के ई लर्निंग पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। संस्थान इन वीडियो लेक्चर का उपयोग करके क्लास रूम टीचिंग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित कर रहा है, जो छात्रों को

मुख्य परीक्षा की तैयारी में काफी मदद करते हैं। सीएस कोर्स के बारे में जागरूकता पैदा करने और पेशे में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वाणिज्य, प्रबंधन और विधि कॉलेजों के छात्रों को भी इन सत्रों में आमंत्रित किया गया।

ठ) कैरियर जागरूकता : शहरों एवं नगरों में विशेष जोर देते हुए सीएस कोर्स के लिए प्रतिभाशाली छात्रों के आकर्षण को देखते हुए पूरे देश में 2041 कैरियर जागरूकता कार्यक्रम और 10 बड़े कैरियर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष के दौरान संस्थान ने पूरे देश में 118 से अधिक कैरियर मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। सीएस कोर्स को अधिक पसंदीदा बनाने और देश के दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संस्थान ने 45 आईसीएसआई काउंसलर नियुक्त किये हैं। अप्रैल से सितम्बर 2020 तक 349 कैरियर जागरूकता प्रोग्राम और एक मेगा जागरूकता प्रोग्राम कराये तथा 78 कैरियर फैयर में भाग लिया।

(ड) संस्थान की नई पहलें

(i) आईसीएसआई सिग्नेचर अवार्ड : आईसीएसआई सिग्नेचर अवार्ड स्कीम संस्थान द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा का पोषण करने और विद्यार्थी समुदाय के हित के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में संस्थानों के मध्य सार्थक सहयोग की सुविधा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरंभ की गई थी।

ये पहल विश्वविद्यालयों से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना विकसित कर रही है। इस योजना के तहत, संबंधित विश्वविद्यालयों की बी.कॉम परीक्षाओं में टॉप पर रहने वाले और आईआईएम/आईआईटी के चुनिंदा कार्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के टॉपर को स्वर्ण पदक और मेरिट प्रमाणपत्र दिया जाता है। उपरोक्त परीक्षाओं में टॉप तीन रैंक धारक सीएस के एंजीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराते समय पंजीकरण शुल्क से छूट के भी पात्र होंगे।

31 मार्च, 2020 को संस्थान ने आईसीएसआई सिग्नेचर अवार्ड स्कीम के अंतर्गत 42 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ समझौता/एमओयू हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/आईआईएम के साथ समझौता/एमओयू हस्ताक्षर किये हैं:

1. कन्नूर विश्वविद्यालय
2. कालीकट विश्वविद्यालय,
3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
4. केरल विश्वविद्यालय,
5. आईआईएम, शंभलपुर
6. आईआईएम, बैंगलोर
7. केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश,
8. भारथिअर विश्वविद्यालय,
9. केएसकेवी कच्छ विश्वविद्यालय,
10. पेरियार विश्वविद्यालय,
11. मैंगलोर विश्वविद्यालय,
12. आईआईएम, शिलोंग
13. आईआईएम, रांची

1 अप्रैल 2020 से 15 सितम्बर 2020 को एक एमओयू अनुबंध हुआ आईआईएम जम्मू के साथ

(ii) वाणिज्य ओलिम्पियाड : संस्थान ने साइंस ओलिम्पियाड फाउंडेशन (एसओएफ) के सहयोग से अकादमिक वर्ष 2019-20 के दौरान भारत भर के स्कूलों में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य ओलिम्पियाड आयोजित किया था। यह करीब 1950 स्कूलों में 28.11.2019 और 19.12.2019 को आयोजित किया गया था और 44000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसके लिए नामांकन किया था।

(iii) आईसीएसआई अध्ययन केंद्र योजना : अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की पहुंच और स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से, 'आईसीएसआई अध्ययन केंद्र योजना' की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 की गई। अध्ययन केंद्र योजना का उद्देश्य आईसीएसआई और इसके विद्यार्थियों के बीच दूरी के बाधा को तोड़ना है। योजना के तहत, ऐसे क्षेत्रों/स्थानों में अध्ययन केंद्र खोले गए हैं जहां संस्थान के क्षेत्रीय/चैप्टर कार्यालय मौजूद नहीं हैं।

मूलभूत सेवाएं प्रदान के अलावा, अध्ययन केंद्र विभिन्न चरणों के विद्यार्थियों को कोचिंग भी देते हैं।

31 मार्च, 2020 को पूरे देश में 115 अध्ययन केंद्र थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रतिष्ठित कॉलेजों में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 16 नये अध्ययन केंद्र और लेह / लद्दाख में एक संपर्क केंद्र स्थापित किये गये हैं तथा 1 अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक 4 नये शिक्षण शाखाओं का निर्माण हुआ।

(iv) विद्यार्थी माह : संस्थान ने जुलाई, 2019 के दौरान विद्यार्थी माह आयोजित करने की नई पहल की। विद्यार्थी माह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। विद्यार्थी माह संस्थान की ओर से विद्यार्थियों के बीच उत्साह पैदा करने और उन्हें नवीन अध्ययन अनुभवों से परिचित कराने का एक प्रयास है। यह सामाजिक कार्यों में भी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। छात्रों द्वारा कार्यकलापों में पूरे

उत्साह के साथ भाग लेना अभूतपूर्व होता है। पूरे भारत में सभी स्तरों पर टीम वर्क एवं निस्वार्थ सहायता पूरे भारत में विविध कार्यकलापों के सफल आयोजन को सुनिश्चित करती है। विद्यार्थी माह के दौरान आयोजित मुख्य कार्यकलापों में वन महोत्सव दिवस, रक्तदान शिविर, कैरियर जागरूकता कार्यकलाप, छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता, पूरे देश में एक समान क्लास रूम टीचिंग बैच की शुरुआत, समाधान दिवस, वेबिनार आदि शामिल होती है। जुलाई 2020 में एक ऑन लाइन प्रोग्राम किया कोविड-19 के चलते।

(v) विद्यार्थियों के लिए वेबकॉस्ट : स्टेकहोल्डरों को इंजस्ट-मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी का कुशल उपयोग करने में संस्थान हमेशा अग्रणी रहा है। वेबकॉस्ट संस्थान में महत्वपूर्ण कार्यकलापों/विकास पर छात्रों को जानकारी देने के एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों पर वर्ष के दौरान नियमित वेबकॉस्ट आयोजित की गई थी। इसके अलावा, परीक्षा पर विशेष ध्यान देने वाले छात्रों के लिए वेबिनार भी आयोजित किए गए थे।

(vi) "संवाद"— कर्मचारियों के लिए एक इन-हाउस ई-पत्रिका : संस्थान ने कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दिये गये आर्टिकल के साथ संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक इन-हाउस ई-पत्रिका "संवाद" तैयार की है। यह पहल कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने और उन्हें संस्थान के नवीनतम विकासों के बारे में जानकारी देने में सहायता कर रही है।

(vii) शिकायत समाधान प्रकोष्ठ : संस्थान एक सेवा उन्मुख संगठन है, संस्थान के हितधारकों से प्राप्त शिकायतों, सुझावों और प्रश्नों की निगरानी एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है जो संस्थान को समय-समय पर अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संस्थान ने एक शिकायत समाधान प्रकोष्ठ बनाया है, जो <http://support.icsi.edu> पर सहायता पोर्टल के माध्यम से प्राप्त संवाद की निगरानी कर रहा है। शिकायत समाधान प्रकोष्ठ, संस्थान द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव के अलावा संबंधित निदेशालय / इकाइयों से इस तरह की शिकायतों के समाधान के लिए समन्वय के साथ समयबद्ध समाधान की भी सुविधा प्रदान कर रहा है।

(viii) शहीदों की विधवाओं और उनके पारिवारिक सदस्यों, स्थायी विकलांगता मामले, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्ध सैन्य बलों के सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सीएस कोर्स में पंजीकरण के लिए शुल्क में रियायत।

देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों का बलिदान सराहनीय है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के योगदान को पहचानने और शहीदों के परिवारों के लिए एक सद्भावना संकेत के रूप में, संस्थान ने सीएस कोर्स में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित रियायतें देने का फैसला किया है :

1. भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के पारिवारिक सदस्यों और विधवाओं को सीएस कोर्स और परीक्षा शुल्क के विभिन्न चरणों में पंजीकरण के समय देय पूर्ण शुल्क में 100% रियायत
2. युद्ध और अन्य मिशनों में भाग लेने के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता वाले भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्ध सैन्य बलों के कर्मियों को सीएस कोर्स और परीक्षा शुल्क के विभिन्न चरणों में पंजीकरण के समय देय पूर्ण शुल्क में 100% रियायत।
3. भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों के सभी कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मियों को सीएस कोर्स और परीक्षा शुल्क के विभिन्न चरणों में पंजीकरण के समय देय पूर्ण शुल्क में 50% रियायत।

छात्रों के उपरोक्त श्रेणी द्वारा देय अन्य सभी शुल्क सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए लागू दरों के अनुसार होंगे। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी थे।

(ix) जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए 100% शुल्क छूट योजना और हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए फीस में 50 % की रियायत।

देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों के समावेशी विकास के लिए भारत सरकार की पहल की दिशा में संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और समर्थन के रूप में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए 100% प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए फीस में 50% रियायत की शुल्क छूट योजना शुरू कर रहा है। छूट इन संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के युवाओं को मुख्यधारा में आने का अवसर प्रदान कर रही है। भारत सरकार पहले से ही इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जागरूक प्रयास कर रही है और संस्थान बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है।

(x) अखिल भारतीय ऑनलाइन कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी(Quiz): संस्थान पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय कंपनी विधि प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता के प्रारूप को वर्ष 2019 में बदल दिया गया था और छात्रों एवं ऑनलाइन कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को इस वर्ष तीन स्तरों में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कंपनी कानून और संबद्ध क्षेत्रों में छात्रों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना और अधिक से अधिक वैचारिक स्पष्टता सहित विषय के गहन अध्ययन के लिए छात्रों के बीच रुचि पैदा करना है। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया था। इसमें तीन राउंड हुए। प्रारंभिक राउंड और सेमीफाइनल राउंड ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया गया था, जबकि फाइनल राउंड एक स्थान पर शारीरिक उपस्थिति रूप में आयोजित किया गया था जिसे अहमदाबाद शाखा कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। प्रथम पुरस्कार के रूप में रु. 50,000/- का नकद पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार रु. 30,000/ का और तृतीय पुरस्कार के रूप में रु. 20,000/- के साथ प्रशस्ति, प्रत्येक स्तर अर्थात् फाउंडेशन, कार्यकारी और व्यावसायिक के विजेताओं को दिया गया।

(xi) छात्र कंपनी सचिवों का 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन: स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी, 2020 को कोलकाता में "युवोत्सव 2020" नामक छात्र कंपनी सचिवों का 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय "भविष्य की प्रतियोगिता वर्तमान से" (Future Meets Present) था।

छात्र सम्मेलन के लिए छात्रों को नामांकित करने वाले क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों की भागीदारी जबर्दस्त थी। बीस विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय परिषदों और संस्थान की शाखाओं ने भाग लिया। यह छात्रों के लिए एक महान अवसर और उससे सीखने का अनुभव था।

(xii) अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता और अखिल भारतीय कृत्रिम कोर्ट प्रतियोगिता: छात्रों की भागीदारी के स्तर और सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए, अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता और अखिल भारतीय कृत्रिम कोर्ट प्रतियोगिता के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। सीएस कोर्स के प्रत्येक चरण के छात्रों के लिए उपरोक्त प्रतियोगिताओं को तीन स्तरों अर्थात् शाखा कार्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान, क्षतिपूर्ति के राष्ट्रीय दौर को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित किया गया :

प्रतियोगिता का नाम	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के मेजबान क्षेत्रीय परिषद	प्रतियोगिता की तिथि
अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता	एनआईआरसी	17 जनवरी, 2020
अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता	एसआईआरसी	2 नवम्बर, 2019
अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता	एसआईआरसी	अक्टूबर, 2019

(xiii) शिक्षक सप्ताह समारोह : संस्थान ज्ञान पहल के रूप में है और देश भर में आम जनता तक पहुंचने के आव्हान के साथ और अपनी शिक्षा प्रणाली में क्षमता निर्माण करने और अपने संसाधनों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

इसे आगे बढ़ाते हुए, संस्थान ने 5 सितंबर, 2019 से 11 सितंबर, 2019 तक के सप्ताह को शिक्षक सप्ताह के रूप में मनाया। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, संस्थान ने 45 क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय स्थानों पर विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संकायों के लिए “शिक्षकों का सशक्तीकरण” विषय पर शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए। नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। विभिन्न प्रमुख संस्थानों, कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वाणिज्य, प्रबंधन और कानून संकायों से बड़े पैमाने पर भागीदारी देखने को मिली। इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों अकादमियों को अपने ज्ञान और आईसीएसआई को अधिनियम, जीएसटी आदि से सम्बंधित नवीनतम विषयों पर उसे अद्यतन जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। देश भर से शिक्षण समुदाय की भारी प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण, समारोह को 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया था।

(xiv) सम-सामयिकी और सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी: संस्थान ने एक अनोखी पहल के माध्यम से, पेशे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सम-सामयिकी और सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसमें कोई भागीदारी शुल्क नहीं था और छात्र दो अलग-अलग श्रेणियों में पंजीकरण कर सकते थे:

i. श्रेणी 1 —कक्षा 11 और 12 के छात्र

ii. श्रेणी 2— स्नातक स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्र।

दोनों श्रेणियों के तीन राउंड —प्रारंभिक, सेमीफाइनल और फाइनल तीन अलग-अलग तिथियों में आयोजित किए गए और प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

50000 रु., 25000 रु. और 10000 रु. क्रमशः के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के टॉपर्स के लिए 5000 रुपये का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का टॉपर पुरस्कार और दोनों श्रेणियों में 1000 रुपये प्रत्येक के 10 सांत्वना पुरस्कार भी थे। प्रश्नोत्तरी को न्यू करियर अवेयरनेस इनिशिएटिव के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था क्योंकि इसने कैरियर जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रतिभागियों और विजेताओं के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचने में मदद की। पहल को बड़ी सफलता मिली।

(xv) ई-विद्या वाहिनी-आईसीएसआई मूक्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स का प्रारंभ

आईसीएसआई ने संस्थान के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स ई व विद्या वाहिनी शुरू किया, जो जून 2020 की परीक्षा में उपस्थित हुए थे। व्यापक कोरोना वायरस महामारी और आगामी लॉकडाउन शैक्षणिक संस्थानों के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है। ऐसे कठिन समय के दौरान संस्थान के छात्रों का समर्थन करने के लिए जब महामारी ने हमारे जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, संस्थान ने जून 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन मुफ्त क्रैश कोर्स शुरू किया। बाद में सभी छात्रों के अनुरोधों और बड़े हित को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं सभी छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गईं। ऑनलाइन क्रैश कोर्स के वीडियो व्याख्यान संस्थान के छात्रों के लिए <https://elearning.icsi.in> और आईसीएसआई के ट्यूब चैनल पर एक साथ उपलब्ध कराए गए थे।

नए और पुराने सिलेबस के छात्रों के लिए फाउंडेशन, एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के सभी विषयों के लिए क्रैश कोर्स की कक्षाएं 18 मई, 2020 से शुरू की गईं, शिक्षा में समृद्ध अनुभव के साथ प्रसिद्ध संकायों द्वारा सत्र लिया गया। कक्षाओं के दौरान, छात्रों की शंकाओं का समाधान भी किया गया जिससे उन्हें परीक्षा की तैयारी में मदद मिली।

(xvi) सीएसईईटी में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए निशुल्क ऑनलाइन रिव्रेशर / संदेह समाशोधन कक्षाएं 29 अगस्त 2020 को आयोजित

आईसीएसआई ने सीएसईईटी में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए निरु शुल्क ऑनलाइन रिव्रेशर / डाउट क्लियरिंग क्लासेस का आयोजन किया, जो 29 अगस्त 2020 <<https://www.icsi.edu/media/webmodules/1cseet.pn>> पर आयोजित किया गया था। विषयों में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रसिद्ध संकायों द्वारा कक्षाएं ली गईं। 16 अगस्त 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुईं।

बड़ी संख्या में सीएसआईटी में उपस्थित होने वाले छात्रों द्वारा कक्षाओं में भाग लिया गया था और उन छात्रों के लिए आईसीएसआई के YouTube चैनल पर कक्षाओं के वीडियो व्याख्यान भी अपलोड किए गए थे जो ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते थे।

21. ब्रांड निर्माण / मीडिया दृश्यता :

(i) संस्थान अपने ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है और सीएस पेशे ने पूरे वर्ष प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त की है। संस्थान और सीएस कोर्स एवं पेशे को अखिल भारतीय दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए आईसीएसआई समाचार और घटनाओं को प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरव्यू, लाइव पैनल चर्चा, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कवर किया गया है।

विवरण	संख्या
आईसीएसआई घटनाओं, घोषणाओं की प्रेस कवरेज	1647
प्रेस कॉन्फ्रेंस	23
प्रिंट मीडिया में आईसीएसआई प्रवक्ता के विशेष साक्षात्कार और लेखन	32
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज	27
ब्रांड प्रचार के लिए बनाए गए वीडियो की संख्या	24
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधे घंटे के विशेष एपिसोड (ईटी नाउ, दूरदर्शन, टाइम्स नाउ, सीएनबीसी टीवी 18 और इंडिया टुडे टीवी)	4

(ii) समाचार पत्रों के साथ सहभागिता : आईसीएसआई ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सीएस सदस्यों को विशेष ई-समाचार पत्र प्रदान करने के विचार की शुरुआत की। सदस्यों के लिए निः शुल्क आधार पर इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जर्नल, छपतेछपते और दैनिक विश्वामित्र के साथ ई-पेपर प्रदान करने के लिए समझौता-प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। समाचार पत्रों को एक मेल में संकलित किया जाता है और उसे दैनिक आधार पर सभी सदस्यों को भेजा दिया जाता है।

(iii) सोशल मीडिया उपस्थिति

आईसीएसआई सोशल मीडिया पेज	फॉलोअर्स (15 सितम्बर 2020 तक)
Facebook - https://www.facebook.com/ICSI	1,25,502
Twitter - https://twitter.com/icsi_cs	4,6154
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/theicsi	9,950
Instagram - https://www.instagram.com/theicsi/	37,400
Youtube - https://www.youtube.com/user/TheCsInstitute/videos	62,700

(iv) पत्रिका विज्ञापन:

सीएस पाठ्यक्रम पंजीकरण विज्ञापन शिक्षा विशेष / बी-स्कूल विशेष /अग्रणी कैरियर पत्रिकाओं जैसे आउटलुक, द वीक पत्रिका, द डायलाग और फ्री प्रेस जर्नल में जारी किए गए।

- **प्रतियोगिता पत्रिका में विज्ञापन:** सीएस कार्यकारी और फाउंडेशन कार्यक्रम के लिए पंजीकरण के लिए कट-ऑफ की तारीखों को उजागर करने वाले विज्ञापन प्रतियोगिता दर्पण, कंपटिशन रिफ्रेशर, कंपटिशन रिफ्रेशर- ईयर बुक और कैरियर गाइड में जारी किए गए।
- **हाई हिट वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर आईसीएसआई विज्ञापन अभियान:** सीएस एक्जीक्यूटिव एवं फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए पंजीकरण हेतु कट-ऑफ तारीखों को उजागर करने वाला आईसीएसआई विज्ञापन अभियान Shiksha.com, Jagranjosh.com, educationtimes.com, Google ad words, फेसबुक और लिंकडइन पर जारी किया गया।
- **बिजनेस मैगजीन में आईसीएसआई कॉर्पोरेट विज्ञापन:** "सीएस की भूमिका" पर प्रकाश डालते हुए पूर्ण रंगीन पृष्ठ—“कॉर्पोरेट विज्ञापन” बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और रूरल बिजनेस समिट एंड ट्रेड फेयर 2019 की स्मारिका में जारी किए गए।
- **इंटीग्रेटेड कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के लिए विज्ञापन:** “इंटीग्रेटेड कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स” के लिए विज्ञापन एजुकेशन टाइम्स, हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया गया।
- **आईसीएसआई इवेंट्स विज्ञापन:** 51वें स्थापना दिवस, आईसीएसआई उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे प्रमुख आईसीएसआई इवेंट्स के लिए क्वार्टर पेज कलर विज्ञापन जारी किए गए।

22. कॉरपोरेट सोशन रिसर्पोसिबिलिटी

(i) शहीद की बेटी की पढ़ाई के लिए पहल

4 अक्टूबर 2017 को आयोजित आईसीएसआई के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में और भारत सरकार की पहल के प्रति "शहीद की बेटी" पहल शुरू की गई, और संस्थान को इसके तहत पहला प्रमाण पत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी को प्रदान करने का सौभाग्य मिला। योजना शहीद की बेटी 'प्रमाणपत्र पहल के तहत, संस्थान अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहीदों की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

एक अलग कोष बनाया गया है और संचित राशि को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित विंग को दान कर दिया गया है और 31 मार्च 2020 तक संस्थान ने रु. 20 लाख की संचित राशि दान कर दी है। इस संबंध में श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से वर्ष के दौरान एक ऐसा योगदान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।

(ii) दान

पब्लिक हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने की आवश्यकता को समझते हुए, संस्थान ने प्रसार द्वारा इस अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पीएम कॉर्पस फंड को कुल पांच करोड़ तीस लाख रुपये का योगदान दिया है। कोविड -19 महामारी, और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए। योगदान में आईसीएसआई के कॉर्पस से योगदान, आईसीएसआई के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक योगदान और आईसीएसआई के कर्मचारियों द्वारा स्व-एक दिवसीय वेतन का स्वैच्छिक योगदान शामिल है।

23. आईसीएसआई-कॉर्पोरेट शासन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईसीएसआई-सीसीजीआरटी)

केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य महत्व वाले क्षेत्र के रूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस 'के साथ गुणात्मक अनुसंधान और उच्च-स्तरीय कॉर्पोरेट प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के पेशेवर विकास में एक उत्प्रेरक संगठन के रूप में कार्य करना है। अपनी स्थापना के बाद से, केंद्र ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिविधियां शुरू की हैं। सीसीजीआरटी में वातानुकूलित और वाई-फाई सक्षम प्रशिक्षण हॉल, सम्मेलन कक्ष, संकाय कक्ष और एक बड़े सभागार के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। इसके अलावा, सीसीजीआरटी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के प्रतिभागियों के ठहरने के लिए बाइस अच्छी तरह से सुसज्जित दोहरे -साइजा वातानुकूलित कमरे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, सीसीजीआरटी द्वारा की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं:

1. व्यावसायिक विकास कार्यक्रम: आईसीएसआई-सीसीजीआरटी सदस्यों, छात्रों, कॉर्पोरेट और नियामक / सरकारी निकायों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपी) आयोजित करता है। कंपनी सचिवों के ज्ञान आधार को अद्यतन करने के कार्यक्रमों के अलावा, आईसीएसआई-सीसीजीआरटी ने कंपनी सचिवों को अभ्यास के नए क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रूप से उद्यम करने के लिए सक्षम करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए हैं। सीसीजीआरटी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तीन दिन का आवासीय कार्यक्रम (सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सहयोग से, एमसीए द्वारा सौंपा गया), मसौदा पर दो दिन का आवासीय कार्यशाला, 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैकरोफ़ी कोड' पर तीन दिन का आवासीय अनुसंधान संगोष्ठी, क्रॉस बॉर्डर रीस्ट्रक्चरिंग पर पूरे दिन की कार्यशाला, अनुसंधान प्रतियोगिता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), नेतृत्व की स्थिति में महिला पर कार्यशाला शामिल थे ।

लॉकडाउन अवधि के दौरान,आईसीएसआई-सीसीजीआरटी ने दो दिवसीय एमएस & ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल्स पर कार्यशाला, राष्ट्रीय राय लेखन प्रतियोगिता ,कुछ का नाम सहित विभिन्न आभासी प्रशिक्षण पहल की।

2. एकीकृत कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम :कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को आज की चुनौतियों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाने और ऐसे शासन प्रोफेशनल्स का आला कैंडर तैयार करने जो विकासशील बिजनेस माहौल में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का वहन कर सकें और सही मायनों में शासन को सुनिश्चित कर सकें, के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) का कारपोरेट शासन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीजीआरटी) एकीकृत कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक) का 6वां बैच प्रस्तुत कर रहा है। 17 छात्रों ने कोर्स के लिए दाखिला लिया था, जिनमें से आठ ने सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर लिया है।

3. आवासीय प्रबंधन कौशल ओरिएंटेशन कार्यक्रम (आर-एमएसओपी):

वर्ष 2019-20 में सीसीजीआरटी ने 281 छात्रों की कुल संख्या के साथ आठ आर -एमएसओपी को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पाठ्यक्रम आयोजित किया। निकट भविष्य में, आईसीएसआई-सीसीजीआरटी बड़े पैमाने पर छात्रों के लाभ के लिए वर्चुअल एमएसओपी के लिए कमर कस रहा है।

4. प्रकाशन (ई-सूचनापत्र और बुलेटिन) : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीसीजीआरटी मासिक ई-न्यूजलेटर 'सुशासन' के साथ आया है, जो शासन पेशेवरों में अंतर्दृष्टि के व्यापक प्रसार पर केंद्रित है। यह मासिक आधार पर भी प्रकाशित हुआ था, एक ई-प्रकाशन, अमृतकलश जिसने शासन के क्षेत्र में ज्ञान के प्राचीन शब्द पर चर्चा की।

राष्ट्रीय लॉकडाउन ने अधिक अनुसंधान संचालित समकालीन ई-बुलेटिन जैसे 'कंपनी अधिनियम पर एक व्यापक चेकलिस्ट' के साथ आने का अवसर दिया, जिसे सदस्यों से व्यापक प्रतिक्रिया मिल रही है।

5. अद्वितीय पहल-सीसीजीआरटी आप के द्वार : नई पहल के एक अंग के रूप में, आईसीएसआई के सभी शाखाओं / क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञता, गुणवत्ता और ब्रांड आईसीएसआई- सीसीजीआरटी को सुलभ बनाने के लिए और आईसीएसआई के सदस्यों के विकास और वृद्धि तथा पेशेवरों के क्षमता निर्माण के लिए, आईसीएसआई ने इस अद्वितीय अभियान "सीसीजीआरटी आप के द्वार" को शुरू किया है। इस पहल में, सीसीजीआरटी एनसीएलटी पर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के संचालन में शाखाओं की मेजबानी करने के लिए अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग के किए इसका विस्तार करता है।

इन कार्यशालाओं में, सदस्यों को कठोर अनुसंधान गतिविधियों के साथ प्रारूपण और वकालत कौशल सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। कार्यशालाओं के लिए मूट-जज के रूप में काम करने वाले अनुभवी पेशेवरों के सामने उपस्थित होने के लिए वास्तविक मंच प्रदान करने के लिए मूट कोर्ट संरचना तैयार किया जाता है। कार्यशालाओं के दौरान, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बैठे सदस्यों को भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वे अधिनस्थ अधिकारियों के सामने आने के लिए वकालत के कौशल में सुधार कर सकें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीसीजीआरटी ने जयपुर, सूरत, कोच्चि, भायंदर, हैदराबाद में छह कार्यशालाएं और सीसीजीआरटी परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

6. सदस्यों और छात्रों के लिए क्षमता निर्माण पहल : सीसीजीआरटी द्वारा आईसीएसआई के सदस्यों की प्रस्तुति कौशल सहित मौखिक और गैर-मौखिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यावसायिक संवाद पर तीन दिवसीय आवासीय कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया। सदस्यों के आईटी कौशल को बढ़ाने के लिए, एमएस-एक्सेल पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सीसीजीआरटी ने कार्यकारी छात्रों के विभिन्न स्तरों हेतु व्याख्यान श्रृंखला की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पहल की। इसके अलावा, इसने आईसीएसआई के विभिन्न बोर्ड और समिति की बैठकों जैसे पीएमव्यू, निधि आदि भी आयोजित की।

24. आईसीएसआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), हैदराबाद

(i) मध्यस्थता में व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र

आर्बिट्रेशन के उभरते हुए क्षेत्र में सीएस पेशेवरों के सक्षमता विकास के लिए, आईसीएसआई और सीओई "मध्यस्थता एक विकल्प" लॉन्च किया है: व्यावसायिक मध्यस्थता और सामंजस्य के लिए इन दिनों बेसिक और एडवांस लेवल रिकल ओरिएंटेड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे प्रोफेशनल्स के लिए मार्ग प्रशस्त हो आर्बिट्रेटर के रूप में अभ्यास करने के लिए। इस श्रृंखला में पहला आवासीय कार्यक्रम दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था और बाद में ऑनलाइन मोड में दो कार्यक्रम जून 2020 और जुलाई 2020 के महीनों में आयोजित किए गए थे।

(ii) सतत व्यावसायिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम

आईसीएसआई-सीओई ने "बहुमुखी" लॉन्च किया: सदस्यों के लिए कैलेंडर आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, जिसका उद्देश्य कंपनी सचिव के रूप में कार्य करने पर सदस्यों के ज्ञान के आधार और कौशल में वृद्धि के लिए एक मंच प्रदान करना है।

(iii) छात्र प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान, सीओई ने संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार फाउंडेशन और बाहरी छात्रों, शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों, कार्यकारी विकास कार्यक्रमों आदि के लिए ओरिएंटेड कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अन्य स्थानों के प्रतिभागियों को आवासीय आवास की पेशकश की जाती है।

(iv) आवासीय प्रबंधन कौशल अभिविन्यास कार्यक्रम (आर-एमएसओपी) / सीएलडीपी

वर्ष के दौरान, आईसीएसआई-सीओई ने तीन "15 दिन RMOSP का संचालन किया।

(v) अनुसंधान गतिविधियाँ

आईसीएसआई-सीओई ने समकालीन विषयों पर अनुसंधान आधारित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क विकसित किया है।

(vi) प्रकाशन

पोस्ट कोविड -19 परिदृश्य में आर्थिक पुनरुद्धार के उपायों पर पेशेवरों के विचारों को इकट्ठा करने के प्रयास में, आईसीएसआई-COE ने कंपनी के "द इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ टर्बुलेंट टाइम्स" के तत्वावधान में सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोणों का एक विशेष संकलन सामने लाया है। सचिव "ई-प्रकाशन जून 2020 में जारी किया गया है, जिसमें देश भर के 26 चयनित सदस्य शामिल हैं और कंपनी सचिवों की सेवाओं के विस्तार के लिए अशांत समय के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास परिदृश्यों की खोज में कंपनी सचिवों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। आधुनिक युग के कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल प्राचीन भारतीय शास्त्रों में पाए गए ज्ञान से प्रभावित हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, मई 2020 के महीने में आईसीएसआई-COE ने "ज्ञान गंगा: कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स" नाम से एक पाक्षिक ई-पब्लिकेशन जारी किया। यह श्रृंखला कुछ प्राचीन भारतीय शास्त्रों के स्रोतों पर सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रस्तुत करती है जो आधुनिक शासन व्यवस्था की प्रथाओं और प्रथाओं का वर्णन करते हैं और कॉर्पोरेट में नैतिक और विनियामक आवश्यकताओं दोनों के सामंजस्य के तरीकों पर पाठक को संवेदनशील बनाते हैं। सीओई ने इस श्रृंखला में अब तक 7 लेख प्रकाशित किए और सभी सदस्यों को प्रसारित किया। सभी प्रकाशनों को पढ़ने के लिए COE वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

25. सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के तेजी से विकास के साथ, शिक्षा और व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में उपयोग के नए तरीके और क्षेत्र विकसित हुए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित क्रियाकलाप ध्यान देने योग्य हैं :

(i) ई-सीएसआईएन पोर्टल का सृजन

इसे कम्पनी सचिव की नियुक्ति एवं कार्यालय से पदत्याग की निगरानी करते समय तैयार किया गया होगा। इस ई-सीएसआईएन सिस्टम को आईसीएसआई द्वारा अपने सदस्यों को उनकी नियुक्ति या सेवा समाप्ति के सत्यापन के समय सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

(ii) यूडीआईएन पोर्टल का सृजन

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने स्व-प्रशासन की उच्च समझ और व्यावसायिक सीएस द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों के बारे में तैयार उपलब्ध जानकारी को आगे बढ़ाने के प्रयास में एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (UDIN) के रूप में एक पहल शुरू की है। यह इसके सदस्यों की सुविधा के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और प्रमाणन तथा नियामकों द्वारा दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणन करने के लिए विकसित किया गया है।

(iii) अनुशासनात्मक मामलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल:

आईसीएसआई ने एकीकृत रूप में एक वेब आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से आईसीएसआई के अनुशासन निदेशालय के दुराचार और अन्य आचरण संबंधी मामलों और पेशेवरों के विभिन्न अनुशासनात्मक संबंधित जांच की मौजूदा मैनुअल प्रक्रियाओं के स्वचालन की पहल की है। इस पोर्टल का मूल उद्देश्य एक एकीकृत रूप में वेब आधारित सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से आईसीएसआई के अनुशासन विभाग के अन्य दुराचरणों और आचरण संबंधी मामलों तथा पेशेवरों के विभिन्न अनुशासनात्मक संबंधित जांच की मौजूदा मैनुअल प्रक्रियाओं का स्वचालन करना है। इसे <https://discipline.icsi.edu> के जरिए एक्सेस किया जा सकता है।

(iv) प्लेसमेंट पोर्टल

प्लेसमेंट पोर्टल वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे सदस्यों, छात्रों को उपयुक्त नौकरी व प्रशिक्षण के अवसरों के लिए विकसित किया गया है और योग्य कंपनी सचिवों और प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए संगठनों की सुविधा है। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो भर्तीकर्ताओं को वास्तविक आधार पर रिक्तियों को रखने में सक्षम बनाती हैं। उसी समय, सदस्य नौकरी के लिए देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसे <https://placement.icsi.edu/> पर पहुँचा जा सकता है

(v) STIMULATEproject के तहत, संस्थान से त्वरित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण सेवाएँ अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। छात्रों के प्रशिक्षण के निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वचालित हैं:

- छात्र अब ईडीपी, पीडीपी, 15 दिन शैक्षणिक कार्यक्रम, एमएसओपी, आरसी ६ अध्याय और मुख्यालय के लिए 15 दिनों के विशेष प्रशिक्षण जैसे सभी प्रकार के लघु प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- छात्र भुगतान गेटवे के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
- कंपनियों और पीसीएस अब व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- सभी व्यावहारिक प्रशिक्षण को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निष्पादित किया जाएगा जिसमें छात्र अपना प्रशिक्षण समझौता भेज सकते हैं, नियुक्ति पत्र और आयुध डिपो को प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण में ऑटो जनरेटेड प्रशिक्षण प्रायोजन पत्र, ऑटो जेनरेटेड मेल, ऑटो जेनरेटेड एसएमएस मिलेगा।
- प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं दोनों अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- दोनों त्रैमासिक रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है।
- छात्र प्रशिक्षण छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं
- छात्रों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के इतिहास को दर्शाते हुए प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाणपत्र मिलेगा, जो उन्हें अन्य स्थितियों के लिए एसीएस सदस्यता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।

(vi) नया केंद्रीकृत भुगतान गेटवे प्रणाली

सभी क्षेत्रीय / अध्याय कार्यालयों के लिए नया केंद्रीकृत भुगतान गेटवे सिस्टम विकसित किया गया है जिसे सीधे उनके संबंधित स्थानीय बैंकों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

(vii) पीसीएस कौशल निर्देशिका खोज

संस्थान द्वारा विकसित इस उपयोगिता में स्थान, विशेषज्ञता आदि के आधार पर कंपनी सचिवों के कौशल को खोजने के लिए एक खुला खोज विकल्प है

(viii) ई एजेंडा प्रबंधन प्रणाली: संस्थान ई-प्लेटफॉर्म पर एजेंडा / मिनट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत ई-एजेंडा मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि काउंसिल के सदस्यों को यात्रा के दौरान एजेंडा / मिनट का उल्लेख करने में सक्षम बनाया जा सके।

इसके अलावा, संस्थान ने कई अन्य ऑनलाइन / ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास किया। ऐसी कुछ पहलों में नेशनल कन्वेंशन के लिए स्टाल बुकिंग, कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति मॉड्यूल, राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान दान के संग्रह के लिए पोर्टल, आईसीएसआई कार्यक्रमों का कैलेंडर, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए पंजीकरण पोर्टल, क्लास रूम शिक्षण के तहत परीक्षाओं के परिणामों को पोस्ट करने के लिए मॉड्यूल का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय / अध्याय कार्यालयों द्वारा, संकाय / शैक्षणिक संसाधनों के सशक्तिकरण के लिए मॉड्यूल, ई-चार्टर्ड सेक्रेटरी, पेंशनर्स पोर्टल, प्रोग्राम क्रेडिट ऑवर्स का ऑनलाइन अपडेशन, सदस्यों के लिए डिजी-लॉकर, कॉम्प्लिनेटी कम्प्लायंस सॉफ्टवेयर, आईसीआईसी मध्य पूर्व सदस्यता योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल, आईसीएसआई-आईसीएसई के तहत सदस्य सत्यापन, कॉर्पोरेट सदस्यता शुल्क के संग्रह के लिए ऑनलाइन सुविधा, Google Chrome समस्या, सीएसईईटी पंजीकरण पोर्टल, आदि के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईसीएसआई अनुप्रयोगों का उन्नयन।

- पहल पर काम करने वाले संस्थान: सीएसआर पुरस्कार पोर्टल
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड पोर्टल
- सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट अवार्ड पोर्टल
- लाइसेंस पोर्टल
- पीयर रिव्यू बोर्ड पोर्टल

26. आईसीएसआई आईआईपी

आईसीएसआई इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईसीएसआई आईआईपी) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत पंजीकृत एक फ्रंटलाइन रेगुलेटर है, जो देश भर में पंजीकृत 3 इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों के बीच है। आईसीएसआई आईआईपी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है और भारत के इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आईसीएसआई आईआईपी के मुख्य कार्य पेशेवर सदस्यों को भर्ती करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, निगरानी करना और अनुशासित करना है। आईसीएसआई आईआईपी पेशेवर आचरण के मानकों का पालन करता है और अपने पेशेवर सदस्यों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करता है। आईसीएसआई आईआईपी ने 986 इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में पंजीकरण किया है जो कंपनी सचिव, प्रबंधन विशेषज्ञ, अधिवक्ता, लागत लेखाकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आईसीएसआई आईआईपी के गवर्निंग बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक और आईसीएसआई से नामित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।

कार्यक्रम / कार्यशालाएं / इंटरएक्टिव बैठकें

नए इन्सॉल्वेंसी रिजिम आईसीएसआई आईआईपी में खुद को स्थापित करने में IP का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न वेबिनार / कार्यक्रम / कार्यशालाएं / इंटरएक्टिव मीटिंग आयोजित की जाती हैं। 1 अप्रैल, 2019 से आगे:

- 16 प्री-रजिस्ट्रेशन कोर्स आईआईपी के लिए आयोजित किए गए हैं
- आईसीएसआई आईआईपी द्वारा देश भर में अधिकतम पेशेवरों की संख्या तक पहुंचने वाले विषयों पर 28 वेबिनार आयोजित किए गए हैं। (1 अप्रैल, 2019 से)
- इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के साथ 6 इंटरएक्टिव मीटिंग्स आईसीएसआई आईआईपी द्वारा आयोजित की गई हैं, ताकि इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की राय और चिंताओं को संचित किया जा सके।
- 6 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है
- 4 राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए हैं
- सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
- 12 राउंडटेबल्स, मीटिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आदि का आयोजन किया गया है

अनुसंधान और ज्ञान संस्थान

आईसीएसआई आईआईपी ने व्यावहारिक उन्मुख प्रकाशनों को बाहर लाने के लिए इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों की शिक्षा और विकास के लिए कई गतिविधियाँ की हैं:

1. अब तक प्रकाशित प्रकाशनों में शामिल हैं:

1. IBC के तहत अंतिम शब्द
2. सीमित इन्सॉल्वेंसी परीक्षा की तैयारी गाइड
3. IBC लर्निंग कर्व्स
4. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (नियमों और विनियमों के साथ) (अब तक के पांच संस्करण)रु
5. अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल- एक हैंडबुक (अब तक 3 संस्करण)
6. इन्सॉल्वेंसी लॉ का व्यावहारिक पहलू (अब तक 4 संस्करण)

7. एनसीएलएटी के 100 लैंडमार्क निर्णय – आईबीसी में एक अंतर्दृष्टि
8. हितधारकों के लिए न्यायिक & नियामक नियम— एक पुस्तिका (अब तक 2 संस्करण)
9. सैद्धांतिक परिसमापन एक हैंडबुक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (नियम और विनियम के साथ)
10. IBC केस लॉ कम्पेंडियम (केस ब्रीफ्स के साथ)
11. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत इश्योरेंस – इश्यू एनालिसिस
12. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर सरलीकृत गाइड
13. ब्रॉशर फॉर बैंकर्स— "दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016" – ए बून फॉर बैंकर्स

बी. दिवाला और दिवालियापन पत्रिका (एक मासिक पत्रिका)

ICSI IIP नवंबर, 2017 से अपनी मासिक पत्रिका (निगमन के एक वर्ष से कम) के साथ सामने आया है। आईसीएसआई आईआईपी सदस्यों के लिए मासिक पत्रिका (आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन जर्नल) प्रकाशित करने वाला पहला संगठन है। आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जर्नल IBC पर देश की पहली पत्रिका थी।

सी- अन्य ज्ञान पहल

1. अन्य ज्ञान संबंधी पहलों में नॉलेज रेपोरे को शामिल करना— एक साप्ताहिक अपडेट, नॉलेज कैप्सूल— एक पाक्षिक अपडेट, दैनिक सीखने की अवस्था, दैनिक आधार पर रीडर्स रेंडिशन, लिमिटेड इन्सॉल्वेंसी एग्जामिनेशन के लिए डब्लू सीरीज कवर सिलेबस शामिल हैं।

27. आईसीएसआई—आरवीओ

आईसीएसआई—आरवीओ—एक सेक्शन 8 कंपनी है, जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ़ सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और IBBI के साथ पंजीकृत है, जो पंजीकृत वालुअर्स को शिक्षित, विनियमित करने और उनकी निगरानी के उद्देश्य से बनाई गई है। जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी कंपनी के शेयरों, शेयरों, डिबेंचर, प्रतिभूतियों आदि के संबंध में मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, यह एक ऐसी योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा मान्य किया जाएगा और इस तरह एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, कंपनी के सचिव को मान्यता प्राप्त है कि वे परिसंपत्ति वर्ग प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पंजीकृत वल्लर को कंपनियों (पंजीकृत वल्लर और मूल्यांकन नियम, 2017) के तहत पंजीकृत मानते हैं।

मुख्य विचार:

- पैन इंडिया, कंपनी ने विभिन्न स्थानों में सफलतापूर्वक 50 घंटे शैक्षिक पाठ्यक्रम (भौतिक मोड में) के अट्टाईस बैचों का संचालन किया था, जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गौहाटी, बंगलुरु, नोएडा, आगरा, लुधियाना, पुणे आदि शामिल हैं।
- दोनों पंजीकृत वालुअर्स के साथ—साथ वेल्थुर मेंबर्स के संदर्भ में, कंपनी ने संख्या में कई गुना वृद्धि हासिल की है।
- कंपनी IBBI द्वारा गठित "डिस्क्लेमर के लिए एक मानक खाका विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति" में एक सक्रिय सदस्य है और एक नेतृत्व के रूप में सफलतापूर्वक अप्रैल, 2020 में अपनी रिपोर्ट IBBI को सौंप दी है।
- कंपनी ने 14 फरवरी 2020 को IBBI द्वारा आयोजित कंपनियों (पंजीकृत मान्यताओं और मूल्यांकन) नियमों, 2017 के अनुसार तीन एसेट वर्गों के लिए पीयर रिव्यू के निष्कर्षों को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया।
- कंपनी ने मान्यता के सात सक्रिय क्षेत्रों में एक अनूठा कार्यक्रम यानी रिसर्च पेपर राइटिंग प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें आईसीएसआई के सदस्यों के साथ—साथ आईसीएसआई—आरवीओ भी शामिल हैं।
- लॉक डाउन अवधि के दौरान समय की व्यस्तता और फुलर उपयोग के लिए, आईसीएसआई आरवीओ अपने साथियों के बीच पहला आरवीओ है जो एसेट क्लास सिम्युलेशन या फाइनैशियल एसेट्स में 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के ऑनलाइन बैचों की घोषणा करता है। पहला ऑनलाइन बैच 26 अप्रैल, 2020 को संपन्न हुआ था।
- आईसीएसआई आरवीओ 50 घंटे शैक्षिक पाठ्यक्रमों के सात ऑनलाइन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अपने साथियों के बीच पहला आरवीओ है। सभी बैच इंटरएक्टिव थे और न केवल कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल से बल्कि अन्य प्रोफेशनल्स से भी जबरदस्त रिसर्च मिला।
- अध्याय स्तर पर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने मानेसर में 6 से 8 फरवरी, 2020 तक आयोजित 2 वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में आईसीएसआई ने दो पुरस्कार प्राप्त किए। बेंगलुरु चौपटर को मेट्रो शहरों के लिए आईसीएसआई आरवीओ वैल्यूएशन अवार्ड 2019 की श्रेणी में और जयपुर चौपटर को गैर-मेट्रो शहरों के लिए आईसीएसआई आरवीओ वैल्यूएशन अवार्ड 2019 की श्रेणी में सम्मानित किया गया।

28. भविष्य का दृष्टिकोण

- पिछले कुछ महीनों में न केवल कॉरपोरेट्स या पेशेवर, अपने गतिविधि के कार्यक्षेत्र की परवाह किए बिना विश्व स्तर पर संगठनों और व्यक्तियों के कामकाज में लागू दृष्टिकोणों में एक 360 डिग्री बदलाव प्रकट करने में सक्षम रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इससे अलग नहीं है। देशव्यापी तालाबंदी के बाद महामारी के प्रसार ने सीमाओं और चुनौतियों का एक नया आयाम प्रस्तुत किया है इसबीच सबसे बड़ी चुनौती संस्थान के कामकाज की यथास्थिति बरकरार रखने की थी, अन्य सभी गतिविधियों की यथास्थिति को असमान रूप से चुनौती दी गई थी। न केवल मुख्यालय द्वारा बल्कि सभी शाखाओं में कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के विभिन्न चरणों के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान वृद्धि की पहल के रूप में होने वाली घटनाओं से, बुनियादी चीजों के स्कीमा ने एक गतिशील परिवर्तन की मांग की।
- इस सब से बचाव के लिए प्रौद्योगिकी सामने आई। डिजिटल क्रांति, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म और ऐप, जिन्होंने न केवल पहुंच में आसानी की, बल्कि कहीं अधिक पहुंच और कनेक्टिविटी प्रदान की। वेबिनार जो अध्ययन मंडलों, सेमिनारों और सम्मेलनों के रूप में भौतिक बैठकों की कमी को अच्छा बनाने के लिए आयोजित किए गए, यह वेबिनार न केवल पेशेवर कौशल और नेतृत्व गुणों बल्कि व्यक्तिगत जीवन कौशल को समान रूप से बढ़ाने वाले विषयों से सम्बंधित थे।
- जहां तक राष्ट्र के भविष्य के लिए शासन पेशेवरों का संबंध है, बहुत चिंतन, विचार-विमर्श और स्थगन के बाद, जून, 2020 के सत्र को दिसंबर, 2020 के परीक्षा सत्र के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया और इसकी सराहना भी की गई। हालांकि, वर्ष की पहली सीएसईईटी तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच करने की कोशिश की जा रही, वही सभी घटनाएं आने वाले समय के लिए सही प्रेरणा के रूप में काम करेगी, जिसमें हम, संस्थान, इसके सदस्य, छात्र और अन्य सभी हितधारक इसके लिए अपना पक्ष रखेंगे और हमारे शानदार रवैये और हमारी एकजुटता की ताकत में नए सिरे से विश्वास पैदा होगा।
- एक कहावत है कि 'भविष्य अनिश्चित है' शायद महीनों के दौरान अपनी असली समझ पाए लेकिन जो व्यावसायिकता हमारे पास है वह हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रेरणा और शक्ति देती है। सबसे अधिक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों में से कुछ के साथ वेबिनार सत्रों में चर्चा से यह अहसास हुआ है कि न केवल भारत के संस्थान में, बल्कि सभी क्षेत्रों में शासन संरचनाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी संस्थान और उसके सदस्यों या शासन के कंधों पर है। चाहे वह देश का जमीनी स्तर हो या दुनिया के लिए ऊपर से सुशासन की मशाल थामें दुनिया के आधे से अधिक कंपनी सचिव सदस्यता वाले आईसीएसआई को न केवल सुशासन बल्कि विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शासन के मोर्चे पर नेतृत्व करना होगा। एक लक्ष्य जो अच्छी तरह से इस सक्षमसंस्थान के विजन, मिशन और आदर्श वाक्य के साथ मेल खाता है।

29. आभार

देश के प्रथम नागरिक, भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, परिषद अपनी ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जीएसटी काउंसिल, आईसीपीएफसेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, सीसीआई, स्टॉक एक्सचेंज, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों एवं कार्यालयों के साथ ही विनियामक प्राधिकरणों का उनके पेशे पर विश्वास करने और पेशे के विकास के लिए निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट करती है।

परिषद क्षमता निर्माण पहल के रूप में आयोजित वेबिनार के माध्यम से देश के सभी हिस्सों से आने वाले यहां तक की राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं से परे, सभी गणमान्य व्यक्तियों और तेजस्वी व्यक्तियों के अपनी तरह की उपस्थिति के लिए उनके शब्द—ज्ञान और हमारे साथ ज्ञान साझा करने के लिए अपनी असीम और गहरी प्रशंसा व्यक्त करती है। व्यवसाय से आपकी उम्मीदें आने वाले समय में हमारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करेंगी।

परिषद पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्तीय, औद्योगिक एवं निवेश संस्थानों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघों एवं अन्य एजेंसियों का भी आभार व्यक्त करती है। परिषद अपने सभी सहयोगियों सहित भारतीय उद्योग संघ का कम्पनी सचिव की दक्षता को पूर्णतः सम्मानित करने एवं अच्छे अभिशासन को सुनिश्चित करने, बढ़ावा देने एवं उसके प्रसार के लिए हमारी सेवाएं शामिल करने के लिए उनका तहे दिल से सराहना करती है।

परिषद अनुशासनात्मक समिति के सदस्यों, अनुशासन बोर्ड, सचिवीय मानक बोर्ड, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड, पीर रिव्यू बोर्ड, संपादकीय सलाहकार बोर्ड, विशेषज्ञ सलाह बोर्ड, कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के निर्णायक मंडल, विजन नए आईसीएसआई 2022 के कार्यान्वयन पर मुख्य समूह, मुख्य समूह एवं संस्थान के टास्क फोर्स का भारतीय परिदृश्य में आईसीएसआई कार्यकलापों के वर्तमान एवं भावी प्रभाव को आकार देने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद करती है। अंत में परिषद क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टर्स के सहयोग एवं समन्वय के लिए उनकी सराहना करती है और परिषद पूरी आईसीएसआई टीम का परिषद के निर्णयों में सहयोग, कार्यान्वयन एवं बहु-आयामी व बहु-केन्द्रित निष्पादन में उनके जोश, समर्पण, प्रतिबद्धता की लिए अपनी ओर से सभी का आभार व्यक्त करती है।

कृते परिषद की ओर से

सीएस आशीष गर्ग, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 267 / 2020—21]

परिशिष्ट—'क'

वर्ष 2019 के लिए परिषद की स्थायी, गैर-अस्थायी समितियों / बोर्ड की सूची

सर्व / श्री			
1	कार्यकारी समिति		
1.	आशीष गर्ग	अध्यक्ष	
2.	नगेन्द्र राव डी	सदस्य	
3.	रंजीत पाण्डे	सदस्य	
4.	मनोज पांडे	सदस्य (सरकारी नामित)	
5.	देवेन्द्र वी देशपाण्डे	सदस्य	
6.	मनीश गुप्ता	सदस्य	
7.	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य	
2	.वित्त समिति		
1.	आशीष गर्ग	अध्यक्ष	
2.	नगेन्द्र राव डी	सदस्य	
3.	रंजीत पाण्डे	सदस्य	
4.	डॉ. मधु विज	सदस्य (सरकारी नामित)	
5.	चेतन बी पटेल	सदस्य	
6.	दीपक कुमार खेतान	सदस्य	
7.	एनपीएस चावला	सदस्य	
3	परीक्षा समिति		
1.	आशीष गर्ग	अध्यक्ष	
2.	नगेन्द्र राव डी	सदस्य	
3.	ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	सदस्य (सरकारी नामित)	
4.	बी नरसिम्हन	सदस्य	
5.	एनपीएस चावला	सदस्य	
6.	प्रवीण सोनी	सदस्य	
7.	विनीत के चौधरी	सदस्य	
4	.वित्तीय सेवाएं समिति		
1.	प्रवीण सोनी	अध्यक्ष	
2.	अनिल गुप्ता	सदस्य (सरकारी नामित)	
3.	बी नरसिम्हन	सदस्य	
4.	चेतन बी पटेल	सदस्य	
5.	दीपक कुमार खेतान	सदस्य	
6.	देवेन्द्र वी देशपाण्डे	सदस्य	
7.	रामासुब्रमणियम सी	सदस्य	
5	कॉर्पोरेट कानून एवं अभिषासन समिति		
1.	एनपीएस चावला	अध्यक्ष	
2.	चेतन बी पटेल	सदस्य	
3.	मनीश गुप्ता	सदस्य	
4.	रामासुब्रमणियम सी	सदस्य	
5.	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य	
6	व्यावसायिक विकास समिति		
1.	आशीष गर्ग	अध्यक्ष	
2.	रंजीत पाण्डे	सदस्य	
3.	अनिल गुप्ता	सदस्य (सरकारी नामित)	
4.	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य	
5.	चेतन बी पटेल	सदस्य	
6.	हितेन्द्र मेहता	सदस्य	
7.	एनपीएस चावला	सदस्य	
8.	रामासुब्रमणियम सी	सदस्य	
9.	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य	
7	प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सुविधा समिति		
1.	नगेन्द्र राव डी	अध्यक्ष	
2.	डॉ. मधु विज	सदस्य (सरकारी नामित)	
3.	बी नरसिम्हन	सदस्य	

	4.	दीपक कुमार खेतान	सदस्य
	5.	देवेन्द्र वी देशपाण्डे	सदस्य
	6.	मनीष गुप्ता	सदस्य
	7.	प्रवीण सोनी	सदस्य
	8.	विनीत के चौधरी	सदस्य
8	पेशेवर कम्पनी सचिव समिति		
	1.	दीपक कुमार खेतान	अध्यक्ष
	2.	बी नरसिम्हन	सदस्य
	3.	चेतन बी पटेल	सदस्य
	4.	मनीष गुप्ता	सदस्य
	5.	प्रवीण सोनी	सदस्य
	6.	रामासुब्रमणियम सी	सदस्य
	7.	विनीत के चौधरी	सदस्य
9	सूचना प्रौद्योगिकी समिति		
	1.	चेतन बी पटेल	अध्यक्ष
	2.	रंजीत पाण्डे	सदस्य
	3.	एस संधनाकृष्णन	सदस्य (सरकारी नामित)
	4.	देवेन्द्र वी देशपाण्डे	सदस्य
	5.	एनपीएस चावला	सदस्य
10	सहकर्मी समीक्षा बोर्ड		
	1.	रामासुब्रमणियम सी	अध्यक्ष
	2.	सिद्धार्थ मुरारका	उपाध्यक्ष
	3.	जीएम गणपति	सदस्य
	4.	हितेन्द्र मेहता	सदस्य
	5.	एलएन जोशी	सदस्य
	6.	आर श्रीधरन	सदस्य
	7.	विनीत के चौधरी	सदस्य
11	प्लेसमेंट समिति		
	1.	प्रवीण सोनी	अध्यक्ष
	2.	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य
	3.	बी नरसिम्हन	सदस्य
	4.	चेतन बी. पटेल	सदस्य
	5.	रामासुब्रमणियम सी	सदस्य
12	पीएमक्यू कोर्स समिति		
	1	मनीष गुप्ता	अध्यक्ष
	2	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य
	3	दीपक कुमार खेतान	सदस्य
	4	देवेन्द्र वी. देशपाण्डे	सदस्य
	5	हितेन्द्र मेहता	सदस्य
	6	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य
13	सचिवीय मानक बोर्ड		
	1	सतविन्दर सिंह	अध्यक्ष
	2	एस सुधाकर	उपाध्यक्ष
	3	अवनीश द्विवेदी	सदस्य
	4	बी.रनगनाथन	सदस्य
	5	डी. सी. जैन	सदस्य
	6	दीपक कुमार खेतान	सदस्य
	7	धनंजय शुक्ला	सदस्य
	8	द्वारका नाथ सी.	सदस्य
	9	मकारंद जोशी	सदस्य
	10	मोरुर इलायप्पन वादिवेल सेल्वम	सदस्य
	11	नारायण शंकर	सदस्य
	12	प्रवीण सोनी	सदस्य

	13	राजवीर सिंह	सदस्य
	14	आर. कालिदास	सदस्य
	15	आर एस भाटिया	सदस्य
	16	संजय ग्रोवर	सदस्य
	17	एस. सी. शारदा (सुश्री)	सदस्य
	18	एस सी वासुदेवा	सदस्य
	19	रूपेश कुमार अग्रवाल	सदस्य
	20	टी वेंकट रमन	सदस्य
	21	आरबीआई के प्रतिनिधि	सदस्य
	22	आईसीएआई के प्रतिनिधि	सदस्य
	23	एमसीए के प्रतिनिधि	सदस्य
	24	आईसीएआई-कॉस्ट के प्रतिनिधि	सदस्य
	25	सीआईआई के प्रतिनिधि	सदस्य
	26	सेबी के प्रतिनिधि	सदस्य
	27	बीएसई के प्रतिनिधि	सदस्य
	28	एनएसई के प्रतिनिधि	सदस्य
	29	फिक्की के प्रतिनिधि	सदस्य
14	विशेषज्ञ सलाह बोर्ड		
	1	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	अध्यक्ष
	2	अनिल गुप्ता	सदस्य (सरकारी नामित)
	3	सांताकृष्णन एस.	सदस्य (सरकारी नामित)
	4	एनपीएस चावला	सदस्य
	5	शिल्पेश दलाल	सदस्य
	6	अशोक कुमार कसेरा	सदस्य
	7	अवनीश मटका	सदस्य
	8	एसएम प्रमोद	सदस्य
	9	जेपी शर्मा (डॉ)	सदस्य
	10	पुनीत हांडा	सदस्य
	11	राज के अग्रवाल (डॉ)	सदस्य
	12	संजीव गुप्ता (डॉ)	सदस्य
	13	संतोष माचेरला	सदस्य
	14	के सेठुरमन	सदस्य
	15	जोय घोष	सदस्य
	16	राकेश सिंह	सदस्य
	17	आशीष कुलकर्णी	सदस्य
	18	प्रवीण वी. पाटिल	सदस्य
	19	राकेश गर्ग	सदस्य
15	अनुसंधान और प्रकाशन समिति		
	1.	एनपीएस चावला	अध्यक्ष
	2.	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य
	3.	हितेन्द्र मेहता	सदस्य
	4.	प्रवीण सोनी	सदस्य
	5.	विनीत के चौधरी	सदस्य
16	संपादकीय सलाहकार बोर्ड		
	1	हितेन्द्र मेहता	अध्यक्ष
	2	अनिल गुप्ता	सदस्य (सरकारी नामित)
	3	डॉ. मधु विज	सदस्य (सरकारी नामित)

	4	अखिल प्रसाद (डॉ.)	सदस्य
	5	आस्था गुप्ता (सुश्री)	सदस्य
	6	डॉ. डी के जैन	सदस्य
	7	जी आर भाटिया	सदस्य
	8.	एच एम दत्तात्रेय	सदस्य
	9	मनोज बिष्ट	सदस्य
	10	रत्नेश रुखारियन	सदस्य
	11	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य
	12	वासुदेव राव देवकी	सदस्य
	13	विनोद सिंघानिया (डॉ.)	सदस्य
17	आईसीएसआई-सीसीजीआरटी एवं सीओई प्रबंधन समिति		
	1	देवेन्द्र वी. देशपांडे	अध्यक्ष
	2	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य
	3	आशीष करोडिया	सदस्य
	4	बी. नरसिम्हन	सदस्य
	5	दीपक कुमार खेतान	सदस्य
	6	गोपाल चामल	सदस्य
	7	कौशिक झावेरी	सदस्य
	8	मनीष गुप्ता	सदस्य
	9	ओम प्रकाश बगड़िया	सदस्य
18	चुनाव सुधार समिति		
	1.	बी नरसिम्हन	अध्यक्ष
	2.	एस सांताकृष्णन	सदस्य (सरकारी नामित)
	3.	चेतन बी पटेल	सदस्य
	4.	देवेन्द्र वी देशपांडे	सदस्य
	5.	मनीष गुप्ता	सदस्य
19	विनियमन एवं चैप्टर दिशानिर्देश समिति		
	1.	सिद्धार्थ मुरारका	अध्यक्ष
	2.	डॉ. अहलादा राव वुमनथला	सदस्य
	3.	हितेन्दर मेहता	सदस्य
	4.	प्रवीण सोनी	सदस्य
	5.	रामासुब्रमणियम सी.	सदस्य
20	गुणवत्ता समीक्षा समिति		
	1	सुश्री निशि सिंह	अध्यक्ष
	2	देवेन्द्र कुमार	सदस्य
	3	रितिका भाटिया	सदस्य
	4	मनीष गुप्ता	सदस्य
	5	प्रमोद कुमार राय	सदस्य
21	अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति		
	1.	रंजीत पाण्डे	अध्यक्ष
	2.	बी नरसिम्हन	सदस्य
	3.	हितेन्दर मेहता	सदस्य
	4.	एनपीएस चावला	सदस्य
22	लेखापरीक्षा मानक बोर्ड		
	1	विनीत के चौधरी	अध्यक्ष
	2	देवेन्द्र वी देशपांडे	उपाध्यक्ष
	3	अमित गुप्ता	सदस्य
	4	अंशुल कुमार जैन	सदस्य
	5	अशोक त्यागी	सदस्य
	6	दीपक शर्मा	सदस्य
	7	जी वी श्रीनिवासमूर्ति	सदस्य
	8	कुमुदिनी भालेराव (सुश्री)	सदस्य
	9	मनोज राजाराम हुरकत	सदस्य
	10	मुकेश जैन	सदस्य
	11	मुनीश कुमार शर्मा	सदस्य

	12	पंकज विरमानी	सदस्य
	13	राघवेन्द्र जोशी	सदस्य
	14	राजीव भांबरी	सदस्य
	15	रामासुब्रमणियम सी.	सदस्य
	16	रवि शर्मा	सदस्य
	17	रेखा नायक (सुश्री)	सदस्य
	18	सचिन अग्रवाल	सदस्य
	19	संतोष कुमार	सदस्य
	20	शिखा राय (सुश्री)	सदस्य
	21	सिद्धार्थ मुरारका	सदस्य
	22	विशाल अरोड़ा	सदस्य
	23	बीएसई के प्रतिनिधि	सदस्य
	24	एनएसई के प्रतिनिधि	सदस्य
	25	एमसीए के प्रतिनिधि	सदस्य
23	अनुशासनात्मक समिति		
	1.	नगेन्द्र राव डी.	पीठासीन अधिकारी
	2.	रंजीत पाण्डे	सदस्य
	3.	मीनाक्षी दत्ता घोष (सुश्री)	सदस्य (सरकारी नामित)
	4.	नलिन कोहली	सदस्य (सरकारी नामित)
	5.	बी नरसिम्हन	सदस्य
24	अनुशासनात्मक बोर्ड		
	1.	दीपक कुमार खेतान	पीठासीन अधिकारी
	2.	मनीश गुप्ता	सदस्य
	3.	आशीष मोहन	सदस्य

विभिन्न बाहरी समितियों पर नामजद सदस्य

क्र. सं.	समिति/इंस्टीट्यूशन के नाम	वर्ष 2020 में समिति में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि
1.	लेखा मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.)—एमसीए	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
2.	कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद (एनएफसीजी)	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
3.	कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन का ट्रस्टी बोर्ड (एनएफसीजी)	सीएस अशोक कुमार दीक्षित कार्यवाहक सचिव
4.	इंडो-यूके एकाउंटेंसी टास्क फोर्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
5.	इसोल इंटरनेशनल की न्यू इंडिया सदस्यता विकास समिति	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
6.	भारत-नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित एलओआई के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में गठित कार्यरत समूह	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष सीएस रंजीत पाण्डे आईपीपी और परिषद सदस्य
7.	जीआरआई फोकल प्वाइंट इंडिया के लिए सलाहकार ग्रुप	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
8.	आईआईसी इंडियन बैंक एसोसिएशन	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
9.	एकीकृत प्रबंधन के लिए श्री अरविन्दो फाउंडेशन का पदेन सदस्य सलाहकार बोर्ड (एसएएफआईएम)	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष
10.	प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष सीएस रंजीत पाण्डे आईपीपी और परिषद सदस्य
11.	दिवाला कानून समिति	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष सीएस रंजीत पाण्डे आईपीपी और परिषद सदस्य
12.	मूल्यांकन मामलों पर सलाह के लिए समिति	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष सीएस रंजीत पाण्डे आईपीपी और परिषद सदस्य
13.	लेखाकरण मानक बोर्ड, आईसीएसआई	हितेन्द्र मेहता परिषद सदस्य
14.	लागत लेखाकरण मानक बोर्ड, आईसीओआई	नगेन्द्र राव डी परिषद सदस्य
15.	लागत लेखापरीक्षा एवं एंशोरेंस मानक बोर्ड, आईसीओआई	डॉ. अहलादा राव वुमनथला परिषद सदस्य
16.	सीएसआईए	सीएस आशीष गर्ग अध्यक्ष सीएस रंजीत पाण्डे आईपीपी और परिषद सदस्य

परिशिष्ट—'ख'

परिषद और स्थायी तथा गैर-अस्थायी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	परिषद/समिति	परिषद		कार्यकारी समिति		वित्त समिति		परीक्षा समिति		अनुशासन समिति	
	नाम	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति
1	सीएस आशीष गर्ग	9	9	7	6	5	4	7	6	-	-
2	सीएस नागेन्द्र राव डी.	9	9	7	6	1	1	1	1	19	16
3	सीएस डॉ. अहलादा राव वुमनथला	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सीएस बी नरसिम्हन	9	8	-	-	-	-	7	5	19	16
5	सीएस चेतन बी पटेल	9	8	-	-	5	3	-	-	-	-
6	सीएस दीपक कुमार खेतान	9	9	-	-	5	5	-	-	-	-
7	सीएस देवेन्द्र वी देशपाण्डे	9	8	7	5	-	-	-	-	-	-
8	सीएसहितेन्दर मेहता	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
9	सीएस मनीश गुप्ता	9	8	7	6	-	-	4	4	-	-
10	सीएस एनपीएस चावला	9	9	-	-	5	1	2	0	-	-
11	सीएस प्रवीण सोनी	9	8	-	-	4	2	1	1	-	-
12	सीएस रंजीत पाण्डे	9	9	7	7	5	5	6	5	19	17
13	सीएस रामासुब्रमणियम सी	9	7	-	-	-	-	2	1	-	-
14	सीएस सिद्धार्थ मुरारका	9	9	7	6	-	-	3	2	-	-
15	सीएस विनीत के चौधरी	9	8	-	-	-	-	7	3	-	-
16	श्री अनिल गुप्ता	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	श्री मनोज पांडे	6	1	5	0	--	-	-	-	-	-
18	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	9	1	-	-	-	-	7	0	-	-
19	डॉ. मधु विज	9	2	-	-	5	3	-	-	-	-
20	श्री एस सांताकृष्णन	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री अनुराग अग्रवाल	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
22	सीएस अशोक कुमार दीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बैठकों की तारीखें	04.05.2019 and 05.05.2019, 27.06.2019, 07.08.2019, 23.09.2019, 05.10.2019, 17.11.2019, 09.01.2020, 19.01.2020, 12.03.2020 and 13.03.2020		02.04.2019, 03.05.2019, 04.07.2019, 11.09.2019, 07.11.2019, 22.12.2019, 08.01.2020(Adj.) 03.03.2020		03.05.2019, 27.07.2019, 29.08.2019, 04.11.2019, 02.03.2020		5.04.2019 and 06.04.2019 and 7.04.2019, 12.04.2019 and 13.04.2019 and 14.04.2019, 15.07.2019, 19.08.2019, 11.10.2019 and 12.10.2019 and 13.10.2019 18.10.2019 and 19.10.2019 and 20.10.2019, 17.01.2020, 19.02.2020		23.04.2019, 24.04.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 03.06.2019, 26.06.2019, 27.06.2019, 26.07.2019, 27.07.2019, 21.08.2019, 12.09.2019, 21.10.2019, 29.11.2019, 18.12.2019, 30.12.2019, 15.01.2020, 27.02.2020, 06.03.2020, 07.03.2020	

परिषद और स्थायी तथा गैर-अस्थायी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	परिषद / समिति	वित्त सेवाएं समिति		कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस समिति		पीडीसी		टीईएफसी		पीसीएससी	
	नाम	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	सीएस आशीष गर्ग	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-
2	सीएस नागेन्द्र राव डी.	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3
3	सीएस डॉ. अहलादा राव वुमनथला	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-
4	सीएस बी नरसिम्हन	2	2	-	-	-	-	4	2	5	3
5	सीएस चेतन बी पटेल	2	2	1	0	1	1	3	2	5	4
6	सीएस दीपक कुमार खेतान	2	1	-	-	-	-	4	2	5	5
7	सीएस देवेन्द्र वी देशपाण्डे	2	0	-	-	-	-	4	2	-	-
8	सीएस हितेन्द्र मेहता	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-
9	सीएस मनीश गुप्ता	-	-	1	1	3	2	1	1	5	5
10	सीएस एनपीएस चावला	1	0	1	1	1	0	3	2	-	-
11	सीएस प्रवीण सोनी	1	1	-	-	3	2	1	1	5	2
12	सीएस रजित पाण्डे	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
13	सीएस रामासुब्रमणियम सी	2	0	1	0	4	0	-	-	1	0
14	सीएस सिद्धार्थ मुरारका	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-
15	सीएस विनीत के चौधरी	-	-	-	-	3	0	1	1	5	5
16	श्री अनिल गुप्ता	2	0	-	-	4	0	-	-	-	-
17	श्री मनोज पांडे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	डॉ. मधु विज	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
20	श्री एस साताकृष्णन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री अनुराग अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सीएसअशोक कुमार दीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बैठकों की तारीखें		27.07.2019, 29.02.2020		03.03.2020		28.07.2019, 22.09.2019, 23.12.2019, 20.02.2020		28.07.2019, 21.10.2019, 08.01.2020, 26.02.2020		13.04.2019, 06.07.2019, 11.09.2019, 19.12.2019, 20.02.2020	

परिषद और स्थायी तथा गैर-अस्थायी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	परिषद / समिति	सूचना प्रौद्योगिकी समिति		पीयर समीक्षा बोर्ड		रोजगार समिति		पीएमक्यू कोर्स समिति		अनुशासन बोर्ड	
	नाम	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	सीएस आशीष गर्ग	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
2	सीएस नागेन्द्र राव डी.	-	-	-	-	1	0	4	4	-	-
3	सीएस डॉ. अहलादा राव वुमनथला	-	-	3	2	2	2	6	2	-	-
4	सीएस बी नरसिम्हन	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
5	सीएस चेतन बी पटेल	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-
6	सीएस दीपक कुमार खेतान	-	-	-	-	1	1	2	1	18	18
7	सीएस देवेन्द्र वी देशपाण्डे	4	4	-	-	1	0	6	2	-	-
8	सीएस हितेन्द्र मेहता	-	-	1	1	1	0	6	4	-	-
9	सीएस मनीश गुप्ता	-	-	-	-	-	-	2	2	18	15
10	सीएस एनपीएस चावला	4	1	-	-	-	-	4	3	-	-
11	सीएस प्रवीण सोनी	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-
12	सीएस रजित पाण्डे	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	सीएस रामासुब्रमणियम सी	-	-	1	1	2	0	4	1	-	-
14	सीएस सिद्धार्थ मुरारका	3	2	4	2	-	-	6	2	-	-
15	सीएस विनीत के चौधरी	-	-	4	3	1	0	-	-	-	-
16	श्री अनिल गुप्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	श्री मनोज पांडे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	डॉ. मधु विज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	श्री एस साताकृष्णन	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री अनुराग अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सीएस अशोक कुमार दीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17
बैठकों की तारीखें		28.07.2019, 11.09.2019, 05.01.2020, 19.02.2020		03.05.2019, 29.08.2019, 22.12.2019, 15.02.2020		22.09.2019, 29.02.2020		14.05.2019, 26.07.2019, 05.10.2019, 18.12.2019, 07.02.2020, 19.02.2020		03.04.2019, 26.04.2019, 17.05.2019, 22.06.2019, 12.08.2019, 29.08.2019, 29.08.2019 (Adj.), 30.08.2019,	

क्र. सं.	परिषद/समिति	सूचना प्रौद्योगिकी समिति		पीयर समीक्षा बोर्ड		रोजगार समिति		पीएमव्यू कोर्स समिति		अनुशासन बोर्ड	
	नाम	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
										12.09.2019, 09.10.2019, 23.10.2019, 04.11.2019, 09.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 19.12.2019, 06.01.2020, 17.01.2020, 02.03.2020	

परिषद और स्थायी तथा गैर-अस्थायी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	परिषद/समिति	सेक्रेट्रियल स्टैंडर्ड बोर्ड		संपादकीय सलाहकार बोर्ड		आईसीएसआई-सीसी जीआरटी प्रबंधन समिति		रेगुलेशन एवं चेप्टर गाइडलाइंस रिफॉर्म समिति		चुनाव सुधार समिति	
	नाम	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	सीएस आशीष गर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सीएस नागेन्द्र राव डी.	-	-	-	-	2	2	-	-	3	2
3	सीएस डॉ. अहलादा राव वुमनथला	-	-	-	-	1	1	5	1	3	2
4	सीएस बी नरसिम्हन	-	-	-	-	1	1	4	2	4	4
5	सीएस चेतन बी पटेल	-	-	1	1	2	2	4	3	1	1
6	सीएस दीपक कुमार खेतान	6	5	-	-	1	1	-	-	-	-
7	सीएस देवेन्द्र वी देशपाण्डे	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3
8	सीएस हितेन्द्र मेहता	-	-	1	1	-	-	5	2	-	-
9	सीएस मनीश गुप्ता	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1
10	सीएस एनपीएस चावला	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-
11	सीएस प्रवीण सोनी	6	3	-	-	2	2	5	3	-	-
12	सीएस रंजीत पाण्डे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	सीएस रामासुब्रमणियम सी	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-
14	सीएस सिद्धार्थ मुरारका	-	-	1	1	-	-	5	5	3	2
15	सीएस विनीत के चौधरी	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
16	श्री अनिल गुप्ता	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
17	श्री मनोज पांडे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	डॉ. मधु विज	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20	श्री एस सांताकृष्णन	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
21	श्री अनुराग अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सीएस अशोक कुमार दीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बैठकों की तारीखें	27.04.2019 and 28.04.2019, 20.07.2019, 31.08.2019, 14.12.2019 and 15.12.2019, 14.03.2020, 27.03.2020 and 28.03.2020 and 29.03.2020		27.07.2019, 20.02.2020		16.06.2019, 09.11.2019, 10.02.2020		01.06.2019, 28.06.2019, 27.07.2019, 10.09.2019, 19.02.2020		03.05.2019, 10.07.2019, 06.11.2019, 19.02.2020	

परिषद और स्थायी तथा गैर-अस्थायी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	परिषद/समिति	एक्सपर्ट एडवायजरी बोर्ड		गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड		ऑडिटिंग मानक बोर्ड		ब्रांड प्रमोशन समिति		अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति	
	नाम	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति	आयोजित बैठके	बैठक में उपस्थिति
1	सीएस आशीष गर्ग	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
2	सीएसनागेन्द्र राव डी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सीएस डॉ. अहलादा राव वुमनथला	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सीएस बी नरसिम्हन	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
5	सीएस चेतन बी पटेल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	सीएसदीपक कुमार खेतान	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
7	सीएसदेवेन्द्र वी देशपाण्डे	-	-	-	-	1	1	-	-	1	0
8	सीएस हितेन्द्र मेहता	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
9	सीएस मनीश गुप्ता	-	-	-	-	5	1	-	-	1	0
10	सीएस एनपीएस चावला	1	0	-	-	-	-	-	-	2	1
11	सीएस प्रवीण सोनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	सीएस रंजीत पाण्डे	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	सीएस रामासुब्रमणियम सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	सीएस सिद्धार्थ मुरारका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	सीएस विनीत के चौधरी	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-
16	श्री अनिल गुप्ता	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	श्री मनोज पांडे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	डॉ. मधु विज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	श्री एस सांताकृष्णन	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री अनुराग अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सीएस अशोक कुमार दीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बैठकों की तारीखें	27.02.2020,		21.06.2019, 16.12.2019, 11.03.2020 and 12.03.2020		20.04.2019 and 21.04.2019, 03.08.2019 and 04.08.2019, 21.09.2019 and 22.09.2019, 08.11.2019 and 09.11.2019, 14.12.2019, 07.03.2020 and 08.03.2020		03.05.2019, 10.09.2019		21.10.2019, 20.02.2020	

2019 में परीक्षा के नगरों की सूची

क्र.सं.	परीक्षा शहर	क्र.सं.	परीक्षा शहर	क्र.सं.	परीक्षा शहर
1	आगरा	48	हैदराबाद	95	पुणे जोन I
2	अहमदाबाद	49	इंदौर	96	पुणे जोन II
3	अहमदनगर	50	जबलपुर	97	पुणे जोन III
4	अजमेर	51	जयपुर	98	पुणे जोन IV
5	अकोला	52	इम्फाल	99	रेवाड़ी
6	अलीगढ़	53	जलगांव	100	रायपुर
7	अमृतसर	54	जम्मू	101	राजकोट
8	अलवर	55	जामनगर	102	रांची
9	अंबाला	56	जमशेदपुर	103	राउरकेला
10	अमरावती	57	झांसी	104	सागर
11	औरंगाबाद	58	झुन्झुनु	105	सेलम
12	बंगलौर	59	जोधपुर	106	सम्बलपुर
13	बरेली	60	कानपुर	107	सतारा
14	ब्यावर	61	कोल्हापुर	108	शिमला
15	बेलगाम	62	कोलकाता (उत्तर)	109	सीकर
16	भयंदर	63	कोलकाता (दक्षिण)	110	सिलिगुड़ी
17	भिलाई	64	कोटा	111	सोलापुर
18	भीलवाड़ा	65	कोट्टायम	112	सोनीपत
19	भोपाल	66	लखनऊ	113	श्रीनगर
20	भुवनेश्वर	67	लुधियाना	114	सूरत
21	बीकानेर	68	मुदरई	115	थाणे जोन I
22	बिलासपुर	69	मंगलौर	116	थाणे जोन II
23	गांधीधाम	70	मेरठ	117	थाणे जोन III
24	चंडीगढ़	71	मुरादाबाद	118	तिरुवनंतपुरम
25	चैन्नई	72	मुम्बई जोन I	119	त्रिसूर
26	चित्तौड़गढ़	73	मुम्बई जोन II	120	तिरुचिरापल्ली
27	कोयम्बटूर	74	मुम्बई जोन III	121	उदयपुर
28	देहरादून	75	मुम्बई जोन IV	122	उज्जैन
29	दिल्ली (पूर्व)	76	मुम्बई जोन V	123	वडोदरा
30	दिल्ली (उत्तर)	77	मुम्बई जोन VI	124	वाराणसी
31	दिल्ली (दक्षिण)	78	मुजफ्फरनगर	125	विजयवाड़ा
32	दिल्ली (पश्चिम)	79	मैसूर	126	विशाखापट्टनम
33	धनबाद	80	नागपुर	127	यमुनानगर
34	दुबई	81	नासिक	128	वापी
35	एरणाकुलम	82	नवी मुम्बई	129	पोर्ट ब्लेयर
36	फरीदाबाद	83	नोएडा	130	आसनसोल*
37	गांधीनगर	84	पालाकाड	131	दुर्गापुर*
38	गाजियाबाद	85	पटियाला	132	लातूर*
39	गोरखपुर	86	पाली	133	मथुरा*
40	गुटूर अमरावती	87	पणजी	134	नांदेड़*
41	गुडगांव	88	पानीपत	135	रोहतक*
42	गुवाहाटी	89	पटना	136	सुरेन्द्र नगर*
43	ग्वालियर	90	पिम्परी-चिंचवाड	137	तुमकूर*
44	हिसार	91	पुदुच्चेरी		
45	हुगली	92	जलंधर		
46	हावड़ा	93	कोझिकोड		
47	हुबली-धारवाड़	94	प्रायजराज		

*फाउंडेशन कार्यक्रम परीक्षा केवल

परिशिष्ट—'घ'

परीक्षा परिणामों के आंकड़े (जून 2019 का सत्र)

परीक्षा-स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या		
	नामांकित		नामांकित
फाउंडेशन प्रोग्राम	14034	13095	8450
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (O/S) *			
माड्यूल-I	21597	14947	1725
माड्यूल-II	21136	14931	2512
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (N/S) #			
माड्यूल-I	10599	8700	893
माड्यूल-II	4424	3478	299
प्रोफेशनल प्रोग्राम (O/S) @			
माड्यूल-I	13632	9671	2633
माड्यूल-II	11182	7632	2345
माड्यूल-III	12209	9137	3053
प्रोफेशनल प्रोग्राम (N/S) \$			
माड्यूल-I	757	629	175
माड्यूल-II	472	368	91
माड्यूल-III	501	425	119

* एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (O/S) के दोनों माड्यूलों में 11578 परीक्षार्थियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 9158 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा दोनों माड्यूलों के 391 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (N/S) के दोनों माड्यूलों में 3139 परीक्षार्थियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 2885 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा दोनों माड्यूलों के 157 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

@ प्रोफेशनल प्रोग्राम(O/S) के सभी माड्यूलों में 3391 परीक्षाओं का नामांकन हुआ, जिनमें से 2741 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा सभी माड्यूलों में 160 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

\$ प्रोफेशनल प्रोग्राम(N/S) के सभी माड्यूलों में 242 परीक्षाओं का नामांकन हुआ, जिनमें से 220 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा सभी माड्यूलों में 31 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

परीक्षा परिणामों के आंकड़े (दिसम्बर 2019 का सत्र)

परीक्षा-स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या		
	नामांकित	परीक्षा-स्तर	नामांकित
फाउंडेशन प्रोग्राम	12095	11255	7557
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (O/S) *			
माड्यूल-I	19175	12973	1762
माड्यूल-II	18740	12381	2053
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (N/S) #			
माड्यूल-I	17868	14779	1136
माड्यूल-II	9944	8093	968
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (O/S) @			
माड्यूल-I	13265	8698	2626
माड्यूल-II	11608	7675	1826
माड्यूल-III	11334	7737	2652
एकजीक्यूटिव प्रोग्राम (N/S) \$			
माड्यूल-I	2413	1966	789
माड्यूल-II	1851	1483	424
माड्यूल-III	2011	1712	532

- * एकजीव्युटिव प्रोग्राम (O/S) के दोनों माड्यूलों में 13246 परीक्षार्थियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 9761 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा दोनों माड्यूलों के 324 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।
- # एकजीव्युटिव प्रोग्राम (N/S) के दोनों माड्यूलों में 7007 परीक्षार्थियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 6396 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा दोनों माड्यूलों के 286 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।
- @ प्रोफेशनल प्रोग्राम(O/S) के सभी माड्यूलों में 3385 परीक्षाओं का नामांकन हुआ, जिनमें से 2544 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा सभी माड्यूलों में 64 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।
- * प्रोफेशनल प्रोग्राम(N/S) के सभी माड्यूलों में 1107 परीक्षाओं का नामांकन हुआ, जिनमें से 1044 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा सभी माड्यूलों में 198 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

बंसल सिन्हा एण्ड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 18/19, ओल्ड राजेन्द्र नगर,
 नई दिल्ली-110060
 दूरभाष नं. : 011-25853424, 25722270
 ईमेल : bsc@bansalsinha.com
 वेबसाइट : www.bansalsinha.com

पी.के. चोपड़ा एण्ड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एन-1001, बाम्बे लाइफ बिल्डिंग
 कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 (इंडिया)
 दूरभाष नं. : +91-11-40043977
 ईमेल : info@pkchopra.com
 वेबसाइट : www.pkchopra.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान("आईसीएसआई")की परिषद के सदस्यगणों के लिए

आईसीएस आई की समेकित वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("संस्थान") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है, जिसमें संस्थान के मुख्यालय, कॉर्पोरेट प्रशासन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र (सीसीजीआरटी) मुम्बई एवं सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई), हैदराबाद, चार क्षेत्रीय कार्यालयों के समेकित अंकेक्षित खाते शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को रु. 65.98 करोड़ की कुल संपत्ति, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रु. 24.42 करोड़ का कुल राजस्व और रु. 2.35 करोड़ का शुद्ध नकदी प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किये गये हैं और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्ट पर विधिवत विचारित और शामिल किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और खातों पर अन्य टिप्पणियों और हमारी रिपोर्ट के अन्य मामलों के पैराग्राफ में और मामलों पर अन्य टिप्पणी में वर्णित मामलों के साथ पठित, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980("अधिनियम") द्वारा आवश्यक तरीके से जरूरी जानकारी और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं :

- तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2020 की तारीख को संस्थान के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति);
- आय और व्यय खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान का अधिशेष(वित्तीय प्रदर्शन);
- नकद प्रवाह के ब्यौरे के मामले में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह।

राय के आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपना अंकेक्षण पूरा किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षक की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इकाई से स्वतंत्र हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने उन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण सीमाएं

• उपरोक्त के कारण अचल संपत्तियों, स्टॉक और नकद का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

• एफडीआर के लिए बैंकों से निवेश पर ब्याज प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, हालांकि, आंकड़ों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच की गई है, जिसमें निवेश मूल्य एवं उस पर दर ब्याज तथा परीक्षण जाँच और भौतिकता की अवधारणा के आधार पर ब्याज आय की गणना शामिल है।

• इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्राप्त करना। आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को दस्तावेजों की सीमित पहुंच और कोविड-19 के कारण विभागों की यात्रा के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका है।

उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद (NIRC) के मामले में, अंकेशक ने आवश्यक जानकारी प्राप्त की है और उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद परिसर में दिसंबर 2019 तक ऑडिट प्रक्रियाओं का कार्य किया है, हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण, ऑडिट टीम चौथी तिमाही के लिए आवश्यक ऑडिट करने के लिए उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद परिसर का दौरा नहीं कर सकी और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग के मानकों पर निर्धारित मानकों के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्राप्त किए, जिसमें शामिल है किन्तु सीमित नहीं :-

- मूल दस्तावेजों / फाइलों का निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षा और सत्यापन,
- पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों सहित नकदी / अचल संपत्तियों / स्टॉक का भौतिक सत्यापन,
- विभिन्न खर्चों के संबंध में विभिन्न दस्तावेजों की जांच,
- अचल सम्पत्ति रजिस्टर की जांच, भौतिक सत्यापन प्रक्रिया,
- कोई अन्य जो ऑडिट टीम की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

कार्यक्षेत्र की सीमा

परीक्षा अनुभाग के संबंध में सभी दस्तावेजों की समीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गयी है क्योंकि अपेक्षित रिकॉर्ड और जानकारी प्रबंधन से प्राप्त नहीं हुई, जो अत्यंत गोपनीय होने के कारण प्रबंधन से संबंधित है, इसका सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से किया गया है और इस संबंध में हमें पुष्टि प्रदान की गई है और हमने उस पर भरोसा किया है। (परीक्षा व्यय के लिए नोट संख्या 18 देखें)।

मामले की अवधारणा

i) नोट 21 (बी) का संदर्भ संख्या 6 देखें, जो अंतर इकाई शेष सहित विभिन्न दलों के साथ शेष के संतुलन, उनकी पुष्टि और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है।

ii) एनआईआरसी के मामले में, हम अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क. निर्माणाधीन भवन के खाते पर रु.28,44,250/- की एक राशि, जिसमें लखनऊ शाखा का कार्यालय पिछले सात वर्षों से चल रहा है, अभी भी प्रगति में पूंजीगत कार्य में पड़ा हुआ है, जबकि लागत को निश्चित परिसंपत्तियों पर डेबिट किया जाना चाहिए और उचित मूल्यव्यास इस इमारत के कच्चे की तारीख से लिया जाना चाहिए। आय और व्यय खाते में वर्ष के दौरान अधिशेष उस मूल्यव्यास की राशि से अधिक हो जाता है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लगाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वित्तीय विवरणों के टिप्पण-1 में मौजूद सामान्य विवरणों में शेष राशि में दिखाई देती है जो कई वर्षों से मूल्यव्यास की राशि से अधिक है।

ख. जीएसटी के आंकड़े समाधान के अधीन हैं।

iii) एसआईआरसी एवं वाईआईआरसी के मामले में, नोट 21(बी) का संदर्भ संख्या 18 देखें, हम रु. 22,73,999/- और रु. 4,54,573/- की राशि पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसे देनदार /अग्रिम के रूप में दिखाया गया है और वही राशि लंबे समय से वसूली के लिए लंबित है और इसे संदिग्ध माना गया। हालांकि, संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन को उम्मीद है कि राशि पार्टियों से वसूल ली जाएगी और वसूली के लिए कानूनी कार्यवाई शुरू की गई है या शुरू की जाएगी।

मैटर्स पैराग्राफ के अवधारण में बताए गए मामलों की भौतिकता को ध्यान में रखते हुए और अवधारण के मामलों के आकार और प्रकृति पर विचार करते हुए, यह समग्र रूप से इकाई के समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता है और तदनुसार हमारी राय इन मामलों के संबंध में संशोधित नहीं होती है।

अन्य मामले

हमने आईसीएसआई-मुख्यालय के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। हमने सीसीजीआरटी, मुम्बई एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), हैदराबाद के वित्तीय विवरणों, 4 क्षेत्रीय परिषदों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है क्योंकि इनके वित्तीय विवरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किये गये हैं। समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इनके द्वारा किये गये कार्य पर हमारे भरोसे और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासकों की जिम्मेदारी

संस्थान की परिषद (संस्थान का प्रबंधन) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 ('अधिनियम') के अनुसार मान्य लेखांकन मानकों के साथ भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकद प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करे। इस जिम्मेदारी में संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का

रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग, ऐसे निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें, जोकि ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से प्रासंगिक हैं जो एक सच्चे और निष्पक्ष विचार दें तथा धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त रहें।

समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने में, प्रबंधन संस्थान की सतत संस्थान के रूप में कार्य करने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा कि लागू हो, सतत संस्थान से संबंधित मामले तथ्यस सतत संस्थान आधारित लेखांकन लागू करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो संस्थान के परिचालनों को समाप्त या बंद करने का इरादा रखता है या कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं है। संस्थान की परिषद संस्थान की वित्तीय प्रदर्शन प्रक्रिया को देखने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण मुख्य गलतियों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने वाले मुख्य गलतियों का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि महत्वपूर्ण है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो वे इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा रखती हैं।

एसए (SAs) के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम करते हैं :

- समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को निर्धारित और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम का परिणाम त्रुटि से होने वाले परिणाम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ रखने के लिए प्रासंगिक नियंत्रण प्राप्त करना।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखा के साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो संस्थान की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है यह एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से संस्थान की सतत संस्थान स्थिति प्रभावित हो सकती है।
- प्रदर्शन सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकती हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, में मात्रात्मक महत्वपूर्णता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों सहित, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध संभावना और समय एवं महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम अपने लेखा-परीक्षा के दौरान पहचानते हैं, प्रशासन के लिए जिम्मेदारों को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को एक बयान प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि: —

उपरोक्त स्कोप सीमा के पैरा के तहत मामले के विषय के अतिरिक्त हम अपनी रिपोर्ट देते हैं कि :

- क. हमने वे सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- ख. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकद प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों से मेल खाते हैं;
- ग. हमारी राय में, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की आवश्यकताओं के अनुरूप खातों की उचित पुस्तकों को बनाए रखा जाता है, अब तक यह पुस्तकों और अभिलेखों की परीक्षण से प्रकट होता है।

- घ. हमने कॉर्पोरेट प्रशासन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र (सीसीजीआरटी) मुम्बई एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), हैदराबाद के अंकेक्षित खाते और चार क्षेत्रीय कार्यालयों समेकित अंकेक्षित खाते प्राप्त किए हैं और अपनी रिपोर्ट में हमने उन्हीं को शामिल किया है।
- ङ. वित्तीय विवरण संस्थान की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के वित्तीय प्रभाव का प्रकटन करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 21(ख) का प्वाइंट नं. 1 कासंदर्भ ले।
- च. संस्थान के पास डेरिवेटिव अनुबंध सहित किसी लम्बी अवधि के अनुबंध नहीं है जिन पर किसी महत्वपूर्ण पूर्वाभाषी हानि हो।
- छ. हमारी राय में, तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकद प्रवाह का विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक के अनुपालन में है;

कृते बंसल सिन्हा एवं कंपनीकृते पी.के. चोपड़ा एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीआई के साथ एफआरएन 006184एनआईसीआई के साथ एफआरएन 006747एन

(हरी ऊबरियानी)(राहुल जिंदल)

सदस्य

सदस्यता सं.: 084437

यूडीआईएन : 20084437AAAAA9401

सदस्य

सदस्यता सं.: 537709

यूडीआईएन : 20537709AAAACJ1135

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2020

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
I. स्रोत और देयताएं			
(1) संचय एवं अधिशेष			
(क) संचय एवं अधिशेष	1	7,045,790,151	6,724,119,578
(ख) निर्धारित निधि	2	1,474,683,282	1,463,474,871
उप-जोड (1)		8,520,473,433	8,18,75,94,449
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घ अवधि उधार		-	-
(ख) दीर्घ अवधि देयताएं		74,580	2,112,080
(ग) दीर्घ अवधि प्रावधान		10,500	10,500
उप-जोड(2)		85,080	2,122,580
(3) चालू देयताएं			
(क) लघु अवधि उधार		-	32,948
(ख) विविध लेनदार	3	118,158,841	121,593,600
(ग) अन्य चालू देयताएं	4	193,777,215	207,095,918
(घ) लघु अवधि प्रावधान	5	32,108,438	75,469,119
उप-जोड (3)		344,044,494	404,191,585
कुल (1+2+3)		8,864,603,007	8,593,908,614
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) अचल परिसम्पत्तियां	6		
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां		1,389,098,860	1,428,928,795
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां		2,799,337	2,828,215
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति में		74,540,593	55,817,473
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		33,040	33,040
उप-जोड(क)		1,466,471,830	1,487,607,523
(ख) गैर चालू निवेश	7	4,909,322,228	4,711,166,956
(ग) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	8	45,156,297	65,121,797
(घ) दीर्घ अवधि के ऋण और पेशगियां		1,096,169	1,381,178
उप-जोड (1)		6,422,046,524	6,265,277,454
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) चालू निवेश	9	608,845,236	688,961,708
(ख) इवेंट्रीज (स्टॉक)	10	6,013,714	6,358,734

(ग) विविध देनदार	11	43,520,544	2,578,789
(घ) नकद और नकद समकक्ष	12	291,010,497	310,927,286
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	13	1,493,166,492	1,319,804,644
उप-जोड़ (2)		2,442,556,483	2,328,631,161
कुल(1 + 2)		8,864,603,007	8,593,908,614
लेखांकन नीतियाँ और खातों के लिए अन्य टिप्पणियाँ	21	7,045,790,151	6,724,119,578

उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान परिषद की ओर से और उनके लिए

सीए समीर गुप्ता सीएस आशीष मोहन सीएस नागेन्द्र डी. रावसीएस आशीष गर्ग
संयुक्त सचिव सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष
(वित्त एवं लेखा)

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बंसल सिन्हा एवं कंपनीकृते पी.के. चोपड़ा एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्सचार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीआई के साथ एफआरएन 006184एनआईसीआई के साथ एफआरएन 006747एन

(हरी ऊबरियानी)(राहुल जिंदल)

सदस्य

सदस्यता सं.: 084437

यूडीआईएन : 20084437AAAAA9401

सदस्य

सदस्यता सं.: 537709

यूडीआईएन : 20537709AAAACJ1135

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2020

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाता

(राशि रु. में)

विवरण	नोट सं.	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
आय			
गतिविधियों से ब्याज	14	1,117,526,873	1,146,840,553
निवेश से आय	15	533,342,644	515,579,762
अन्य आय	16	180,732,848	83,855,215
कुल आय		1,831,602,365	1,746,275,530
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	17	47,65,42,553	439,322,024
अध्ययन सामग्री और अन्य/मौखिक शिक्षा व्यय		67,876,395	70,601,363
प्रकाशन और ब्रांडिंग सामग्री		15,187,064	20,615,599
परीक्षा व्यय	18	143,167,781	134,059,459
यात्रा और परिवहन व्यय		24,109,494	28,083,403
कार्यक्रम/सेमिनार व्यय		176,262,188	112,081,381
कैरियर जागरुकता और संवर्धन व्यय		31,950,120	27,735,079
अवमूल्यन और परिशोधन		73,128,946	65,135,499
जर्नल एंड बुलेटिन	19A	43,599,916	51,269,268
लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेस	19B	13,651,179	15,572,352
बिजली और पानी	19C	19,944,267	17,447,249
संचार व्यय	19D	49,559,315	58,876,455
अन्य व्यय	19E	145,971,226	101,718,784
सीसीजीआरटी गतिविधियाँ	20	13,100,900	9,579,349
कुल व्यय		1,294,051,344	1,152,097,265
अतिविशेष और असाधारण मदों के पहले अधिशेष		537,551,021	594,178,265
जोड़े/घटाये असाधारण मद		(87,113)	252,048

जोड़े/घटायें अनौपचारिक मद		(13,911,394)	-
संपत्तियों के निपटान पर अधिशेष		77,833	35,185
परिसंपत्तियों को बिक्री/निपटान/बटटे खाते में डालने पर हानि		(1,060,599)	(252,464)
पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध)		(22,184,080)	(12,285,228)
अतिविशेष और असाधारण मदों के बाद अधिशेष		500,385,668	581,927,806
कोष/आरक्षित निधि कायोगदान और विनियोग:			
— प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन राशि		2,500,000	7,590,000
— एमार्कड फंड को ब्याज		114,534,650	123,235,234
— आईसीएसआई पेंशन फंड ट्रस्ट		68,545,474	-
— आईसीएसआई स्टूडेंट एजुकेशन फंड ट्रस्ट		10,000,000	10,000,000
— सीएस हितग्राही निधि ट्रस्ट		20,000,000	5,000,000
— आईसीएसआई कर्मचारी बनेवोल्ट फंड ट्रस्ट		500,000	500,000
— आईसीएसआई कर्मचारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती ट्रस्ट		7,500,000	7,500,000
— बिलडिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिजर्व		2,000,000	1,000,000
कुल विनियोजन		225,580,124	154,825,234
सामान्य संचय को अंतरित शेषअधिशेष		274,805,544	427,102,572
कुल		500,385,668	581,927,806
लेखांकन नीतियां और खातों के लिए अन्य टिप्पणियां	21		

उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान परिषद की ओर से और उनके लिए

सीए समीर गुप्ता सीएस आशीष मोहन सीएस नागेन्द्र डी. रावसीएस आशीष गर्ग
संयुक्त सचिव सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष
(वित्त एवं लेखा)

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बंसल सिन्हा एवं कंपनीकृते पी.के. चोपड़ा एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्सचार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीआई के साथ एफआरएन 006184एनआईसीआई के साथ एफआरएन 006747एन

(हरी ऊबरियानी)(राहुल जिंदल)

सदस्य

सदस्यता सं.: 084437

यूडीआईएन : 20084437AAAAA9401

सदस्य

सदस्यता सं.: 537709

यूडीआईएन : 20537709AAAACJ1135

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2020

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
31 मार्च 20120 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(राशि रु.में)

विवरण	2019-20		2018-19	
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		500,385,668		581,927,806
पूर्व अवधि के बाद शुद्ध अधिशेष, आई और ई खाते के अनुसार अतिरिक्त सामान्य और असाधारण आइटम आय		16,298,172		11,940,950
जोड़े: कैपिटल रिजर्व में सीधे जमा किए गए सदस्यों के प्रवेश शुल्क				
समायोजन :		73,128,946		65,135,498
जोड़े: अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास		4,922,562		-
पूर्व अवधि के खर्चों सहित लीज होल्ड भूमि का परिशोधन		-		20,282
स्टॉक बट्टे खाते में डाला गया		131,304		393,876
बुरा ऋण और डूबंत ऋण के लिए प्रावधान		1,060,599		252,464
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		595,927,251		659,670,876
गैर-नकद खर्चों के समायोजन के पश्चात् परिचालन से नकद प्रवाह	533,342,644		515,579,762	
घटाएँ: निवेश पर ब्याज	60,355,438		48,568,111	
: प्रावधान नो लॉन्गर वापसी की आवश्यकता नहीं और राशि समाप्त प्राय	-		252,048	
एसआईपी शुल्क की जब्ती	77,833	593,775,915	35,185	564,435,106
परिसंपत्तियों के निपटान पर अधिशेष		2,151,336		95,235,770
कार्यशील पूंजी और निधियों में परिवर्तन से पहले परिचालन अधिशेष				
चालू परिसंपत्तियां और चालू देयताओं और निर्धारित कोष के शेष में वृद्धि/(कमी)				
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	345,020		(1,853,514)	
बुरे ऋणों के शुद्ध देनदार में (वृद्धि)/कमी	(41,073,059)		2,642,484	
लघु अवधि ऋण और पेशगियों में (वृद्धि)/कमी	-		(5,544,139)	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(173,361,848)		(302,781,304)	
दीर्घ अवधि ऋण और पेशगियों में (वृद्धि)/कमी	285,009		(551,172)	
अन्य गैर परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	19,965,500		5,544,139	
आरसी/चेप्टरस को योगदान/उपयोग में (वृद्धि)/कमी	14,914,275		160,085,629	
विविध लेनदार में वृद्धि/(कमी)	(34,34,759)		(19,304,538)	
अन्य वर्तमान देनदारियों और अल्पकालिक उधारों (आई और ई से निधियों में योगदान एवं विनियोग को छोड़कर) में वृद्धि (कमी)	(119,897,125)		(141,554,796)	
वापस लिखे गए प्रावधानों को छोड़कर लघु अवधि के प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	16,994,757		(21,390,979)	
दीर्घ अवधि के दायित्व एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(2,037,500)		2,501	
कार्पोरेट गर्वनेंस अवार्ड कोष (शुद्ध) में प्राप्ति/(उपयोग)	(3,865,748)		(3,551,623)	
स्टॉफ प्रशिक्षण कोष प्राप्ति/(उपयोग)	(911,415)		(954,533)	
अवकाश नकदीकरण कोष प्राप्ति/(उपयोग)	(48,080,425)		(13,059,943)	
पुरस्कार सम्मान कोष अक्षय निधि में प्राप्ति/(उपयोग)	(205,820)		(204,172)	
व्यवसायिक विकास कोष प्राप्ति/(उपयोग)	(8,940,478)		(11,639,328)	
निपादन संबंधित प्रोत्साहन कोष प्राप्ति/(उपयोग)	(9,572,519)		(10,086,799)	
अवसंरचना कोष प्राप्ति/(उपयोग)	(8,957,103)	(367,833,238)	-	(364,202,087)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद		(365,681,902)		(268,966,317)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह	533,342,644		515,579,762	
निवेश से आय	914,050,476		1,195,175,333	
निवेश/म्यूचुअल फंड्स के शोधन की बिक्री से प्राप्त आय	(1,032,089,276)		(1,116,612,665)	
निवेश/म्यूचुअल फंड यूनिटों का अधिग्रहण	1,731,227		-	
सावधि परिसंपत्तियों की बिक्री प्रक्रियों और सावधि परिसंपत्तियों के लिए अन्य समायोजन	(59,629,808)		(337,347,142)	
अचल परिसंपत्तियों डब्ल्यूआईपी सहित का अधिग्रहण		357,405,263		256,795,288
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी				

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कॉर्पस दान में वृद्धि		-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद		-	-
अवसंरचना कोष (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	29,970	(50,470)	
सामान्य संचय एवं कॉर्पस दान में वृद्धि	(15,112,806)	329,024	
पुस्तकालय संचय (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	74,833	161,451	
आई और ई से विनियोग को छोड़कर भवन संचय (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	(1,432,862)	1,000,000	
अन्य संचय एवं कोष (शुद्ध) में वृद्धि/(कमी)	4,800,715	682,541	
प्रवेश शुल्क के अलावा पूंजी संचय में वृद्धि/कमी	-	(153,692)	
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद		(11,640,150)	1,968,854
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में शुद्ध नकद प्रवाह (क)		(19,916,789)	(10,202,175)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (ख)		310,927,286	321,129,461
वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समकक्ष (क+ख)		291,010,497	310,927,286

नोट :

- उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण एएस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके बनाया गया है।
- संलग्न नोट्स 1 से 20 प्रारूप, नकद प्रवाह विवरण के अभिन्न हिस्से हैं।
- नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं :

(क) नकदी, बैंक/ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डरस और पोस्टेज स्टैम्प/फ्रेकिंग यूनिट	10,06,682	29,17,149
(ख) अनुसूचित बैंकों में शेष- बचत खातों में (सावधि जमा सहित)	29,00,03,815	30,80,10,137
	-----	-----
कुल	21,10,10,497	31,09,27,286
	=====	=====

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान परिषद की ओर से और उनके लिए

सीए समीर गुप्ता सीएस आशीष मोहन सीएस नागेन्द्र डी. रावसीएस आशीष गर्ग
संयुक्त सचिव सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष
(वित्त एवं लेखा)

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बंसल सिन्हा एवं कंपनीकृते पी.के. चोपड़ा एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्सचार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आईसीआईआई के साथ एफआरएन 006184एनआईसीआईआई के साथ एफआरएन 006747एन

(हरी ऊबरियानी)(राहुल जिंदल)

सदस्य

सदस्यता सं.: 084437

यूडीआईएन : 20084437AAAAA9401

सदस्य

सदस्यता सं.: 537709

यूडीआईएन : 20537709AAAACJ1135

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2020

संचय और अधिशेष

नोट-1

(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
(1) आरक्षित पूंजी		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	86,712,289	74,771,339
जोड़े : सदस्यों से प्रवेश शुल्क		
- एसोसिएट्स सदस्य	13,997,002	10,404,521
- फेलो सदस्य	2,301,170	11,940,950
उप-जोड़ (1)	103,010,461	86,712,289
(2) सामान्य संचय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6,564,593,905	5,935,865,250
जोड़े : वर्ष के दौरान जोड़	-	-

जोड़े : कोष दान		212,101		106,908
जोड़े : अवसंरचना कोष से स्थानांतरण		25,792,730		210,264,879
जोड़े : संचय/योगदान से स्थानांतरण		17,174		-
जोड़े/(घटाएँ) : अन्य संचय को स्थानांतरण/समायोजित		(15,308,837)		(6,215,388)
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग		(33,244)		(2,530,317)
		6,575,273,829		6,137,491,332
आय और व्यय खाता से अधिशेष (आय की व्यय से अधिकता)		274,805,544		427,102,573
उप-जोड़ (2)		6,850,079,373		6,564,593,905
(3) लाइब्रेरी संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		2,800,542		2,639,091
जोड़े : दान		41,663		216,116
जोड़े : ब्याज		33,170		(73,627)
जोड़े : आरक्षित / परिवर्धन से अंतरण		-		-
घटाएँ : उपयोग		-		18,962
उप-जोड़ (3)		2,875,375		2,800,542
(4) भवन संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		152,936,092		151,936,092
जोड़े : दान		-		-
जोड़े : संचय से अंतरण		3,637,041		-
जोड़े : योगदान से स्थानांतरण		-		-
जोड़े : आय और व्यय खाता से स्थानांतरण		1,500,000		1,000,000
घटाएँ : समायोजन / उपयोग		(5,069,903)		-
उप-जोड़ (4)		153,003,230		152,936,092
(5) अवसंरचना संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		34,261,131		34,311,601
जोड़े : आरक्षित से अंतरण		79,970		23,500
जोड़े : दान		-		6,000
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग		(50,000)		(79,970)
उप-जोड़ (5)		34,291,101		34,261,131
(6) अन्य संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		49,535,900		48,773,389
जोड़े : वर्ष के दौरान जोड़		4,797,107		672,340
जोड़े : संचय से / (को) स्थानांतरण		-		79,970
जोड़े : ब्याज		99,340		48,662
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग		(95,732)		(38,461)
उप-जोड़ (6)		54,336,615		49,535,900
(7) भूमि / भवन/अन्य परिसंपत्तियों के लिए/से योगदान				
जोड़े : आरसी/वैक्टरस से परिसंपत्तियों के लिए योगदान		117,540,829		110,372,852
घटाएँ : आरसी/वैक्टरस को परिसंपत्तियों के लिए योगदान		(269,346,833)		(277,093,131)
उप-जोड़ (7)		(151,806,004)		(166,720,279)
कुल (1 से 7)		7,045,790,151		6,724,119,578

निर्धारित कोष

नोट-2
(राशि रु. में)

विवरण	कारपोरेट गवर्नंस में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार कोष		स्टाफ प्रशिक्षण कोष		अवकाश नकदीकरण कोष		पुरस्कार कोष के लिए अक्षय निधि	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	156,765,700	148,573,507	9,947,596	10,129,917	160,024,310	141,082,387	8,423,902	8,094,475
जोड़े : वर्ष के दौरान योगदान	-	-	-	-	5,000,000	20,716,075	287,777	-
जोड़े : सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	-	-	-	22,869,084	-	-	-
जोड़े : ब्याज आबंटन	12,386,626	11,743,816	759,351	772,212	12,801,945	11,285,791	547,791	533,599
उप-जोड़	169,152,326	160,317,323	10,706,947	10,902,129	200,695,339	173,084,253	9,259,470	8,628,074
घटाएँ : उपयोग के लिए सामान्य संचय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग	3,865,748	3,551,623	911,415	954,533	75,949,512	13,059,943	493,597	204,172
वर्ष समाप्ति पर शेष	165,286,578	156,765,700	9,795,532	9,947,596	124,745,827	160,024,310	8,765,873	8,423,902

विवरण	प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन कोष		इंफ्रास्ट्रक्चर कोष (प्रौद्योगिकी विकास कोष सहित)		व्यवसायिक विकास कोष		कुल राशि	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9,657,527	8,062,776	1,067,118,503	1,183,024,504	51,537,338	58,797,918	1,463,474,871	1,557,765,484
जोड़े : वर्ष के दौरान योगदान	2,500,000	11,000,000	500,000	359,776	-	-	8,287,777	32,075,851
जोड़े : सामान्य सचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-	-	48,000	248,200	135,084	23,117,284	183,084
जोड़े : ब्याज आबंटन	489,701	681,550	83,783,868	93,974,602	3,765,368	4,243,664	114,534,650	123,235,234
उप-जोड़	12,647,228	19,744,326	1,151,402,371	1,277,406,882	55,550,906	63,176,666	1,609,414,582	1,713,259,653
घटाए : उपयोग के लिए सामान्य सचय में स्थानांतरण	-	-	-	23,500	-	-	-	23,500
घटाए : वर्ष के दौरान उपयोग	9,572,519	10,086,799	8,957,103	-	9,188,678	11,639,328	108,938,572	39,496,398
घटाए : भूमि/भवन अधिग्रहण पर	-	-	25,792,730	210,264,879	-	-	25,792,730	210,264,879
वर्ष समाप्ति पर शेष	3,074,709	9,657,527	1,116,652,538	1,067,118,503	46,362,228	51,537,338	1,474,683,282	1,463,474,871

विविध लेनदार

नोट-3
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
विविध लेनदार		
माल और सेवाओं के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बकाया राशि	-	-
माल और सेवाओं के लिए अन्य लेनदारों के बकाया राशि	111,277,306	119,028,927
आर डी (ई/डब्ल्यू/एस/एन) - निवेशक शिक्षा सुरक्षा कोष	252,762	274,597
अन्य देनदारियां	6,628,773	2,290,076
कुल	118,158,841	121,593,600

अन्य चालू देयताएं

नोट-4
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
अन्य चालू देयताएं		
सदस्यों/छात्रों से अग्रिम में प्राप्त शुल्क	89,089,162	131,606,916
ट्रस्ट/फंड को देय	63,262,210	36,889,605
सुरक्षा जमा	2,494,812	2,803,234
संपत्ति कर देय	1,370,000	1,200,000
टीडीएस देय	20,385,162	16,185,451
जीएसटी देय	613,531	248,306
इंटर यूनिट बैलेंस	-	15,669,371
अन्य देय	16,562,338	2,493,035
कुल	193,777,215	207,095,918

लघु अवधि के प्रावधान

नोट-5
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
खर्चों के लिए प्रावधान	32,108,438	75,469,119
कुल	32,108,438	75,469,119

**स्थायी
परिसम्पत्तियां**

नोट - 6

(राशि रु. में)

मद		सकल ब्लॉक	जोड़ें	समायोजन/ स्थानांतरण/ बिक्री	31.3.2020 कुल लागत	मूल्यवृद्धि/ हानि				निवल ब्लॉक	31.3.2019 की स्थिति
		1.4.2019 की लागत				31.3.2019 को कुल राशि	वर्ष के दौरान	समायोजन/ स्थानांतरण/ बिक्री	31.3.2020 को कुल राशि	31.3.2020 की स्थिति	
(i)	मूल परिसंपत्तिया										
	भूमि										
	—फ्रीहोल्ड	209,889,542	-	3,294,922	213,184,464	-	-	-	-	213,184,464	209,889,542
	— पट्टे पर	305,745,724	-	-3,294,922	302,450,802	8,778,445	3,251,451	4,922,562	16,952,458	285,498,344	296,967,279
	भवन	980,196,511	400,334	-	980,596,845	206,766,011	38,686,946	-	245,452,957	735,143,888	773,430,500
	फर्नीचर और फिक्सचर्स	127,249,557	3,985,318	-515,034	130,719,841	64,702,908	6,484,604	104,191	71,291,703	59,428,138	62,546,649
	कंप्यूटर सहायक उपकरण	100,420,291	12,961,374	-7,101,615	106,280,050	85,153,247	8,986,722	-	87,585,003	18,695,047	15,267,044
	मोबाइल फोन	18,790	-	-	18,790	12,211	2,632	-	14,843	3,947	6,579
	कृत्रिम उपकरण	48,271,483	13,572,425	-2,024,549	59,819,359	21,709,917	5,257,384	-	25,868,023	33,951,336	26,561,566
	इलेक्ट्रिकल उपकरण	39,678,138	1,393,279	299,948	41,371,365	28,082,465	2,037,528	-60,110	30,059,883	11,311,482	11,595,673
	कार्यालयीनशीनऔरसंचारउपकरण	54,175,249	2,085,890	-2,575,883	53,685,256	26,425,004	4,153,936	-	29,374,936	24,310,320	27,750,245
	अन्य उपकरण	10,853,916	2,621,066	258,213	13,733,195	6,551,518	1,035,636	-	7,334,715	6,398,480	4,302,398
	पुस्तकालय की पुस्तकें	6,196,976	185,282	-	6,382,258	6,189,425	161,983	21,096	6,372,504	9,754	7,551
	वाहन	1,616,942	856,682	-734,999	1,738,625	1,013,176	219,524	-657,737	574,963	1,163,662	603,766
	चालू वर्ष का योग (i)	1,884,313,119	38,061,650	-	1,909,980,850	455,384,327	70,278,346	-	520,881,988	1,389,098,860	1,428,928,795
	विगत वर्ष का योग (i)	1,552,444,489	337,276,540	5,407,910	1,884,313,119	396,853,638	62,354,423	3,823,735	455,384,326	1,428,928,793	1,155,590,851
	(ii)	अमूर्त परिसंपत्तिया									
सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन		28,288,048	2,845,038	-22,667	31,110,419	25,459,833	2,850,600	649	28,311,082	2,799,337	2,828,215
चालू वर्ष का योग (ii)		28,288,048	2,845,038	-22,667	31,110,419	25,459,833	2,850,600	649	28,311,082	2,799,337	2,828,215
विगत वर्ष का योग		28,270,896	70,602	-53,450	28,288,048	22,732,208	2,781,075	-53,450	25,459,833	2,828,215	5,538,688

स्थायी परिसम्पत्तियां (पूँजीगत कार्य प्रगति)

नोट - 6(जारी)

(राशि रु. में)

मद	सकल ब्लॉक			
	1.4.2019 को लागत	जोड़ें	समायोजन/ स्थानांतरण / बिक्री	31.3.2020 को कुल राशि
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर				
अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि	62,28,677	-	-	62,28,677
भवन / नवीनीकरण / सुधार	4,95,88,796	3,01,74,853	1,14,51,733	6,83,11,916
चालू वर्ष का योग (iii)	5,58,17,473	3,01,74,853	1,14,51,733	7,45,40,593
पिछले वर्ष का योग (iii)	18,73,29,644	20,96,84,247	34,11,96,418	5,58,17,473
(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	33,040	-	-	33,040
चालू वर्ष का योग (iv)	33,040	-	-	33,040
पिछले वर्ष का योग (iv)	33,040	-	-	33,040

गैर-चालू निवेश

नोट-7

(राशि रु. में)

विवरण	01.04.2019 की स्थिति	जोड़े	घटाए	चालू निवेश को/से हस्तांतरित	31.03.2020 की स्थिति
I. सरकारी प्रतिभूति में निवेश					
जीओआई बांड (सीयूएम-एचवाई)	2,455,000,000	-	-	-	2,455,000,000
जीओआई सेविंग बांड	30,090,000	-	-	-	30,090,000
उप-जोड़ (I)	2,485,090,000	-	-	-	2,485,090,000
II. डिबेंचर/बांड में निवेश					
पीएनबी-एचएफएल	48,114,680	-	86,542	-	48,028,138
आईडीएफसी लिमिटेड	50,230,529	-	37,071	-	50,193,458
उप-जोड़ (II)	98,345,209	-	123,613	-	98,221,596
III. अन्य गैर-चालू निवेश					
(क) बैंकों में सावधि जमा					
आंध्रा बैंक	3,974,779	316,909	-	-	4,291,688
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,735,861	42,103	563,033	-	1,214,931
बैंक ऑफ बड़ौदा	135,227,266	-	20,227,266	-	115,000,000
केनरा बैंक	95,890,992	13,735,123	42,952,408	(28,395,447)	38,278,260
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	230,200	14,776	-	-	244,976
कारपोरेशन बैंक	70,201,549	18,980,137	3,045,207	-	86,136,479
देना बैंक	3,577,418	-	-	-	3,577,418
फेडरल बैंक	326,473	20,234	-	-	346,707
एचडीएफसी बैंक	92,523,868	55,789	251,035	-	92,328,622
आईसीआईसीआई बैंक	26,760	1,843	-	-	28,603
इंडियन ऑवरसिज बैंक	29,208,617	25,285,431	21,419,217	-	33,074,831
कनाटका बैंक	1,287,586	72,125	-	-	1,359,711
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	100,000,000	-	-	100,000,000
अन्य बैंक	708,237	2,165,607	1,100,470	-	1,773,374
पीएनबी	1,281,000	30,623,803	15,000,000	(15,000,000)	1,904,803
रेपको बैंक	1,527,468	-	27,468	-	1,500,000
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	78,410,825	6,559,618	1,005,842	(60,000,000)	23,964,601
सिंडिकेट बैंक	100,000	4,152,836	-	-	4,252,836
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई)	55,000,000	25,000,000	40,000,000	-	40,000,000
उप-जोड़ (III- क)	571,238,899	227,026,334	145,591,946	(103,395,447)	549,277,840
(ख) बैंकों के अलावा अन्य संस्थानों के साथ सावधि जमा					
बैंक ऑफ बड़ौदा	2,850,000	900,000	-	-	3,750,000
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस	1,008,419	-	1,008,419	-	-
टी टी डी एफ सी लिमि	34,568	22,307	-	-	56,875
एलआईसी के पास जमा (अवकाश नकदीकरण)	133,082,278	-	7,273,944	-	125,808,334
हुडको	97,400,000	-	-	(97,400,000)	-
केटीडी एफ सी	82,110,292	-	-	-	82,110,292
एलआईसी-एचएफएल	850,000,000	500,000,000	-	(150,000,000)	1,200,000,000
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	50,000,000	-	-	-	50,000,000
पीएनबी-एचएफएल	180,000,000	95,000,000	-	(120,000,000)	155,000,000
उप-जोड़ (III-ख)	1,396,485,557	595,922,307	8,282,363	(367,400,000)	1,616,725,501
(ग) अन्य (विशेष प्रकृति)					
बैंकबे एक्स प्री सोस लि०	1,000	-	-	-	1,000
बैंकबाय एक्स प्रेम सोसायटी लिमिटेड	5,781	-	-	-	5,781
सच्चिदानंद सीएचएस लिमिटेड के साथ शेयर	510	-	-	-	510
आईसीएसआई-आईपीए के साथ निवेश	140,000,000	-	-	-	140,000,000
आईसीएसआई-आरवीओ के साथ निवेश	20,000,000	-	-	-	20,000,000
उप-जोड़ (III-ग)	160,007,291	-	-	-	160,007,291
उप-जोड़ (III:क+ख+ग)	2,127,731,747	822,948,641	153,874,309	(470,795,447)	2,326,010,632
कुल(I+II+III)	4,711,166,956	822,948,641	153,997,922	(470,795,447)	4,909,322,228

(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम (श्रेणी/प्रकृति उल्लिखित करें)		
प्रतिभूत, अच्छे समझे गये	-	-
आईसीएसआई ट्रस्ट/फंड	8,413,702	9,801,507
कर्मचारी अग्रिम	2,372,978	5,040,429
अन्य	191,649	9,740,050
अप्रतिभूत, अच्छे समझे गये		
एमसीए से आईएपी के लिए प्राप्त राशि	148,716	219,473
अन्य	34,223,400	40,320,338
संदिग्ध	105,852	43,680
	45,456,297	65,165,477
घटाएं: खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	300,000	43,680
कुल	45,156,297	65,121,797

चालू निवेश

नोट-9

(राशि रु. में)

विवरण	01.04.2019 की स्थिति	जोड़े	घटाएं	गैर चालू निवेश से हस्तांतरित	31.03.2020 की स्थिति
I. सरकारी प्रतिभूति में निवेश					
जीओआई बांड्स(सीयूएम एचवाई)	-	-	-	-	-
जीओआई बांड्स (एनसी-एचवाई)	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (I)	-	-	-	-	-
II. डिबेंचर/बांड में निवेश					
हुडको	-	-	-	-	-
आरईसी	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (II)	-	-	-	-	-
III. अन्य चालू निवेश					
(क) बैंकों में सावधि जमा					
इलाहाबाद बैंक	648,537	-	49,044	-	599,493
आंध्रा बैंक	5,538,687	-	203,168	-	5,335,519
एक्सिस बैंक	88,291	6,624	-	-	94,915
बैंक ऑफ बड़ौदा	13,635,221	2,041,941	512,000	-	15,165,162
बैंक ऑफ इंडिया	3,577,842	4,614,096	3,638,429	-	4,553,509
केनरा बैंक	233,556,066	121,241,856	289,685,188	28,395,447	93,508,181
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,069,905	2,401,822	2,473,995	-	1,997,732
कारपोरेशन बैंक	76,083,974	1,783,453	77,043,359	-	824,068
देना बैंक	1,360,634	451,413	-	-	1,812,047
एचडीएफसी बैंक	1,674,742	601,035	-	-	2,275,777
आईसीआईसीआई बैंक	5,061,987	1,631,837	1,306,979	-	5,386,845
आईडीबीआई बैंक	2,376,583	1,635,465	2,376,583	-	1,635,465
इंडियन बैंक	5,319,455	2,602,884	-	-	7,922,339
करूर वैश्य बैंक	417,243	36,438	-	-	453,681
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	790,791	51,245	-	-	842,036
अन्य बैंक	8,419,600	2,066,223	70,000	-	10,415,823
पीएनबी	1,995,080	20,400,000	35,469,123	15,000,000	1,925,957
पी एण्ड एस बैंक	283,168	-	-	-	283,168
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	22,934,206	16,364,715	76,016,798	60,000,000	23,282,123
सिंडीकेट बैंक	1,364,146	2,035,485	-	-	3,399,631
यूको बैंक	1,364,939	147,359	-	-	1,512,298

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	13,287,203	5,965,074	1,796,269	-	17,456,008
	विजया बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा)	37,113,408	23,061,670	19,411,619	-	40,763,459
	उप-जोड़ (III-क)	438,961,708	209,140,635	510,052,554	103,395,447	241,445,236
(ख)	बैंकों के अलावा अन्य संस्थानों के साथ सावधिक जमा					
	एलआईसी एचएफएल	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000
	पीएनबी एचएफएल	100,000,000	-	100,000,000	120,000,000	120,000,000
	हुडको	-	-	-	97,400,000	97,400,000
	उप-जोड़ (III-ख)	250,000,000	-	250,000,000	367,400,000	367,400,000
(ग)	अन्य (विशेष प्रकृति)					
	उप-जोड़ (III-ग)	-	-	-	-	-
		688,961,708	209,140,635	760,052,554	470,795,447	608,845,236
		688,961,708	209,140,635	760,052,554	470,795,447	608,845,236

मालसूची

नोट-10
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
प्रकाशन एवं अध्ययन सामग्री	3,743,713	2,074,316
उपभोगीय, स्टोर और अन्य	2,270,001	4,284,418
कुल	6,013,714	6,358,734

विविध देनदार

नोट-11
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
(क) विविध देनदार (6 महीने से अधिक के लिए बकाया)		
सुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	8,150	529,758
असुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	15,744,280	372,524
संदिग्ध	3,905,329	4,249,329
	19,657,759	5,151,611
घटाए : अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	3,450,756	3,750,756
उप-जोड़ (क)	16,207,003	1,400,855
(ख) अन्य विविध देनदार		
सुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	67,295	7,473
असुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	27,246,246	1,170,461
संदिग्ध	-	-
	27,313,541	1,177,934
घटाए : अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
उप-जोड़ (ख)	27,313,541	1,177,934
कुल (क+ख)	43,520,544	2,578,789

नकदी और नकदी समकक्ष

नोट-12
(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
बैंक शेष (लिक्विड अवधि जमाओं के साथ)	290,003,815	308,010,137
चैक/ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर/स्टैम्प्स/हाथ में फ्रेंकिंग यूनिट	35,111	2,362,337
हाथ में नकदी	971,571	554,812
कुल	291,010,497	310,927,286

अन्य चालू परिसंपत्तियां

नोट-13

(राशि रु. में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च 2019 की स्थिति
अन्य चालू परिसंपत्तियां (प्रकृति दर्शाएं)		
मौजूदा निवेश पर उपार्जित ब्याज	1,410,265,447	1,232,967,351
पूर्व प्रदत्त व्यय	19,826,598	3,439,361
धरोहर जमा	5,040,921	4,043,054
सेनवेट / जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	10,677,230	18,984,446
पिछले वर्ष के बकाया आयकर की वापसी	29,483,288	37,619,694
स्त्रोत पर कर कटौती (चालू वर्ष)	9,085,551	10,689,294
इंटर यूनिट बैलेंस	1,972,949	-
अन्य वसूलियां	1,680,876	7,789,017
पार्टियों को अग्रिम	5,133,632	4,272,427
कुल	1,493,166,492	1,319,804,644

कार्यकलापों से आय

नोट-14
(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
सदस्य से आय	152,509,801		131,888,856	
वार्षिक शुल्क	7,310,335	159,820,136	2,909,518	134,798,374
अन्य शुल्क				
छात्र से आय				
पंजीकरण शुल्क	104,447,577		134,767,675	
छूट के लिए शुल्क	33,386,560		21,832,390	
पोस्टल शिक्षा शुल्क	262,917,301		313,196,832	
परीक्षा शुल्क	311,863,053		353,109,281	
मौखिक शिक्षा शुल्क	50,050,320		46,110,896	
अन्य शुल्क	12,710,188	775,374,999	14,154,114	883,171,188
प्रकाशनों की बिक्री		12,988,004		8,910,684
कार्यक्रम/संगोष्ठी				
छात्र	89,387,926		67,126,027	89,387,926
सदस्य	79,955,808	169,343,734	52,834,280	119,960,307
कुल		1,117,526,873		1,146,840,553

निवेश से आय

नोट-15
(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
निवेश और बैंक बैलेंस पर ब्याज	528,139,469	510,811,961
निवेश पर इनसेटिव	5,203,175	4,767,801
कुल	533,342,644	515,579,762

अन्य आय

नोट-16

(राशि रु.में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
जर्नल/बुलेटिन /समाचार पत्रिका के लिए सदस्यता	9,449,037	11,300,594
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	371,711	437,009
निवेशक जागरुकता कार्यक्रम – एमसीए/आरडी	181,162	508,326
निवेशक जागरुकता कार्यक्रम/आरबीआई डीए डब्ल्यू – अन्य	-	41,525
सलाहकार सेवाएं	50,000	1,084,000
प्रकाशकों से रॉयल्टी/कमीशन	-	43,281
प्रावधान जो अब जरूरी नहीं है, की वापसी	60,355,438	48,567,599
चिन्हित कोष से से वास्तविक लाभ / आहरण	33,903,641	-
दान- सामान्य	75,312	204,177
किराया	1,083,833	1,465,582
एमसीए से प्राप्तियां – सीआरसी मानेसर स्थापना व्यय	44,719,851	3,100,606
राशि लिखि गई – ईएमडी / एसडी, आदि	-	512
समर्थन सेवाओं और छूट के लिए आईसीएसआई-आईआईपी से प्राप्तियां।	6,660,937	7,858,027
सेवायें और व्यय के लिए आईसीएसआई-आरवीओ से से प्राप्तियां।	4,375,989	3,330,876
इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज	3,012,110	-
विविध अन्य आय	16,493,827	5,913,101
कुल	180,732,848	83,855,215

कर्मचारी लाभ खर्च

नोट-17

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वेतन और भत्ते	383,559,187	363,973,611
निम्न में योगदान :		
भविष्य निधि	41,925,356	24,253,414
ग्रेज्युटी निधि	30,194,923	8,485,560
अवकाश नकदीकरण निधि	-	53,455,049
कर्मचारी कल्याण	20,863,087	21,893,364
कुल	476,542,553	439,322,024

परीक्षा खर्च

नोट-18

(राशि रु.में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
पेपर सेटर्स/परीक्षकों को मानदेय	64,404,325	49,114,826
सामान्य प्रेक्षक	6,558,124	5,867,021
परीक्षा केन्द्र	37,869,031	40,216,608
दस्तावेजों का प्रेषण	7,499,036	10,500,218
उत्तर पुस्तिका	4,862,479	6,078,875
प्रश्न पत्र	9,225,000	8,500,000
कैनवस बैग्स और ताले	858,450	222,784
कार्यालयी उपयोग के फार्म	-	30,349
लिफाफे	766,709	988,817
पास प्रमाणपत्र	201,511	353,208
यात्रा खर्च	339,014	441,527
कंप्यूटर आधारित परीक्षा – फाउंडेशन	9,929,020	11,321,957
परीक्षा –अन्य	655,082	423,269
कुल	143,167,781	134,059,459

अन्य खर्च

नोट—19
(राशि रु.में)

विवरण		समाप्त हुए वर्ष के लिए			
		31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
जर्नल और बुलेटिन / समाचार पत्रिका	19A		43,599,916		51,269,268
कानूनी और पेशेवर सेवाएं	19B		13,651,179		15,572,352
बिजली एवं पानी	19C		19,944,267		17,447,249
संचार खर्च	19D				
— टेलीफोन / फैक्स / ई-मेल / एसएमएस			17,003,060		25,741,638
कोरियर/डाक			32,556,255		49,559,315
अन्य खर्च	19E				
किराया, दर और कर			13,517,850		10,292,913
स्टेशनरी			9,247,415		8,384,840
बीमा			831,445		743,307
मरम्मत और रखरखाव					
भवन			4,926,747		2,623,121
कंप्यूटर			17,667,788		12,131,585
अन्य परिसंपत्तियां			6,835,257		6,784,741
वाहन			793,405		684,672
कार्यालयी खर्च			28,405,689		26,009,583
समाचार पत्र और पत्रिकाएं			225,207		180,825
बैठकों पर खर्च			4,763,051		4,836,228
कंप्यूटरीकरण (डाटा प्रसंस्करण)			4,654,060		4,920,500
पैकिंग एवं प्रेषण			29,410		82,484
हानि/स्टॉक बट्टे खाते डालना			-		20,282
बैंक शुल्क			7,959,359		9,547,842
छात्र छात्रवृत्ति और पुरस्कार			379,190		453,584
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (जीएसटी के साथ)					
लेखा परीक्षा शुल्क : मुख्य कार्यालय			250,000		270,810
: अन्य कार्यालय			1,027,909		784,134
अन्य सेवाएं : मुख्य कार्यालय			3,381		256,650
: अन्य कार्यालय			414,861		1,415,515
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क			1,634,738		1,601,650
आरबीआई जमाकर्ता जागरुकता कार्यक्रम			-		933,236
निवेशक जागरुकता कार्यक्रम			167,345		534,481
जीएसटी इनपुट रिवर्सल			488,065		-
सीएसबीएफ को दान			133,377		132,111
विविध खर्च			751,774		271,167
चुनाव व्यय (निवल)			-		8,740,241
अशोध्य ऋण			131,304		93,876
सीआरसी मानेसर स्थापना व्यय			40,732,599		-
खराब / संदिग्ध ऋणों का प्रावधान			-		300,000
कुल			145,971,226		101,718,784

सीसीजीआरटी गतिविधियां

नोट-20
(राशि रु.में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
सीसीजीआरटी				
स्थापना	107,085		150,512	
पुस्तकें और पत्रिकाएं	40,365		32,717	
मुद्रण और स्टेशनरी	207,583		76,090	
संचार	182,080		289,688	
यात्रा और परिवहन	47,638		24,530	
कार्यक्रम और सेमिनार खर्च	5,160,978		2,997,243	
अन्य	7,355,171	13,100,900	6,008,569	9,579,349
कुल		13,100,900		9,579,349

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

नोट-21(समेकित)

1. सामान्य जानकारी

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("संस्थान या आईसीएसआई") भारत में कंपनी सचिव के पेशे का विकास एवं संचालन के लिए एकमात्र मान्यता-प्राप्त व्यावसायिक निकाय है। भारत में कंपनी सचिव के व्यवसाय के संचालन के प्रयोजन हेतु 10 दिसंबर, 1980 को कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन स्थापित यह एक अग्रणी राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कथित अधिनियम के संदर्भ में संस्थान की परिषद को संस्थान के कार्यों के प्रबंधन का लक्ष्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए परिषद ने 4 क्षेत्रीय परिषद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं नई दिल्ली में एक-एक और पूरे भारत में 72 शाखा(वर्ष के दौरान बंद यमुनानगर और सोनीपत नामक 2 शाखाओं को छोड़कर) गठित किये हैं। आईसीएसआई, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। संस्थान छात्रों को कंपनी सचिव (सीएस) कोर्स के तौर पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और सीएस सदस्यों के लिए बेहतर गुणवत्ता मानक स्थापित करता है।

2. अर्थपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क. लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

संस्थान की वित्तीय विवरणियां इतिवृत्त लागत परम्परा के आधार पर की जाती हैं और इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी और आम तौर पर भारत में स्वीकृत सिद्धांत द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है तथा जब तक अन्यथा संकेत न दिया हो तब तक ये प्रोद्भूत आधार पर होते हैं। सभी आय और खर्चों का हिसाब वास्तविक आधार पर लगाया जाता है, जब तक अन्यथा न कहा जाए। लेखांकन नीतियां निरंतर संस्थान द्वारा और पिछले वर्ष में उपयोगकर्ताओं के अनुरूप लागू की गई हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कुछ अनुमानों और मान्यताओं को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं और वर्ष के दौरान, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों और राजस्व एवं खर्च की कथित राशि का खुलासा होता है, वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अन्तर उस अवधि में प्राप्त होते हैं जिसमें परिणामों का पता चलता है/प्रकट होते हैं।

3. चालू एवं गैर-चालू के वर्गीकरण का आधार

तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू एवं गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, सामान्य परिचालन चक्र में बिक्री या खपत के लिए इरादा है; या यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है; या रिपोर्टिंग तिथि के बारह माह के भीतर यह महसूस किये जाने की उम्मीद है; या नगद एवं नगद समतुल्य के समान है, तब तक इसे विनियमित करने से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है या रिपोर्टिंग तिथि के बाद न्यूनतम बारह माह के लिए दायित्व के निपटान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह अनुमान हो सामान्य परिचालन चक्र या इसके व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्यतः धारित या रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह माह के भीतर निपटान का अनुमान हो या संस्थान न्यूनतम बारह माह के लिए दायित्व के निपटान के अंतरण को अनियमित शर्त को नहीं मानता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र प्रक्रिया के लिए परिसम्पत्ति के अधिग्रहण और नगद एवं नगद समतुल्य में उसकी वसूली के बीच का समय है।

4. राजस्व मान्यता

(क) किसी सदस्य से प्रवेश के समय उसके प्रवेश शुल्क की प्राप्ति को सीधे **पूँजी रिजर्व** खाते में दिखाया गया है।

(ख) सदस्यों से जितना शुल्क प्राप्त होता है, उतनी राशि नकद आधार पर हिसाब में ली गई है। किन्तु अग्रिम में प्राप्त शुल्क को देयता के रूप में आगे ले जाया गया है।

(ग) विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्कों को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(घ) परीक्षा शुल्क परीक्षा संचालन के आधार पर लिया जाता है।

(ङ) प्रकाशन की बिक्री से मिली राजस्व राशि को बिक्री का बिल तैयार करते समय लिया जाता है अर्थात् जब वस्तु का अधिकार तथा उसका जोखिम एवं पुरस्कार खरीददार को हस्तांतरित हो जाए।

(च) निवेश से आय

(i) निवेश पर लाभांश को प्राप्ति के आधार पर माना गया है।

(ii) ब्याज वाली प्रतिभूतियों और सावधि जमा की आय को बकाया राशि और प्रयुक्त दरों के हिसाब से समय-अनुपात आधार पर माना गया है।

(छ) किसी विशिष्ट सरकारी प्रयोजित कार्यक्रम से प्राप्त धन राशि को आय और व्यय लेखा में उतनी आवश्यक अवधियों में एक प्रणालीबद्ध आधार पर लिया गया है ताकि उससे सम्बन्धित लागत के साथ उसकी वांछित अवधि के साथ संगत बनाया जा सके। इन प्राप्त राशियों के अप्रयुक्त धन को यदि कोई हो तो अगले वर्ष में लिया गया है।

5. निवेश

(क) दीर्घकालीन निवेशों को लागत के आधार पर लिया जाता है और अस्थायी निवेश को छोड़ कर मूल्यों के ह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(ख) चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य जो कम हो पर लिया जाता है।

(ग) एक प्रीमियम पर खरीदे गए निवेश को अंकित मूल्य पर तुलन पत्र पर लिया है और शेष निवेशों के अनुपात में प्रीमियम राशि को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है।

6. स्थायी परिसम्पत्तियाँ/मूल्यह्रास और परिशोधन

क) भूमि को छोड़कर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर और इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, के अनुसार होता है।

ख) अमूर्त परिसम्पत्तियों की गणना तब की जाती है जब यह संभावित हो कि भावी आर्थिक लाभ जो कि परिसम्पत्ति के आरोप्य है, इंटरप्राइज के अधिकता होंगे और परिसम्पत्ति की कीमत विश्वस्त रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, की ऐतिहासिक लागत घटाकर वर्णित किया जाता है।

ग) 99 वर्ष से ज्यादा स्थायी पट्टे पर और पट्टे पर अधिग्रहीत भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में माना जाता है। 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए पट्टे पर अधिग्रहित भूमि को लीजहोल्ड भूमि माना जाता है।

घ) फ्रीहोल्ड भूमि लागत पर दिखाया गया है। पट्टे के अधिकार प्राप्त करने के लिए स्टैप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सहित प्रीमियम की राशि पर लीजहोल्ड भूमि का उल्लेख किया गया है। पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार भूमि का मूल्य परिशोधित होता है।

ङ) अलग अलग परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर परिषद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर लिखित मूल्य की विधि के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

मद	प्रतिशत
भवन	5
फर्नीचर एवं फिवचर्स	10
लिफ्ट/एयरकंडीशनर्स/अन्य उपकरण	15
वाहन	20
कम्प्यूटर्स एवं मोबाइल	40

च) स्थायी परिसम्पत्तियों के परिवर्धनों पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके परिवर्धनों के महीने से यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

छ) 5000 रुपए या इससे कम मूल्य की स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यहास खरीद के वर्ष में किया जाता है।

ज) लाइब्रेरी की पुस्तकों का मूल्यहास खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

झ) अमूर्त परिसम्पत्तियों (साफ्टवेयर) का परिशोधन तीन वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर किया जाता है।

ञ) परिसम्पत्ति की बिक्री/निपटान/गैर-मान्यता से लाभ या हानि को निवल निपटान प्रक्रिया और परिसम्पत्ति की अग्रेनीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और प्रासंगिक वर्ष की आय और व्यय खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

7. परिसम्पत्तियों की क्षति

यदि आंतरिक/वाह्य कारकों पर आधारित क्षति का संकेत मिलता है तो परिसम्पत्तियों की आवर्ती राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है। जब कभी भी परिषद परिसम्पत्ति की आवर्ती राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो ऐसी क्षति को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति की निवल राशि या प्रयुक्त मूल्य से अधिक होती है। प्रयुक्त मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भावी नकद प्रवाह से पूंजी के भारित लागत पर उसके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है।

8. मालसूची

पेपर, कंज्यूमेबल्स, प्रकाशन, अध्ययन सामग्री आदि की मालसूची को वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर आधारित लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। कीमत को एफआईएफओ आधार पर निर्धारित किया जाता है। यद्यपि, 1 वर्ष से अधिक पुरानी मालसूची को चालित/गैर-चालित/अप्रचलित की मानी हुई लागत केवल रु. 1/- में मूल्यांकित किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक खरीद के वर्ष में आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है और वर्ष की समाप्ति पर रु. शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

क. विदेशी मुद्रा ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन की तारीख के समय जो एक्सचेंज दर होती है उस पर विदेशी करेंसी राशि को लागू कर औपचारिक करेंसी की प्रारंभिक मान्यता का रिकार्ड रखा जाता है।

ख. सभी आय और व्यय को औसत दर पर लिया जाता है। सभी मौद्रिक परिसम्पत्ति/देयताओं को वर्ष के अंत की दरों पर लिया जाता है जबकि गैर-मौद्रिक परिसम्पत्तियों को ट्रांजेक्शन की तारीख की दरों पर लिया जाता है।

ग. विनियम दर के अन्तर के कारण होने वाली आय या व्यय को आय तथा व्यय खातों में दिखाया जाता है।

10. कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजना

क. इंस्टीट्यूट द्वारा रखे गए प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में अंशदान को व्यय के रूप में माना जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

क. उपदान फंड ट्रस्ट से देय राशि/वसूली योग्य राशि को वर्ष के अंत में वर्तमान दायित्व के लिए एलआईसी से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर तुलन पत्र में देयता/परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है।

ख. पेंशन फंड ट्रस्ट के अंशदान को बीमाकित मूल्यांकन के आधार पर होता है और एएस-15 (संशोधित) के अनुसार व्यय में माना जाता है।

ग. एलआईसी से प्राप्त बीमाकित मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान एएस-15 (संशोधित) के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

11. नगद एवं नगद समतुल्य

तुलनपत्र में नगद एवं नगद समतुल्य में बैंक खाता के साथ जुड़ा फ्लैक्सी जमा सहित बैंक एवं स्वयं के पास नगदी और तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ संक्षिप्त अवधि जमा शामिल है जो कि मूल्य के परिवर्तन के निरर्थक जोखिमों के अधीन हैं।

12. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह को लेखाकरण मानक-3 "नगदी प्रवाह विवरण" में निर्धारित पद्धति के रूप में दर्ज किया जाता है जिससे गैर-नगदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव के रूप में कर पूर्व लाभ/(हानि) और पूर्व या भावी नगदी प्राप्ति या भुगतान की अस्थगित अदायगी या उपार्जन को समायोजित किया जाता है। संस्थान की परिचालन, निवेश एवं वित्तीय कार्यक्रमों से नगदी प्रवाह को उपलब्ध डाटा एवं सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

13. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियों को तुलन पत्र में इस धारणा पर कहा गया है कि गतिविधि के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर, मूल्य कुल दर्शाई गई राशि के बराबर होगा।

विविध देनदार और अग्रिम राशियों को तीन साल से अधिक के लिए बकाया और प्रबंधन की राय में संदिग्ध वसूली को खाताबही में प्रावधानों के लिए और शुद्ध प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

14. प्रावधान

किसी प्रावधान को तभी स्वीकार किया जाता है जब किसी विगत घटना के कारण उस उद्यम का वर्तमान दायित्व बनता है संभव है कि उस दायित्व का निपटान करने के लिए जिसके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया है संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता पड़े। प्रावधानों को वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों के निपटान के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और उनका समायोजन चालू सर्वोत्कृष्ट अनुमानों में दर्शाया जाता है।

15. क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के लिए प्रकाशनों की बिक्री पर अनुदान/व्यय की प्रतिपूर्ति एवं सब्सिडी

क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के लिए प्रकाशनों की बिक्री पर वार्षिक अनुदान, व्यय की प्रतिपूर्ति और सब्सिडी की गणना नगदी आधार पर की जाती है।

16. अनुमोदित निधियों/संस्थानों/संगठनों के लिए अंशदान/अनुदान

समय-समय पर परिषद द्वारा अनुमोदित राशि के आधार पर आईसीएसआई विद्यार्थी शिक्षा निधि ट्रस्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन पर आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, आईसीएसआई कर्मचारी चिकित्सा अस्पताल में भर्ती ट्रस्ट, कम्पनी सचिव उदार निधि, आईसीएसआई कर्मचारी उदार निधि, कार्यप्रदर्शन-संबंधी इंसेटिव निधि, व्यावसायिक विकास निधि और अवसंरचना निधि को आवंटन/अंशदान।

17. आरक्षित और अधिशेष तथा निर्वाचित निविदों का आवंटन/स्थानांतरण

क. वर्ष में प्राप्त कार्पस डोनेशन/भवन तथा अन्य विशिष्ट निधियों के लिए डोनेशन को सीधे सामान्य रिजर्व में डाला जाता है।

ख. निर्धारित निधियों से प्राप्त आय को औसत प्राप्ति के आधार पर तथा अंत शेषों की औसत पर उनकी निर्धारित 8%प्रतिवर्ष की दर पर आवंटित किया जाता है और खर्च की गई राशि को इन निधियों में डेबिट किया जाता है।

18. "धरोहर राशि जमा, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा और गतावधि चैक" शीर्षको के अंतर्गत पुरानी बकाया राशि

"धरोहर राशि जमा, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा और गतावधि चैक" शीर्षको के अंतर्गत तीन वर्षों से अधिक के लिए गैर-विवादित बकाया का वित्त वर्ष के अंत में भुगतान नहीं किया गया, एवं उसे बड़े खाते में डाल दिया गया और वर्ष के लिए आय के रूप में मान लिया गया। उसके तदुपरांत बड़े खाते में डाली गई राशि के दावे का भुगतान दावे के वर्ष में किया जाएगा और तदनुसार वर्ष के लिए व्ययों को निर्धारित किया जाएगा।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक दयताएं

(क) संस्थान के खिलाफ ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता है 16.90 लाख रुपए (पिछले वर्ष 27.27 लाख रुपए) हैं, ब्याज छोड़कर जिसका अभी पता नहीं।

(ख) इंस्टीट्यूट के खिलाफ स्टाफ/श्रमिकों द्वारा श्रम एवं अन्य मामलों में दायर किए गए कानूनी मामलों सम्बन्धी दावों की राशि निश्चित नहीं है (किन्तु 31.3.2020 तक राशि का प्रावधान शून्य रुपए है) (पिछले वर्ष शून्य रुपए है)

(ग) ट्रेसेस द्वारा प्रदर्शित आयकर प्राधिकरण की चूक से लंबित समायोजन राशि 2.35 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.69 लाख रुपए)

(घ) संस्थान ने निर्माण, प्रचालन एवं अंतरण (बीओटी) आधार पर छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल के लिए मैसर्स गुरुकुल ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (जीओएलएस) के साथ एक समझौता किया था। 13.09.2015 को समझौता समाप्त हो गया। जीओल (GOLS) जुलाई, 2015 से संस्थान के पक्ष में कार्य सौंपने में विफल रहा और आईसीएसआई को पोर्टल हस्तांतरित करने में भी विफल रहा। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने 06.03.2017 के अपने आदेश के माध्यम से पार्टियों को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

संस्थान ने अपने बकाए के लिए रु 43,24,920/- और हर्जाने के रूप में रु 2,00,00,000/- का दावा किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ने माननीय न्यायमूर्ति एम एल मेहता को दिल्ली पंचाट परिषद का एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। जीओएलएस ने भी लगभग रु 32 करोड़ का अपना दावा दायर किया और संस्थान के दावे के बारे में अपना उत्तर दिया है। उक्त मामला अभी भी लंबित है।

उपर के संदर्भ में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्णय मिलने के पश्चात भविष्य नगद प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा।

2. पूंजी प्रतिबद्धताओं और अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 31.03.2020 को रु. 883.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 953.58 लाख) अग्रिम का निवल है। अन्य प्रतिबद्धताओं की राशि रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य) है। संस्थान की सामान्य प्रक्रिया में किये गये सामान एवं सेवाओं की बिक्री/अधिप्राप्ति के संबंध में कार्यकलाप को अतिरिक्त विवरण के कारण प्रकटित नहीं किया जाता है।

3. प्रबंधन की राय है कि वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियों और सक्रिय उपयोग में नहीं आ रही परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त लेखांकन मानक-28 के अनुसार और कोई हानि नहीं हुई है।

4. कर्मचारी हितलाभ :

लेखाकरण मानक-15 में जिन कर्मचारी हितलाभों का वर्णन है, वे इस प्रकार हैं :

परिभाषित अंशदान योजना —परिभाषित अंशदान योजना में नियोक्ता का अंशदान, जैसे भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष में रुपांतरित कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंध आईसीएसआई एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

(i) उपदान

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित कर्मचारी उपदान निधि परिभाषित हितलाभ योजना है। वर्तमान दायित्व मूल्य का निर्धारण लेखाकरण मानक-15 में परिभाषित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) विधि का इस्तेमाल करते हुए बीमांकित मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

(ii) छुट्टी नकदीकरण

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण निधि परिभाषित हितलाभ योजना है। वर्तमान दायित्व मूल्य का निर्धारण लेखाकरण मानक-15 में परिभाषित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) विधि का इस्तेमाल करते हुए एलआईसी द्वारा बीमांकित मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

(iii) पेंशन

पेंशन का प्रबंध एक अलग ट्रस्ट करता है जिसका नाम है — आईसीएसआई कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट और लेखाकरण मानक-15 के अनुसार निम्नलिखित पीयूसी विधि द्वारा 31.3.2020 को पेंशन बनेफिट प्लान की देयताओं का बीमांकित मूल्यांकन किया गया है और पेंशन हितलाभ योजना की देयताओं के लिए पूरी निधि जुटाई जाती है।

I. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन की सारणी

(आकड़ें रु. लाख में)

	उपदान निधिपोषित	पेंशन निधिपोषित	एलआईसी के साथ निधिपोषित एवं आईसीएसआई के साथ चिन्हित
वर्ष के आरम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1546.49	5969.29	1600.24
ब्याज लागत	115.99	460.94	*128.02
विगत सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य
चालू सेवा लागत	104.40	81.85	141.81
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	166.28	544.79	(409.27)
प्रदत्त हितलाभ	(154.98)	(240.38)	(213.34)
निपटान लागत	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	1778.18	6816.49	1247.46

* नोट-2 के अनुसार निर्धारित निधियों पर आवंटित ब्याज

II. योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन की सारणी

(आकड़ें रु. लाख में)

	उपदान निधिपोषित	पेंशन निधिपोषित	एलआईसी के साथ निधिपोषित एवं आईसीएसआई के साथ चिन्हित
वर्ष के आरम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1520.50	5896.67	1330.82
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित/वास्तविक प्रतिफल	125.69	455.33	97.22
अंशदान	147.28	शून्य	43.38
प्रदत्त हितलाभ	(154.98)	(240.38)	(213.34)
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	शून्य	19.41	शून्य
कोष प्रबंधन शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1638.49	6131.03	1258.08

III. तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(आकड़ें रु. लाख में)

	उपदान निधिपोषित	पेंशन निधिपोषित	एलआईसी के साथ निधिपोषित एवं आईसीएसआई के साथ चिन्हित
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1778.18	6816.49	1247.46
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1638.49	6131.03	1258.08
फंडेड स्टेटस	(139.68)	(685.46)	10.63
तुलन पत्र में निवल मान्यता प्राप्त परिसम्पत्ति/(देयता)	(139.68)	(685.46)	10.63

IV. आय और व्यय लेखा का मान्यता प्राप्त व्यय

(आकड़ें रु. लाख में)

	उपदान निधिपोषित	पेंशन निधिपोषित	एलआईसी के साथ निधिपोषित एवं आईसीएसआई के साथ चिन्हित
चालू सेवा लागत	104.40	81.85	141.81
ब्याज लागत	115.99	460.94	*128.02
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(125.69)	(455.33)	(97.22)
विगत सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल बीमाकित (लाभ)/हानि	166.28	525.38	(409.27)
मान्यता प्राप्त व्यय	260.98	612.84	(236.66)
घटाए : निर्धारित निधियों पर आवंटित प्रतिलाभ	-	-	--
जमा : वर्ष के प्रारंभ में वर्तमान दायित्वों से अधिक राशि/प्लान/फंडेड परिसम्पत्तियां	-	72.62	--
निवल लागत	260.98	685.46	(236.66)

* नोट-2 के अनुसार निर्धारित निधियों पर आवंटित ब्याज

V. फंडेड निवेश विवरण

ग्रेच्युटी	पेंशन	छुट्टी नकदीकरण
एलआईसी के साथ 100 प्रतिशत बीमा पॉलिसी	केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉर्ड्स, विशेष जमाराशि योजना और अनुसूचित बैंकों के पास मियादी जमाराशियां	एलआईसी में रु. 1258.08 लाख का निवेश

VI. बीमाकित धारणा

	ग्रेच्युटी	पेंशन	छुट्टी नकदीकरण
मृत्यु दर सारणी	एलआईसी (2006-08) अल्टीमेट	2012-14	2006-08
छूट दर	7.25% p.a.	7.00% p.a.	7.25% p.a.
भावी वेतन वृद्धि	10.00% p.a.	8.00% p.a.	10.00% p.a.
योजनागत परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	7.25% p.a.	7.50% p.a.	7.25% p.a.

5. लघु एवं मध्यम उद्यमों के बकायों को पार्टियों द्वारा दी गई एवं प्रबंधन द्वारा संग्रहित जानकारी के आधार पर चिन्हित करके निर्धारित किया गया है। संस्थान को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अपने स्टेटस के संबंध में "आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं" से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए अधिनियम के अधीन अपेक्षित प्रदत्त/देय ब्याज के साथ वर्ष के अंत में अप्रदत्त राशि के संबंध में प्रकटन, यदि कोई हो, नहीं दिया गया है। इसे शून्य के रूप में माना जाता है।

6. संस्थान ने वर्ष के अंत में विभिन्न पार्टियों/विक्रेताओं को उनकी शेष पुष्टि के लिए संवाद जारी किया है। हालांकि, महामारी कोविड-19 के कारण अधिकांश मामलों में पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए, विभिन्न पार्टियों की शेषधनराशि अंतर इकाई शेषराशि सहित सामंजस्य और उनकी पुष्टि के अधीन हैं।

7. संस्थान मुख्य रूप से भारत में और एक भौगोलिक खंड में अपना कार्य संचालित करता है क्योंकि पूरे भारत की आर्थिक स्थिति एक समान है, आगे संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी सचिव के पेशे का विकास करना है। इसलिए एएस-17, सेगमेंट रिपोर्टिंग के संदर्भ में इसके सभी प्रचालन केवल एक सेगमेंट के भीतर आते हैं।

8. संस्थान के परिचालन चक्र को वित्तीय विवरणों में चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए बारह माह के रूप में माना जाता है।

9. समापन सूचियों का मूल्यांकन संस्थान की नीति के अनुसार मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में वर्ष के अंत में उपलब्ध अभिलेखों और क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक जानकारी के आधार पर किया जाता है। कुछ शाखाओं ने 31-03-2020 तक की मात्राओं, सूचियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, हालांकि मुख्यालय के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार इसे माना गया है। कोविड 19 और लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, वर्ष के अंत में समापन सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

10. 31 मार्च, 2020 को बकाया क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के भवन ऋण का सारांश निम्नानुसार है:

(रु. लाख)

स्थान	31.3.2020 के अनुसार	31.3.2019 के अनुसार	31.03.2020 को पुनर्भुगतान के लिए बकाया राशि
मैसूर चैप्टर	2.00	2.00	2.00
थाणे चैप्टर	शून्य*	10.50	शून्य
फरीदाबाद चैप्टर	5.00	5.00	5.00
कुल	7.50	17.50	7.50

* सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार जनरल रिजर्व से इसे ह्रासित और समायोजित किया गया है।

11. पूर्व अवधि आय/व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख)

आय	2019-20	2018-19
टीडीएस	0.13	0.25
क्षेत्रीय परिषद / शाखा प्रतिपूर्ति	0.50	--
यात्रा /वाहन व्यय	-	0.17
टीडीएस सुधार	-	9.67
जीआरकेएफ	-	0.46
बीमा	-	42.23
दावा नहीं किया गया राशि आय में हस्तांतरित (स्टेल चेक)के लिए सुधार प्रविष्टि	-	4.13
डल्यूआईआरओ सम्मेलन	-	3.33
सीआरसी- रसीदें	45.26	-
कुल	45.89	60.24
व्यय	2019-20	2018-19
विज्ञापन	0.92	3.47
एएमसी - कार्यालय उपकरण और अन्य	5.25	5.78
सीओई कोलकाता स्थित भूमि का परिशोधन	49.23	--
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.05	--
सम्प्रेषण व्यय	0.19	--
सीआरसी के खर्च	70.21	--
डीआर क्लाउड	30.53	--
परीक्षा व्यय	0.79	--
मैसर्स संरचना का पूर्ण और अंतिम निपटान	12.07	--
जीएसटी देयता	6.84	--
विविध बैलेंसिंग ह्रासित	4.84	--
मानदेय	0.17	--
लीज रेंट	1.59	--
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	5.47	1.26
अन्य विविध व्यय	19.64	10.11
मुद्रण और डिजाइनिंग व्यय	0.32	13.12
कार्यक्रम और सेमिनार	2.31	25.14
संपत्ति कर	10.62	9.38
44वां राष्ट्रीय अधिवेशन	12.53	-
छात्रों को शुल्क का रिफंड	7.34	96.49
सदस्यों को रिफंड	0.51	--
क्षेत्रीय परिषद / शाखा विस्तार प्रतिपूर्ति	13.13	--
कर्मचारी कल्याण	1.21	--
यात्रा और आवागमन	11.97	18.34
कुल	267.73	183.09
निवल (आय) / व्यय	221.84	122.85

12. आयकर

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आयकर अधिनियम 1961 के 12ए के अंतर्गत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम की धारा 11/12 के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है।

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11/12 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए आयकर निर्धारण वर्ष 2016-17 का आकलन धारा 143(3) के अधीन पूर्ण हो गया है जिसमें रिटर्न आय को स्वीकार कर लिया गया है। आयकर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए इसके अतिरिक्त इस मूल्यांकन आदेश के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार के लिए रु. 14,95,916/- से कम रिफंड प्राप्त होने के सम्बन्ध में 8 जुलाई, 2019 को एक आवेदन दाखिल किया गया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आयकर विभाग के साथ मूल्यांकन प्रगति पर है और पिछले मूल्यांकन एवं वर्तमान तिथि तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मांग के संदर्भ में कोई भी अनुमानित अतिरिक्त देयता नहीं है। आईटीआर जमा में मांग के अनुसार आगे आयकर रिफंड निर्धारण वर्ष 2019-20 तक प्राप्त हुआ है।

13. आईपी, उप्पल, हैदराबाद में आवटित कुल 4918 वर्ग मीटर (1.215 एकड़) के कुल क्षेत्रफल के लिए भूमि की लागत हेतु आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (अब तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड) को 2,88,56,250/- रु का भुगतान किया, जिसमें से (i) बिक्री समझौते को निष्पादित करने और प्रथम चरण में 3140 वर्गमीटर के लिए पंजीकरण, (ii) 2 चरण में 912 वर्गमीटर हेतु बिक्री कार्यान्वयन के लिए समझौता और (iii) 3 चरण में 866 वर्गमीटर हेतु (50,82,500/- रुपये की लागत) बिक्री के लिए समझौते का निष्पादन और कब्जा लेने और देने के लिए कार्यवाही किया है क्योंकि मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। 1 और 2 चरण के लिए बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड से अनुरोध किया गया था। रिट पिटीशन नं. 31594/2014 दिनांक 18-10-2014 को तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय में दायर किया गया है और संस्थान के पक्ष में दिनांक 24-08-2015 को अदालत के आदेश द्वारा खाली किए गए निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

14. संस्थान ने बिक्री समझौते और विलेख को पंजीकृत कराने के निष्पादन के समय इंदौर में बहुमंजिला इमारत "दि ग्रेस" (पूर्व नाम-नासा) के पांचवें तल के एक भाग की खरीद के अधीन रु. 3,21,00,000/- की कुल सहमत बिक्री प्रतिफल के अंतर्गत आंशिक भाग के भुगतान के लिए रु. 80,25,000/- की राशि का भुगतान किया गया है। स्टाप ड्यूटी और पंजीकरण सहित इस संबंध में कुल व्यय रु. 83,23,000/- है। सक्षम प्राधिकारी से विक्रेता द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है और इसके कारण अब तक सेल डीड निष्पादित नहीं की गई है। मामला न्यायिक विचाराधीन होने के कारण राशि को पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत दर्शाया और रखा गया है। संपत्ति के विक्रेताओं के खिलाफ संस्थान द्वारा दायर मुकदमों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) जिला न्यायालय, इंदौर में दिनांक 19-12-2016 को सिविल सूट-केस नं. 2016 आईसीएसआई बनाम 9800255 सिराजुद्दीन मलिक और अन्य।

(ii) जिला न्यायालय, इंदौर में दिनांक 05-02-2018 को अवमानाना मुकदमा-आईसीएसआई बनाम सिराजुद्दीन मलिक और अन्य।

(iii) जिला न्यायालय, इंदौर में दिनांक 04-07-2017 को क्रिमिनल सूट-ट्रायल नं. 2017 का 3135-आईसीएसआई बनाम सिराजुद्दीन मलिक और अन्य।

15. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय का विवरण :

(रु. लाख)

क. विदेशी मुद्रा में आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विदेशी सदस्यों से शुल्क
कन्वेंशन स्टॉल
कुल
ख. विदेशी मुद्रा में व्यय		
सदस्यता शुल्क	13.59	6.52
अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	3.45	19.89
यात्रा व्यय
उद्घाटन समारोह (एनपीआईओ, दुबई)	3.60	...
दुबई परीक्षा केंद्र	1.12	..
विविध व्यय	.	4.51
कुल	21.76	30.92

16. संस्थान को दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान सदस्यता शुल्क पर सेवा कर (शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर सहित) जमा करने हेतु वस्तु एवं सेवाकर इंटेलिजेंस महानिदेशालय (पूर्व में सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस महानिदेशालय), भोपाल इकाई से 23 अक्टूबर, 2018 को एक कारण बताओ नोटिस-196/बीएचजेडयू/एडीजी/एसटी/2018 प्राप्त हुआ।

सेवा कर के लिए कुल 2,78,22,787/- रुपए मांग की गयी थी। संस्थान ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है और मांग की गई राशि का भुगतान न करने पर जुर्माने सहित रु. 5,04,36,250/- (ब्याज को छोड़कर) के लिए आदेश प्राप्त किया है। इस बीच, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विवादों के निपटारे की एक योजना - सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (एसवीएलडीआर एस) शुरू की है जिसमें संस्थान ने इस निपटान के लिए आवेदन किया है। उक्त छूट योजना के तहत मामला सुलझा

लिया गया है और वर्ष के दौरान आय एवं व्यय खाते में असाधारण मदों के रूप में 1,39,11,394/-रुपए की अंतिम मांग का भुगतान और बुकिंग की गई।

17. वर्ष के दौरान, संस्थान की नीति के अनुसार, तीन साल से अधिक पुरानी अपने बकाया शेष राशि के रिटेन ऑफ होने के कारण उसके सामान्य रिजर्व से 69.94 लाख रुपए की राशि समायोजित की गई है।

18. दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद और पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार, रु. 22,73,999/- और रु. 4,54,573/-को क्रमशः संदिग्ध देनदार / अग्रिम माना गया है। हालाँकि, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और प्रबंधन को उम्मीद है कि यह राशि संबंधित पक्षों से वसूली जाएगी और वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है या शुरू की जाएगी।

19. पिछले वर्ष के आकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, वहां पुनः वर्गीकरण/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है ताकि उनका मेल नए प्रारूप में चालू वर्ष के साथ बिठाया जा सके।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान परिषद की ओर से और उनके लिए

सीए समीर गुप्ता सीएस आशीष मोहन सीएस नागेन्द्र डी. रावसीएस आशीष गर्ग
संयुक्त सचिव सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष
(वित्त एवं लेखा)

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बंसल सिन्हा एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई के साथ एफआरएन 006184

(निशांत चौधरी)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 513802

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2020

**कृते पी.के
चोपड़ा एवं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एनआईसीएआई के साथ एफआरएन 006747एन

(राहुल जिंदल)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 537709

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2020

REPORT OF THE COUNCIL**F.No.104/40/Accts.—1. INTRODUCTION**

In terms of the requirements of sub-section(5B) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to present its 40th Annual Report and audited statements of consolidated accounts along with the Auditors' Report thereon for the year ended March 31,2020. The programmes and activities organized and initiatives taken subsequent to the above period, till the date of this report have also been included in this report.

President and Vice-President

CS Ashish Garg and CS Nagendra D. Rao were elected by the Council as President and Vice-President respectively of the Institute w.e.f. January 19, 2020.

Council Meetings

The Council held 9 Meetings during the Financial Year 2019-20.

Composition of Committees

The composition of various Standing and Non-Standing Committees, Expert Groups, Advisory Boards and Outside Committees is placed at **Appendix-A**.

Details of meetings held and attended by the Members are placed at **Appendix- B**.

Regional Councils and Chapters

Continuous updation of knowledge and capacity building of its members is one of the prime responsibilities of the Institute. Regional Councils and Chapters of the Institute across the country continued to provide valuable support and assistance to the Council and conducted their activities with enthusiasm carrying out their functions and responsibilities diligently throughout the year. In the process, they conducted Professional Development Programmes, Seminars, Webinars, Workshops, Training Programmes, Management Skills Orientation Programmes, Class Room Teaching, Study Circle Meetings, Regional and State Conferences, Career Awareness Programmes and Investor Awareness Programmes. In addition, they focused on areas like up-gradation of library systems, publication of news bulletins and e-newsletters, and providing of assistance to the members seeking placement by way of organizing placement drives and HR Conclaves.

Chapters: During the year under report, there were 72 Chapters (including new Chapters viz. Belagavi, Gorakhpur, Patiala and Karnal) of the Institute.

Statistics at a Glance

The region-wise statistics of Members and Students are as under :

ITEM	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	Total
NUMBER OF MEMBERS					
As on 15.09.2020	6344	22412	11926	21910	62592
As on 31.3.2020	6275	22684	11071	21160	61190
As on 31.3.2019	5989	21391	10409	19757	57546
NUMBER OF STUDENTS FOR REGULAR PROGRAMME					
As on	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	TOTAL
15.09.2020	20764	60070	45421	63877	190132
31.03.2020	22820	66433	50432	70760	210445
31.03.2019	24911	74365	53175	77686	230137

NUMBER OF STUDENTS FOR FOUNDATION PROGRAMME					
As on	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	TOTAL
15.09.2020	4113	9591	7046	9556	30406
31.03.2020	5104	11745	8699	11705	37257
31.03.2019	6110	14955	10021	16997	48083

Best Regional Council and Best Chapter Awards for the Calendar Year 2018

In order to recognize the contributions made by the Regional Councils and Chapters as well as to encourage and create competitive spirit amongst them, the Best Regional Council Award and Best Chapter Awards were instituted.

The Best Regional Council, Best National Chapter and Grade-wise Best Chapter Awards for the year 2018 were as follows:

Best Regional Council : Southern India Regional Council		
Best Chapters		
Sl. No.	Category	Name of the Chapter
1.	National Best Chapter	Bhubaneshwar
2.	Grade A +	Bengaluru
3.	Grade A	Indore
4.	Grade B	Coimbatore
5.	Grade C	Bhubaneshwar
6.	Grade D	Amravathi

In order to encourage the Chapters, ICSI introduced new categories of awards in the year 2018. The recipients for the same were as under.:

Sl.No.	Awards Category	Evaluation Criteria	Recipient
1	Best Study Centers Awards	Maximum numbers of students registered	D M College of Commerce, DM College Campus, Imphal, Manipur 795001
2	Best Chapter Award for Career Awareness Programmes (CAP) Activities	Maximum numbers of CAP conducted	Bengaluru
3	Best Chapter Award for Class Room Teaching Activities	Maximum numbers of Student registered for Class Room Teaching	Coimbatore
4	Emerging Chapter Award	Chapter which activated itself in very first month	Belagavi
5	Best Chapter for Placement Services	Chapter which has conducted maximum activities for Placement Services	Chandigarh
6	Best Chapter for Student Registration	Chapters which achieved the targets for Student Registrations	Guwahati (NE)

All the Awards mentioned above were presented at the 47th National Convention of Company Secretaries held from 14th to 16th November, 2019 at the Jaipur Exhibition & Convention Centre, Jaipur.

2. INFRASTRUCTURE

I) Existing own premises:

A) Head Office

Lodi Road, New Delhi and Noida

B) CCGRT/ COE:-

ICSI-Centre for Corporate Governance, Research and Training (ICSI-CCGRT) at Navi Mumbai

ICSI-Centre of Excellence (ICSI-CoE) at Hyderabad

C) Regional Office –

EIRO- Kolkata; NIRO- New Delhi; WIRO - Mumbai; SIRO – Chennai.

D) Chapters –

Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Bhilwara, Dombivli, Faridabad, Ghaziabad, Goa, NE-Guwahati, Hyderabad, Hooghly, Indore, Jaipur, Kanpur, Kolhapur, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mysore, Nagpur, Patna, Pune, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara.

II) Initiatives undertaken for improvement of Infrastructure

A) Head office

- i) **ICSI CoE-Kolkata** - The Institute had purchased 1.5 Acres of land from WBHIDCO at New Town, Kolkata for establishment of Centre of Excellence (CoE). The activities related to construction of premises (Academic Block and Hostel Block) like appointment of architect, submission of building plan to Local Authority for its approval, depositing the building plan sanction fees to concerned Authority, soil testing, obtaining approval of WBHIDCO for extension of allowable construction period, construction of boundary wall and short listing of contractors through Pre-qualification press notice have been completed. Finalization of tender documents (Technical Bid and Financial Bid) to be issued to the short listed contractors is in process.
- ii) **ICSI CERT-Manesar** – The Institute had purchased a plot measuring 1567.5 Sq. mtr. at Sector -2, IMT Manesar from HSIIDC. This land was initially procured for Gurgaon Chapter Office but later on it was decided by the Council at its 260th Meeting held on 4th & 5th May, 2019 to make it a headquarters project by converting it into a Centre of Excellence for Research & Training (CERT) and also for accommodating the activities of Gurgaon Chapter in the premises. The proposed premises (single block) will accommodate both academic and residential facilities. The activities related to construction of premises like appointment of architect, submission of building plan to Local Authority for its approval, soil testing and construction of boundary wall have been completed. Short listing of contractors through Pre-qualification press notice and finalisation of tender Documents (Technical Bid and Financial Bid) are in progress.
- iii) **ICSI HQ, at C-37, Noida** – The Repairing & Structural Strengthening of outside portion of entire building is almost completed and Renovation work of 1st and 2nd floors is nearing completion. After completion of renovation work of 1st and 2nd floors, renovation work of remaining floors will be taken up.
- iv) **CCGRT Building at Navi-Mumbai** – Structural Audit of the building before execution of Repairing & Renovation work has been completed in November, 2019. Selection of architect for the project is in progress.
- v) **CoE-Hyderabad** – Construction of the structure of entire premises (Institutional Block & Hostel Block) has been completed. In the first Phase entire Hostel Block, Reception, Ground floor (excluding Auditorium) and 1st floor of Institutional block were made operational in August, 2018. Now, in the second phase, the furnishing work i.e. the interior work of one Classroom, Computer Lab, Library, Toilets and Painting work of the complete 2nd floor will be taken up.
- vi) **CoE Ajmer** – Ajmer Development Authority (ADA) Vide letter dated 23rd September, 2013 allotted a plot of 24000 sq.yards jointly to three Professional Institutes (ICAI, ICSI & ICoAI) at Maharana Pratap Nagar, Ajmer for setting up Centre of Excellence for Quality & Ethics. Possession of the plot was taken over jointly on 28th September, 2013. Execution of lease deed is yet to be done. Both ICAI and ICoAI offered their share of land to ICSI. The ICSI accepted their offers. Thereafter, request has been made to

ADA for transfer of land i.e. share of other two Professional Institutes in favour of ICSI. The matter is under consideration of ADA.

- vii) **Solar Project** – On-grid rooftop Solar Panel System having capacity of 20 KW was installed and commissioned in Headquarters' building at Lodi Road. Order has already been placed for Installation and commissioning of on-grid rooftop solar panel system having capacity of 30 KW in Institute's building at C-36, Sector-62, Noida and Implementation of the same is in progress.

B) Regional/ Chapter Offices

i) ICSI-NIRC –

- *Roof-top Solar Project* – Order has already been placed for installation and commissioning of on-grid rooftop solar panel system having capacity of 25 KW and implementation of the same is in advanced stages of completion.
- *Rain Water Harvesting* – Feasibility study has been completed. Tender document is under finalization.
- *Lift*-Feasibility study for the replacement of the lift has been completed.

- ii) **Bhopal Chapter** - Built-up premises was acquired from Bhopal Development Authority (BDA) for use of office of Bhopal Chapter. The activities related to furnishing work of premises like appointment of Architect and award of work to the Contractor (vide Letter of Intent dated 1st September, 2020) have been completed.

- iii) **Coimbatore Chapter** – The activities related to construction of premises on plot of 13068 sq.ft like execution of rectification of Sale Deed, appointment of architect, finalization of building plan, soil Testing have been completed. Submission of Building plans to Local Authority for its approval is in process.

- iv) **Kochi Chapter**–The activities related to construction of new building like appointment of architect and receipt of Building permit for construction from the local authority have been completed. Demolition of existing building and Construction work are yet to be undertaken.

v) Jaipur Chapter –

- *Auditorium*–Committee has been constituted. Structural Audit for feasibility of creation of an Auditorium at the chapter in advance stage of completion.
- *Solar panel*- On-grid Roof top Solar panel system having capacity of 15 KW installed and commissioned.

vi) Bhilwara Chapter –

- *Guard Room*- Reconstruction of Guard Room was completed.
- *Solar panel*- On-grid rooftop Solar panel system having capacity of 12 KW installed and commissioned.

vii) Faridabad Chapter –

- *Building*- Balance work pertaining to the renovation of the building has been completed.
- *Solar panel*- Order has already been placed for installation and commissioning of on-grid rooftop solar panel system having capacity of 12 KW and implementation of the same is in advanced stages of completion.

viii) Pune Chapter –

- Work pertaining to making of classrooms sound proof has been completed and
- New furniture has been purchased and put to use.

- ix) **Raipur Chapter**- Possession of a plot of 3229 sq.ft. has been taken from Raipur Development Authority (RDA) for construction of premises for the Chapter. .

III) Priority Fixing for Acquisition of Land/Built-up property for Chapters as per approval of the Council.

- i) **Mangalore Chapter** – Invitation of Expression of Interest (EOI) for acquisition of premises was done and evaluation of the applications received is in progress.
- ii) **Ahmedabad Chapter** – Invitation of Expression of Interest (EOI) for acquisition of premises was done and evaluation of the applications received is in progress.
- iii) **Jodhpur Chapter** - Acquisition of land from Jodhpur Development Authority (JDA) is in process.
- iv) Priority fixing for Acquisition of Land/Built-up property/Construction of building was approved by the Council for Nagpur, Hooghly, Hyderabad, Aurangabad, Lucknow, Trivandrum, Vishakhapatnam, Shimla, Chandigarh, Rajkot, Surat, Agra, Ghaziabad, Kanpur, Prayagraj, Ludhiana and Noida Chapters.

3. HUMAN RESOURCE – STRENGTHENING TEAM ICSI**(1) Employee Development**

In order to enhance the capabilities & effectiveness of the employees to meet and exceed the expectations of the stakeholders and to provide better services, efforts have been made for continuous training and updation of knowledge & skills of the employees. Employees were sent for 23 training programmes /workshops /seminars/conferences from 01.04.2019 to 15.09.2020.

(2) Recruitment

Secretary of the Institute took charge with effect from 1st June 2020. Further, during the year under report 2 Directors and 1 Joint Director were appointed to strengthen the team.

(3) Staff Welfare Schemes

During the year, the following initiatives were taken:-

1. A rebate of 75% in all fees payable has been granted by the Institute to all its employees, their spouse and children for pursuing the 3 months certificate course on "Certified CSR Professional".
2. The ICSI Medical Hospitalization Trust Rules have been amended to include some diseases which do not require 24 hours hospitalization
3. The Institute had organized Health and Eye Check-Up camps for employees at HQ in the month of February, 2020.

(4) Employee Relations

As on 15.09.2020, the manpower strength of the Institute stood at 373 including 103 female employees which comprised 27% of the manpower strength. The relationship between Employees remained cordial and harmonious.

(5) Prevention of Sexual Harassment at Work Place

Report of Cases filed & their disposal under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 for the financial year 2019-2020:

S.No.	Description	HQ	NIRO & its Chapters	EIRO & its Chapters	WIRO & its Chapters, ICSI-CCGRT	SIRO & its Chapters, ICSI-COE, Hyderabad
(i)	Number of complaints of sexual harassment received	01	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Number of complaints disposed off	01	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(6) E- Performance Management System (e-PMS)

The Institute has implemented a web based performance management system for its employees for the year commencing from April 2020. The System among others has the following main features :

1. Performance Planning
2. Performance Evaluation
3. Analysis of unsatisfactory rating
4. Grievance redressal system

The e-PMS has been implemented for appraisal for the 1st and 2nd quarters of the year 2020 by the Directorate of Human Resource.

(7) Engagement of Young Professionals

ICSI has been engaging young professionals in its various directorates so as to get the assigned work in a time bound manner. During the year under report 17 young professionals were engaged under the scheme.

4. PROFESSIONAL DEVELOPMENT INITIATIVES

(i) WEBINARS

During the period under report a total of 51 webinars were conducted. The details of the same are as follows;

Date	Topic	Faculty
24 th May 2019	Form DPT 3 & MSME Form-I	<ul style="list-style-type: none"> • Mr. Chandan Kumar, Deputy Director, MCA • Mr. Shashi Raj Dara, Joint Director, MCA
17 th June, 2019	Recent developments in Companies Act, 2013(Form DPT-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Mr. Shashi Raj Dara, Joint Director, MCA • Shri Bhaskar Subramanian, Industry Principal, Infosys
4 th July, 2019	ICSI Auditing Standards -CSAS1-CSAS 4	<ul style="list-style-type: none"> • Members of ASB
12 th July, 2019	Recent Developments under Companies Act, 2013 (FORM BEN-2 and NFRA-1)	<ul style="list-style-type: none"> • CS Vinod Kothari, Practising Company Secretary
9 th October, 2019	eCSIN and UDIN	<ul style="list-style-type: none"> • ICSI Council Members
25 th February, 2020	Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus SPICe+	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Manoj Pandey, IRS, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri K.V.R. Murty, Joint Secretary, MCA • Mr. Surya, Assistant Director, MCA • Mr. K.M.S Narayanan, Assistant Director, MCA • Shri Bhaskar Subramanian, Industry Principal, Infosys
16 th March, 2020	Webinar on FEMA – FDI & ODI Contravention and Compounding	<ul style="list-style-type: none"> • CS Atul Mittal, Partner Deloitte Haskins & Sells
1 st April, 2020	Companies Fresh Start Scheme, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Shri K.V.R. Murty, Joint Secretary, MCA • Shri Bhaskar Subramanian, Industry Principal, Infosys • Shri K.M.S Narayanan, Assistant Director, MCA
3 rd April, 2020	Related Party Transactions	<ul style="list-style-type: none"> • CS Makarand Joshi, Practising Company Secretary
6 th April, 2020	Companies (Amendment) Bill, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. K S Ravichandran, Managing Partner, KSR & Co LLP
15 th April, 2020	CSR : The Practical Way	<ul style="list-style-type: none"> • CS Vinod Kothari, Practising Company Secretary
17 th April, 2020	Relaxations in holding Board Meetings and EGMs under Companies Act, 2013 during COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • CS S Sudhakar, Vice-President (Corporate Secretarial), Reliance Industries Limited
20 th April, 2020	Recent Amendments under the Companies Act, 2013	<ul style="list-style-type: none"> • CS (Dr.) D. K. Jain, Practising Company Secretary
22 nd April, 2020	Secretarial Audit – Audit & Reporting during Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> • CS K Sethuraman, Group Company Secretary and Chief Compliance Officer, Reliance

		Industries Limited
24th April, 2020	Positivity & Power of Thoughts	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Sri Sri Swami Veereshananda Saraswathi, President Ramkrishna Vivekananda Ashram, Karnataka
27th April, 2020	Recent Changes and Open Issues in GST	<ul style="list-style-type: none"> • CS Bimal Jain, Executive Consultant, A2Z TaxCorp, LLP
29th April, 2020	Balancing the Mind, Body and Soul	<ul style="list-style-type: none"> • Gurudev Sri Sri Ravishankar, Art of Living
30th April, 2020	Healthy living, Happy living	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Devi Prasad Shetty, Chairman and Founder Narayana Health
1st May, 2020	NCLT amidst Pandemic	<ul style="list-style-type: none"> • Hon'ble Mr. Justice A K Sikri, Former Supreme Court Judge • Hon'ble Mr. Balvinder Singh, Member, NCLAT • Hon'ble Mr. Jinan KR, Member NCLT Kolkata Bench
7th May, 2020	Mastering The Art of Work Life Balance	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs and Heavy Industries & Public Enterprises • CS(Dr.) Shyam Agrawal, Member, Appellate Authority and Past President, The ICSI
9th May, 2020	Dream, Dare, Deliver	<ul style="list-style-type: none"> • Ms. Priya Kumar, Motivational Speaker
11th May, 2020	Impact of COVID -19 on the Indian Economy: Opportunities & Threats	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Injeti Srinivas, Former Secretary, MCA
13th May, 2020	Determination and Disclosure of UPSI – Case Studies	<ul style="list-style-type: none"> • Shri V S Sundaresan Executive Director, SEBI
14th May, 2020	Yoga: Way to Manage Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Swami Ramdev, Yoga Guru • Dr. Girish Ahuja, Past Council Member, The ICSI • CS Satwinder Singh, Past Council Member, The ICSI
16th May, 2020	Transforming Challenges Into Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Amogh Lila Prabhu, Vice President, ISKCON Temple Dwarka
18th May, 2020	Aatmanirbhar Bharat The dawn of a new India	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha • Shri K J Alphons, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha • Shri Ashutosh Sharma, Secretary to the Government of India, Department of Science and Technology • Shri Atul Sobti, Director General, SCOPE • Shri Narayanan Sadanandan, MD & CEO, SBI Pension Funds Limited • Shri Nixon Joseph, President & COO, SBI Foundation • Shri Amit Goenka, Director, Winbrid Pvt Ltd & Executive Editor CSR Times
21st May, 2020	Social Media & its Role in Nation Building	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Priyank Kanoongo, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights • Shri Sunil Kumar, Director (HR & EB), MTNL • Prof Mukti Kanta Mishra, Co-Founder & President, Centurion University of Technology & Management • Shri Venkata K. Narayana, CEO Prestige Group, • Shri Rakesh Maheshwari, Scientist G and

		<p>Group Coordinator, Meity, GOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shri D K Aggarwal, President , PHDCCI
22nd May, 2020	SEBI LODR – A Journey So Far	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Khushro Bulsara, CGM Listing, BSE Limited • Shri Neeraj Kulshrestha, Chief Regulatory Officer, BSE Limited • CS B. Renganathan, Executive Vice President Edelweiss Financial Services Ltd • Ms. Ishita Sharma, Manager, Corporate Finance Department, SEBI
23rd May, 2020	Role of IEPFA in Investor Education & Protection	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Manoj Pandey, IRS, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Dr. Kamakhya Nr. Singh IEPFA Chair, Professor, IICA • Dr. Naveen J Sirohi Head, School of Finance, IICA
25th May, 2020	Crisis Management: The new age strategic professionalism	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Sandeep M. Tamgadge, IPS Addl. DGP, Nagaland
29th May, 2020	Fitness A way of life	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Kiren Rijiju, Hon'ble Minister of Youth Affairs and Sports (I/C) • Shri Gagan Narang, Olympic Medalist • Shri Manish Batavia, Sports Commentator • Shri Sandip Pradhan, IRS , Diector General, Sports Authority of India • Ms. Ekta Vishnoi(IRS), Mission Direct
5th June, 2020	World Environment Day: Time for Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Ms. Sumaira Abdulali, Environmentalist & Founder, Awaaz Foundation • Ms. Sunita Narain, Director General, CSE & Editor, Down to Earth • CS (Dr.) P V SJagan Mohan Rao, Past President The ICSI
8th June, 2020	MSMEs: The New Age Catalyst for Indian Economy	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India • Shri Rajiv Chawla, Chairman, Integrated Association of Micro, Small & Medium Enterprises in India
10th June, 2020	Youth for Nation Building	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Kiran Bedi, Hon'ble Lieutenant Governor of Puducherry • Shri Anil Gupta, Council Member (Govt. Nominee), The ICSI
13th June, 2020	Cyber Security Threats & Challenges	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Varun Kapoor, IPS, Additional Director of Police, Madhya Pradesh
16th June, 2020	Ordinary Faces, Extra Ordinary Work: Making difference in people's life	<ul style="list-style-type: none"> • Padam Shri Dr. Prakash Amte & Dr. Mandakini Amte, (Magsaysay Awardees, Social Worker Founder, Lok biradari Prkalp)
17th June, 2020	IT Empowerment for Corporate Leader	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Ajay Pandey, General Manager – IT Services Softel Solutions Pvt. Ltd. • Shri Rushabh Shah, VP (Marketing & Sales), SwarnimTouch Solutions Pvt. Ltd.
21st June, 2020	International Day of Yoga: Wellness & Immunity And Ghar Ghar Me Yog	<ul style="list-style-type: none"> • CS Preeti Malhotra, Preventive Healthcare Crusader, Chairperson, Smart Bharat Group, India, • Dr. Namrata Bagaria, Health Evangelist & Podcaster for Health 4.0, Canada, • Dr. Pamela Smith, Anti-Aging and Functional Medicine Specialist, USA

		<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Shabnam Das Kar, Specialist in Functional and Metabolic Medicine, Canada • CA Gopal Krishna Agrawal, Former CCM, Govt Nominee • CA Anil Gupta, CCM Govt Nominee • Prof Dr Tanuja Manoj Nesari, Director AIIA • CS Sudhir Jain, Yoga Trainer
27th June, 2020	Governance from Grassroots to Global	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Om Birla, Hon'ble Speaker, Lok Sabha • Prof. Ramesh Arora, Chairman, Development Academy & Former Prof. Department of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur • CS (Dr.) Shyam Agrawal, Member, Appellate Authority & Past President, The ICSI
3 rd July, 2020	Life Management Skills for Success	<ul style="list-style-type: none"> • Swami Avdheshanand Giri Ji Maharaj, Acharya Mahamandaleshwar of the Juna Akhara • Smt. Malini Laxman Singh Gaur, Former Mayor of Indore & Member of Legislative Assembly, MP
24 th July, 2020	Empowerment of the Company Secretary Profession: International View	<ul style="list-style-type: none"> • CS Nitin B Kotak, Strategic Finance and Business Consultant • CA Kunal Singhania, Bice President External Reporting, American Express, New York City • CS Lakshmi Kant Garg, Chairman ICSI Overseas Centre, USA • CS Renuka Raman, Vice- Chairperson, ICSI Overseas Centre, USA
11 th August, 2020	Corporate Governance and Leadership: Creating Synergistic Nexus	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. B S Sahay, Director, IIM Jammu • Mr. Rajeev Bhadauria, Co-Founder, My Transform • Dr. Jabir Ali, Professor Economics and Business Environment, IIM Jammu • Dr. Muqbil Burhan, Chairperson Executive Education, IIM Jammu • CA Rajat Jain, Chief Account Officer, IIM Jammu
22 nd August, 2020	Relaxations by SEBI during COVID-19 and SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Pradeep Ramakrishnan, General Manager, SEBI • Ms. Roshan Sara Cherian, AGM, SEBI
27 th August, 2020	Regulatory Regime for Nidhi Companies	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Rajesh Verma, IAS, Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri Manoj Pandey, IRS, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri S K Vashishtha, Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs • CS V Sreedharan, Past Council Member, ICSI
1 st September, 2020	National LIVE Webinar on EASE OF DOING BUSINESS	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Rajesh Verma, IAS, Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri Manoj Pandey, IRS, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri Gyaneswar Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri K.V.R Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs

4 th September, 2020	VC & OAVM Meetings : Law, Technology and People	<ul style="list-style-type: none"> • CS Sudhakar Saraswatula , Vice-President (Corporate Secretarial), Reliance Industries Limited
7 th September, 2020	Investor Education and Awareness	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Rajesh Verma, IAS, Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri Manoj Pandey, IRS, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri K P Krishnan, IAS, Former secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship & IEPFA Chair • Shri Navneet Chauhan, General Manager, IEPFA
8 th September, 2020	Joint webinar with ASSOCHAM on Investor Protection, Education and Awareness	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Manoj Pandey, IRS Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs • Shri J N Gupta, Former Executive Director, SEBI • Shri S K Jindal, Chairman, National Council on Commodity Markets, ASSOCHAM • Shri Lav Chaturvedi, Co- Chairman, Capital Markets & Investors Protection Council, ASSOCHAM • Ms. Mona Bhide, Managing Partner, Dave & Girish & Co. • Shri K Sukumaran, Former Dean, NISM • Shri Khushro Bulsara, Head – IPF, BSE Limited • Shri Rishi Nathany, Head BD & Marketing, MCX • CS Ashish Garg, President, The ICSI
10 th September, 2020	International Summit on India Corporate Governance Stewardship Jointly with ASSOCHAM	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Minister of State, Ministry of Corporate Affairs and Finance • Dr. M S Sahoo, Chairman, IBBI • CS Preeti Malhotra, Past President The ICSI • Dr. Niranjan Hiranandani, President, ASSOCHAM and Founder & Managing Director, Hiranandani Group of Companies • CS Ashish Garg, President, The ICSI • Mr. Vineet Agarwal, Sr. Vice President, ASSOCHAM and Managing Director, Transport Corporation of India Limited • Mr. Ashish Kumar Chauhan, MD & CEO, BSE Ltd. • Mr. Deepak Sood, Secretary General, ASSOCHAM • Ms. Kerrie Waring, CEO, International Corporate Governance Network (U.K) and Member Expert of Japan Financial Service Agency
12 th September, 2020	Webinar on Intricacies in filing of e-form PAS-6	<ul style="list-style-type: none"> • CS Makarand Joshi, Practising Company Secretary
16 th September, 2020	Webinar on Investment Opportunities and Challenges 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Shri Khushro Bulsara, Head – IPF BSE Limited • Mr. Rajeev Garg, Regional Head, BSE – North • Mr. Prateek Mohan, CDSL, Delhi • Mr Harbinder Singh Sokhi, BSE IPF

(ii) PCS Day (15th June)

This date is a reminiscence of show of faith, entrustment of confidence and a marking of instilment of greater responsibility in the practicing brigade of this profession, i.e., the Company Secretaries in Practice by the regulatory authorities and is celebrated across the nation with much fanfare.

PCS Day, 2019

Taking the spirit forward, the PCS Day was sprawled to an entire week in the year 2019 under which Pan India PCS Induction Programmes were organised at Regional Councils and Chapters during June 15-22, 2019

PCS Day, 2020

The celebrations of ICSI PCS Day were conducted through day-long deliberations with dignitaries from the Government and India Inc. on June 15, 2020. The Inaugural Ceremony was presided over by Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs and his address instilled amongst the members a new zeal to serve the nation.

(iii) National PCS Conference

The 20th National Conference of Practising Company Secretaries was organised at Bengaluru on 5th and 6th of July 2019 on the theme "Expanding Dynamics of professional Excellence". The Conference was attended by over 500 delegates. The Awards for Best Regional Council and Best Chapters for the year 2017 were also presented during the event. The event marked the launch of various significant initiatives of the ICSI of the likes of:

- a. Unique Document Identification Number (UDIN) Portal
- b. Employee Company Secretary Identification Number (eCSin) Guidelines
- c. Company Secretary in Practice – Ready Reckoner
- d. Best Secretarial Audit Report Award
- e. Revamped ICSI Website
- f. PCS Portal

(iv) Capital Markets Week – Redefining the Indian Capital Market-Vision 2022

In order to strengthen the structure of good governance in the capital market leading to a balance between economic and social goals, the Institute has been observing Capital Markets Week annually as one of the mega events throughout the country. Taking this initiative forward, the 'ICSI Capital Markets Week – 2019' was organised during August 9-17, 2019, on the theme 'Redefining the Indian Capital Market-Vision 2022'. Mega programs were organised at Kolkata, Chennai, Mumbai and New Delhi.

The mega program on the theme 'Amplifying Professional Horizons – Garnering National Growth' at Mumbai during the Capital Markets Week was observed in the presence of Shri G. Mahalingam, Whole Time Member, SEBI as Chief Guest and Shri Ashish Kumar Chauhan, Managing Director & CEO, BSE Limited as Guest of Honour on August 10, 2019.

(v) 47th National Convention of Company Secretaries

Organized under the theme 'Empowering New India – Reform, Perform, Transform', the 47th National Convention of Company Secretaries was held from 14th November, 2019 – 16th November, 2019 at the Jaipur Exhibition and Convention Centre, Jaipur, Rajasthan. The three day event was divided into multiple Technical and Special Sessions. The Inaugural Session was graced by Shri Ramcharan Bohra, MP, Jaipur. The Valedictory Session of the Convention was graced by Dr. Sudhanshu Trivedi, MP, Rajya Sabha, Dr. Satish Poonia, State President, BJP and Shri Ashish Chauhan, MD and CEO, BSE Limited. The dignitaries while acknowledging the role played by Company Secretaries guided the members and the ICSI with their motivating words.

(vi) 1st National Conference of Corporate CS

The two-day National Conference of Corporate CS was held at Mumbai on 4th-5th January, 2020. The Conference was inaugurated by Shri Bhagat Singh Koshiyari, Governor, Maharashtra. Keeping in sight the transforming role of professionals and the ever increasing need to strive for excellence, the theme for the Conference has been centred at 'Governance beyond Compliance: Expanding Horizons for Company Secretaries. Attended by around 500 participants from across the nation, the National Conference comprised

three Technical Sessions on areas of professional interest and various Motivational and Special Sessions. Two special sessions were dedicated to Expectations of the Board: CS as Catalyst to Board Functioning and Cyber Theft.

(vii) Celebration of 71st Republic Day – 2020

The Institute celebrated 71st Republic Day, 2020 on January 26, 2020 by organizing flag hoisting ceremony at the Headquarters, Regional Offices and Chapters Pan India. Various other events were organised across the Chapters and Regional Offices.

(viii) Celebration of International Women's Day – 2020

The ICSI celebrated International Women's Day on the 8th March, 2020, On the said day a Seminar was organised by Indore Chapter of the Institute. Ms. AryamaSanyal, Airport Director was the Chief Guest. The day was celebrated with much fanfare at various other ICSI Chapters and Regional Offices.

(ix) Fit India – Fit ICSI Walkathon

The Institute of Company Secretaries of India celebrated its Foundation Day on 4th of October, 2019 by aligning with the recently launched Fit India Movement. The ICSI organised Pan India 'Fit IndiaFit ICSI' Walkathon at all the Regional Councils and Chapter Offices of the Institute. Members and students along with their peers participated in the Walkathon which was flagged-off in the presence of dignitaries. The Fitness Pledge was also administered to propagate the adoption of a healthy lifestyle. The same was well appreciated by the Hon'ble President of India.

(x) 51st Foundation Day of ICSI

The 51st Foundation Day of the Institute of Company Secretaries of India was celebrated in the benign and gracious presence of **Shri Ram Nath Kovind, Hon'ble President of India** on 5th October, 2019 at VigyanBhawan, New Delhi. During his address, the Hon'ble President said that "Company Secretaries have played a seminal role in the development and growth of India; we are, indeed, proud of your contribution, hard work and success". Along with the First Citizen of the nation, Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Union Minister of State, Ministry of Corporate Affairs; Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises and Shri Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs presided over the event. The dignitaries while acknowledging the role played by Company Secretaries guided the members and the ICSI with their motivating words.

(xi) Sankalp se Siddhi – Single Use Plastic Free ICSI

The celebration of the Foundation Day of ICSI was a day of reiteration of the commitment towards its intended goals and towards building a sustainable nation and serving the society and stakeholders in an unprecedented manner. In pursuit of this vision and with the theme of India @ 75 – Sankalp se Siddhi in sight, the ICSI has stepped up to the responsibility and has intended to contribute to the national mission of 'Single use Plastic Free India' by launching 'Single use Plastic Free ICSI' initiative.

(xii) Three Days Online Workshop on Securities Laws & Capital Markets

The Institute organized a 3 Days Online Workshop on Securities Laws & Capital Markets during June 5-7, 2020. Hon'ble Mr. Justice Jog Singh, Former Judicial Member, SAT was the Chief Guest at the Inaugural Session. Aspects pertaining to Capital Markets, SEBI (LODR) Regulations, SEBI Act, 1992, Governance challenges, Insider Trading, etc. were deliberated. Total number of 432 participants participated in the programme.

(xiii) Programme for Familiarization of Independent Directors

The MCA & IICA launched the Independent Directors databank under the Companies Act, 2013 with an aim to strengthen the institution of Independent Directors. Keeping in view the role of IDs in strengthening the governance structure of India Inc., the ICSI in joint collaboration with IICA conducted a Programme for Familiarization of Independent Directors. The 3 hour Online Course was held on 20th June, 2020 covering aspects pertaining to the Due Diligence entailing in Becoming an Independent Director and Code of Conduct and Liabilities for Independent Directors. Total number of 346 participants participated in the programme.

(xiv) Two Days Online Workshop on New Dynamics New Opportunities

The Institute organized a first of its kind Two Days Online Workshop on the theme New Dynamics New Opportunities during May 23-24, 2020. Over 600 participants comprising Members and Students of the Institute participated in the Two Day Workshop. The deliberations during the two days covered contemporary

topics such as RERA, Arbitration, Secretarial Audit - Scope, Planning & Strategies, NGOs, Societies, Nidhi Companies, Producer Companies, CSR, FEMA, MSMEs. A motivational session on Embarking on a Journey towards Success & Satisfaction was also organized. Total number of 660 participants participated in the programme.

(xv) State level Conference on Investor Education and Awareness organized by IEPF Authority, Ministry of Corporate Affairs at Dharamshala on 20th December, 2019

The Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs, Government of India organized an State level Conference on Investor Education and Awareness and a Mega Career Awareness Programme, for the youth of Dharamshala, Himachal Pradesh. Hon'ble Union Minister of State, Ministry of Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur graced the occasion as the Chief Guest. The programme was intended to create awareness amongst the youth of Dharamshala regarding the various Investment and Career Opportunities as Company Secretaries available to them so that they can make an informed investment and career choice from among many. The programme was attended by more than 1200 delegates and received an overwhelming response and accolades. President and Vice-President has represented the Institute.

(xvi) Workshops and Events in partnership with PHD Chamber of Commerce and Industries (PHDCCI) and SCOPE

The Institute had played the role of Associate Partner in workshops organized by PHDCCI and Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE). The details of the same are as follows:

- (i) Sixth Conclave of the series on theme "Filing of GST Annual Return (GSTR -9) & GST Audit Report (GSTR - 9C) - Outward Supply & Input Tax Credit - Understanding Issues & Compliances Clause by Clause" on 7th June, 2019 at PHD Chamber House, Delhi.
- (ii) Recent Developments under Companies Act 2013 & SEBI Regulations on 10th June, 2019 at SCOPE, Lodi Road, New Delhi.
- (iii) Seminar on Latest Developments under Economic & Commercial Laws on 26th June, 2019 at PHD Chamber House, Delhi.
- (iv) GST Conclave on "Practical aspects of GST Annual Return (GSTR-9) and how to fill up the Form clause by clause" at PHD House, New Delhi.
- (v) Conference on Risk based Internal Audit : Good Governance Advisor on 19th July, 2019.
- (vi) GST Conclave on "Important Changes in Customs and GST – Union Budget 2019 and GST Outward Supply - Detailed analysis & discussion on various provisions with relevant Advance Ruling and GSTR-9 & 9C" on 24th July, 2019.
- (vii) Interactive Session on Recent Changes under the Companies Act, 2013 on 3rd December, 2019, at SCOPE Convention Centre, New Delhi.

(xvii) Relaxation in Guidelines for Compulsory Attendance of Professional Development Programmes for the Current Block 2017-20

In view of the advisory issued by the Government of India regarding COVID-19 and the lockdown imposed Pan-India, the time period for obtaining the mandatory PCH for the current block of 2017-20 has been extended to 30th September, 2020. Further, with a view to facilitate the members in obtaining the mandatory PCH (for the current block of 2017-20) the following measures have been taken:

- (i) Ceiling of maximum 8(eight) PCH through webinars is relaxed and the members shall be entitled for PCH through webinars without any limits.
- (ii) Members may also obtain upto 60 PCH by qualifying the online assessment modules.
- (iii) Members may also obtain 10 PCH for every PMQ/Certificate Course at the time of enrolment.
- (iv) Such members are allowed to make payment of annual membership fee, starting w.e.f. 1st April, 2020, on furnishing a declaration that they undertake to complete the shortfall in PCH requirement by 30th September, 2020.

(xviii) Facility of E-Credit hours

With a view to facilitate the members to comply with Guidelines issued by ICSI for attaining credit hours for the current block of three years ending on March 31, 2020, the Council has decided to grant the credit hours through e-learning programmes/ webinars, online exam and certification courses etc.

(xix) Launch of a special loan scheme for the members

The Institute facilitated an unique loan scheme for the Members of the Institute through Poonawalla Finance Private Limited. Loans are tailor made to meet their professional/ personal needs. The same is available without any Collateral or prepayment charges and Loan application process is completely online thus removing difficulties of physical visit.

(xx) ICSI (Continuous Professional Education) Guidelines, 2019

The Council of the Institute approved the amendment to the ICSI (Continuous Professional Education) Guidelines, 2019. These Guidelines replace the erstwhile Guidelines for Compulsory Attendance of Professional Development Programmes by the Members and have come into force from 1st April, 2020. These guidelines shall be mandatory for all the members irrespective of whether they are in practice or otherwise. It is mandatory for all members of the Institute, to secure 20 CPE Credits in a year through structured and unstructured learning program. However, no carry forward for excess Program Credit Hours from one year to another year will be allowed.

(xxi) ICSI Continuing Professional Education: Self-Assessment Modules

In an attempt to assist our members in fulfilling the necessary requirement of obtaining Programme Credit Hours, the Institute rolled out a unique initiative under the aegis of ICSI Continuing Professional Education: Self-Assessment Modules on 16th March, 2020. Under the initiative, members have an option to undertake online Examination in any of the six modules, as provided under the programme and obtain 10 PCH for each module qualified, for the block of three years 2017-20. The members can avail the benefit of the programme upto 30th September, 2020. As on September 15, 2020 total number of registrations under the programme were 2478.

(xxii) ICSI Online crash courses

Organizations as well as professionals faced challenges posed by pandemic. It is imperative for the professionals to get constant and updated knowledge even during the lockdown situation. ICSI, realizing the need of updated knowledge for members on evolving areas having impact on the profession of Company Secretaries has introduced online crash courses on:-

- (i) Compliances of Securities Laws
- (ii) Intellectual Property Rights
- (iii) Laws related to Arbitration and
- (iv) IT Tools for professionals
- (v) Insolvency and Bankruptcy Code
- (vi) National Company Law Tribunal
- (vii) Corporate Meetings
- (viii) Audits, Reports & Certifications
- (ix) Corporate Restructuring
- (x) Offences & Penal Provisions under CA, 2013

The objective of the ICSI Online Crash Courses is to provide quick and uninterrupted learning. These courses are delivered through interactive webinars and video based lectures followed by online assessment and project report submission for some courses. ICSI awards certificate to candidates on successful completion of the certificate courses. Commencing from April, 2020 onwards, the Courses have received overwhelming response and cumulative registration of more than 2286 members.

(xxiii) ICSI Certificate Courses:

- (i) Continuing Professional Development is the holistic commitment of your institute towards professionals for enhancement of personal skills and proficiency throughout their careers, allowing professionals to continually 'up skill' or 're-skill' themselves, the following certificate courses are being conducted by your institute in the year 2019-2020:
 - Certified CSR Professionals
 - Goods and Service Tax

- Forensic Audit
- PoSH(The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
- Women Directors
- Startup
- FEMA
- Commercial Contract Management
- RERA
- MSME
- Independent Director
- Cyber Security

- (ii) Total, 3482 number of candidates are registered in cumulatively these certificate courses for their continual development and updation of knowledge base.
- (iii) These courses are delivered through interactive webinars and video based lectures followed by online assessment and project report submission. ICSI awards certificate to candidates on successful completion of the certificate courses.

(xxiv) ICSI PMQ Courses

- (i) The Council has approved the launch of Post Membership Qualification Courses in the following areas:
- (i) PMQ Course on Internal Audit
 - (ii) PMQ Course on Arbitration
 - (iii) PMQ Course on CSR
 - (iv) PMQ Course on Labour Laws
- (ii) Further, the PMQ Course in Corporate Governance has been completely revamped and is being offered as per the revised modalities applicable to all PMQ Courses.
- (iii) The PMQ Courses has been revamped to make it more vibrant using technology. 25-30 hours of online web-based classes and Recorded Lectures on the subject will be provided. Further, reference material/study material will be provided. All the resources shall be available on the ICSI online Learning Management System platform.
- (iii) Further, the modalities of assessment has also been revamped whereby the MCQ based examination will be conducted online, it will be proctored that can be taken from anywhere and will be held twice a year i.e. June and December. Further,
- (iv) In addition candidates will be required to submit a Project Report is to be and make presentation which may be offline or online. The passing marks for each of these is 50%.
- (v) Admissions shall remain open throughout the year in online mode. Candidates registered between 1st January to 30th June – will be eligible to appear in same year December attempt of examination and candidates registered between 1st July to 31st December - will be eligible to appear in June attempt of examination.

5. FACILITATION AND STANDARDIZATION

(i) ICSI (Guidelines for Attire and Conduct of Company Secretaries), 2020

The intent behind these Guidelines is to provide the rules of etiquette and decorum for appearance before the courts, statutory bodies and quasi-judicial bodies such as NCLT, NCLAT, SEBI, CCI, etc., ensure respect for authority and to maintain dignity of the profession of company secretaries, prevent Company Secretaries from contemptuous behaviour to the judicial authorities and project a professional image amongst the regulators and build a brand for the profession of Company Secretaries. The said guidelines prescribe the following dress code :

For Male Members:

- a. Navy Blue Suit (Coat & Trouser), preferably with CS Logo/ Insignia OR Navy Blue Blazer over a sober coloured Trouser, Insignia
- b. Neck Tie (ICSI)
- c. White full sleeve Shirt d. Formal Shoes

For Female Members:

- a. Navy Blue corporate suit (Coat & Trouser), preferably with CS Logo/ Insignia OR
- b. Saree / any other dress of sober colour with Navy Blue Blazer with CS logo, Insignia c. A sober footwear like Shoes/Bellies/Wedges, etc.

(ii) The Institute of Company Secretaries of India (Protocol Guidelines), 2019

Another set of guidelines under the aegis of ‘The Institute of Company Secretaries of India (Protocol Guidelines), 2019’ provide for the protocol to be followed for orderly conduct of various programmes and other formal events of the Institute in a well planned and professional manner so as to accord a focused learning experience to the participants at every programme.

(iii) ICSI Expert Advisory Board Scheme

The ICSI formulated an Expert Advisory Board comprising 20 members as a conglomeration of experts from various fields including Corporate laws, Securities laws, legal advisory, finance, media and other relevant areas with rich Industry experience. The Board shall provide the advice and guidance in various matters pertaining to Corporate & Security Law. The Council of the Institute approved a Scheme for rendering/availing the services of the Board, such scheme is named as ICSI Expert Advisory Board Scheme, 2020.

(iv) Guidance Note on Prevention of Insider Trading

The existence of a fair, transparent and efficient securities market is one of the essential ingredients for economic growth of a country. To instil confidence, trust and integrity in the securities market, SEBI has taken various initiatives to ensure fair market conduct and promulgated the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations (“PIT Regulations”) 2015 to replace the earlier 1992 PIT Regulations. The ICSI, in its effort to promote good corporate governance brought out a Guidance Note on SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations under the aegis of Guidance Note on Prevention of Insider Trading, which aims to provide necessary guidance and detailing on the PIT Regulations, wherever necessary.

(v) Guidance on applicability of Secretarial Standards

Due to COVID-19 outbreak and lockdown situation prevailing in the Country, various provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under have been relaxed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for ease of compliance by the stakeholders.

Consequent to the relaxations granted by the MCA, queries of the members on the compliance of Secretarial Standard on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) were suitably addressed by issuing necessary guidance thereon. The guidance provided by the ICSI was voluntary in nature and was in line with the relaxations given by the MCA and will be applicable only for the period of relaxation so extended by the MCA. The said guidance on SS-1 and SS-2 has been circulated to all the members of ICSI and also made available on the website of ICSI to facilitate compliance of Secretarial Standards.

(vi) Guidance Notes on ICSI Auditing Standards

To facilitate compliance of the Standards by stakeholders and explaining practical aspects of various provisions contained in ICSI Auditing Standards, Guidance Notes on ICSI Auditing Standards were issued by the ICSI. These Guidance Notes on Auditing Standards have been formulated to set out the explanations, procedures and practical aspects of various provisions contained in ICSI Auditing Standards [CSAS-1 to CSAS-3] to facilitate compliance thereof by the stakeholders.

6. STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE

(i) CS Regulations

The Institute after the prior approval of Central Government has amended the Company Secretaries Regulations, 1982 vide the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020. Notification of Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020 dated 03rd February, 2020 is published in the Gazette of India dated 03rd February, 2020. The Company Regulations, 1982 amended upto date are available at website of the Institute.

(ii) Guidance Note on Annual Secretarial Compliance Report

Realising the need of growing Compliance Reporting mechanism in letter and spirit, the Indian Capital Market Regulator, SEBI came out with the Circular dated February 08, 2019 mandating Annual Secretarial

Compliance Report to be submitted by a Company Secretary in Practice to the listed entity on an annual basis, regarding compliance of all applicable SEBI Regulations and Circulars/ Guidelines issued thereunder. The Institute brought out this Guidance Note on 3rd April 2019 to sensitize the members of the Institute to accomplish the task to the utmost satisfaction of all the stakeholders. This Guidance Note highlights the process and scope of Annual Secretarial Compliance Report and also provides detailed checklists with respect to all mandatory laws as specified in the prescribed format by SEBI.

(iii) A Guide to Board Evaluation

Board evaluation is directly tied to achieving the outcomes and results outlined in the board's strategic plan. In view of the same, this publication discusses "the need and importance of board evaluation, international trends, legal framework in India, methodologies, steps involved, post-evaluation activities and barriers to board evaluation. The revised edition comprising international trends and practices in Board Evaluation and the prevailing legal framework in India, methodologies, parameters and other aspects shall serve as a perfect reference and guide in undertaking this activity. The publication was released at the Webinar held on the occasion of Independence Day on 15th August, 2020.

7. CAPACITY BUILDING

(i) Referencer on Boards' Report

The fact that the Board's Report is a significant document can be understood from the fact that not only has the document been mandated to be attached to the Financial Statements but the contents comprising the same have also been prescribed under the Companies Act, 2013. This Revised Referencer on Board's Report is a comprehensive document detailing the specimen formats, check lists, etc. which was released at the Webinar held on the occasion of Independence Day on 15th August, 2020.

(ii) Referencer on E-Form PAS-6

Every unlisted public company governed by Rule 9A of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 is required to submit Form PAS-6 to the Registrar within sixty days from the conclusion of each half year duly certified by a company secretary in practice or chartered accountant in practice. This Referencer on PAS-6 released at the Webinar held on the occasion of Independence Day on 15th August, 2020 is an endeavor to guide and facilitate the professionals on certification aspects of PAS-6. It addresses the practical issues faced while certifying PAS-6.

(iii) FAQs on Virtual Meetings

Given the situation of 'new normal' ushered in by the pandemic, the functioning of the India Inc., the adherence with the laws applicable while still holding its significance has shifted to the virtual modes. The Board meetings and other meetings have taken to the Audio and Video means. These relaxations accorded by the Regulatory Authorities have brought with them the need to acquaint not just with the technology but with the laws so as to ensure their compliance in the true letter and spirit. The Institute has brought out this publication on 9th September, 2020, with the intent of providing detailed insight into the aspects of conducting meetings through Virtual means.

(iv) Release of Compliance Software for PCS

Complinty is an integrated cloud-based Compliance Management Software for Practising Company Secretaries to help them manage their practice operations and manage their clients efficiently. The Institute has facilitated in the release of the said Compliance Software, which has been made available to all Practising Company Secretaries (PCS) by Complinty free of cost for the next 3 years. Complinty will immensely help the PCS to make the use of technology in Governance, Risk management and Compliance of their Clients.

(v) ICSI Guidance on Scale of Fees for various professional services rendered by Practicing Company Secretaries

This Guidance on Scale of Fees for various Professional Services containing *inter alia* the guiding principles for fixing the scale of fee would ensure transparency between the client and the PCS and also pave the way for a just and reasonable scale of fees to be charged by professionals on the basis of their experience, expertise, exposure, operational costs, associated risks, penalties for wrong certification and the market forces.

8. SELF- GOVERNANCE

(i) FAQs on eCSIN

Employee Company Secretaries Identification Number is a unique number which is mandatorily required to be generated by every member of the Institute who is in employment in any capacity at the time of appointment and at the time of resignation unless the same is exempted. Generation of eCSIN is a very simple process for which no document is required to be uploaded by the member. As a step towards regulation of the profession, the Council of the Institute of Company Secretaries of India issued the ICSI (Employee Company Secretaries Identification Number) Guidelines, 2019 which provides for generation of this unique number eCSIN. These guidelines were made effective from October 01, 2019. In an endeavour to facilitate the members in generation of eCSIN, the Institute came out with this booklet to provide guidance in the form of FAQs on 10th January, 2020.

(ii) FAQs on UDIN

Unique Document Identification Number is a unique number which is mandatorily required to be generated by every practicing member of the Institute at the time of issuing / certifying any document. Generation of UDIN is a very simple process for which no document is required to be uploaded by the member. As a step towards regulation of the profession, the Council of the Institute of Company Secretaries of India issued the ICSI Unique Document Identification Number (UDIN) Guidelines, 2019 which provides for generation of this unique number (UDIN). These guidelines were made effective from October 01, 2019. In an endeavour to facilitate the members in generation of UDIN, the Institute came out with this booklet to provide guidance in the form of FAQs on 10th January 2020.

(iii) UDIN Amnesty Scheme

A UDIN Amnesty Scheme valid from 1st September, 2020 till 30th September, 2020 was introduced wherein a PCS may:

- i. Generate the UDINs missed earlier
- ii. Rectify the UDIN details recorded at the time of generation
- iii. Revoke the UDINs not used.

Given the situations posed by the spread of global pandemic COVID-19 followed by nation-wide lockdown, the Scheme was initiated giving an online request window from 1st September, 2020 to 30th September, 2020.

(iv) ICSI Peer Review Mechanism

- (i) 11 Training Programmes for empanelment of Peer Reviewers were conducted across the length and breadth of the country, where around 70 members were empanelled as Peer Reviewers.
- (ii) During lockdown in the Country, two online training programmes on 17th May, 2020 and 22nd August, 2020 were conducted where more than 300 members participated.
- (iii) During the year 2019-20, 45 peer reviewers were empaneled and 64 peer reviewers were empaneled from 01.04.2020 to 15.09.2020 and as on date there are 610 peer reviewers.
- (iv) During the year 2019-20 approximately 153 Practice Units were reviewed under the Guidelines for Peer Review of Attestation and Audit Services by Company Secretary in Practice and Peer Review Certificates were issued to them.
- (v) During the period from April 1, 2020 till August, 2020 approximately 135 Practice Units have been reviewed and certificates issued. As on date there are 784 number of Peer Reviewed Units..
- (vi) The 3rd revised edition of Peer Review Manual was released at 47th National Convention held at Jaipur during 14-16 November, 2020.

9. QUALITY REVIEW BOARD

- (i) To assist Quality Reviewers in performing their duties while conducting Quality Review, a Guide to Conduct Quality Review was released at National Corporate Governance Award, 2019 ceremony held at New Delhi on 10th January, 2020.

(ii) *Re-constitution of Quality Review Board:*

As per Rule 8(1) of Company Secretaries (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board) Rules, 2006 the tenure of the Chairperson and members of the Quality Review Board shall be four years.

- (iii) Accordingly, the tenure of the following members of the Board completed their tenure during the year 2019-20:

- Ms. Kiran Oberoi Vasudev Chairperson
- Mr. Ashish Kushwaha Member
- Mr. Vineet K. Chaudhary Member

Further, CS Ilam Kamboj resigned during the year.

- | | | |
|------|--|-------------|
| (iv) | The Institute acknowledges their invaluable contribution and initiatives towards enhancement and maintenance of the Quality of Professional Services rendered by the members. | |
| (v) | The Ministry vide Gazette Notification No. G.S.R.339 (E) and G.S.R.33 (E) dated 1 st June, 2020 and 14 th January, 2020, respectively appointed the following members on the Quality Review Board. | |
| | • Ms. Nishi Singh, Ex-Member, CBDT | Chairperson |
| | • Shri Devendra Kumar, Advisor (Cost), Ministry of Corporate Affairs | Member |
| | • Shri Manish Gupta, Council Member, Institute of Company Secretaries of India. | Member |
| | • Shri Pramod Kumar Rai, Deputy Company Secretary, Nestle India Ltd. | Member |

(vi) Quality Review undertaken

The Review of Quality of professional services rendered by Secretarial Auditors of Nifty50/BSE30 companies and the members in practice against whom disciplinary action was initiated under the direction of Quality Review Board

10. REPRESENTATION OF ICSI AT VARIOUS COMMITTEES FORMED BY THE GOVERNMENT / REGULATORY AUTHORITIES

(i) Primary Market Advisory Committee of the Securities and Exchange Board of India (SEBI)

With the aim and objective to advise SEBI on issues related to regulation and development of primary market in India and to ensure simplification and transparency in systems and procedures in the primary market, the Securities and Exchange Board of India has formed the Primary Market Advisory Committee (PMAC), consisting of experts from related fields. The Institute is a representative member of PMAC, and the meetings of the same are held at SEBI Bhawan, Mumbai.

(ii) Committee to Advise on Valuation Matters constituted by the Ministry of Corporate Affairs and administered by IBBI

The Ministry of Corporate Affairs had constituted a “Committee to advise on Valuation matters” to make recommendations to the Central Government on formulations and laying down of valuation standards and policies for compliance by companies and registered valuers. The ICSI-RVO is represented by the President, ICSI in the said Committee. The report has been submitted by the Committee

(iii) Insolvency Law Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs to recommend amendments to Insolvency and Bankruptcy Code of India

The provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code are evolving as a result of various judicial pronouncements and amendments made in the Code. Keeping in view the dynamic nature of the issues involved in the implementation of the Code, the Ministry considered the re-constitution of the Insolvency Law Committee as Standing Committee for review of implementation of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The President, ICSI is a member of the said Committee.

(iv) High Level Committee of the Ministry of Corporate Affairs on Corporate Social Responsibility

A High Level Committee on Corporate Social Responsibility-2018 (HLC-2018) was constituted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to review the existing framework and to guide and formulate a coherent policy on Corporate Social Responsibility (CSR). The President, ICSI was the special invitee to share the views of ICSI and its stakeholders on the future of CSR. The Report for the same has been submitted.

(v) **Committee for finalizing the Business Responsibility Reporting (BRR) Format for Listed and Unlisted companies**

The Ministry of Corporate Affairs had constituted a Committee in 2018 for finalizing the Business Responsibility Reporting (BRR) Format for Listed and Unlisted companies based on the BRR Framework of the updated NGRBCs, i.e., National Guidelines on Responsible Business Conduct issued in March, 2019 under the Chairmanship of Mr. Gyaneshwar Kumar Singh, Joint Secretary. The Report has been formally

released for the stakeholders by Shri Rajesh Verma, Secretary, Ministry of Corporate Affairs on 11th August, 2020. The President, ICSI is a member of the Committee and the ICSI has played a significant role in drafting of the BRR format.

(vi) High Level Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for preparation of investigation manual for Serious Fraud Investigation Office (SFIO)

Ministry of Corporate Affairs constituted a High Level Committee for preparation of the Investigation Manual for strengthening the process of Investigation by SFIO under the Chairmanship of Secretary, MCA. The President, ICSI is a member of the Committee. Meetings of the Committee were held on March 16, 2020 and May 26, 2020 and detailed deliberations on the contents of the investigation manual were held during the meetings.

(vii) Committee on the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India by Insurance Development and Regulatory Authority of India (IRDAI)

The IRDAI had issued the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies in India in the year 2016. In the light of the same, the Authority, in order to review the Guidelines and to make it more effective and robust, constituted a Committee to review the Guidelines for Corporate Governance for Insurers and suggest changes. ICSI is representing the Institute at the Committee. Meeting of the Committee was held on May 28, 2020 and suggestions were invited from them.

(viii) Consultation Committee of GSTN

The Goods And Services Tax Network has constituted Consultation Committee of GSTN for simplification of existing process and procedures in GST and taking feedback on various emerging issues. ICSI is representing in the Committee. The meeting of the Committee was held on July 14, 2020 and September 4, 2020.

(ix) Standardization Cell of Ministry of Corporate Affairs for Bureau of Indian Standards (BIS)

A Standardization Cell for the Ministry of Corporate Affairs has been set-up under the Chairmanship of Economic Adviser. The major functions of the Standardization Cell include identification of relevant experts for standardization in different sectors. The Secretary, ICSI is a member of the Committee.

(x) Accounting and Finance Services Sectional Committee of Bureau of Indian Standards (BIS)

Keeping in mind the growing importance of Services Sector in Indian and Global economy, BIS has established a dedicated Division Council (Services Sector Division Council - SSDC) for the work related to standardization in Service Sector areas, specially the 12 Champion Service Sectors as identified by the Ministry of Commerce and Industry. Under this Division Council, one of the Sectional Committee is 'Accounting and Finance Services Sectional Committee', the scope of the Committee is standardization in the field of accounting and financial services. The Vice President, ICSI is representing the Institute in the Committee.

(xi) Committee on Start ups constituted by the Ministry of Corporate Affairs(MCA)

A Committee has been constituted by MCA to deliberate and discuss various issues raised by certain startups pertaining to aspects of the various laws encasing them and seeking clarity thereon. ICSI is representing in the Committee. Meeting of the Committee was held on March 16, 2020 to resolve the various issues being raised by the StartUps.

(xii) Committee to review the compliances under the Companies Act, 2013 and LLP Act, 2008 constituted by the Ministry of Corporate Affairs(MCA)

The MCA had constituted a Committee to examine the provisions of the Companies Act, 2013 and LLP Act, 2008 and Rules there under with the objective of scrutinizing the relevance and requirements of various compliances and rationalizing, reducing, and simplifying the related processes. The Committee is chaired by Shri M M Juneja, Regional Director, MCA. The ICSI is member of the Committee. Meeting of the Committee was held on August 20, 2020 to review the various compliances and rationalizing, reducing and simplifying the related processes.

(xiii) Committee to look into regulatory regime for Nidhi Companies

The MCA had constituted a Committee to examine regulatory regime with reference to Nidhi Rules and to recommend amendments, if any. The Committee is chaired by Shri Manoj Pandey, Joint Secretary, MCA. The President, ICSI is a member of the Committee. One meeting of the Committee was held on September

15, 2020 and wherein detailed deliberations on monitoring and compliance mechanism for Nidhi Companies were held.

11. ICSI TASK FORCES

(i) Task Force on Banking and Finance Sector

The ICSI has constituted a Task Force on Banking and Finance Sector to explore and identify the areas where Company Secretaries can render services to the banking and finance industry and to suggest measures for the capacity building of the members to take-up these future assignments. The Task Force is being chaired by Shri DK Mittal, Ex-Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The first meeting of the Task Force was held on July 14, 2020 to deliberate upon the suggestions of the Institute on the discussion paper of RBI on Governance of Commercial banks in India

(ii) Task Force on Labour Laws

The Institute has constituted a Task Force on Labour Laws to deliberate upon the Labour Codes for giving suggestions and views from ICSI on the same and exploring opportunities for Company Secretaries in Labour Laws. The Task Force is being chaired by Ms. Sudha Pillai, Former Secretary, Ministry of Labour and Employment. Meetings were held on October 22, 2019, November 26, 2019, January 27, 2020 and August 4, 2020 to deliberate upon the suggestions of the Institute on the four labour codes and the Code on Wages (Central) Rules, 2020.

(iii) Core Group on NCLT

ICSI has constituted a Core Group on NCLT. The objective for the constitution of this Core Group inter-alia is to upgrade the representation and advocacy skills of Company Secretary Professionals and to suggest standardization of diverse practices being followed at various NCLT benches. The Core Group is being chaired by Chief Justice (Retd.) Shri M M Kumar, Hon'ble President, NCLT. The meeting of the Task Force was held on August 22, 2020 to deliberate upon the up gradation of the representation skills of Company Secretaries and also the standardization of the diverse practices being followed at various NCLT Benches.

(iv) Task Force on Nidhis

Keeping in view to revisit the provisions of Nidhi rules and to suggest monitoring mechanism to MCA, task force on Nidhis was constituted. Meeting of the task force was held on February 6, 2020 to revisit the provisions of Nidhi rules.

(v) Core Group on Secretarial Audit

A Core Group comprising Senior Practitioners, Bureaucrats and Company Secretaries in Employment has been constituted to revisit the existing format. The report of the core group has been submitted to the MCA.

(vi) Task Force on Start Ups, MSME & Ease of Doing Business

The Task Force has been constituted to create awareness amongst Start Ups and MSMEs about the role of Company Secretaries in their entrepreneurial pursuits and to set up help desks/ contact centers in this regard at various institutions across the country. The meeting of the Task Force was held on October 21, 2019 to deliberate on the various initiatives to support MSMEs & Start Ups and also to organise capacity building programmes for Company Secretaries to render customised and focused professional services to Start Ups & MSMEs.

(vii) Task Force on Company Law

The Institute has constituted a Task Force on Company Law to deliberate upon the draft rules, practical difficulties under the Companies Act for giving suggestions and views from ICSI on the same and exploring further opportunities for Company Secretaries in Company law. The meetings of the Task Force were held on January 4, 2020, November 22, 2019, October 3, 2019, September 24, 2019, August 16, 2019 and July 31, 2019 to deliberate upon various practical difficulties being faced under Companies Act, 2013 and the suggestions of the ICSI on the draft rules under the Companies Act, 2013.

(viii) Core Group for Central Registration Centre (CRC)

The ICSI has constituted a Core Group for CRC to consider and deliberate on the matters relating to recruitment and training of CRC Executives, and to fulfill the terms mentioned in the MOU entered between the ICSI and MCA.

(ix) Sub-group on Referencer on MCA E-forms

The Institute has constituted a Sub-group on Referencer on MCA E-Forms comprising of Company Secretaries both in employment and in practice Chairman, PCS Committee to provide necessary guidance to members by way of updating the Referencer on MCA E-Forms. It is an endeavour of knowledge updation and capacity building of members to equip them to comply with the regulatory developments. The meetings of the Sub Group were held on 18th July, 2020, 20th July, 2020, 23rd July, 2020 and 31st August, 2020 to deliberate upon revision in Referencer on MCA E-Forms.

(x) Core Group to review the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India

The IRDAI has constituted a Committee to review the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India. A Core Group has been constituted by the ICSI to provide feedback/suggestions on the Corporate Governance Guidelines for Insurers in India. The meeting of the Task Force was held on 26th August, 2020 to deliberate upon the suggestions on Corporate Governance Guidelines for Insurers in India.

12. RECOGNITIONS, SUGGESTIONS AND REPRESENTATIONS**(i) Recognitions received**

- **Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019**

Company Secretaries in Practice have been included of in the 'Qualification and Experience of Arbitrator' in the Eighth Schedule to the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019.

- **Actuarial Profession**

- Company Secretaries have been accorded relaxation in the condition of entry to actuarial profession from the Institute of Actuaries of India (IAI) - A Statutory body established under an Act of Parliament.

- **Net Worth Certificate**

- Company Secretaries in Practice have been authorized to issue the Net Worth Certificate to be submitted by the issuer at the time of admitting securities in demat form as per the requirement of NSDL.
- Company Secretaries in Practice have been authorized to issue the Net Worth Certificate to be submitted by the issuer at the time of admitting securities in demat form as per the requirement of CDSL.

- **Secretarial Audit**

- SEBI vide circular dated 8th February, 2019 has authorized Company Secretaries in Practice to conduct Secretarial Audit of every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India
- Company Secretaries in Practice have been authorized to conduct the Secretarial Audit of every Company having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of one hundred crore or more under Section 204 of the Companies Act, 2013.

- **Pre-Certification of E form**

- Authorization to Company Secretaries in Practice for Half yearly reconciliation certificate for unlisted public companies in e Form PAS 6 under Rule 9A of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014

- **Authorized Collection Centre**

- Authorization to Company Secretaries in Practice to act as Authorized Collection Centre in the State of Gujarat.

(ii) Representations submitted for gaining recognitions or seeking relaxations from the compliances of various provisions:

- **TO MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS:**

- Request for relaxation in filing of forms and certain compliances under the Companies Act, 2013.
- Request for Secretarial Audit for Bigger companies under the Companies Act, 2013
- Request for amendment to Rule 8A to (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2020 notified on 3rd January, 2020
- Request for inclusion of ICSI UDIN and eCSINunique numbers in the e-forms.
- Request for Deployment of e-Form PAS-6
- Request for Filing of Form INC-22A
- Request to allow filing of resignation of company secretary in case of company under liquidation
- Request for filing of Form DPT-3: need for uniformity in procedure
- Request for Pre-certification of e-forms under the Companies Act, 2013
- Request on amendment to Section 137 (1) of the Companies Act, 2013, enabling filing of financial statement within sixty days
- Request for extension of last date for filing of DIR-3 KYC under the Companies Act, 2013
- Request to allow extension of time for filing e-forms under the Companies Act, 2013 for the companies in the State of Odisha due to severe cyclone – Fani - 2019
- **TO SEBI:**
 - Request to consider Peer Reviewed Company Secretary in Practice (PCS) for engagement by an administrator while discharging his functions under Regulation 7 (2) (a) of the SEBI (Appointment of Administrator and Procedure for Refunding to the Investors) Regulations, 2018.
 - Representation relating to issue of Secretarial Audit and Annual Secretarial Compliance Report by a Peer Reviewed firm of Company Secretary in Practice submitted to Shri G Mahalingam, Whole Time Member, SEBI.
- **Labour Laws:**
 - To consider Company Secretaries in Practice for empanelment as expert for conducting Third Party Audit and Certification under Section 37 of the proposed 'The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019'- Submitted to Shri Bhartruhari Mahtab, Hon'ble Chairperson, Standing Committee on Labour
 - To consider formulation of Third Party Certification/ Audit Scheme in the State of Madhya Pradesh and to authorize Company Secretaries in Practice submitted to Shri Kamal Nath, Hon'ble Chief Minister, Madhya Pradesh
- **GST Law:** Request to authorize Company Secretary to conduct Audit u/s 35(5) & Special Audit u/s 66 of the CGST Act, 2017 and to certify Form GSTR-9C u/r 80(3) of CGST Rules, 2017- Submitted to Shri Rajeev Ranjan, Special Secretary and Shri S K Rahman, Joint Secretary GST Council Secretariat. Representation was also submitted to Shri Yogendra Garg, Principal Commissioner, GST. Several representation have also been submitted to respective states for conducting the Audit.
- **Consumer Protection Act, 2019:** To allow Company Secretaries as Authorized Representatives and consider the qualification of Company Secretaries for empanelment as Mediator under the Consumer Protection Act, 2019 a representation was submitted to Shri Raosaheb Patil Danve, Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
- **Authorised Collection Centre for e-stamping:** Request to authorize Company Secretaries to act as Authorized Collection Centre (ACC) for e-stamping Submitted to Principal Secretary (Revenue)-cum Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi and also letters were sent to twenty-one States and UTs
- **PFRDA:** Request to authorize Company Secretaries in Practice to issue Certificate of Compliance under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations 2018

read along with Circular No. PFRDA/2019/13/REG-POP/1 dated June 17, 2019 submitted to Shri Ravi Mital, Chairman, Pension Fund Regulatory and development Authority.

- **POSH:** Request to introduce mandatory Compliance Certificate under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder and authorise Company Secretaries in Practice
- **IRDA:** Request for recognition to Company Secretaries under Regulation 34(7) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 submitted to Dr. Subhash Chandra Khuntia, Chairman, IRDA.
- **DRT and DRAT:** Request to authorize Company Secretary in Practice to appear before the Debt Recovery Tribunal (DRT) and Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) submitted to Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs.
- **Miscellaneous:**
 - Request to consider Company Secretary in Practice to conduct internal audit of Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) at par with other professionals-submitted to Gujarat Urja Vikas Nigam Limited
 - Request to appoint Company Secretary on the pay roll of the Public Sector Undertaking submitted to Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State (Heavy Industries and Public Enterprises)

(iii) Suggestions and Views of ICSI submitted:

a. TO MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS:

- i. Comments on draft Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2020.
- ii. Comments on (Compromise, Arrangements and Amalgamation) Amendment Rules, 2019.
- iii. Submissions on draft e-Form relating to CSR of Ministry of Corporate Affairs.
- iv. Views and suggestions on decriminalisation of offences under LLP Act, 2008.
- v. Views and suggestions on Draft Valuers Bill, 2020.
- vi. Views and suggestions on the Competition (Amendment) Bill, 2020.

b. TO SEBI:

- i. Views and Suggestions on SEBI Consultation Paper on SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993.
- ii. Views and Suggestions on SEBI Consultation Paper on SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993.
- iii. Comments on the SEBI Report of the Working Group on Related Party Transactions.
- iv. Suggestions of ICSI on the SEBI Consultation Paper on 'Review of the Regulatory Framework for Corporate bonds and Debenture Trustees'.
- v. Comments on the 'SEBI Consultative Paper with respect to guarantees provided by a listed company'.
- vi. Comments on the SEBI Consultation Paper on "Pricing of Preferential Issues and exemption from open offer for acquisitions in Companies having Stressed Assets".
- vii. Suggestions on the SEBI Consultation Paper on 'Review of Regulatory Framework for Investment Advisers' (IA) submitted to SEBI.
- viii. Views and suggestions on Report of the SEBI Social Stock Exchange Working Group.

c. TO MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS:

- i. View and suggestions on the Consumer Protection (Mediation) Regulations, 2019

- ii. Views and Suggestions of ICSI on the Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020 submitted to Department of Consumer Affairs.
- iii. View and suggestions on the Draft Rules under the Consumer Protection Act, 2019 submitted to Department of Consumer Affairs

d. TO THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

- i. Views and suggestions on draft Code on Wages (Central) Rules, 2019.
- ii. Suggestions on the draft Code on Social Security, 2019.
- iii. Views and suggestions of the Institute under Industrial Relations Code, 2019.
- iv. Views and suggestions on the Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020.

e. TO OTHER AUTHORITIES

- i. Views and suggestions of the ICSI on Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020 have been submitted to Ministry of Power including the suggestion to recognize Company Secretaries in the relevant clauses of the Bill.
- ii. Views and suggestions on the RBI Discussion Paper on Governance in Commercial Banks in India - Submitted to Reserve Bank of India.
- iii. Views and suggestions on the Draft Pension Fund (Foreign Investment) Rules, 2020 - Submitted to Department of Financial Services, Ministry of Finance.
- iv. Views and suggestions on the Draft Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020 - Submitted to Secretary, Petroleum & Natural Gas Regulatory Board.
- v. Views and suggestions on the Draft Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2020 - Submitted to Secretary, Central Electricity Regulatory Commission.
- vi. Suggestions on De-criminalisation of offences under GST Law submitted to Ministry of Finance.
- vii. Suggestions of ICSI on 'RBI draft framework for recognition of a Self-Regulatory Organisation (SRO) for Payment System Operators' submitted to RBI.

(iv) Representations Submitted for seeking relaxations from the compliances of various provisions due to COVID 19

(i) TO MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

- i. Request for relaxation in filing of forms and certain compliances under the Companies Act, 2013 due to COVID -19
- ii. Request for amendment in Rule 4 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 to allow companies to consider the restricted matters at meetings of the Board conducted through video conferencing or other audio visual means in accordance with Rule 3 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014
- iii. Request for relaxation in holding meeting through video conferencing and other audio visual mean for restricted matters, in view of travel restrictions on account of global pandemic lockdown
- iv. Request for relaxation in filing e Form MGT 14
- v. Request for extension of LLP Settlement Scheme, 2020 and Companies Fresh Start Scheme, 2020
- vi. Request for relief under the Companies Fresh Start Scheme, 2020
- vii. Request for extension for holding AGM due to Covid-19
- viii. Request for relaxation in filing of forms and certain compliances under the Companies Act, 2013 due to Covid-19

(ii) TO SEBI:

- i. Request for extension of time for filing of Annual Secretarial Compliance Report under Regulation 24A of SEBI(LODR) due to the COVID-19 pandemic

- ii. Request for relaxation from compliance with the provisions of Regulation 76 of the SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- iii. Representation in connection with issuing clarification regarding the use of digital signatures w.r.t. authentication/certification of any filing/submission made to stock exchanges under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to the COVID-19 pandemic.

(iii) TO NSDL and CDSL

Representation to NSDL and CDSL for relaxation in time period for filing of quarterly return of reconciliation of capital by Listed Entities for the quarter ending on March 31, 2020.

(iv) TO RBI

Request for relaxation from compliance with provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) due to the COVID-19 pandemic submitted to Reserve Bank of India.

(v) TO GST COUNCIL

Request for amendment in GST law due to COVID-19 submitted to Smt. Nirmala Sitharaman, Chairperson, GST Council.

13. INTERNATIONAL FOOTPRINTS

(i) International Centres

➤ **Launch of ICSI Overseas Centre, USA**

ICSI Overseas Centre, USA was launched on 12th October 2019. The Committee of Members of the ICSI Overseas Centre, USA was constituted with following members:

- (i) CS Lakshmikanth Garg, Chairperson
- (ii) CS Renuka Raman, Vice Chairperson
- (iii) CS Chandramouli Subramaniam, Secretary
- (iv) CS Hiren Jagdishbhai Mistry, Treasurer
- (v) CS Prafulla Kumar Kacholia, Member
- (vi) CS Vinita Sithapathy, Member
- (vii) CS Neena, Member

➤ **Inauguration of ICSI Overseas Centre, United Kingdom (UK)**

The ICSI inaugurated the ICSI Overseas Centre, United Kingdom on 24th August, 2020, in the benign presence of Ms. Smriti Zubin Irani, Hon'ble Union Minister for Women & Child Development and Textiles. The objective of setting up ICSI Overseas Centre, UK to strengthen the global outreach of the profession. The ICSI Overseas centers would augment professional opportunities for ICSI members and students internationally.

The ICSI Overseas Centre, UK will function with the following Committee of Members:

- i. Inderpreet Kaur Bedi, Chairperson
- ii. Manish Temani, Vice-Chairperson
- iii. Somya Rastogi, Secretary
- iv. Janak Popatlal Prajapati, Treasurer
- v. Deepa Grace Goudar, Member
- vi. Srikant Kankanala, Member
- vii. Sukhpreet Kaur Makkar, Member

The Institute is in process of setting up the Overseas Centre in Singapore, Australia and Canada to facilitate its Stakeholders.

(ii) Asia Sustainability Reporting 2019

ICSI representatives participated in Asia Sustainability Reporting Summit 2019 held on 4-5 September, 2019 at Singapore. The theme for the Summit 'Sustainability Reporting: Is Mandatory Better' reflected upon the growing trend of legislating ESG disclosures around the world. The Summit focused on best practices in sustainability reporting and emerging topics. ICSI delegation has also explored the opportunities to open overseas center at Singapore.

(iii) CSIA Council Meeting and ICSI-CSIA Conference 2019

ICSI hosted the Council meeting of Corporate Secretaries International Association Limited (CSIA) on 9-10 September, 2019. CSIA is an international federation of professional bodies based at Hong Kong, representing fourteen Corporate Secretaries Institutions from Australia; Bangladesh; Brazil; Canada; Hong Kong; India; Kenya; United Kingdom; Malaysia; Nigeria; Singapore; Southern Africa; USA; Zimbabwe and represents membership span of around 1,00,000 Corporate Secretaries. It creates platform for Governance Professionals to promote best practices in Corporate Secretarial, Corporate Governance and Compliance Services. ICSI is representing India in CSIA.

On 11th September, 2019, ICSI-CSIA conference was organized on the theme “Redefining Global Governance - Dawn of a New Era” at New Delhi. The Conference was hosted by NIRC-ICSI and was attended by Company Secretaries and Governance professionals from India and other Countries.

(iv) Leadership Role in CSIA

CS Ranjeet Pandey, the then President, ICSI was unanimously elected as the Vice-President of CSIA for the year 2020.

CS Ashish Garg, President, ICSI has been unanimously elected as the President of the CSIA for the year 2021.

(v) Meeting with President, Institute of Chartered Secretaries & Administrators of Nigeria

Mr. Bode Ayeku, President, Institute of Chartered Secretaries & Administrators of Nigeria visited the ICSI Headquarters, New Delhi on 26th September, 2019 to discuss the issues of mutual interest and also to seek guidance on Board Evaluation and Corporate Governance Evaluation from ICSI. Board Evaluation and Corporate Governance Evaluation were recently introduced in Nigeria.

(vi) Annual Conference of Malaysian Association of Company Secretaries (MACS) 2019

On the invitation of Malaysian Association of Company Secretaries (MACS), ICSI representatives participated in Annual Conference of MACS 2019 held at One World Hotel, Bandar Utama, Petaling Jaya, Malaysia on 18-19 September, 2019 with the theme “Company Secretaryship in the Digital Landscape- Challenges & Transformation”. President, ICSI addressed the delegates in Plenary Session on “Cyber Risk” which was very much appreciated by the delegates. MACS launched Secretarial Practice Guide on meetings of the Board of Directors by adopting ICSI Secretarial Standard (SS-1).

(vii) MACS Secretarial Practice Guide (MSPG 2) on meetings of Members of Private Companies

Malaysian Association of Company Secretaries (MACS) completed the second MACS Secretarial Practice Guide (MSPG 2) on meetings of members of private companies. MSPG 2 adopted Secretarial Standard (SS-2) on General Meetings of ICSI for its benchmark.

This Practice Guide was developed and prepared based on the Malaysian Companies Act, 2016

(viii) Incorporation of ICSI Middle East (DIFC) NPIO

- a. The ICSI incorporated ICSI Middle East (DIFC) NPIO as a Non Profit Incorporated Organization under the Non Profit Incorporated Organization Law, DIFC Law No. 6 of 2012 of Dubai on September 24, 2019, with following founding members and board:
 - i. Ms. Bhawna Srivastava, Chairperson
 - ii. Mr. Lakshmi Narasimha Das Nyayapathi, Secretary (representative of Crowe Mak Limited)
 - iii. Mr. Vijay Kumar Ojha, Member
 - iv. Mr. R. Lakshmanan, Member
 - v. Mr. G V S Sai Arvind, Member
- b. The ICSI Middle East (DIFC) NPIO will strengthen the global outreach of the profession and facilitate the students and members residing in Middle East and North Africa (MENA) region. The presence of ICSI in UAE will pave way for expanding the dimensions of corporate governance in the MENA region as well.
- c. The inauguration ceremony of NPIO was organised on 10th December, 2019 at Dubai, UAE. The Inaugural Ceremony was graced by H.E. Mr. Vipul, Consul General of India, Dubai as Chief Guest, Mr. Manoj

Pandey, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India as Guest of Honour and Mr. Nick Nadal, Vice-President, Hawkamah Institute for Corporate Governance as Keynote Speaker.

- d. ICSI Middle East (DIFC) NPIO had launched its membership scheme for the year ending 31st December, 2020 on 28th May, 2020. For transparency and better control, ICSI developed the online membership registration through its portal. The same is accessible at <https://apps.icsi.edu/icsinpio/login.aspx>

(ix) AICPA & CIMA Finance Transformation New York

ICSI delegation attended the AICPA & CIMA Finance Transformation New York held on 15-16 October, 2019 at New York and met with other professional organizations and also geared up the ICSI Overseas Centre at USA.

(x) Delegation of Kenya Accountants and Secretaries National Examination Board visited ICSI Headquarter at New Delhi.

The representatives of Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board undertook a study visit to ICSI HQ at New Delhi on 6th November, 2019 to discuss about benchmarking of the Certified Secretaries qualification and emerging competencies for governance professionals.

(xi) Delegation of University of Sydney visited ICSI HQ at New Delhi.

The representatives of Sydney University had visited ICSI HQ, New Delhi on 21st November, 2019 to discuss the issues of mutual interest with the Institute.

(xii) ICGN 2019 Global Stewardship Forum

The ICSI representatives participated in ICGN 2019 Global Stewardship Forum on 26th November, 2019 at London. The event focused on strengthening investor voting policies, rationale and evidencing company engagement outcomes on impact of stewardship activities on long-term corporate value through purposeful engagement. During the visit, the ICSI delegation met with Head of Membership, The Chartered Governance Institute (erstwhile ICSA), UK to discuss the progress of MoU between both Institutes. ICSI delegation also explored the opportunities to open overseas center at UK.

(xiii) Revision in the Guidelines for Overseas Centre

The Council approved revision in “Guidelines for establishing and functioning of ICSI Overseas Centre(s)”.

(xiv) Online Endorsement of Member Verification under ICSI-ICSA MoU

For smooth and speedy processing of ICSI member verification form under ICSI-ICSA MoU, Institute has developed online platform and the same was launched during the webinar “Empowerment of the Company Secretary Profession- International View” held on 24th July, 2020.

(xv) International Webinars

In furtherance of vision of ICSI i.e. “To be a global leader in promoting Good Corporate Governance” and to provide its members with the right acumen attuned to the ever changing global scenario, the ICSI has been organizing International Webinars. These Interactive webinars addressed by eminent speakers from India and abroad, have not just bolstered the capabilities of the ICSI stakeholders but are also progressively raising the standard and status of the CS profession globally.

Following International Webinars were held:-

Date	Topic	Speakers
15 th May, 2020	Impact of COVID19 on Global Economy: Role of Professionals & Way Forward	i. Ms. Karyn Southgate, President, CSIA ii. CS Ashish Garg, President, ICSI iii. CS Ranjeet Pandey, Vice President, CSIA & Immediate Past President, ICSI iv. Mr. Tim Sheehy, Director General, CGI v. Mr. Saad Maniar, Senior Partner, Crowe Mak Ltd. vi. CS Lakshmi Kant Garg, Managing Director,

		Deloitte&Touche LLP
28 th May, 2020	Economic Substance Regulations (ESR)	i. CS Ashish Garg, President, ICSI ii. CS Ranjeet Pandey, Vice President, CSIA & Immediate Past President, ICSI iii. Mr. M. Hanumantha Kumar, MD, MCA Auditing & Management Consultant iv. Mr. Narasimha Das, Associate Partner, Crowe Mak Limited v. Mr. Harikishan Rankawat, Managing Partners, RNG Auditors vi. CS R. Lakshamanan, Founding Member, ICSI Middle East (DIFC) NPIO
23 rd July, 2020	Digitalising Corporate Governance in a Covid-19 Age	i. Mr. Benjamin Quinlan, CEO & Managing Partner, Quinlan & Associates ii. Mr. Alan Evans, Exco Member, CSIA
24 th July, 2020	Empowerment of the Company Secretary Profession: International View	1. CS Ashish Garg, President, ICSI 2. CS Ranjeet Pandey, Vice President, CSIA & Immediate Past President, ICSI 3. CS Nitin V Kotak, Strategic Finance & Business Consultant 4. CA Kunal Singhania, Vice President, External Reporting, American Express, New York City. 5. CS Lakshmikanth Garg, Chairperson, ICSI Overseas Centre, USA 6. CS Renuka Raman, Vice-Chairperson, ICSI Overseas Centre, USA
24 th August, 2020	Evolving Role of Company Secretaries- UK Perspective	i. CS Abhijit Mukhopadhyay, President (Legal) & General Counsel, Hinduja Group ii. CS Inderpreet Kaur Bedi, Chairperson, ICSI Overseas Centre, UK iii. CS Manish Temani, Vice-Chairperson, ICSI Overseas Centre, UK

14. CORPORATE GOVERNANCE AWARDS

The Presentation Ceremony for the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance was held on 10th January, 2020 at The ITC Maurya, New Delhi. Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs and Hon'ble Justice Shri Dipak Misra, Former Chief Justice of India were the Guests of Honour at the presentation ceremony and presented the Awards to the winners. The Presentation Ceremony was preceded by two special sessions by Dr. Ritesh Malik, Founder, Innov8 Coworking and Mr. Sonam Wangchuk, Founder, The Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL).

(i) ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance, 2019

• New Award Categories under ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance:

In an attempt to motivate corporates across all segments ICSI introduced new categories of awards under the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance., the Awards for Best Governed

Companies were given to companies in the Listed and Unlisted Segment further categorizing them into Large, Medium and Emerging categories, in accordance with the turnover of the company given as under.

(a) Listed Companies Segment (3 Awards)

Three Awards to the Best Governed Companies one each in the following Listed category:

- Large: Turnover \geq Rs. 10000 Cr.
- Medium: Turnover $<$ Rs. 10000 Cr. and \geq Rs. 1000 Cr.
- Emerging: Turnover \leq Rs. 1000 Cr.)

(b) Unlisted Companies Segment (3 Awards)

Three Awards to the Best Governed Companies one each in the following Unlisted category:

- Large: Turnover \geq Rs. 10000 Cr.
- Medium: Turnover $<$ Rs. 10000 Cr. and \geq Rs. 1000 Cr.
- Emerging: Turnover \leq Rs. 1000 Cr.)

• Expert Group for ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance

The First and Second Questionnaire, Evaluation Methodologies pertaining thereto and the Questionnaire for the Independent Directors, Secretarial Auditors and Statutory Auditors were finalised by an Expert Group constituted for the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance. The Expert Group was chaired by CS N Hariharan, Executive Vice President & Company Secretary, Larsen & Toubro Ltd. Interactions with the independent directors of shortlisted companies were also undertaken by the members of the Expert Group.

• Award Winners of the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance

(a) LISTED CATEGORY

- Mahindra & Mahindra Limited (Listed Company: Large Category)
- Blue Star Limited (Listed Company: Medium Category)
- Tata Steel Long Products Limited (Listed Company: Emerging Category)

(b) UNLISTED CATEGORY

- BSES Rajdhani Power Limited (Unlisted Company: Large Category)
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited (Unlisted Company: Medium Category)
- Route Mobile Limited (Unlisted Company: Emerging Category)

(ii) 4th ICSI CSR Excellence Awards

• Award Categories

All companies having spent CSR of ₹ 1 crore and above were eligible to participate for the 4th ICSI CSR Excellence Awards. The categories of Awards under the ICSI CSR Excellence Awards are:

Best Corporate – One award to be given under each of the following category:

- Large - (Actual CSR spending $>$ ₹25 Crores)
- Medium - (Actual CSR spending $>$ ₹10 crores and \leq ₹25 crores)
- Emerging - (Actual CSR spending $>$ ₹ 1 crore and \leq ₹ 10 crores)

• Expert Group for ICSI CSR Excellence Awards

The Questionnaire, Evaluation Methodology, parameters for field assessment were finalised by an Expert Group chaired by CS J. Sridhar, Company Secretary, Bajaj Auto Ltd.

For the first time, field assessment was introduced and undertaken for the short listed companies. The parameters for the field assessment were finalised by experts from TATA Power Company Limited, Bajaj Auto Limited, Company Secretary Professionals & Academicians.

• **Award Winners of the 4th ICSI CSR Excellence Awards**

The award for the Best Corporate under the 4th ICSI CSR Excellence Awards was conferred upon:

- Apollo Tyres Limited (Large Category)
- SRF Limited (Medium Category)
- Persistent Systems Limited (Emerging Category)

(iii) ICSI Best Secretarial Audit Report Award

The Council of the Institute with the aim of recognizing the efforts of Company Secretaries in Practice in their roles as Secretarial Auditors in elevating the culture of governance in corporate sector and enhancing the importance of Secretarial Audit Reporting, instituted a new category of Award i.e. “Best Secretarial Audit Report Award”.

• **Expert Group for Best Secretarial Audit Report Award**

The Questionnaire and Evaluation Methodology was finalised by an Expert Group constituted for Best Secretarial Audit Report Award, chaired by Late CS Sanjay Grover. An interaction with the shortlisted Secretarial Auditor was also undertaken by the members of the Expert Group.

• **Award Winners of the Best Secretarial Audit Report Award**

The ICSI Best Secretarial Audit Report Award was jointly presented to:

- CS Atul Mehta, Mehta & Mehta Associates for Secretarial Audit Report of The New India Assurance Company Limited
- CS (Dr.) CV Madhusudhanan, KSR & Co. for Secretarial Audit Report of Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
- CS Vinita Nair, M/s Vinod Kothari & Co. for Secretarial Audit Report of Housing Development & Finance Corporation Limited

(iv) ICSI Lifetime Achievement Award for Translating Excellence in Corporate Governance into Reality

The prestigious ICSI Lifetime Achievement Award was conferred on Mrs. Indu Jain, Chairperson, Bennett Coleman & Company Limited for Translating Excellence in Corporate Governance into Reality.

15. ICSI – INDIA’S GST PARTNER

Standing shoulder to shoulder with the government towards directed implementation of GST, the Institute has been committed to building the capacity of its members, students and related stakeholders by advancing their understanding about GST and also by constantly apprising them with updates in GST through various initiatives. Some of the major initiatives in this direction are listed below:

(i) GST Day, 2019

The GST Day was celebrated on 1st July, 2019 and was marked by the launch of a dedicated course titled Certificate Course in Goods & Services Tax aiming to give a comprehensive insight about principles of GST as well as other nuances of the indirect tax regime enabling the candidates to gain an understanding of GST concept and its implementation and apprise them about the current developments with respect to GST. Also, the Institute had organized Pan-India events across Chapters and Regional Offices

(ii) GST Day, 2020

To commemorate the third anniversary of the introduction of the Goods and Services Tax, a mega programme was organized on 1st July 2020 through live webinar mode. Shri Piyush Goyal, Hon’ble Minister of Railways and Commerce and Industry was the Chief Guest at the Inaugural Session. A special interactive session with Shri Sushil Kumar Modi, Hon’ble Deputy Chief Minister of Bihar along with President, Vice-President and other Council Members, ICSI was also organized on the occasion.

A video on “ICSI unlocking the opportunities in the Lockdown” was also released during the Inaugural Session along with the GST Newsletter and Info Capsule.

Along with these, three Technical Sessions were held on the topics “GST- The Way Forward”, “Pertinent Issues and Professional Opportunities in GST”, and Contemporary Issues in Writ Jurisdiction in GST”.

(iii) GST Newsletter

The Institute is regularly bringing out a monthly newsletter dedicated to the Goods & Services Tax (GST). Considering the importance and far reaching impact of initiative under new indirect tax regime and upholding the “One Nation One Tax” motto of the Government of India, the 37th issue of the ICSI – GST News letter was published in August, 2020. All the issues of GST Newsletter are available on the GST Corner of the Institute’s website at <https://www.icsi.edu/GSTEducationalSeries.aspx>.

(iv) GST Educational Series

Furthering capacity building initiatives in the regime of GST, the Institute has developed a GST Educational Series. The Institute in this series, which has been successful and academically useful, has brought out more than 490 issues. All the issues of GST Educational Series are available on the GST Corner of the Institute’s website at <https://www.icsi.edu/GSTEducationalSeries.aspx>.

16. ACADEMIC INITIATIVES AND DEVELOPMENTS

(i) Introduction of Info Capsule- A daily update for members in revamped manner.

The Institute has re-introduced the revamped version of ‘Info capsule’- a daily update for members, in a structured form with knowledge rich inputs. The info capsules are also made available to students under Academic Corner.

The Info capsule focuses on areas including latest happenings in ICSI, Important regulatory updates from Ministry of Corporate Affairs, SEBI and other Regulators, news relating to Restructuring and Insolvency; Valuation; Regulatory takeaways from NCLT and NCLAT and other judicial pronouncements; Market Watch, developments on Corporate Governance etc.

(ii) Case Digest Series

The Institute has taken up a new initiative of bringing out a case digest series where the case snippets related to Company Law, Insolvency Law, Competition Laws, Securities Laws, Consumer Law, Corporate Fraud, Money Laundering, General Laws, Labour Laws, Direct Tax Laws, Goods and Services Tax Laws, Banking Laws, etc. are covered. Besides, it also covers case study on recent issues from business and regulatory perspective. Case Digest series is circulated to students and members of the Institute.

(iii) COVID 19- Regulatory Updates

To support the members in understanding and updating themselves on the relaxations and the new compliance deadlines, the Institute has brought out three volumes of comprehensive booklet ‘Covid19-Regulatory Updates’, covering the initiatives of Judiciary, Ministries and various Regulators.

(iv) Introduced CS Executive Entrance Test (CSEET) Bulletin- a monthly e-journal for CSEET students.

This monthly bulletin broadly covers various developments pertaining to CSEET syllabus including updates on economics, current affairs, etc., in addition to sample question answers pertaining to each subject.

(v) Revamped Student Company Secretary a monthly e-journal for students

The Institute has revamped the journal by adding several new sections including subject wise updates/ case laws, etc. along with following features:

- Theme based journal with theme article and articles on recent developments
- Articles on recent Regulatory/business development
- Subject wise Regulatory Updates
- Company Law corner
- Usage of Legal Maxims

(vi) Subject wise Monthly Updates

In order to educate the students on real time basis ICSI has introduced subject wise and chapter wise monthly update, covering recent regulatory developments.

(vii) Practice manual for students

A practice manual for the subject “Direct tax and Indirect Tax” has been developed and placed on the ICSI Website to help the students in preparation for the examinations.

(viii) Constitution of Subject Experts Committee

The Institute constituted subject wise experts committee for each of the 24 subjects comprising members from academics, industry and practicing professionals, for imbibing practical insights into the study materials of various subjects. The Committee held meetings and the Institute has incorporated their suggestions in the study material.

(ix) CSEET Reading Material

Reference Reading material for all four subjects under CSEET have been prepared and uploaded on the Website of ICSI.

(x) CSEET Mock Test

Five sets of Mock Test for Part-A of CSEET examination have been launched on the ICSI website.

(xi) Availability of Study material for Executive and Professional programme on ICSI Website.

The Study material relevant for the June 2020 Examination (now merged with December 2020 examinations) has been updated and placed on the website of Institute. The study material has been revised after considering the views of the Subject Experts in the domain.

(xii) Uploading of Guideline answers on the Academic portal

The Guideline Answers having the past session questions and solutions year wise and module wise from June 2015- December 2019 have been uploaded under Academic Portal on ICSI website, Students can download the same free of cost.

(xiii) Support to training in revision, review and revamping of the following training modules

The following Modules were updated and revamped:

- EDP Module 5 Days entrepreneurship
- 2 Days EDP Training Module – Induction
- 15 Days New EDP Module
- 3 days XBRL and E voting
- 5 days Skill Development eMSOP Modules

(xiv) Video Lectures/ Video Recording of Webinars through E-Learning: Portal

- More than 180 videos of webinars, video lectures and crash courses related to different subjects of old and new syllabus were uploaded for the benefit of students on E-learning portal.

17. MEMBERS

- During the period from 1st April, 2019 till 15th September, 2020, 5109 and 659 members were admitted as Associates and Fellows, respectively. As on 15th September, 2020 the Institute had 52409 Associate and 10183 Fellow members aggregating to 62592 members. During the period from 1st April, 2019 till 15th September, 2020, 1726 Certificates of Practice were issued. There were 10918 members who were holding Certificates of Practice as on 15th September, 2020. The bi-annual ICSI Convocations were successfully organized at four regions.
- The Council regrets to report the sad demise of 29 members during the period from 1st April, 2019 till 15th September, 2020, of whom 21 were also life members of the Company Secretaries Benevolent Fund (CSBF).

1) List of Members: In pursuance of section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980, read with Regulation 161 of the Company Secretaries Regulations, 1982, a List of Members as on 1st April, 2020 has been made available in CD.

2) Licentiate-ship: During the period from 1st April, 2019 till 15th September, 2020, 26 Final/Professional Examination pass students of the Institute were admitted as Licentiate-ICSI. The number of Licentiates as on 15th September, 2020 stood at 110.

3) Company Secretaries Benevolent Fund (CSBF):

The region-wise break-up of life members of CSBF is as under:

Region	As on 31 st March, 2020	As on 15 th September, 2020
EIRO	1033	1043
NIRO	4648	4693
SIRO	4057	4105
WIRO	4181	4225
Foreign	55	55
Total	13974	14121

4) Honorary Fellowship : Honorary Fellowship of the Institute was conferred on Shri Ajun Ram Meghwal, Minister of State for Paliamentay Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises and Shri Injeti Srinivas, Secretay, MCA on 5th October, 2019 by the Hon'ble President of India, Sh. Ram Nath Kovind during the 51st Foundation Day Celebrtions of ICSI held at Vigyan Bhawan, New Delhi.

18. STUDENT TRAINING AND CAPACITY BUILDING

(i) Training

a) Empanelment of Companies/Company Secretaries in Practice for imparting training

The Institute strives to expand its training base by empaneling more companies/other entities as well as Practicing Company Secretaries for providing training to students. During the year **273** companies and **715** Practicing Company Secretaries were empaneled for imparting Practical training to the students

(b) Executive Development Programme (EDP)

During the year 2019-2020, a total of **10** Executive Development Programmes were organized wherein **262** students successfully completed 8 days EDP in classroom environment.

Due to COVID-19, no training programmes were organized in physical class room mode from March 2020 onwards. However, two e-EDPs (3 days e-governance and 5 days skill Development) were organised as a part of 15 days online Academic programme.

The details of 8 days e-EDP (3 days e-governance and 5 days Skill development) are given herein below:

Sl. No.	Details	Total students attended
1	First batch of 8 days e-EDP (3 days e-governance and 5 days skill development) 3 days e-governance 5 days Skill Development	310 349
2	Second batch of 8 days e-EDP (3 days e-governance and 5 days skill development) 3 days e-governance 5 days Skill Development	291 285

(c) Management Skills Orientation Programme (MSOP)

During the year, following MSOPs were organised :

S. No.	MSOP Programmes	Numbers of students	Number of programmes from 01.04.2019 to 31.03.2020
I	Regular MSOP	2,454	64
II	Residential MSOP	281	8

Due to COVID-19, no training programmes were organized in physical class room mode from March 2020 onwards.

e-MSOP (i.e. through online mode as on 15.09.2020)

S. No	Programmes	Numbers of students
III	e-MSOP	2,522

(d) LAUNCH OF ONE DAY ORIENTATION PROGRAMME

- The Institute for the first time has introduced a mandatory One day orientation program for Executive and Foundation Programme students. Now every student who is getting enrolled into the CS course shall have to compulsorily undergo this program immediately after the registration.
- One day orientation programme is applicable to all the students of Foundation and Executive Program registered on or after 1st June, 2019.
- The purpose of one day orientation program is to apprise the students about the scheme of studies, course curriculum, duration of the programme, examination pattern, training structure etc. so that the students could get all the updated information about the CS course and also get connected with the Institute.
- Till 15th September, 2020, a total of 12,415 Foundation Programme students and 22,460 Executive Programme students have registered for undergoing the mandatory One Day Orientation Programme.

(d) EMPANELMENT OF FACULTIES FOR VARIOUS TRAINING PROGRAMMES

- In order to have a pool of Academicians, Corporate Trainers, Industry leaders and Professionals for taking sessions in various training programs in ICSI, the Institute has introduced an online facility for empanelment of faculties/trainers who are having adequate academic background, teaching experience to register with the Institute as a faculty for various training programs of students.
- The announcement for empanelment of faculties/trainer for training programs in ICSI was circulated amongst the CS members, professionals/academicians, all Regional and Chapter Offices for empanelment of Visiting Faculties /Guest Faculties/ Corporate Trainers /Leaders from Industries and Academia.
- The 1229 applications received are scrutinized from time to time by a Committee duly constituted and 776 eligible faculties are selected for empanelment.

(f) LAUNCH OF TOT (TRAINING OF THE TRAINERS) PROGRAMME

- The Institute in order to train the newly inducted trainers has launched the Training of the Trainers (TOT) Programme. The TOT is a kind of induction program for newly registered trainers of ICSI for imparting practical training to CS students. The first TOT program was organised on 19th October, 2019 at HQ in presence of President and Secretary. Approximately 30 registered trainers participated in the TOT programme. The objective of the programme was:
 - To guide how to deliver the training;
 - To apprise them of 4 Ps of training, i.e., Purpose, Planning, Presentation and Performance;
 - To apprise what is expected from the trainer while imparting training;
 - To suggest how to evaluate the performance of trainees and how to remove their shortcomings
- The TOT manual was also launched during the first TOT programme. It was also proposed to involve all four regions and Centre of Excellence for conducting the TOT. Accordingly, the second TOT was held on 14th December 2019 at COE, Hyderabad with more than 25 trainers and on 11th January, 2020 at CCGRT in which 32 trainers participated.

(g) Launch of project “STIMULATE”

The Institute, in order to bring automation in the training services for trainers and trainees launched e-governance portal on 27.02.2020. E Governance portal is aimed at providing students timely and fast replies on various training activities. Now the students can submit requests for practical training registration, NOC/Completion certificates and exemption from training through their online portal. Students can also book their seats for various in-house training programs organized by Regional and Chapter Offices.

(h) Making e-MSOP accessible to all eligible students during the period of lock down due to COVID 19

The Institute vide Circular dated 31.03.2020 and 19.06.2020 has relaxed the eligibility criteria for taking admission in e-MSOP by temporarily removing the two years' time bar between professional pass and e-MSOP registration. By providing this relaxation, the Institute allowed all Professional Programme passed students irrespective of their year of passing, to undergo e-MSOP subject to fulfillment of other conditions as mentioned in the guidelines. This was done to facilitate the students to apply for membership without waiting for the classroom based MSOP held in regions and chapters. Total 1986 e MSOP applications have been approved as on date.

(i) Making provision of 15 days e Academic Programme including 08 days e-EDP (3 Days e Governance and 05 Days Skill Development Programme) for the students.

Due to the lockdown on account of Covid 19, all the short-term training organized by the ROs and Chapters were discontinued. Many students were thus not able to complete their 15 days academic program and EDP. In order to provide the best possible services to the students during the period of lock down, the Institute had organized 15 days e Academic Programme including 8 days e EDP (3 Days e Governance and 5 days Skill Development Programme). The training was organized from 17th April, 2020 to 19th May 2020. Total 3952 students completed the above training.

(j) Relaxation in submitting the first and second quarterly report of the trainees in the Institute records during the period of lock down due to COVID 19 .

The Institute had relaxed the last date of submission of the first quarterly reports till 30th June 2020 during the first phase of lockdown. However, keeping in view of the complete lockdown, the Institute decided to further extend the last date of submission of quarterly reports which was further extended vide circular dated 19.06.2020 for submission of first and second quarterly reports upto 30th September 2020.

(k) 5 days online Professional Skill Development Training (PSDT) for CS Trainees and Aspirants

In order to build confidence among the trainees by enhancing their skill sets, and also to develop their functional competency in core and emerging areas, the Institute had conducted 5 days PSDT for the CS trainees from 2nd June, 2020 to 6th June 2020. The objective of such training was capacity building of CS trainees during working from home, confidence building and motivation among the trainees, enhancing their soft skills, IT Skills and drafting skills. Total 593 students completed the training.

(l) Online Professional Development Program (e PDP)

In order to facilitate the students registered in Executive Program on or before 31.03.2014 to complete the requirement of 24 PDP hours, the Institute organized PDP through online mode. The first batch of e PDP was organized from 06th May, 13th May and 22th May 2020. Total 1290 students completed the 24 hours of e PDP .

(m) Treating the Lock Down Period on account of Covid-19 as continuity of Practical Training for the CS trainees

The outbreak of Global Pandemic (“COVID 19”) has resulted in complete lock down, therefore, the Institute vide circular dated 30th March 2020 informed all the Trainers / employers (Companies, PCS and other entities) to allow the CS trainees registered with the Institute and undergoing their Practical training, to work from Home under the direction and monitoring of their trainers (online/electronic mode).

In view of the above, the working from home during the lock down period (including extension thereof if any by the government) shall be counted for the purpose of training period.

(n) Relaxation for complying with the requirement of Pre Examination test and One day Orientation Programme for enrollment to December 2020 session of CS examination (in view of unprecedented crisis in the country due to Corona virus outbreak)

The students are required to comply with the above two requirements of pre-examination test and ODOP for enrolling themselves to appear in the Company Secretaries Examinations, December 2020 Session. Now the

students have been temporarily allowed to enroll themselves for the examination without complying with the requirement of ODOP. However, they have to comply with the above requirement by 20th November, 2020.

(o) Second batch of 15 Days e-Academic Programme including 8 days e-EDP (3 days e-governance and 05 days Skill Development Programme)

Keeping in view the overwhelming response from students in first batch of 15 days e-Academic program and due to COVID-19, the Institute organized second batch of 15 days e-Academic Programme including 8 days e-EDP (3 Days e Governance and 5 days Skill Development Programme) from 25th June, 2020 -31st July 2020.

(p) Second batch of 5 days online Professional Skill Development Training (PSDT) for CS Trainees and Aspirants

Keeping in view the response from the stakeholders in the first batch of 5 days online Professional Skill Development Training (PSDT), the Institute had organized a second batch of online PSDT from 11th July, 2020 - 15th July, 2020.

(q) Providing temporary relaxation from Regulations 46BA and 46BB of the Companies Secretaries Regulations 1982 (as amended upto 3rd February, 2020) due to COVID-19 pandemic.

As per the recommendations of the Council and subsequent approval of the Ministry of Corporate affairs, temporary relaxations have been granted under Regulation 46BA and 46BB. The students under the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020 are allowed to commence their 21 months Practical training after completion of 15 days EDP in online mode instead of One Month EDP as prescribed in regulation 46 BB of the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020. However, they shall be required to complete the remaining 15 days of EDP in classroom mode within six months of commencement of their Practical training. The said EDP in classroom mode shall be undertaken, once the regions and chapters are reopened for conducting such training.

(r) CS TRAINEE DRIVE - organised in September, 2019 at ICSI House, Noida

The Institute of Company Secretary of India (ICSI), with an objective to provide a common platform to the CS Trainees and Trainers organised an exclusive CS Trainee Drive (II) - 2019 on 5th September, 2019 at ICSI House, Noida. The event was successfully organised in terms of bridging the gap between Corporates, Firms and aspiring Students as the drive witnessed an overwhelming response from students and organisations.

19. PLACEMENT

In 2019-20, various activities were undertaken to ensure placement opportunities were available for ICSI members.

i. Publishing the list of ICSI Top 25 rank holders in Professional Exam of December, 2018 and June, 2019 at ICSI website

Details of the Top 25 rank holders were displayed at the ICSI website to facilitate requirement of trainees and CS Professionals from Top Corporates.

The lists of 25 rank holders, each from successful students in exam of December 2018 and June 2019 was published on the Institute's website after taking consent from the students.

ii. Mega Placement Drives

The Institute organised the first phase of Mega Placement Drive, 2019 in the month of May, 2019 in all four regions of ICSI. The Mega Placement Drive was conducted on 04th May, 2019 at WIRC-Mumbai. Thereafter, it was conducted at NIRC-Delhi on 17th May, 2019, followed by EIRC-Kolkata on 18th May, 2019 that concluded on 24th May, 2019 at SIRC-Chennai.

The second phase of Mega Placement Drive, 2019 was conducted in the month of November-December, 2019. It was conducted at SIRC-Chennai on 22 November, 2019, at NIRC-New Delhi and WIRC-Mumbai on 30th November, 2019. The Drive for EIRC-Kolkata was conducted on December 10, 2019.

iii. Profile mapping of Young Company Secretaries from 1st January 2014 to 25th June 2019

ICSI conducted a nationwide survey among its members who received their membership on or after 1st of January, 2014 till 25th June, 2019 to understand their employment status, map the area of expertise, specific domain knowledge and the employment opportunities offered by the industry across the country.

iv. **ICSI Placement Portal for newly Members and Students**

With a view to provide placement services to members, the Institute moved a step forward to assist members to identify job opportunities in the market. A tab for Placement at the ICSI website was regularly updated with the job opportunities ranging from 0 to 2 years/ 2-5 years/ 5 years and above experience. The said tab made it simpler for ICSI members to find the existing job opportunities, it also supported students to find trainings. This tab was active till November 14, 2019 at www.icsi.edu.

Effective 14th November 2019, the ICSI Placement Portal, <https://placement.icsi.edu/>, was launched for all members and students. Through the said portal, opportunities for jobs and trainings are posted by corporates and other recruiters enabling the members and students to apply for the same.

v. **ICSI Strategic Meet:**

An Interactive session with senior HR Professionals, experienced Members of the corporate fraternity, Technological Experts, etc. was organised on 29th February, 2020 at ICSI CCGRT, CBD Belapur, Mumbai.

vi. **HR Conclaves**

The ICSI – SIRC organized HR Conclave on 22nd August, 2019 at ICSI – SIRC House, Chennai for HR Managers and Executives in HR Department in Corporates.

The ICSI-EIRC organized the ICSI HR Conclave-I, 2019 for the Eastern Region on 9th November, 2019 at The Peerless Inn, Kolkata.

vii. **Assistance in Recruitment of Company Secretary at PSUs like**

a. **Rural Electrification Corporation of India**

b. **OIL India Limited (reserved category for SC/ST/OBC(NCL))**

c. **National Pension System Trust**

d. **National Informatics Center Services Incorporated**

In response to the advertisements posted on the Institute's website regarding vacancy for Company Secretary in various PSUs, applications in large numbers were received which were scrutinized and filtered as per the pre-defined criteria set by organizations concerned. Valid responses were shared with them, out of which top candidates were invited, based on merit, for interview and final selections for the positions were made.

viii. **Shortlisting of CS Students for training at various Government entities**

The Institute received request from various government entities regarding requirement of Company Secretary Students for Training purposes. Trainee requirements were posted on the Institute's website; shortlisting and scrutiny of responses was carried out based on provided criteria for organizations like:

a. **Office of the Official Liquidator**

b. **CL-II section of the Ministry of Corporate Affairs**

c. **Office of the Regional Director North (MCA)**

d. **Registrar of Companies, and other Govt. entities.**

ix. **Exclusive Campus Drives for trainee and members for leading organisations at ICSI House, Noida**

The Institute in order to provide one more platform to assist the organisations and students and members in their trainee and job search. Exclusive drives have been organised by the Institute for the organisation's trainee and job requirement.

x. **Setting up of Placement Kiosk at Various Convocations**

Placement Kiosks were set up at Hyderabad, Chandigarh, Ranchi and New Delhi to provide assistance and address all member related queries pertaining to placement. In addition, a Placement Kiosk was set up at the National Conference of Corporate CS, Mumbai to make members aware about the new Placement Portal and encourage them to register themselves and their organizations at the portal for various jobs and Trainee requirements.

xi. **Inviting Expression of Interest from Placement Agencies**

Expression of Interest has been floated inviting applications from agencies interested for facilitating the Placement activities of the Institute. Instead of having an outside agency it was decided to hire an external

agency on prompt basis for branding, marketing and inviting corporates to the placement drive of the Institute.

The agency, would bring more corporates for various placement initiatives of the ICSI, having more shortlisting/ selections, approaching various corporates/ Stock Exchanges/ RTA/ Banking & Finance industry / Regulators / Government Department and other segments in the industry on pan India basis as regular activity on daily basis and to devote at least one skilled qualified manpower for every two States of India to market the ICSI profession, its curriculum and deliverables.

20. CAPACITY BUILDING FOR STUDENTS

a) CS Regular Programme

During the year, up to 31st March 2020, 25681 students registered in Executive Programme and 4806 students registered in Professional Programme. As on 31st March, 2020, there were 210445 students with valid registration in the regular programme.

During the year, from 1st April 2020 to 15th September 2020, 521 students registered in Executive Programme and 541 students registered in Professional Programme. As on 15th September, 2020, there were 190132 students with valid registration in the regular programme.

b) CS Foundation Programme

During the year up to 31st March 2020, 14373 students were admitted to the Foundation Programme. As on 31st March, 2020, there were 37253 students with valid registration in Foundation Programme.

Foundation Programme has been discontinued w.e.f 3rd February 2020. As on 15th September, 2020, there were 30406 students with valid registration in Foundation Programme.

c) CS Executive Entrance Test (CSEET)

The Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020 has introduced CS Executive Entrance Test (CSEET). With the introduction of CSEET from February 3, 2020, new registration to the Foundation Programme has ceased to exist and w.e.f. February 3, 2020, CSEET is the only qualifying entrance test for registration to the CS Executive Programme. CSEET has been introduced keeping in view the diverse academic standards of students seeking admission in the Company Secretaryship Course, to attract meritorious students and to test their aptitude for the profession. The candidates who are appearing or have passed class 12th examinations are eligible for appearing in the CSEET. All the students seeking admission in the Company Secretaryship Course including graduates/ post graduates, etc. shall be required to qualify the CSEET from February 3, 2020 onwards. The process of selecting meritorious candidates through CSEET will enhance the quality of future members to meet the expectations of the industry and the regulators. During the year, from 3rd February 2020 to 31st March 2020, 4522 students registered for the CS Executive Entrance Test (CSEET) and from 01.04.2020 to 15.09.2020, 13489 students registered for the CS Executive Entrance Test (CSEET).

d) ICSI Students Education Fund Trust

The Institute has created 'ICSI Students Education Fund Trust' to financially support economically backward students and motivate academically bright students to pursue the Company Secretaryship Course. The Institute is thus facilitating free education to economically needy and academically bright students thus contributing to the objectives of nation building and social responsibility.

As per the guidelines of the of the Trust, the Institute reimburses the Registration / Admission Fee, Education Fee, Exemption Fee and other fees usually payable at the time of admission to Foundation / Executive Programmes to the eligible students. Based on their performance in the examinations, such students are also reimbursed all fee applicable at Executive Programme/ Professional Programme stages.

During the year, from 1st April 2019 to 31st March 2020, 99 students belonging to Economically Backward and 356 students under the Academically Bright category were granted financial assistance from the Trust and from 1st April, 2020 to 31st August, 2020, 4 students belonging to Economically Backward and 23 students under the Academically Bright category were granted financial assistance from the Trust.

e) Conduct of Examinations

During the period under report, Company Secretaries examinations for Executive Programme and Professional Programme as per syllabus prescribed in the Company Secretaries Regulations, 1982 were held at 166 and 172 Examination centres all over India and one overseas Examination centre at Dubai in June and

December, 2019 sessions of examinations respectively. A total number of **66,718** and **70,361** candidates sought enrolment for appearing in June and December, 2019 sessions of examinations respectively. Further, the Computer Based Examinations for Foundation Programme was conducted at **125** and **127** Examination Centres all over India including one overseas Examination centre at Dubai in which **14,034** and **12,095** candidates sought enrolment for appearing in June and December, 2019 sessions of examinations respectively. Number of candidates successfully completed various stages of examinations during the year 2019-20 is tabulated below:

Stage of Examination	Examination Session	
	June, 2019	December, 2019
Foundation Programme	8,450	7,557
Executive Programme(Old Syllabus)	2,233	2,185
Executive Programme(New Syllabus)	222	752
Professional Programme (Old Syllabus)	2,719	2,619
Professional Programme (New Syllabus)	39	280

List of cities for examinations and the statistics relating to examination results are given in **Appendix – ‘C’** and **Appendix – ‘D’** respectively.

f) Conduct of Post Membership Qualification (PMQ) Examination

The Institute conducted the Post Membership Qualification (PMQ) Course examination in Corporate Governance in June, 2019. The 6 number of Candidate enrolled, appeared 5 and 2 were passed in the PMQ Examination.

g) All India Prize Awards

In order to motivate bright students, the Institute has instituted a number of awards. The following students won the President's All-India Awards for June and December, 2019 Examinations:

<i>Medal/ Examination</i>	June, 2019	Centre	December, 2019	Centre
President's Gold Medal for Professional Programme	Tanya Kathuria	Kanpur	Shruti Kalpesh Shah	Mumbai
President's Silver Medal for Executive Programme	Khushi Agarwal	Ajmer	Kalyani Ashwin Pundlik	Pune

Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award was won by Ritesh Mehta of Pali (Rajasthan). The particulars of other prize winners along with existing all-India Prize Schemes, Regional and Chapter Prize Schemes were hosted on the Institute's website: www.icsi.edu.

h) Merit Certificates/ Merit Scholarships/ Financial Assistance

Merit Certificates were awarded to 25 top-ranked successful students each in Foundation Programme, Executive Programme and Professional Programme examinations held in June, 2019 as well as in December, 2019.

Pursuant to Merit Scholarship Scheme, Scholarships were awarded to 25 toppers who passed all papers of Foundation Programme and Executive Programme in the first attempt in June, 2019 and December, 2019 sessions of examinations for pursuing Executive Programme and Professional Programme of Company Secretaryship Course respectively. Likewise, under the Merit-cum-Means Assistance Scheme, financial assistance was granted to eligible candidates considering their economic background and meritorious performance in June, 2019 and December, 2019 examinations.

i) Re-Registration of Students to CS Professional Programme

As per the guidelines of Re-Registration, students who have passed the Intermediate Course / Executive Programme under any syllabus may directly register/ enroll for Professional Programme Stage. The Re-Registration policy was introduced by the Institute to facilitate the students to continue their studies who had dropped out due to various reasons and were not eligible to seek Registration Denovo / Extension as per the regulations. During the year, up to

31st March 2020, 44 students were registered and 15 students were registered during the period from 1st April 2020 to 15th September 2020 as per the Re-Registration guidelines.

j) Class Room Teaching

The Institute is providing the facility of Class Room Teaching on optional basis to its students through the Class Room Teaching Centres operational at the Regional and Chapter Offices of the Institute located in different parts of the country. In addition to the Institute's own Class Room Teaching Centres, Study Centres are also conducting classes for the students.

Due to the pandemic, the classes in physical mode became a challenge and to overcome the same, the Institute conducted Online Classes for its students. To augment the regular online classes, the Institute conducted Online Crash courses, Revision Classes and Mock Tests. Subject wise video lectures were also made available to all the students of the Institute free of cost through the e-learning portal of the Institute, <https://elearning.icsi.in>

Apart from the students of Foundation, Executive and Professional programme Stages, the Institute also conducted online classes for the students registered for CS Executive Entrance Test (CSEET).

k) Video lecture sessions organised for Class Room Teaching Students of ICSI and Students of Commerce/Management Colleges

Recorded video lectures of eminent faculties were uploaded on the E learning portal of the Institute. Using these video lectures, the Institute also organised special sessions on important topics to help the students in their preparation for the main examination. In the said special sessions, the students of Commerce, Management and Law Colleges in nearby locations were also invited to create awareness about CS Course and to attract the best talent to the profession.

l) Career Awareness

During the year, upto 31st March, 2020, 2041 Career Awareness Programmes and 10 mega Career Awareness Programmes were organised across the country. The Institute also participated in 118 Career Fairs /Exhibitions during the year. To popularize CS Course and attract young talent from Remote/Rural areas of the country the Institute appointed 45 ICSI Counsellors.

During April, 2020 to August, 2020, 349 Career Awareness Programmes and 1 mega Career Awareness Programme were organised and participated in 78 Career Fairs /Exhibitions.

M) SPECIAL INITIATIVES FOR STUDENT

(i) ICSI Signature Award

ICSI Signature Award Scheme was introduced by the Institute to recognize the best talent and attract them to the profession.

Under this Scheme, the Institute is tying up with reputed Universities/ Educational Institutions and Top Rank Holder in the B.Com. Examinations of such Universities and topper of selected programmes/ papers of IIMs / IITs are awarded a Gold Medal and Merit Certificate. Top three rank holders in the aforesaid examinations shall also be eligible for waiver of Registration Fee applicable to Executive Programme of CS Course.

As on 31st March, 2020, the Institute has signed agreements/ MOUs with 42 Universities/ educational institutions under the ICSI Signature Award Scheme. During the year 2019-20, the Institute has signed agreements/ MOUs with the following Universities / IIMs :

1.	Kannur University
2.	University of Calicut
3.	Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
4.	University of Kerala, Thiruvananthapuram
5.	IIM Shambhalpur
6.	IIM Bangalore
7.	Central University of Himachal Pradesh
8.	Bharathiar University
9.	KSKV Kachchh University

10.	Periyar University
11.	Mangalore University
12.	IIM Shillong
13.	IIM Ranchi

During the period from 1st April, 2020 to 15th September, 2020, MoU was signed with IIM, Jammu.

(ii) Commerce Olympiad

The Institute in association with Science Olympiad Foundation (SOF) conducted the Commerce Olympiad for students of 11th and 12th Classes during the academic year 2019-20 in schools across India. It was conducted on 28.11.2019 and 19.12.2019 in about 1950 Schools and more than 44000 students were enrolled.

(iii) ICSI Study Centre Scheme

In order to augment the reach and level of services being provided through its Regional Councils & Chapters, 'ICSI Study Centre Scheme' was launched on 2nd October, 2015. The objective of the Study Centre Scheme is to break the distance barrier between ICSI and its students. Under the Scheme, Study Centres are established in association with reputed Colleges in areas / locations, wherein the Institute's Regional/ Chapter Offices are not in existence.

Apart from providing basic services, the Study Centres are conducting classes for the students of various stages. As on 31st March, 2020, there were 115 Study Centres across the country.

During the year 2019-20, 16 new Study Centres and one Contact Centre at Leh / Ladakh were established.

During the period from 1st April, 2020 to 31st August, 2020, 4 new Study Centers were established.

(iv) Student Month

The Institute celebrated Student Month during July, 2019 and July 2020. Multiple activities were organised during the Student Month to create vibrancy among the student community and to provide a platform to have newer learning experiences. This was also to ensure participation of students in socially relevant activities. The enthusiasm shown by the student community for participating in activities were unparalleled. The team work and whole-hearted support at all levels ensured smooth conduct of multiple events across India. Major activities organised during the Student Month in the year 2019 included Van Mahotsav Divas, Blood Donation Camps, Career Awareness Activities, Online Competition for students, Commencement of Class Room Teaching batches uniformly across the country, Samadhi Diwas, Webinars, etc.

During July, 2020, the activities were conducted through online mode, due to the challenge posed by the pandemic

(v) Webcasts for Students

The Institute has always been very proactive in utilising the power of technology in providing hassle free services to the stakeholders. Webcasts have always been used as a tool for communicating with the students on important activities / developments in the Institute. Regular webcasts were organised during the year on different topics for the benefit of student community.

vi) "Samvaad" – An In-house e-magazine for the employees

The Institute is publishing an In-house e-magazine "Samvaad" for the employees of the Institute. The articles are contributed by the employees and their family members. The initiative is helping the employees in showcasing their talent and also keeping them abreast of latest developments in the Institute.

(vii) Grievance Solutions Cell

The Institute being a service oriented organization, the grievances, suggestions and queries received from the stakeholders of the Institute are monitored through a centrally monitored. It is helping the Institute to improve its services provided to the stakeholders. For achieving this objective, the Institute has created a Grievance Solutions Cell which is monitoring the communications received through the Support Portal at <http://support.icsi.edu>. The Grievance Solutions Cell is facilitating time-bound resolution of such grievances in coordination with the respective Directorates/ Units apart from suggesting improvements in existing procedures being followed by the Institute.

(viii) Concession in Fee for Registration to CS Course to the Widows and Wards of Martyrs, Permanent Disability cases, Serving / Retired Personnel of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all para military forces

The sacrifice of the personnel of Indian Armed forces and para military forces for maintaining the security and sovereignty of the country is commendable. In a humble endeavour of the Institute in recognizing the contribution of the serving and retired personnel and as a goodwill gesture to the families of martyrs, the Institute has decided to grant the following concessions for registration to the CS Course effective from 1st April, 2019 :

1. 100% concession in full Fee payable at the time of Registration to various Stages of CS Course and Examination Fee to the wards and widows of martyrs of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all para military forces
2. 100% concession in full Fee payable at the time of Registration to various Stages of CS Course and Examination Fee to the personnel of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all para military forces with permanent disability as a result of participating in act of war and other missions.
3. 50% concession in full Fee payable at the time of Registration to various Stages of CS Course and Examination Fee to all In Service/ Retired personnel of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all para military forces.

All other fee payable by the aforesaid category of students shall be as per the rates applicable to the general category students.

(ix) 100% Fee waiver Scheme for the students of Jammu and Kashmir and Ladakh and 50 % Concession in fees for the students of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands, Lakshadweep and North Eastern States.

The Institute aligning with the initiatives of Government of India for inclusive growth of people from different parts of country introduced a 100% percent Fee Waiver Scheme for the students from Jammu and Kashmir and Ladakh and 50 % Concession in fees for the students of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands, Lakshadweep and North Eastern States. The scheme is expected to provide a window of opportunity to the youth of these UTs and States to come to the mainstream.

(x) All India Online Company Law Quiz

The Institute has been conducting All India Company Law Quiz for the last several years. The format of the competition was changed during the year 2019 to enhance the participation levels and the competitive spirit among the students. Online Company law quiz was conducted during the year separately for Foundation, Executive and Professional Programme students. The Registration for the competition was done through online mode. Preliminary round and semi-final round was conducted through online process, whereas Final round was conducted at a venue in physical mode which was hosted by Ahmedabad Chapter. Cash award of Rs 50,000/- for first prize, Rs 30,000/- for second prize and Rs 20,000/- for third prize, along with commendation certificate, were given to winners of each level i.e. Foundation, Executive & Professional.

(xi) 20th National Conference of Student Company Secretaries

The 20th National Conference of Student Company Secretaries titled “Yuvotsav 2020” was organised at Kolkata, on 12th January, 2020 to mark the 157th Birth Anniversary of Swami Vivekananda. The theme of the conference was “Future Meets Present”. ICSI has decided to celebrate Yuvotsav every year on 12th January.

The enthusiasm shown by the Regional/Chapter offices which nominated the students for the Student Conference was overwhelming. Twenty different competitions were organized wherein teams from Regional Councils and Chapters of the Institute participated. It was a great opportunity and a learning experience for the students.

(xii) All India Essay Writing Competition, All India Debate Competition & All India Moot Court Competition

In order to increase the participation levels and the learning experience of students, the guidelines of All India Essay Writing Competition, All India Debate Competition and All India Moot Court Competition were amended. The aforesaid competitions were organised at three levels i.e. Chapter Level, Regional Level and National Level for students of each stage of CS Course. During the year, the national rounds of the aforesaid competitions were organised as per details given below:

Name of the Competition	Host Regional Council of National Round	Held on
All India Moot Court Competition	NIRC	17th January, 2020
All India Debate Competition	SIRC	2nd November, 2019
All India Essay Writing	SIRC	October, 2019

Competition		
-------------	--	--

(xiii) Celebration of Teachers' Week

The Institute as a part of knowledge initiative, celebrated the week from 5th September, 2019 to 11th September, 2019 as Teachers' Week. As part of the initiative, the Institute organised Teachers' Conferences on the theme "Empowering Educators" by inviting faculties of various Colleges and Universities at 45 Regional/ Chapter Office locations. In the Teachers' Conference organised at New Delhi, Shri Sanjay Dhotre, Hon'ble Minister of State for HRD was the Chief Guest. The Conferences, which witnessed participation of faculties in the fields of Commerce, Management and Law from premier educational institutes, Colleges and Higher Secondary Schools, were aimed at providing a platform to the academia for sharing their knowledge. The Institute also utilized the opportunity to update the participants about the current topics related to Companies Act, GST etc. Due to the overwhelming response from the teaching fraternity from across the country, the more such conferences were organized in the month of September 2019.

During September 2020, the Institute celebrated the Teachers' Week from 5th September, 2020 to 11th September, 2020.

(xiv) Online Quiz on Current Affairs and General Knowledge

The Institute, through a novel initiative, for creating awareness among the prospective students about the profession organised Online Quiz on Current Affairs & General Knowledge. There was no participation fee and the students could register in. The quiz contests were held in two different categories :

i. Category 1 - students of class 11&12

ii. Category 2 - Students pursuing Graduation. For both categories three rounds - prelims, semi-final and final were held on three different dates and the winners in each Category were rewarded with cash prizes.

Apart from the 1st, 2nd and 3rd prize worth Rs. 50000, Rs. 25000 and Rs.10000 respectively there was a State/Union Territory Topper Prize of Rs.5000 and also 10 consolation prizes of Rs. 1000 each in both categories.

(xv) E-Vidhya Vahini - Commencement of ICSI free online Crash Course

ICSI started an online crash course E-Vidhya Vahini for the students of the Institute who were appearing in June 2020 examination. The widespread Corona virus Pandemic and the ensuing lockdown has brought new challenges for Educational Institutions. To Support the students of the Institute during such tough times when pandemic has adversely affected our lives, the Institute rolled out online free crash course for the Students appearing in June 2020 examination. Classes were later made available to all the students keeping in view the requests received and large interest of the Students. The video lectures of the online crash course were also made available simultaneously at <https://elearning.icsi.in> and you tube channel of ICSI for the students of the Institute.

The crash course classes were commenced from 18th May, 2020 for all the subjects of Foundation, Executive and Professional Programme for students of new and old Syllabus. The sessions were taken by the renowned faculties with an enriched experience in education. During the classes, doubts of the students were also solved which helped them in preparing for the examination.

(xvi) Free online Refresher/Doubt clearing classes for the students appearing in CSEET held on 29th August 2020

ICSI organized free online Refresher/Doubt clearing classes for the students who appeared in CSEET which was held on 29th August 2020 <<https://www.icsi.edu/media/webmodules/1cseet.pdf>>. Classes were taken by renowned faculties having wide experience in the subjects. Online classes commenced from 16th August 2020.

Classes were attended by students appearing in CSEET in large numbers and video lectures of classes were also uploaded at the YouTube channel of ICSI for the students who could not attend the online classes.

21. BRAND ENHANCEMENT & MEDIA VISIBILITY

- (i) The Institute in its constant endeavour to enhance the brand visibility of the Institute and the CS profession, gained extensive coverage in Print, Electronic and Digital media throughout the year. ICSI news and events were covered through Press Releases, Press conferences, Media interaction, Live Panel discussions, Social media etc. Brief details are as under:

Particulars	Number
Press Coverage of ICSI events, announcements	1647

Press Conferences	23
Exclusive Interview and write-ups of ICSI Spokesperson in Print media viz., Times of India, Business Standard, Financial Express, Business Line, Pioneer, Indian Express, Free Press Journal, Amar Ujala, Hindustan, Dainik Bhaskar, Patrika, Prabhat Khabar, Nai Dunia, The Week, Outlook, Outlook Business, India Today, Business World, Pratiyogita Darpan, Competition Refresher, Competition Success Review, Careers 360, etc.,	32
Coverage on Electronic Media	27
Number of videos created for brand promotion	24
Half hour special episodes on Electronic Media (ET Now, Doordarshan, Times Now, CNBC TV 18 and India Today TV)	4

(ii) Collaborations with Newspapers

- ICSI initiated the idea of providing special e-newspapers to CS members during the COVID-19 Lockdown period. Tie-up proposal for providing e-papers were finalised with Indian Express, Financial Express, Free Press Journal, ChhapterChhapter & Dainik Vishwamitra on Free of Cost basis for the members. The Newspapers are compiled in a single mail and are being sent to all members on daily basis.

(iii) Social Media Presence

ICSI Social Media Page	Followers (till 15 th September 2020)
Facebook : https://www.facebook.com/ICSI	1,25,502
Twitter : https://twitter.com/icsi_cs	46,154
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/theicsi	9,950
Instagram : https://www.instagram.com/theicsi/	37,400
Youtube : https://www.youtube.com/user/TheCsInstitute/videos	62,700

(iv) Brand Promotion

- General Interest Magazine / Newspapers:** CS Course Registration Advertisement were released in Education Special / B-School Special / leading Career Magazines viz., Outlook, The Week Magazine, The Dialogue and Free Press Journal
- Competition Magazines:** Advertisements highlighting the Cut-off dates for registration, for CS Executive & Foundation Programme were released in Pratiyogita Darpan, Competition Refresher, and Competition Refresher- Year Book & Career Guides.
- Campaign on High Hit Websites & Social Media:** ICSI Advertisement campaign highlighting the Cut-off dates for registration, for CS Executive & Foundation Programme were released on Shiksha.com, Jagranjosh.com, educationtimes.com, Googleadwords, Facebook and LinkedIn.
- Business Magazines:** Full page coloured “Corporate Advertisements” highlighting the “Role of CS” were released in – Business world, Business Standard, India Today, Indian Express and in the Souvenir of Rural Business Summit & Trade Fair 2019.
- Promotion of Integrated Company Secretaryship Course:** Advertisement for “Integrated Company Secretaryship Course” was published in all Editions of Education Times, Hindu, Business Line and Business Standard.
- ICSI Events:** Quarter page Colour Advertisements were released for major ICSI Events like 51st Foundation Day, ICSI Excellence Awards

22. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(i) Shaheed Ki Beti Certificate Initiative

As part of social responsibility and in alignment towards the initiatives of Government of India, “Shaheed Ki Beti” initiative was launched during the Inaugural Ceremony of Golden Jubilee Year of ICSI held on 4th October 2017 and the Institute got the privilege to confer the first certificate under this scheme to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Under ‘Shaheed Ki Beti’ Certificate initiative, the Institute is providing financial support to the girl child of martyrs for her higher education.

A separate corpus has been created and the amount accumulated is donated to the concerned wing of Ministry of Defence, Government of India and as on 31st March 2020, the Institute has donated an accumulated amount of Rs. 20 Lakhs in this regard. Shri Rajnath Singh, Honorable Union Minister of Defence, Government of India was kind enough to receive one such contribution during the year on behalf of Ministry of Defence, Government of India.

(ii) Donations

Understanding the need to support the efforts of the government in scaling up the public healthcare infrastructure, the Institute has contributed a total sum of Five crore thirty lakh rupees to the PM CARES Fund with the primary objective of dealing with this unprecedented challenge posed by the spread of COVID-19 pandemic, and to provide relief to those affected. The contribution comprises contribution from the Corpus of ICSI, voluntary contribution made by the members of ICSI and Voluntary contribution of one-day salary by ICSI employees Pan-India.

23. ICSI-CENTRE FOR CORPORATE GOVERNANCE, RESEARCH AND TRAINING (ICSI-CCGRT)

The primary objective of the Centre is to act as a catalyst organization in the professional development of the Indian corporate sector through qualitative research and high-level corporate training with ‘Corporate Governance’ as the thrust area. Since its inception, the Centre has undertaken a number of activities aimed towards fostering research. CCGRT possesses state-of-the-art infrastructure with air-conditioned and Wi-Fi enabled training halls, conference room, faculty room and a large auditorium. Further, CCGRT has twenty-two well-furnished twin-sharing air-conditioned rooms for stay of participants of research, training and workshops. During the year 2019-20, various initiatives taken up by CCGRT are as follows: -

1. Professional Development Programmes

ICSI-CCGRT conducted Professional Development Programmes (PDPs) for members, students, corporates and regulatory / government bodies. Apart from programmes for updating the knowledge base of Company Secretaries

During the lockdown period, the ICSI-CCGRT took up various virtual training initiatives including two-days MS-Office training programmes, Workshop on soft skills, National Opinion Writing Competition; to name a few.

2. Integrated Company Secretary Course

In order to groom the students of Company Secretary Course better to meet present day challenges and build a niche cadre of governance professionals who can shoulder upon the responsibilities assigned to them in an evolving business environment and ensure governance in true letter and spirit, Centre for Corporate Governance, Research & Training (CCGRT) of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) offered 6th batch of Integrated Company Secretary Course (Full-Time).

3. Residential Management Skills Orientation Programme (R-MSOP)

CCGRT in the year 2019-20, conducted eight R-MSOPs in which 281 students successfully completed the programme. In the near future, the ICSI-CCGRT shall be organizing virtual MSOPs for the benefit of the students at large.

4. Publications (e-newsletter and bulletin)

During the year under review, CCGRT has come out with monthly e-Newsletter ‘Susashanam’, that is focused on wide dissemination of insights among governance professionals. It had also published on a monthly basis, an e-publication, Amrutkalash that discussed ancient word of wisdom in the area of governance.

National lockdown gave an opportunity to come up with more research driven contemporary e-bulletins like ‘A Comprehensive Checklist on Companies Act’ which is evoking good response from the members.

5. Unique Initiative – CCGRT AAP KE DWAR

CCGRT has started this unique campaign “CCGRT AAP KE DWAR”. In this initiative, CCGRT extends its academic and administrative support to host chapters in conducting capacity building workshops on NCLT.

In these workshops, members are provided with the opportunity to learn the drafting and advocacy skills with rigorous research activities. A Moot Court Structure is prepared to provide real like platform for appearance before the seasoned professionals acting as moot-judges for the workshops. During the workshops, sitting members of NCLT and NCLAT are also invited to interact with the participants so as to improve the skills of advocacy for appearing before the adjudicating authorities.

During the year, CCGRT conducted six workshops at, Jaipur, Surat, Kochi, Bhayander, Hyderabad and the one at CCGRT campus.

6. Capacity Building Initiatives for Members and Students

Series of Three Days Residential Workshops on Effective Business Communications were organized by CCGRT to enhance the verbal and non-verbal skills including the presentation skills of the members of the ICSI. To enhance the IT skills of the members, special workshops on MS-Excel were organized.

24. ICSI Centre of Excellence (CoE), Hyderabad

(i) Centre for Professional Training & Research in Arbitration

For the competency development of CS professionals in the emerging area of Arbitration, ICSI-COE has Launched "*MadhyasthaEkVikalp*": A series of three days basic and advanced level skill oriented Certificate Programs and Professional Training Programs on Commercial Arbitration and Conciliation thereby paving the way for professionals to practice as Arbitrators. The first residential program in this series was held in December 2019 and subsequently two programs in online mode were conducted in the months of June 2020 and July 2020.

(ii) Continuing Professional Education and Development Programs

ICSI-COE, has launched "*Bahumukhi*": A Series of calendar based programs, for members which aims to provide a platform for skill enhancement and upgradation of the knowledge base of members on functioning as Company Secretary.

(iii) Student Trainings

During the year, COE has organised Orientation Programs for Foundation and Executive students, Academic Development Programs, Executive Development Programs, etc as per the institute guidelines. Residential accommodation is offered to participants from other locations attending the programs.

(iv) Residential Management Skills Orientation Program (R-MSOP)/CLDP

During the year, ICSI-COE successfully conducted three "*15 days RMOSP*".

(v) Research Activities

ICSI-COE has developed a network of researchers to undertake research based projects on contemporary topics.

(vi) Publications

In an attempt to gather the views of professionals on measures for economic revival in Post Covid-19 Scenario, the ICSI-COE has brought forth an exclusive compilation of the varied perspectives of members under the aegis of "*The Impact Analysis of Turbulent Times on Company Secretaries*". The e-publication released in June 2020, consists of 26 selected articles of members from across the country and highlights the role of Company Secretaries in rebuilding the economy during turbulent times and exploring growth scenarios for expansion of the services of Company Secretaries. The modern age Corporate Governance Models are influenced by the wisdom found in Ancient Indian Scriptures. Extending this thought, ICSI-COE in the month of May 2020 released a *Fortnightly E-Publication* titled "*Gyan Ganga: Corporate Governance through Ancient Indian Scriptures*". This series presents the views expressed by members on some of the ancient Indian Scriptural sources that illustrate the modern governance precepts and practices and sensitising the reader on ways to harmonise both ethical and regulatory requirements in corporates. COE published till date 7 articles in this series and circulated to all members. All the publications are made available on the COE Website for reading.

25. INFORMATION TECHNOLOGY

With the rapid growth of information technology and technology enabled services, new methods and areas of utilization have emerged in the field of education and professional development.

Some of such technology oriented initiatives are as under :

(i) **Development of e-CSIN portal**

The e-CSIN shall be generated by the members at the time of employment as a Company Secretary as well as at the time of demitting office. This e-CSIN System has been developed by ICSI to facilitate its members for verification of their appointment and cessation.

(ii) **Development of UDIN portal**

The Institute has rolled out an initiative in the form of a Unique Document Identification Number (UDIN) in an attempt to ensure self-governance and availability of information about the documents signed by the Practicing Company Secretary. It has been developed to facilitate its members for verification and certification of the documents and for ensuring authenticity of documents submitted to Regulators.

(iii) **Online Portal for Disciplinary Cases**

ICSI has taken an initiative of automation of the various manual processes of disciplinary related investigations of Professionals and other Misconduct and Conduct of Cases of the Directorate of Discipline of the ICSI through the development and implementation of a Web Based Application Software in an integrated form.

(iv) **Placement portal**

Placement portal is web-based platform developed to facilitate the members, students for suitable job/training opportunities and facilitates organizations desirous of recruiting qualified Company Secretaries and Trainees. It has features which enables the recruiters to place vacancies on real time basis. At the same time, members can view and apply for the job. It can be accessed at the link <https://placement.icsi.edu/>

(v) **Under STIMULATE project, the entire training services is now available on Online Platform to facilitate the stakeholders to get quick and timely response from the Institute. The following activities part of the training of students are automated :**

- Students can now apply online for all kinds of short term trainings like EDP, PDP, 15 Days Academic Programme, MSOP, 15 days specialized training to RC/Chapters and Headquarters.
- Students can make online payment for such training programme through Payment gateways.
- Companies and PCS can now register online for imparting practical training.
- All the practical training shall be executed in an online platform in which students can send their training agreement, appointment letter and students will get the auto generated training sponsorship letter, auto generated mail, auto generated SMS at every stage of training.
- Both the trainers and trainees can check their status through using their login credentials.
- Both the quarterly report and project report can be submitted online.
- Student can apply for training exemption online. They can check their application status online
- The students will get the training completion certificate showing the history of all kinds of training undergone by them which will enable them to apply for ACS membership subject to other conditions.

(vi) **New Centralized Payment Gateway system**

New centralized payment gateway system has been developed for all Regional/Chapter Offices and payments can be directly transferred to their respective local Banks.

(vi) **PCS skills directory search.**

This utility developed by the Institute has an open search option to search skills of Company Secretaries in Practice based on location, expertise, etc

- (viii) **eAgenda Management System:** The Institute has been contemplating to implement e-agenda management system as part of the endeavour to make sure the availability of agenda/minutes on e-platform to enable Council Members to refer agenda/ minutes while travelling.

Besides, the Institute took up development of various other online/offline software modules. Some of such initiatives are Stall Booking for National Convention, Reimbursement Module for employees, portal for collection of Donations during national disasters, Calendar of ICSI events, registration portal for One Day Orientation Programme, Module for posting of results of tests under Class Room Teaching organized by Regional/ Chapter Offices, Module for empanelment of faculty/ academic resources, e-Chartered Secretary, Pensioners' Portal, online updation of Programme Credit Hours, Digi-locker for Members, Complinty Compliance Software, Registration Portal for ICSI Middle East Membership Scheme, Member Verification under ICSI-ICSA MOU, online facility for collection of Corporate Membership Fee, upgradation of ICSI applications for enhancing security in view of Google Chrome issue, CSEET Registration Portal, etc.

- The Institute is working on initiatives: *CSR Award Portal*
- Corporate Governance Award Portal
- Secretarial Audit Report Award Portal
- Licentiate Portal
- Peer Review Board Portal

26. ICSI IIP

ICSI Institute of Insolvency Professionals (ICSI IIP) is a frontline regulator registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 amongst 3 Insolvency Professional Agencies registered across the country. ICSI IIP is registered under Section 8 of the Companies Act, 2013 and is a wholly owned subsidiary of the Institute of Company Secretaries of India. Main functions of ICSI IIP are to enrol, educate, train, monitor and disciplining the professional members. ICSI IIP lays down the standards of professional conduct and develops best practices for its professional members. ICSI IIP has registered about 986 Insolvency Professionals who are Company Secretaries, Management experts, Advocates, Cost Accountants and Chartered Accountants. The governing Board of ICSI IIP consists of eminent persons as Independent Directors and the nominees from ICSI.

WEBINARS/PROGRAMMES/ WORKSHOPS/INTERACTIVE MEETINGS

In order to support the IPs in establishing themselves in the new insolvency regime ICSI IIP has organised various webinars/programmes/ workshops/interactive meetings on a regular basis. From 1st April, 2019 onwards:

- 16 Pre-registration courses have been conducted for the IPs
- 28 webinars have been conducted by ICSI IIP on prevailing topics reaching maximum number of professionals across Country. (from 1st April, 2019 onwards)
- 6 interactive meets with insolvency professionals have been conducted by ICSI IIP to accumulate the opinions & concerns of the insolvency professionals.
- 6 workshops have been organised
- 4 national seminars have been organised
- 4 training programmes for preparation of limited insolvency examination have been organised
- 12 roundtables, meets, awareness programmes etc have been organised

RESEARCH & KNOWLEDGE INITIATIVES

ICSI IIP has carried out a number of activities for the education and development of Insolvency professionals such as bringing out practical oriented publications:

A. The publications brought out till now includes:

1. Final word under IBC
2. Limited Insolvency Examination Preparatory Guide
3. IBC Learning Curves
4. Insolvency And Bankruptcy Code, 2016 (With Rules & Regulations) (Five versions till date):
5. Interim Resolution Professional- A Handbook (3 editions till date)
6. Practical Aspect Of Insolvency Law (4 editions till date)
7. 100 Landmark Judgments of NCLAT - An insight into IBC

8. Judicial/Regulatory Rulings for Stakeholders- A handbook (2 editions till date)
9. Voluntary Liquidation: A handbook Insolvency And Bankruptcy Code, 2016 (With Rules & Regulations)
10. IBC Case Law Compendium (With Case Briefs)
11. Pronouncements Under The Insolvency And Bankruptcy Code, 2016 – Issue Analysis
12. Simplified Guide On Insolvency And Bankruptcy Code
13. Brochure For Bankers- “The Insolvency And Bankruptcy Code, 2016” - A Boon For Bankers

B. Insolvency and Bankruptcy Journal (A Monthly Magazine)

ICSI IIP has come out with its monthly journal from November, 2017 (less than one year of incorporation) onwards. ICSI IIP is the first organisation to develop publish monthly journal (ICSI IIP Insolvency and bankruptcy Journal) for the members. ICSI IIP Insolvency and Bankruptcy Journal was the first journal in the Country on IBC.

C. Other knowledge initiatives

1. Other knowledge initiatives include bringing out Knowledge Reponere – A Weekly Update, Knowledge Capsule- A fortnightly update , Daily learning curves, Reader’s Rendition on daily basis, MCQ Series covering syllabus for Limited Insolvency Examination,

27. ICSI Registered Valuers Organisation (ICSI RVO)

ICSI Registered Valuers Organisation (ICSI RVO) is a Section 8 Company, wholly owned subsidiary of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and registered with IBBI is created with the objective of educating, regulating and monitoring the Registered Valuers. Where valuation is required to be made in respect of any stocks, shares, debentures, securities, etc. of a company under the Companies Act, 2013, it shall be valued by a person having such qualifications and experience and registered as a valuer in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed under Section 247 of the Companies Act, 2013. A Company Secretary in practice is recognized to be Registered Valuer for the asset class Securities or Financial Assets under the Companies (Registered Valuer and Valuation) Rules, 2017.

Key Highlights:

- Pan India, the company had conducted twenty eight batches of 50 Hours Educational Courses (in physical mode) successfully in various locations which includes New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Gowahati, Bangalore, Noida, Agra, Ludhiana, Pune etc.
- In terms of both Registered Valuers as well as Valuer Members, the company has achieved manifold increase in numbers.
- The Company is an active member in the “Committee of Experts to Develop a Standard Template for Disclaimers” constituted by IBBI and as a lead successfully submitted its report to the IBBI in April, 2020.
- The Company actively represented in the “Workshop to share findings of Peer Review for the three Asset Classes as per Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017”, organised by IBBI on 14th February, 2020.
- The company has initiated an unique programme i.e., Research Paper Writing Competition in seven active areas of Valuation which includes the members of ICSI as well as ICSI RVO.
- For the engagement and fuller utilisation of time during lock down period, ICSI RVO is the first RVO among its peers to announce Online batches of 50 Hours Educational Course in asset class Securities or Financial Assets. The first online batch was concluded on 26th April, 2020.
- ICSI RVO is the first RVO among its peers to complete seven online batches of 50 Hours educational courses successfully. All the batches were interactive and got overwhelming response not only from Company Secretary professional but also from other professionals.
- To boost the morale of employees at Chapter level, the company, along with ICSI had given two awards in the 2nd Leadership Summit held from 6th to 8th February, 2020 at Manesar. Bengaluru Chapter was awarded in the category of ‘ICSI RVO Valuation Award 2019 for Metro Cities’ and Jaipur Chapter was awarded in the category of ‘ICSI RVO Valuation Award 2019 for Non-Metro Cities’.

28. FUTURE OUTLOOK

- The past few months have been able to manifest a 360 degree turnaround in the approaches applied in the functioning of not just corporates or professionals, but organizations and individuals globally, irrespective of their arena of activity. The Institute of Company Secretaries of India is no different. The spread of the pandemic followed by nationwide lockdown brought with it, a new set of limitations and challenges. In the events organised as capacity building and knowledge enhancement initiatives not only by the Headquarters but all the Chapters, the basic schema of things sought a dynamic alteration.
- To this came the rescue of technology. The connectivity through Communications Technology, social media and the various platforms and apps gave not only ease of access but a far greater reach and connectivity. Webinars were organised to make good for the lack of physical meetings in the form of study circles, seminars and conferences deliberated on topics pertaining to enhancing professional acumen, leadership and personal life skills.
- As far as the future Governance Professionals of the nation are concerned, after much thought, deliberation and postponements, the decision to merge the June, 2020 session with December, 2020 session of Examinations was well appreciated. While the year witnessed the first CSEET held amidst trying circumstances, the same and all the incidents will serve as the perfect motivation for the times to come wherein, we, the Institute, its members, students and all other stakeholders shall have a renewed belief in the strength of our togetherness.
- The adage saying that the 'Future is uncertain' might have found its true sense in the months gone by; but the professionalism that we carry does give us the much needed inspiration and impetus to chalk out our journeys ahead. The discussions in Webinar sessions with some of the most luminary dignitaries have brought along the realisation that the responsibility of strengthening governance structures not only in India Inc. but across all spheres rests on the shoulders of the Institute and its members or the Governance Professionals. Be it the grassroots of the nation or holding the torch of good governance high above for the world; the ICSI with more than half the Company Secretary membership of the world would have to take lead as the frontrunner of not just good governance but best governance globally; a goal that well aligns with the vision, mission and motto of the Institute. And it is for the achievement of this goal and vision that the ICSI while having stepped foot in three different nations through its Overseas Centres at UAE, USA and UK intends to expand the ambit of good governance in many more nations in the times to follow.

29. ACKNOWLEDGEMENTS

The Institute would like to express its gratitude to the First Citizen of the nation, Hon'ble President of India, Hon'ble Vice President of India, Hon'ble Prime Minister of India and places on record its gratefulness to the Prime Minister's Office, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Finance and other Ministries, Governors, Chief Ministers of States, GST Council, IEPF, SEBI, RBI, IBBI, CCI, Stock Exchanges, Departments and Offices of the Central and State Governments, as well as all other regulatory authorities for the faith placed by them on the profession and the Institute and for their continuing guidance and support for the development of the profession.

The Council places on record its appreciation towards all the dignitaries and luminaries hailing from all parts of the nation and even from beyond the territorial boundaries of the nation for their kind presence, their words of wisdom and the knowledge shared with us through the Webinars organised as capacity building initiatives. The expectations from the profession shall serve as guiding light for the Institute in the times to come.

The Council is also grateful to the Financial, Industrial and Investment Institutions, Chambers of Commerce, Trade Associations and other Agencies for pursuing varied collaborations as well as encouraging the activities of the Institute throughout the year. The Council wholeheartedly appreciates the Indian Industry including all its entailing segments, in its entirety for recognising the expertise of the Company Secretaries and engaging their services to ensure, promote and propagate the cause of good governance.

The Council is thankful to the members of the Disciplinary Committee, Board of Discipline, Secretarial Standards Board, Auditing Standards Board, Quality Review Board, Peer Review Board, Editorial Advisory Board, Expert Advisory Board, Jury for the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance, Core Group on implementation of Vision new ICSI 2022, Core Groups and Task Forces of the Institute for their contributions in shaping the present and future impact of the ICSI activities in the Indian scenario. Last but not the least, the co-operation and support of the Regional Offices and Chapters is deeply acknowledged and the Council is equally

grateful to the entire Team-ICSI for their immense enthusiasm, dedication and commitment in supporting, implementing and executing the multi-faceted and multi-focused decisions taken by the Council from time to time.

For and on behalf of the Council of
the Institute of Company Secretaries of India

S ASHISH GARG, President
[ADVT.-III/4/Exty./267/2020-21]

APPENDIX-A

LIST OF STANDING, NON-STANDING COMMITTEES / BOARDS OF THE COUNCIL FOR THE YEAR 2020.

	S/Shri	
1	Executive Committee	
	1.	Ashish Garg Chairman
	2.	Nagendra D.Rao Member
	3.	Ranjeet Pandey Member
	4.	Manoj Pandey Member (Govt. Nominee)
	5.	Devendra V. Deshpande Member
	6.	Manish Gupta Member
	7.	Siddhartha Murarka Member
2	Finance Committee	
	1.	Ashish Garg Chairman
	2.	Nagendra D.Rao Member
	3.	Ranjeet Pandey Member
	4.	MadhuVij (Dr.) Member (Govt. Nominee)
	5.	Chetan B. Patel Member
	6.	Deepak Kumar Khaitan Member
	7.	NPS Chawla Member
3	Examination Committee	
	1.	Ashish Garg Chairman
	2.	Nagendra D. Rao Member
	3.	Gyaneshwar Kumar Singh Member (Govt. Nominee)
	4.	B. Narasimhan Member
	5.	NPS Chawla Member
	6.	Praveen Soni Member
	7.	Vineet K. Chaudhary Member
4	Financial Services Committee	
	1.	Praveen Soni Chairman
	2.	Anil Gupta Member (Govt. Nominee)
	3.	B. Narasimhan Member
	4.	Chetan B. Patel Member
	5.	Deepak Kumar Khaitan Member
	6.	Devendra V. Deshpande Member
	7.	Ramasubramaniam C. Member
5	Corporate Laws and Governance Committee	
	1.	NPS Chawla Chairman
	2.	Chetan B. Patel Member
	3.	Manish Gupta Member
	4.	Ramasubramaniam C. Member
	5.	Siddhartha Murarka Member
6	Professional Development Committee	
	1.	Ashish Garg Chairman
	2.	Ranjeet Pandey Member
	3.	Anil Gupta Member (Govt. Nominee)

	4.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	5.	Chetan B. Patel	Member
	6.	Hitender Mehta	Member
	7.	NPS Chawla	Member
	8.	Ramasubramaniam C.	Member
	9.	Siddhartha Murarka	Member
7	Training & Educational Facilities Committee		
	1.	Nagendra D.Rao	Chairman
	2.	MadhuVij (Dr.)	Member (Govt. Nominee)
	3.	B. Narasimhan	Member
	4.	Deepak Kumar Khaitan	Member
	5.	Devendra V. Deshpande	Member
	6.	Manish Gupta	Member
	7.	Praveen Soni	Member
	8.	Vineet K. Chaudhary	Member
8	Practising Company Secretaries Committee		
	1.	Deepak Kumar Khaitan	Chairman
	2.	B. Narasimhan	Member
	3.	Chetan B. Patel	Member
	4.	Manish Gupta	Member
	5.	Praveen Soni	Member
	6.	Ramasubramaniam C.	Member
	7.	Vineet K. Chaudhary	Member
9	Information Technology Committee		
	1.	Chetan B. Patel	Chairman
	2.	Ranjeet Pandey	Member
	3.	Santhanakrishnan S.	Member (Govt. Nominee)
	4.	Devendra V. Deshpande	Member
	5.	NPS Chawla	Member
10	Peer Review Board		
	1.	Ramasubramaniam C.	Chairman
	2.	Siddhartha Murarka	Vice-Chairman
	3.	G. M. Ganapathi	Member
	4.	Hitender Mehta	Member
	5.	L. N. Joshi	Member
	6.	R. Sridharan	Member
	7.	VineetK.Chaudhary	Member
11	Placement Committee		
	1.	Praveen Soni	Chairman
	2.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	3.	B. Narasimhan	Member
	4.	Chetan B. Patel	Member
	5.	Ramasubramaniam C.	Member
12	PMQ Course Committee		
	1.	Manish Gupta	Chairman
	2.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	3.	Deepak Kumar Khaitan	Member
	4.	Devendra V. Deshpande	Member
	5.	Hitender Mehta	Member
	6.	Siddhartha Murarka	Member
13	Secretarial Standards Board		
	1.	Satwinder Singh	Chairman
	2.	S. Sudhakar	Vice-Chairman
	3.	AwanishDwivedi	Member
	4.	B.Renganathan	Member
	5.	D. C. Jain	Member
	6.	Deepak Kumar Khaitan	Member

	7.	Dhananjay Shukla	Member
	8.	DwarakaNath C.	Member
	9.	Makarand Joshi	Member
	10.	MorurElayappanVadivelSelvamm	Member
	11.	Narayan Shankar	Member
	12.	Praveen Soni	Member
	13.	Rajveer Singh	Member
	14.	R.Kalidas	Member
	15.	R. S. Bhatia	Member
	16.	Sanjeev Grover	Member
	17.	S. C.Sharada (Ms.)	Member
	18.	S. C. Vasudeva	Member
	19.	S. K. Aggarwal	Member
	20.	T.VenkatRamana	Member
	21.	Representative of RBI	Member
	22.	Representative of ICAI	Member
	23.	Representative of MCA	Member
	24.	Representative of ICAI-COST	Member
	25.	Representative of CII	Member
	26.	Representative of SEBI	Member
	27.	Representative of BSE	Member
	28.	Representative of NSE	Member
	29.	Representative of FICCI	Member
14	Expert Advisory Board		
	1.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Chairman
	2.	Anil Gupta	Member (Govt. Nominee)
	3.	Santhanakrishnan S.	Member(Govt. Nominee)
	4.	NPS Chawla	Member
	5.	ShilpeshDalal	Member
	6.	Ashok Kumar Kasera	Member
	7.	AvineeshMatta	Member
	8.	S. M. Pramod	Member
	9.	J. P. Sharma (Dr.)	Member
	10.	PunitHanda	Member
	11.	Raj K. Agarwal (Dr.)	Member
	12.	Sanjeev Gupta (Dr.)	Member
	13.	Santosh Macherla	Member
	14.	K Sethuraman	Member
	15.	Joy Ghosh	Member
	16.	Rakesh Singh	Member
	17.	Ashish Kulkarni	Member
	18.	Pravin V. Patil	Member
	19.	Rakesh Garg	Member
15	Research & Publication Committee		
	1.	NPS Chawla	Chairman
	2.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	3.	Hitender Mehta	Member
	4.	Praveen Soni	Member
	5.	Vineet K. Chaudhary	Member
16	Editorial Advisory Board		
	1.	Hitender Mehta	Chairman
	2.	Anil Gupta	Member(Govt. Nominee)
	3.	MadhuVij (Dr.)	Member(Govt. Nominee)
	4.	Akhil Prasad(Dr.)	Member
	5.	Astha Gupta (Ms.)	Member
	6.	D. K. Jain (Dr.)	Member
	7.	G. R. Bhatia	Member

	8.	H. M. Dattatri	Member
	9.	Manoj Bisht	Member
	10.	Ratnesh Rukhariyan	Member
	11.	Siddhartha Murarka	Member
	12.	Vasudev Rao Devki	Member
	13.	Vinod Singhania (Dr.)	Member
17	ICSI-CCGRT & COEs Management Committee		
	1.	Devendra V. Deshpande	Chairman
	2.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	3.	Ashish Karodia	Member
	4.	B. Narasimhan	Member
	5.	Deepak Kumar Khaitan	Member
	6.	Gopal Chalam	Member
	7.	Kaushik Jhaveri	Member
	8.	Manish Gupta	Member
	9.	Om Prakash Bagdia	Member
18	Election Reforms Committee		
	1.	B. Narasimhan	Chairman
	2.	Santhanakrishnan S.	Member (Govt. Nominee)
	3.	Chetan B. Patel	Member
	4.	Devendra V. Deshpande	Member
	5.	Manish Gupta	Member
19	Regulations and Chapter Guidelines Committee		
	1.	Siddhartha Murarka	Chairman
	2.	Ahalada Rao Vummenthala (Dr.)	Member
	3.	Hitender Mehta	Member
	4.	Praveen Soni	Member
	5.	Ramasubramaniam C.	Member
20	Quality Review Board		
	1.	Ms. Nishi Singh	Chairperson
	2.	Devendra Kumar	Member
	3.	Ritika Bhatia	Member
	4.	Manish Gupta	Member
	5.	Pramod Kumar Rai	Member
21	International Affairs Committee		
	1.	Ranjeet Pandey	Chairman
	2.	B. Narasimhan	Member
	3.	Hitender Mehta	Member
	4.	NPS Chawla	Member
22	Auditing Standards Board		
	1.	Vineet K. Chaudhary	Chairman
	2.	Devendra V. Deshpande	Vice-Chairman
	3.	Amit Gupta	Member
	4.	Anshul Kumar Jain	Member
	5.	Ashok Tyagi	Member
	6.	Deepak Sharma	Member
	7.	G. V. Srinivasa Murthy	Member
	8.	Kumudini Bhalerao (Ms.)	Member
	9.	Manoj Rajaram Hurkat	Member
	10.	Mukesh Jain	Member
	11.	Munish Kumar Sharma	Member
	12.	Pankaj Virmani	Member
	13.	Raghvendra Joshi	Member
	14.	Rajeev Bhambri	Member
	15.	Ramasubramaniam C.	Member
	16.	Ravi Sharma	Member
	17.	Rekha Nayak (Ms.)	Member

	18.	Sachin Agarwal	Member
	19.	Santosh Kumar	Member
	20.	Shikha Rai (Ms.)	Member
	21.	Siddhartha Murarka	Member
	22.	Vishal Arora	Member
	23.	Representative of BSE	Member
	24.	Representative of NSE	Member
	25.	Representative of MCA	Member
23	Disciplinary Committee		
	1.	Nagendra D. Rao	Presiding Officer
	2.	Ranjeet Pandey	Member
	3.	MeenakshiDatta Ghosh (Ms.)	Member (Govt. Nominee)
	4.	NalinKohli	Member (Govt. Nominee)
	5.	B. Narasimhan	Member
24	Board of Discipline		
	1.	Deepak Kumar Khaitan	Presiding Officer
	2.	Manish Gupta	Member
	3.	Asish Mohan	Member

NOMINATIONS ON VARIOUS OUTSIDE COMMITTEES

Sl. No	Name of the Committee/Institution	Institute's representative on the Committee in year 2020
1.	National Advisory committee on Accounting Standards (NACAS) – MCA	CS Ashish Garg, President
2.	Governing Council of the National Foundation for Corporate Governance (NFCG)	CS Ashish Garg, President
3.	Board of Trustees of the National Foundation for Corporate Governance (NFCG)	CS Ashok Kumar Dixit, Officiating Secretary
4.	Indo-UK Accountancy Task Force, Ministry of Commerce and Industry	CS Ashish Garg, President
5.	New India Membership Development Committee of INSOL International	CS Ashish Garg, President
6.	Working Group Constituted in the area of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility as per provisions of LOI signed between India-Netherlands	CS Ashish Garg, President CS Ranjeet Pandey, IPP & Council Member
7.	Advisory Group to the GRI Focal Point India	CS Ashish Garg, President
8.	IEC of Indian Bank Association	CS Ashish Garg, President
9.	Ex-Officio Member of the Sri Aurobindo Foundation for Integral Management (SAFIM) Advisory Board	CS Ashish Garg, President
10.	Primary Market Advisory Committee	CS Ashish Garg, President CS Ranjeet Pandey, IPP & Council Member
11.	Insolvency Law Committee	CS Ashish Garg, President CS Ranjeet Pandey, IPP & Council Member
12.	Committee to advice on Valuation Matters	CS Ashish Garg, President CS Ranjeet Pandey, IPP & Council Member
13.	Accounting Standards Board, ICAI	CS Hitender Mehta, Council Member

14.	Cost Accounting Standards Board, ICAI	CS Nagendra D Rao, Council Member
15.	Cost Audit and Assurance Standards Board, ICAI	CS Ahalada Rao V (Dr.), Council Member
16.	CSIA	CS Ashish Garg, President CS Ranjeet Pandey, IPP & Council Member Vice President, CSIA-2020

APPENDIX-B

**Details of attendance of Members of the Council, Standing,
Non-Standing Committees and Board Meetings**

S. No	Council/Committee	Council		Executive Committee		Finance Committee		Examination Committee		Disciplinary Committee	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
1	CS Ashish Garg	9	9	7	6	5	4	7	6	-	-
2	CS Nagendra D. Rao	9	9	7	6	1	1	1	1	19	16
3	CS (Dr.) Ahalada Rao Vummenthala	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CS B. Narasimhan	9	8	-	-	-	-	7	5	19	16
5	CS Chetan B. Patel	9	8	-	-	5	3	-	-	-	-
6	CS Deepak Kumar Khaitan	9	9	-	-	5	5	-	-	-	-
7	CS Devendra V. Deshpande	9	8	7	5	-	-	-	-	-	-
8	CS Hitender Kumar Mehta	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CS Manish Gupta	9	8	7	6	-	-	4	4	-	-
10	CS NPS Chawla	9	9	-	-	5	1	2	0	-	-
11	CS Praveen Soni	9	8	-	-	4	2	1	1	-	-
12	CS Ranjeet Pandey	9	9	7	7	5	5	6	5	19	17
13	CS Ramasubramaniam C.	9	7	-	-	-	-	2	1	-	-
14	CS Siddhartha Murarka	9	9	7	6	-	-	3	2	-	-
15	CS Vineet K. Chaudhary	9	8	-	-	-	-	7	3	-	-
16	Mr. Anil Gupta	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Mr. Manoj Pandey	6	1	5	0	--	-	-	-	-	-
18	Mr. Gyaneshwar Kumar Singh	9	1	-	-	-	-	7	0	-	-
19	Dr.(Ms.)Madhu Vij	9	2	-	-	5	3	-	-	-	-
20	Mr S.Santhanakrishnan	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mr. Anurag Agarwal	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
22	CS Ashok Kumar Dixit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dates of Meetings	04.05.2019 and 05.05.2019, 27.06.2019, 07.08.2019, 23.09.2019, 05.10.2019, 17.11.2019, 09.01.2020, 19.01.2020, 12.03.2020 and 13.03.2020		02.04.2019, 03.05.2019, 04.07.2019, 11.09.2019, 07.11.2019, 22.12.2019, 08.01.2020(Adj.) 03.03.2020		03.05.2019, 27.07.2019, 29.08.2019, 04.11.2019, 02.03.2020		5.04.2019 and 06.04.2019 and 7.04.2019, 12.04.2019 and 13.04.2019 and 14.04.2019, 15.07.2019, 19.08.2019, 11.10.2019 and 12.10.2019 and 13.10.2019 18.10.2019 and		23.04.2019, 24.04.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 03.06.2019, 26.06.2019, 27.06.2019, 26.07.2019, 27.07.2019, 21.08.2019, 12.09.2019, 21.10.2019,	

S. No	Council/Committee	Council		Executive Committee		Finance Committee		Examination Committee		Disciplinary Committee	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
								19.10.2019 and 20.10.2019, 17.01.2020, 19.02.2020		29.11.2019, 18.12.2019, 30.12.2019, 15.01.2020, 27.02.2020, 06.03.2020, 07.03.2020	

**Details of attendance of Members of the Council, Standing,
Non-Standing Committees and Board Meetings**

S. No	Council/Committee	Financial Services Committee		Corporate Laws and Governance Committee		PDC		TEFC		PCSC	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
1	CS Ashish Garg	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-
2	CS Nagendra D. Rao	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3
3	CS (Dr.) Ahalada Rao Vummenthala	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-
4	CS B. Narasimhan	2	2	-	-	-	-	4	2	5	3
5	CS Chetan B. Patel	2	2	1	0	1	1	3	2	5	4
6	CS Deepak Kumar Khaitan	2	1	-	-	-	-	4	2	5	5
7	CS Devendra V. Deshpande	2	0	-	-	-	-	4	2	-	-
8	CS Hitender Kumar Mehta	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-
9	CS Manish Gupta	-	-	1	1	3	2	1	1	5	5
10	CS NPS Chawla	1	0	1	1	1	0	3	2	-	-
11	CS Praveen Soni	1	1	-	-	3	2	1	1	5	2
12	CS Ranjeet Pandey	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
13	CS Ramasubramaniam C.	2	0	1	0	4	0	-	-	1	0
14	CS Siddhartha Murarka	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-
15	CS Vineet K. Chaudhary	-	-	-	-	3	0	1	1	5	5
16	Mr. Anil Gupta	2	0	-	-	4	0	-	-	-	-
17	Mr. Manoj Pandey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Mr. Gyaneshwar Kumar Singh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dr.(Ms.)MadhuVij	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
20	Mr.S.Santhanakrishnan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mr. Anurag Agarwal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CS Ashok Kumar Dixit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dates of Meetings	27.07.2019, 29.02.2020		03.03.2020		28.07.2019, 22.09.2019, 23.12.2019,		28.07.2019, 21.10.2019, 08.01.2020,		13.04.2019, 06.07.2019, 11.09.2019, 19.12.2019,	

S. No	Council/Committee	Financial Services Committee		Corporate Laws and Governance Committee		PDC		TEFC		PCSC	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
						20.02.2020		26.02.2020		20.02.2020	

**Details of attendance of Members of the Council, Standing,
Non-Standing Committees and Board Meetings**

S. No	Council/Committee	IT Committee		Peer Review Board		Placement Committee		PMQ Course Committee		Board of Discipline	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
1	CS Ashish Garg	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
2	CS Nagendra D. Rao	-	-	-	-	1	0	4	4	-	-
3	CS (Dr.) Ahalada Rao Vummenthala	-	-	3	2	2	2	6	2	-	-
4	CS B. Narasimhan	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
5	CS Chetan B. Patel	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-
6	CS Deepak Kumar Khaitan			-	-	1	1	2	1	18	18
7	CS Devendra V. Deshpande	4	4	-	-	1	0	6	2	-	-
8	CS Hitender Kumar Mehta	-	-	1	1	1	0	6	4	-	-
9	CS Manish Gupta	-	-	-	-	-	-	2	2	18	15
10	CS NPS Chawla	4	1	-	-	-	-	4	3	-	-
11	CS Praveen Soni	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-
12	CS Ranjeet Pandey	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CS Ramasubramaniam C.	-	-	1	1	2	0	4	1	-	-
14	CS Siddhartha Murarka	3	2	4	2	-	-	6	2	-	-
15	CS Vineet K. Chaudhary	-	-	4	3	1	0	-	-	-	-
16	Mr. Anil Gupta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Mr. Manoj Pandey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Mr. Gyaneshwar Kumar Singh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dr. (Ms.) Madhu Vij	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Mr S. Santhanakrishnan	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mr. Anurag Agarwal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CS Ashok Kumar Dixit	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17
	Dates of Meetings	28.07.2019, 11.09.2019, 05.01.2020, 19.02.2020		03.05.2019, 29.08.2019, 22.12.2019, 15.02.2020		22.09.2019, 29.02.2020		14.05.2019, 26.07.2019, 05.10.2019, 18.12.2019, 07.02.2020, 19.02.2020		03.04.2019, 26.04.2019, 17.05.2019, 22.06.2019, 12.08.2019, 29.08.2019, 29.08.2019 (Adj.), 30.08.2019, 12.09.2019, 09.10.2019,	

S. No	Council/Committee	Secretarial Standards Board		Editorial Advisory Board		ICSI-CCGRT Mgmt. Committee		Regulations and Chapter Guidelines Reforms Committee		Election Reforms Committee	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
21	Mr. Anurag Agarwal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CS Ashok Kumar Dixit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dates of Meetings	27.04.2019 and 28.04.2019, 20.07.2019, 31.08.2019, 14.12.2019 and 15.12.2019, 14.03.2020, 27.03.2020 and 28.03.2020 and 29.03.2020		27.07.2019, 20.02.2020		16.06.2019, 09.11.2019, 10.02.2020		01.06.2019, 28.06.2019, 27.07.2019, 10.09.2019, 19.02.2020		03.05.2019, 10.07.2019, 06.11.2019, 19.02.2020	

**Details of attendance of Members of the Council, Standing,
Non-Standing Committees and Board Meetings**

S. No	Council/Committee	Expert Advisory Board		Quality Review Board		Auditing Standard Board		Brand Promotion Committee		International Affairs Committee	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
1	CS Ashish Garg	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
2	CS Nagendra D. Rao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CS (Dr.) Ahalada Rao Vummenthala	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CS B. Narasimhan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
5	CS Chetan B. Patel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CS Deepak Kumar Khaitan	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
7	CS Devendra V. Deshpande	-	-	-	-	1	1	-	-	1	0
8	CS Hitender Kumar Mehta	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
9	CS Manish Gupta	-	-	-	-	5	1	-	-	1	0
10	CS NPS Chawla	1	0	-	-	-	-	-	-	2	1
11	CS Praveen Soni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CS Ranjeet Pandey	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	CS Ramasubramaniam C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CS Siddhartha Murarka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CS Vineet K. Chaudhary	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-
16	Mr. Anil Gupta	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Mr. Manoj Pandey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Mr. Gyaneshwar Kumar Singh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dr.(Ms.)Madhu Vij	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MrS.Santhanakrishnan	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mr. Anurag Agarwal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CS Ashok Kumar Dixit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dates of Meetings	27.02.2020,		21.06.2019,		20.04.2019 and		03.05.2019,		21.10.2019,	

S. No	Council/Committee	Expert Advisory Board		Quality Review Board		Auditing Standard Board		Brand Promotion Committee		International Affairs Committee	
	Name	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended	Held	Attended
				16.12.2019, 11.03.2020 and 12.03.2020		21.04.2019, 03.08.2019 and 04.08.2019, 21.09.2019 and 22.09.2019, 08.11.2019 and 09.11.2019, 14.12.2019, 07.03.2020 and 08.03.2020		10.09.2019		20.02.2020	

APPENDIX-C

LIST OF CITIES FOR EXAMINATION DURING THE YEAR 2019

Sl. No.	Examination City	Sl. No.	Examination City	Sl. No.	Examination City
1	AGRA	47	HUBLI-DHARWAD	93	PRAYAGRAJ
2	AHMEDABAD	48	HYDERABAD	94	PUDUCHERRY
3	AHMEDNAGAR	49	INDORE	95	PUNE ZONE-I
4	AJMER	50	IMPHAL	96	PUNE ZONE-II
5	AKOLA	51	JABALPUR	97	PUNE ZONE-III
6	ALIGARH	52	JAIPUR	98	PUNE ZONE-IV
7	ALWAR	53	JALGAON	99	RAIPUR
8	AMBALA	54	JALANDHAR	100	RAJKOT
9	AMRITSAR	55	JAMMU	101	RANCHI
10	AMRAVATI	56	JAMNAGAR	102	REWARI
11	AURANGABAD	57	JAMSHEDPUR	103	ROURKELA
12	BENGALURU	58	JHANSI	104	SAGAR
13	BAREILLY	59	JHUNJHUNU	105	SALEM
14	BEAWAR	60	JODHPUR	106	SAMBALPUR
15	BELGAUM	61	KANPUR	107	SATARA
16	BHAYANDER	62	KOLHAPUR	108	SHIMLA
17	BHILAI	63	KOLKATA (NORTH)	109	SIKAR
18	BHILWARA	64	KOLKATA (SOUTH)	110	SILIGURI
19	BHOPAL	65	KOTA	111	SOLAPUR
20	BHUBANESWAR	66	KOTTAYAM	112	SONEPAT
21	BIKANER	67	KOZHIKODE	113	SRINAGAR
22	BILASPUR	68	LUCKNOW	114	SURAT
23	CHANDIGARH	69	LUDHIANA	115	THANE ZONE-I
24	CHENNAI	70	MADURAI	116	THANE ZONE-II
25	CHITTORGARH	71	MANGALURU	117	THANE ZONE-III
26	COIMBATORE	72	MEERUT	118	THIRUVANANTHAPURAM
27	DEHRADUN	73	MORADABAD	119	THRISSUR
28	DELHI (EAST)	74	MUMBAI ZONE-I	120	TIRUCHIRAPALLI
29	DELHI (NORTH)	75	MUMBAI ZONE-II	121	UDAIPUR
30	DELHI (SOUTH)	76	MUMBAI ZONE-III	122	UJJAIN
31	DELHI (WEST)	77	MUMBAI ZONE-IV	123	VADODARA
32	DHANBAD	78	MUMBAI ZONE-V	124	VAPI
33	DUBAI	79	MUMBAI ZONE-VI	125	VARANASI
34	ERNAKULAM	80	MUZAFFARNAGAR	126	VIJAYAWADA
35	FARIDABAD	81	MYSURU	127	VISAKHAPATNAM
36	GANDHIDHAM	82	NAGPUR	128	YAMUNA NAGAR

37	GANDHINAGAR	83	NASHIK	129	ASANSOL*
38	GHAZIABAD	84	NAVI MUMBAI	130	DURGAPUR*
39	GORAKHPUR	85	NOIDA	131	LATUR*
40	GUNTUR-AMARAVATI	86	PALAKKAD	132	MATHURA*
41	GURUGRAM	87	PALI	133	NANDED*
42	GUWAHATI	88	PANAJI	134	PORT BLAIR*
43	GWALIOR	89	PANIPAT	135	ROHTAK*
44	HISAR	90	PATIALA	136	SURENDRANAGAR*
45	HOOGHLY	91	PATNA	137	TUMKUR*
46	HOWRAH	92	PIMPRI-CHINCHWAD		

*Computer Based Examination for Foundation Programme only

APPENDIX-D

STATISTICS ON EXAMINATION RESULTS

JUNE, 2019 SESSION

	NUMBER OF CANDIDATES		
STAGE OF EXAMINATION	ENROLLED	APPEARED	PASSED
FOUNDATION PROGRAMME	14034	13095	8450
EXECUTIVE PROGRAMME (O/S) *			
MODULE – I	21597	14947	1725
MODULE - II	21136	14931	2512
EXECUTIVE PROGRAMME (N/S) #			
MODULE - I	10599	8700	893
MODULE - II	4424	3478	299
PROFESSIONAL PROGRAMME (O/S) @			
MODULE - I	13632	9671	2633
MODULE - II	11182	7632	2345
MODULE - III	12209	9137	3053
PROFESSIONAL PROGRAMME (N/S) §			
MODULE - I	757	629	175
MODULE - II	472	368	91
MODULE - III	501	425	119

* **11578** Candidates enrolled, **9158** Candidates appeared for Both Modules of Executive Programme (O/S) out of whom **391** candidates passed Both Modules.

3139 Candidates enrolled, **2885** Candidates appeared for Both Modules of Executive Programme (N/S) out of whom **157** candidates passed Both Modules.

@ **3391** Candidates enrolled, **2741** Candidates appeared for All Modules of Professional Programme (O/S) out of whom **160** candidates passed All Modules.

§ **242** Candidates enrolled, **220** Candidates appeared for All Modules of Professional Programme (N/S) out of whom **31** candidates passed All Modules.

DECEMBER, 2019 SESSION

	NUMBER OF CANDIDATES		
STAGE OF EXAMINATION	ENROLLED	APPEARED	PASSED
FOUNDATION PROGRAMME	12095	11255	7557

EXECUTIVE PROGRAMME (O/S) *			
MODULE - I	19175	12973	1762
MODULE - II	18740	12381	2053
EXECUTIVE PROGRAMME (N/S) #			
MODULE - I	17868	14779	1136
MODULE - II	9944	8093	968
PROFESSIONAL PROGRAMME (O/S) @			
MODULE - I	13265	8698	2626
MODULE - II	11608	7675	1826
MODULE - III	11334	7737	2652
PROFESSIONAL PROGRAMME (N/S) §			
MODULE - I	2413	1966	789
MODULE - II	1851	1483	424
MODULE - III	2011	1712	532

* **13246** Candidates enrolled, **9761** Candidates appeared for Both Modules of Executive Programme (O/S) out of whom **324** candidates passed Both Modules.

7007 Candidates enrolled, **6396** Candidates appeared for Both Modules of Executive Programme (N/S) out of whom **286** candidates passed Both Modules.

@ **3385** Candidates enrolled, **2544** Candidates appeared for All Modules of Professional Programme (O/S) out of whom **64** candidates passed All Modules.

§ **1107** Candidates enrolled, **1044** Candidates appeared for All Modules of Professional Programme (N/S) out of whom **198** candidates passed All Modules.

BANSAL SINHA & CO.

Chartered Accountants

18/19, Old Rajender Nagar, New Delhi-110060

Ph: 011-25853424, 25722270

E-mail: bsc@bansalsinha.com

Website : www.bansalsinha.com

P K CHOPRA & CO.

Chartered Accountants

N-1001, Bombay Life Building, Connaught Place,

New Delhi-110001 (India)

Ph: +91-11-40043977

E-mail: info@pkchopra.com

Website : www.pkchopra.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF COUNCIL OF

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA ("the ICSI")

Report on the Consolidated Financial Statements of the ICSI

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **The Institute of Company Secretaries of India ("The Institute")** which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2020, the Consolidated Income & Expenditure Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated audited accounts of Head Quarter of Institute and Institute's Centre for Corporate Governance Research and Training (CCGRT) Mumbai and Centre of Excellence (COE) Hyderabad, consolidated accounts of Four Regional Councils, whose financial statements reflect total assets of Rs 65.98 Crores as at 31st March 2020, total revenues of Rs 24.42 Crores and net cash inflow amounting to Rs. 2.35 Crores for the year

ended on that date, as considered in the consolidated financial statements have been audited by other Auditor and their report have been incorporated and duly considered while preparing our report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and read with other notes on accounts and matters described in the emphasis of matters and other matters paragraph of our report, the consolidated financial statements give the information required by Company Secretaries Act., 1980 ("the Act.") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs (financial position) of the Institute as at 31st March 2020;
- ii. in the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus (financial performance) of the Institute for the year ended on that date.
- iii. in the case of the Cash Flow Statement, of the Cash Flow for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) as issued by the Institute of Chartered Accountants of India and generally accepted in India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the entity accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Limitations Due to COVID-19 Pandemic and Lockdown restriction

- Physical verification of fixed assets, Inventory & Cash has not been done due to the above.
- Interest certificate from banks for FDRs Investment has not been provided by the banks however, necessary checks have been done to ensure the correctness of the figures, which includes the calculation of interest income based on investment value and corresponding rate of interest and basis of test check and concept of materiality.
- Receiving of necessary information/documents through electronic mode. Further effectiveness of internal controls cannot be verified due to limited access of documents and visit to the departments due to Covid 19.

In case of Northern India Regional Council(NIRC) Auditor has obtained required information and performed audit procedures upto December 2019 at NIRC premises, however, due to the COVID-19 pandemic, the audit team could not visit the NIRC premises for performing the required audit procedures for 4th Quarter of audit period and obtained necessary information/ documents through electronic mode as prescribed under Standards on Auditing issued by ICAI, including but not limited to:

- Inspection, observation, examination and verification of the original documents/ files;
- Physical verification of cash/fixed assets/stocks including adequate internal controls thereof;
- Examination of the various documents with regard to various expenses;
- Examination of the FA Register, physical verification process;
- Any other which require physical presence of the audit team.

Scope limitation

All the documents in respect to the examination section are not reviewed by us due to the non-receipt of the required records and information from management considering the same as highly confidential, verification has been done by the concerned department internally and confirmation in this regard provided to us and we have relied upon the same. (Refer Note No. 18 for the Examination Expenses).

Emphasis of Matter

- i) Refer Point No. 6 of Note 21(B) w.r.t. balance of various parties including inter unit balances are subject to reconciliation and their confirmations and respective consequential adjustments.
- ii) In case of NIRC, We would like to draw attention to the comments given by the other auditors, which state as under:

- a. An amount of Rs. 28,44,250/- on account of building under construction in which the office of the Lucknow branch is running for the last seven years is still lying in the Capital Work in Progress, while the cost should be debited to Fixed Assets and proper depreciation should have been charged from the date of the occupation of this building. The surplus during the year in the Income & Expenditure Account is overstated by the amount of depreciation that needs to be charged for the current financial year, similarly balance in General Reserve appearing in note-1 to the financial statements is overstated by the amount of depreciation to be charged over the years.
- b. GST figures are subject to reconciliation.
- iii) Refer Point No. 18 of Note 21(B), in case of SIRC & WIRC, we draw attention to that an amount of Rs. 22,73,999/- and Rs. 4,54,573/- has been shown as debtors/advances and the same is pending for recovery since long and considered as doubtful. However, no provision for doubtful debts/advances has been made as management is hopeful that the amount will be recovered from the parties and for recovery legal action has been initiated or going to be initiated.

Considering the materiality of the matters stated in the Emphasis of Matters paragraph and keeping in view the size & nature of emphasis matters these do not affect the True & Fair view of Consolidated Financial Statements of the entity as a whole and accordingly our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Matters

We have audited the Financial Statements of ICSI-HQ. We did not audit the Financial Statements of CCGRT, Mumbai, COE, Hyderabad, Consolidated accounts of 4 Regional Councils as the same has been audited by other auditor. Our opinion on the consolidated financial statements and our report, is not modified in respect of the same with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditor.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Council of the Institute ("Institute's Management") is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in accordance with the Company Secretaries Act., 1980 ("the Act.") that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with accounting principles generally accepted in India, including applicable Accounting Standards. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate or to cease operations of the Institute, or has no realistic alternative but to do so.

The Council of the Institute are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Consolidated Financial Statement

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from

fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Further we report that:-

Subject to comment under limitation of scope para above, we report that:

- a. we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- c. in our opinion proper books of accounts are maintained in conformity with requirement of the Company Secretaries Act, 1980 so far it appears from examination of books and records;
- d. we have received the audited accounts of Centre for Corporate Governance Research and Training (CCGRT), Mumbai and Centre of Excellence (COE), Hyderabad and Consolidated Accounts of 4 Regional Council and the same have been dealt with by us in our report;
- e. The financial statements disclose the financial impact of pending litigations on the financial position of the Institute, Refer point no. 1 of Note 21 (B) of the consolidated financial statement;
- f. The Institute did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- g. in our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India;

For BANSAL SINHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN With ICAI 006184 N

For P.K CHOPRA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN With ICAI 006747 N

(Hari Ubriani)

Partner

M.No. 084437

UDIN. 20084437AAAAAR9401

PLACE : New Delhi

DATE : 26th September, 2020

(Rahul Jindal)

Partner

M.No. 537709

UDIN. 20537709AAAACJ1135

**THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020**

(₹ Amount)

PARTICULARS	NOTE NO.	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I. SOURCES AND LIABILITIES			
(1) Reserves & Surplus			
(a) Reserve & Surplus	1	7,045,790,151	6,724,119,578
(b) Earmarked Funds	2	1,474,683,282	1,463,474,871
SUB-TOTAL (1)		8,520,473,433	8,187,594,449
(2) Non- Current Liabilities			
(a) Long Term Borrowings		-	-
(b) Long Term Liabilities		74,580	2,112,080
(c) Long Term Provisions		10,500	10,500
SUB-TOTAL (2)		85,080	2,122,580
(3) Current Liabilities			
(a) Short Term Borrowings		-	32,948
(b) Sundry Creditors	3	118,158,841	121,593,600
(c) Other Current Liabilities	4	193,777,215	207,095,918
(d) Short Term Provisions	5	32,108,438	75,469,119
SUB-TOTAL (3)		344,044,494	404,191,585
TOTAL (1+2+3)		8,864,603,007	8,593,908,614
II. ASSETS			
(1) Non Current Assets			
(a) Fixed Assets	6		
(i) Tangible Assets		1,389,098,860	1,428,928,795
(ii) Intangible Assets		2,799,337	2,828,215
(iii) Capital Work in Progress		74,540,593	55,817,473
(iv) Intangible Assets under development		33,040	33,040
SUB-TOTAL (a)		1,466,471,830	1,487,607,523
(b) Non Current Investments	7	4,909,322,228	4,711,166,956
(c) Other Non Current Assets	8	45,156,297	65,121,797
(d) Long Term Loans & Advances		1,096,169	1,381,178
SUB-TOTAL (1)		6,422,046,524	6,265,277,454
(2) Current Assets			
(a) Current Investments	9	608,845,236	688,961,708
(b) Inventories	10	6,013,714	6,358,734
(c) Sundry Debtors	11	43,520,544	2,578,789
(d) Cash and Cash Equivalents	12	291,010,497	310,927,286
(e) Other Current Assets	13	1,493,166,492	1,319,804,644
SUB-TOTAL (2)		2,442,556,483	2,328,631,161
TOTAL (1) + (2)		8,864,603,007	8,593,908,614
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS	21		

Notes referred to above form an integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Council of the Institute

CA Sameer Gupta	CS Asish Mohan	CS Nagendra D Rao	CS Ashish Garg
Joint Secretary (F&A)	Secretary	Vice President	President

As per our report of even date

For Bansal Sinha & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006184N

For P K Chopra & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006747N

(CA Hari Ubriani)
Partner
Membership No. 084437
UDIN. 20084437AAAAAR9401

(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No. 537709
UDIN 20537709AAAACJ1135

Place : New Delhi

Date : 26th September, 2020

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

(₹ Amount)

PARTICULARS	Note No.	For the year ended	
		31st March 2020	31st March 2019
INCOME			
Income from Activities	14	1,117,526,873	1,146,840,553
Interest from Investments	15	533,342,644	515,579,762
Other Income	16	180,732,848	83,855,215
TOTAL INCOME		1,831,602,365	1,746,275,530
EXPENDITURE			
Employee Benefit Expense	17	47,65,42,553	439,322,024
Study Material & Others / Oral Education Expense		67,876,395	70,601,363
Publications & Branding Material		15,187,064	20,615,599
Examinations Expense	18	143,167,781	134,059,459
Travelling and Conveyance Expense		24,109,494	28,083,403
Programmes / Seminars Expense		176,262,188	112,081,381
Career Awareness and Promotion Expense		31,950,120	27,735,079
Depreciation & Amortization		73,128,946	65,135,499
Journal & Bulletins	19A	43,599,916	51,269,268

Legal and Professional Services	19B	13,651,179	15,572,352
Electricity & Water	19C	19,944,267	17,447,249
Communication Expenses	19D	49,559,315	58,876,455
Other Expenses	19E	145,971,226	101,718,784
CCGRT Activities	20	13,100,900	9,579,349
TOTAL EXPENDITURE		1,294,051,344	1,152,097,265
Surplus before extra ordinary & exceptional items		537,551,021	594,178,265
Add / Less : Extra Ordinary Items		(87,113)	252,048
Add / Less : Exceptional Items		(13,911,394)	-
Surplus on Disposal of Assets		77,833	35,185
Loss on sale / Disposal / write-off of Assets		(1,060,599)	(252,464)
Prior period expenses (net)		(22,184,080)	(12,285,228)
Surplus after extra ordinary & exceptional items		500,385,668	581,927,806
Contributions & Appropriation to Funds / Reserves :			
- Performance related incentive Fund		2,500,000	7,590,000
- Interest to Earmarked Fund		114,534,650	123,235,234
- ICSI Pension Fund Trust		68,545,474	-
- ICSI Student Education Fund Trust		10,000,000	10,000,000
- CS Benevolent Fund Trust		20,000,000	5,000,000
- ICSI Employees Benevolent Fund Trust		500,000	500,000
- ICSI Employees Medical Hospitalisation Trust		7,500,000	7,500,000
- Building & Technology Development Reserve		2,000,000	1,000,000
TOTAL APPROPRIATIONS		225,580,124	154,825,234
Net Surplus transferred to General Reserve		274,805,544	427,102,572
TOTAL		500,385,668	581,927,806
ACCOUNTING POLICIES AND OTHER NOTES TO THE ACCOUNTS	21		

Notes referred to above form an integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Council of the Institute

CA Sameer Gupta
Joint Secretary (F&A)

CS Asish Mohan
Secretary

CS Nagendra D Rao
Vice President

CS Ashish Garg
President

As per our report of even date

For Bansal Sinha & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006184N

For P K Chopra & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006747N

(CA Hari Ubriani)
Partner
Membership No. 084437
UDIN. 20084437AAAAAR9401

(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No. 537709
UDIN 20537709AAAACJ1135

Place : New Delhi

Date : 26th September, 2020

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

(₹ Amount)

	2019-20		2018-19	
Cash Flow from Operating Activity				
Net Surplus after Prior period, Extra ordinary and Exceptional items as per I & E Account		500,385,668		581,927,806
Add : Entrance Fee from Members directly Credited to Capital Reserve		16,298,172		11,940,950
Adjustment for:				
Add : Depreciation on Fixed Assets		73,128,946		65,135,498
: Amortization of Lease hold Land included in prior period expenses		4,922,562		-
: Stock Written off		-		20,282
: Bad Debts and Provision for Doubtful Debts		131,304		393,876
: Loss on Sale of Assets		1,060,599		252,464
Cash flow from operation after adjustment for non cash expenses		595,927,251		659,670,876
Less: : Income from Investment	533,342,644		515,579,762	
: Provisions no longer required back and amount written off	60,355,438		48,568,111	
: Forfeiture of SIP Fee	-		252,048	
: Surplus on Disposal of Assets	77,833	593,775,915	35,185	564,435,106
Operating Surplus before Working Capital and Funds Changes		2,151,336		95,235,770
Increase/(Decrease) in Current Assets and Current Liabilities and Operating Earmarked Fund Balances				
(Increase)/Decrease in Inventory	345,020		(1,853,514)	
(Increase)/Decrease in Sundry Debtors net of bad debts	(41,073,059)		2,642,484	
(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances	-		(5,544,139)	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(173,361,848)		(302,781,304)	
(Increase)/Decrease in Long Term Loans & Advances	285,009		(551,172)	
(Increase)/Decrease in Other Non Current Assets	19,965,500		5,544,139	
(Increase)/Decrease in Contribution / Utilisation to/from RC/ Chapters towards assets	14,914,275		160,085,629	

Increase/(Decrease) in Sundry Creditors	(34,34,759)		(19,304,538)	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities & Short Term Borrowings (Excluding Contribution and appropriation to funds from I & E)	(119,897,125)		(141,554,796)	
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions excluding Provisions written back	16,994,757		(21,390,979)	
Increase/(Decrease) in Long Term Liabilities and Provisions	(2,037,500)		2,501	
Receipts (Utilisation) in Award for Corporate Governance Funds (Net)	(3,865,748)		(3,551,623)	
Receipts (Utilisation) Staff Training Fund	(911,415)		(954,533)	
Receipts (Utilisation)/(transfer) from Leave Encashment Fund	(48,080,425)		(13,059,943)	
Receipts (Utilisation) Endowment Prize Award Fund (Net)	(205,820)		(204,172)	
Receipts (Utilisation) Professional Development Fund	(8,940,478)		(11,639,328)	
Receipts (Utilisation) Performance Related Incentive Fund	(9,572,519)		(10,086,799)	
Receipts (Utilisation) Infrastructure Fund	(8,957,103)	(367,833,238)	-	(364,202,087)
Net cash generated from operating activity.		(365,681,902)		(268,966,317)
<u>Cash flow from Investing Activity</u>				
Income from Investments	533,342,644		515,579,762	
Sale Proceeds of Redemption of Investments/ Mutual Funds	914,050,476		1,195,175,333	
Acquisition of Investments/Mutual Fund Units	(1,032,089,276)		(1,116,612,665)	
Sale Proceeds of Fixed Assets and other adjustment to Fixed Assets	1,731,227		-	
Acquisition of Fixed Assets including WIP	(59,629,808)		(337,347,142)	
<u>Net Cash used in Investing Activity</u>		357,405,263		256,795,288
<u>Cash flow from Financing Activity</u>				
Addition in Corpus Donation		-	-	
Cash Generated From Financing Activities		-		-
Increase/(Decrease) in Infrastructure Reserve (Net)	29,970		(50,470)	
Addition in General Reserve and Corpus Donations	(15,112,806)		329,024	
Increase/(Decrease) in Library Reserve (Net)	74,833		161,451	
Increase/(Decrease) in Building Reserve excluding appropriation from I & E (Net)	(1,432,862)		1,000,000	
Increase/(Decrease) in Other Reserve and Funds (Net)	4,800,715		682,541	
Increase/(Decrease) in Capital Reserve other than entrance fees	-		(153,692)	
Net cash generated from Financing Activities		(11,640,150)		1,968,854
Net Cash Flow for the Year ended as on 31st March 2020 (A)		(19,916,789)		(10,202,175)
Cash and cash equivalent at the beginning of the year (B)		310,927,286		321,129,461
Cash and cash equivalent at the end of the year (A+B)		291,010,497		310,927,286

Note:

- The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3.
- Enclosed Notes 1 to 20 form an integral part of the Cash Flow Statement.

3 Cash and cash equivalents include:

a	Cash, Cheques/Drafts/Postal Orders & Postage Stamps/ Franking units.	1,006,682	2,917,149
b	Balances with Scheduled Banks		
	- In Savings Bank accounts (incl Term deposits)	290,003,815	308,010,137
		291,010,497	310,927,286

For and on behalf of the Council of the Institute

CA Sameer Gupta	CS Asish Mohan	CS Nagendra D Rao	CS Ashish Garg
Joint Secretary (F&A)	Secretary	Vice President	President

As per our report of even date

For Bansal Sinha & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006184N

For P K Chopra & Co.
(Chartered Accountants)
FRN : 006747N

(CA Hari Ubriani)
Partner
Membership No. 084437
UDIN. 20084437AAAAAR9401

(CA Rahul Jindal)
Partner
Membership No. 537709
UDIN 20537709AAAACJ1135

Place : New Delhi

Date : 26th September, 2020**RESERVES & SURPLUS****NOTE - 1****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
(1) CAPITAL RESERVE				
As per last Balance Sheet		86,712,289		74,771,339
Add: Entrance Fees from Members				
- Associate Members	13,997,002		10,404,521	
- Fellow Members	2,301,170	16,298,172	1,536,429	11,940,950
Sub-Total (1)		103,010,461		86,712,289
(2) GENERAL RESERVE				
As per last Balance Sheet		6,564,593,905		5,935,865,250
Add : Additions during the year		-		-
Add : Corpus donation		212,101		106,908
Add : Transfer from Infrastructure Fund		25,792,730		210,264,879
Add : Transfer from Contribution / Reserves		17,174		-
Add/(Less): Adjust/Transfer to Other Reserve		(15,308,837)		(6,215,388)
Less : Utilisation during the year		(33,244)		(2,530,317)

		6,575,273,829		6,137,491,332
Surplus (Excess of Inc over Expe) from I & E		274,805,544		427,102,573
Sub-Total (2)		6,850,079,373		6,564,593,905
(3) Library Reserve				
As per last Balance Sheet		2,800,542		2,639,091
Add: Donation		41,663		216,116
Add : Interest		33,170		(73,627)
Add: Transfer from Reserve /additions		-		-
Less: Utilisation		-		18,962
Sub-Total (3)		2,875,375		2,800,542
(4) Building Reserve				
As per last Balance Sheet		152,936,092		151,936,092
Add: Donation		-		-
Add: Transfer from Reserve		3,637,041		-
Add: Transfer from Contribution		-		-
Add : Transfer from I&E Account		1,500,000		1,000,000
Less : Adjustment / utilisation		(5,069,903)		-
Sub-Total (4)		153,003,230		152,936,092
(5) Infrastructure Reserve				
As per last Balance Sheet		34,261,131		34,311,601
Add: Transfer from Reserve		79,970		23,500
Add: Donations		-		6,000
Less: Utilisation during the year		(50,000)		(79,970)
Sub-Total (5)		34,291,101		34,261,131
(6) Other Reserve				
As per last Balance Sheet		49,535,900		48,773,389
Add : Additions during the year		4,797,107		672,340
Add: Transfer from / (to) Reserve		-		79,970
Add: Interest		99,340		48,662
Less: Utilisation during the year		(95,732)		(38,461)
Sub-Total (6)		54,336,615		49,535,900
(7) CONTRIBUTION TO / FROM TOWARDS L/BLDG/OTHER ASSETS				
Add: Contrib. from RC/Chap towards Assets		117,540,829		110,372,852
Less: Contrib. to RC/Chapters towards assets		(269,346,833)		(277,093,131)

Sub-Total (7)		(151,806,004)		(166,720,279)
Total : (1 to 7)		7,045,790,151		6,724,119,578

EARMARKED FUND**NOTE - 2****(₹ Amount)**

PARTICULARS	ICSI NATIONAL AWARD FOR EXCELLENCE IN CORPORATE GOVERNANCE FUND		STAFF TRAINING FUND		LEAVE ENCASHMENT FUND		ENDOWMENT FOR PRIZE AWARD FUND	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
As per last Balance Sheet	156,765,700	148,573,507	9,947,596	10,129,917	160,024,310	141,082,387	8,423,902	8,094,475
Add: Contribution during the year	-	-	-	-	5,000,000	20,716,075	287,777	-
Add: Transfer from Gen Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Add: Receipts during the year	-	-	-	-	22,869,084	-	-	-
Add: Interest allocation	12,386,626	11,743,816	759,351	772,212	12,801,945	11,285,791	547,791	533,599
Sub-Total	169,152,326	160,317,323	10,706,947	10,902,129	200,695,339	173,084,253	9,259,470	8,628,074
Less: Transfer to GR on utilisation	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Utilised during the year	3,865,748	3,551,623	911,415	954,533	75,949,512	13,059,943	493,597	204,172
Balance as at the close of the year	165,286,578	156,765,700	9,795,532	9,947,596	124,745,827	160,024,310	8,765,873	8,423,902

PARTICULARS	PERFORMANCE-RELATED INCENTIVE FUND		INFRASTRUCTURE FUND (Including Technology Development Fund)		PROFESSIONAL DEVELOPMENT FUND		TOTAL AMOUNT	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
As per last Balance Sheet	9,657,527	8,062,776	1,067,118,503	1,183,024,504	51,537,338	58,797,918	1,463,474,871	1,557,765,484
Add: Contribution during the year	2,500,000	11,000,000	500,000	359,776	-	-	8,287,777	32,075,851
Add: Transfer from Gen Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Add: Receipts during the year	-	-	-	48,000	248,200	135,084	23,117,284	183,084
Add: Interest allocation	489,701	681,550	83,783,868	93,974,602	3,765,368	4,243,664	114,534,650	123,235,234
Sub-Total	12,647,228	19,744,326	1,151,402,371	1,277,406,882	55,550,906	63,176,666	1,609,414,582	1,713,259,653
Less: Transfer to GR on utilisation	-	-	-	23,500	-	-	-	23,500
Less: Utilised during the year	9,572,519	10,086,799	8,957,103	-	9,188,678	11,639,328	108,938,572	39,496,398
Less : On acquisition of Land & Bldg			25,792,730	210,264,879			25,792,730	210,264,879
Balance as at the close of the year	3,074,709	9,657,527	1,116,652,538	1,067,118,503	46,362,228	51,537,338	1,474,683,282	1,463,474,871

SUNDRY CREDITORS**NOTE - 3****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
SUNDRY CREDITORS:-		
Amount due to Micro, Small & Medium Enterprises for Goods & Services	-	-
Amount due to Other Creditors for Goods & Services	111,277,306	119,028,927
RD (E/W/S/N) -Investor Education Protection Fund	252,762	274,597
Other Payables	6,628,773	2,290,076
Total :	118,158,841	121,593,600

OTHER CURRENT LIABILITIES**NOTE - 4****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
OTHER CURRENT LIABILITIES:-		
Fee Received in advance from Members / Students	89,089,162	131,606,916
Payable to Trusts / Funds	63,262,210	36,889,605
Security Deposits	2,494,812	2,803,234
Property Tax Payable	1,370,000	1,200,000
TDS Payable	20,385,162	16,185,451
GST Payable	613,531	248,306
Inter Unit Balance	-	15,669,371
Other Payables	16,562,338	2,493,035
Total :	193,777,215	207,095,918

SHORT TERM PROVISIONS**NOTE - 5****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Provisions for Expenses	32,108,438	75,469,119
Total :	32,108,438	75,469,119

FIXEDASSETS**NOTE - 6****(₹ Amount)**

Items	Gross Block	Additions	Adjustment/ Transfer/Sale	Total cost as on 31.3.2020	Depreciation / Impairment				Net Block	
	Cost				Total	For the	Adjustment/ Transfer/	Total	as on	as on
	as on				as on	Year	Transfer/	as on	31.3.2020	31.3.2019
	1.4.2019				31.3.2020	1.4.2019	Sale	31.3.2020		
(i) Tangible Assets										
Land										
Freehold	209,889,542	-	3,294,922	213,184,464	-	-	-	-	213,184,464	209,889,542
Leasehold	305,745,724	-	-3,294,922	302,450,802	8,778,445	3,251,451	4,922,562	16,952,458	285,498,344	296,967,279
Building	980,196,511	400,334	-	980,596,845	206,766,011	38,686,946	-	245,452,957	735,143,888	773,430,500

Furniture & Fixtures	127,249,557	3,985,318	-515,034	130,719,841	64,702,908	6,484,604	104,191	71,291,703	59,428,138	62,546,649
Computer Peripherals	100,420,291	12,961,374	-7,101,615	106,280,050	85,153,247	8,986,722	-6,554,966	87,585,003	18,695,047	15,267,044
Mobile Phones	18,790	-	-	18,790	12,211	2,632	-	14,843	3,947	6,579
Cooling Equipment	48,271,483	13,572,425	-2,024,549	59,819,359	21,709,917	5,257,384	-1,099,278	25,868,023	33,951,336	26,561,566
Electrical Equipment	39,678,138	1,393,279	299,948	41,371,365	28,082,465	2,037,528	-60,110	30,059,883	11,311,482	11,595,673
Office Machines & Comm Equipment	54,175,249	2,085,890	-2,575,883	53,685,256	26,425,004	4,153,936	-1,204,004	29,374,936	24,310,320	27,750,245
Other Equipment	10,853,916	2,621,066	258,213	13,733,195	6,551,518	1,035,636	-252,439	7,334,715	6,398,480	4,302,398
Library Books	6,196,976	185,282	-	6,382,258	6,189,425	161,983	21,096	6,372,504	9,754	7,551
Vehicles	1,616,942	856,682	-734,999	1,738,625	1,013,176	219,524	-657,737	574,963	1,163,662	603,766
Current Year Total (i)	1,884,313,119	38,061,650	-12,393,919	1,909,980,850	455,384,327	70,278,346	-4,780,685	520,881,988	1,389,098,860	1,428,928,795
Previous Year Total	1,552,444,489	337,276,540	5,407,910	1,884,313,119	396,853,638	62,354,423	3,823,735	455,384,326	1,428,928,793	1,155,590,851
(ii) Intangible Assets										
Softwares & Applications	28,288,048	2,845,038	-22,667	31,110,419	25,459,833	2,850,600	649	28,311,082	2,799,337	2,828,215
Current Year Total (ii)	28,288,048	2,845,038	-22,667	31,110,419	25,459,833	2,850,600	649	28,311,082	2,799,337	2,828,215
Previous Year Total	28,270,896	70,602	-53,450	28,288,048	22,732,208	2,781,075	-53,450	25,459,833	2,828,215	5,538,688

FIXED ASSETS (Capital Work in Progress)**NOTE - 6 (contd...)****(₹ Amount)**

Items		Gross Block			
		Costs on 1.4.2019	Additions	Adjustment/ Transfer/Sale	Total cost as on 31.3.2020
(iii)	Capital Work in Progress				
	Land under acquisition	62,28,677	-	-	62,28,677
	Building/ Renovations/ Improvements	4,95,88,796	3,01,74,853	1,14,51,733	6,83,11,916
	Current Year Total (iii)	5,58,17,473	3,01,74,853	1,14,51,733	7,45,40,593
	Previous Year Total (iii)	18,73,29,644	20,96,84,247	34,11,96,418	5,58,17,473
(iv)	Intangible Assets under Development				
	Computer Software	33,040			
	Current Year Total (iv)	33,040	-	-	33,040
	Previous Year Total (iv)	33,040	-	-	33,040

NON-CURRENT INVESTMENTS**NOTE - 7****(₹ Amount)**

PARTICULARS		AS ON 01.04.2019	ADDITIONS	DELETIONS	Transfer to / from Current Inv	AS ON 31.03.2020
I. INVESTMENT IN GOVT. SECURITIES						
	GOI Bonds (Cum-HY)	2,455,000,000	-	-	-	2,455,000,000
	GOI Saving Bonds	30,090,000	-	-	-	30,090,000
	SUB-TOTAL(I)	2,485,090,000	-	-	-	2,485,090,000
II. INVESTMENT IN DEBENTURES / BONDS						
	PNB-HFL	48,114,680	-	86,542	-	48,028,138
	IDFC LTD	50,230,529	-	37,071	-	50,193,458

	SUB-TOTAL(II)	98,345,209	-	123,613	-	98,221,596
III	OTHER NON-CURRENT INVESTMENTS					
(A)	Fixed Deposits in Banks					
	Andhra Bank	3,974,779	316,909	-	-	4,291,688
	Bank of Maharashtra	1,735,861	42,103	563,033	-	1,214,931
	Bank of Baroda	135,227,266	-	20,227,266	-	115,000,000
	Canara Bank	95,890,992	13,735,123	42,952,408	(28,395,447)	38,278,260
	Central Bank of India	230,200	14,776	-	-	244,976
	Corporation Bank	70,201,549	18,980,137	3,045,207	-	86,136,479
	Dena Bank	3,577,418	-	-	-	3,577,418
	Federal Bank	326,473	20,234	-	-	346,707
	HDFC Bank	92,523,868	55,789	251,035	-	92,328,622
	ICICI Bank	26,760	1,843	-	-	28,603
	Indian Overseas Bank	29,208,617	25,285,431	21,419,217	-	33,074,831
	Karnataka Bank	1,287,586	72,125	-	-	1,359,711
	Oriental Bank of Commerce	-	100,000,000	-	-	100,000,000
	Other Banks	708,237	2,165,607	1,100,470	-	1,773,374
	Punjab National Bank	1,281,000	30,623,803	15,000,000	(15,000,000)	1,904,803
	Repco Bank	1,527,468	-	27,468	-	1,500,000
	State Bank of India	78,410,825	6,559,618	1,005,842	(60,000,000)	23,964,601
	Syndicate Bank	100,000	4,152,836	-	-	4,252,836
	Union Bank of India (UBI)	55,000,000	25,000,000	40,000,000	-	40,000,000
	SUB-TOTAL(III-A)	571,238,899	227,026,334	145,591,946	(103,395,447)	549,277,840
(B)	Fixed Deposits with institutions other than Banks					
	Bank of Baroda	2,850,000	900,000	-	-	3,750,000
	PNB Housing Finance	1,008,419	-	1,008,419	-	-
	TTDFC Ltd	34,568	22,307	-	-	56,875
	Deposit with LIC (Leave Encashment)	133,082,278	-	7,273,944	-	125,808,334
	HUDCO	97,400,000	-	-	(97,400,000)	-
	KTDFC	82,110,292	-	-	-	82,110,292
	LIC-HFL	850,000,000	500,000,000	-	(150,000,000)	1,200,000,000
	National Housing Bank (NHB)	50,000,000	-	-	-	50,000,000
	PNB-HFL	180,000,000	95,000,000	-	(120,000,000)	155,000,000
	SUB-TOTAL(III-B)	1,396,485,557	595,922,307	8,282,363	(367,400,000)	1,616,725,501
(C)	OTHERS (Specify nature)					
	Backbay Exp Prem Soc Ltd	1,000	-	-	-	1,000
	Backbay Exp Prem Soc Ltd	5,781	-	-	-	5,781
	Shares with Satchidanand CHS Ltd.	510	-	-	-	510
	Investments with ICSI-IPA	140,000,000	-	-	-	140,000,000
	Investments with ICSI-RVO	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	SUB-TOTAL(III)-C	160,007,291	-	-	-	160,007,291
	SUB TOTAL (III:A+B+C)	2,127,731,747	822,948,641	153,874,309	(470,795,447)	2,326,010,632
	TOTAL (I+II+III)	4,711,166,956	822,948,641	153,997,922	(470,795,447)	4,909,322,228

OTHER NON-CURRENT ASSETS**NOTE-8****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
LONG TERM LOANS AND ADVANCES (specify category/ nature)		
Secured, considered good	-	-
ICSI Trusts / Funds	8,413,702	9,801,507
Employees Advances	2,372,978	5,040,429
Others	191,649	9,740,050
Unsecured, considered good		
Amount recoverable for IAP from MCA	148,716	219,473
Others	34,223,400	40,320,338
Doubtful	105,852	43,680
	45,456,297	65,165,477
Less: Provision for Bad and Doubtful Debts	300,000	43,680
Total :	45,156,297	65,121,797

CURRENT INVESTMENTS**NOTE-9****(₹ Amount)**

PARTICULARS	AS ON 01.04.2019	ADDITIONS	DELETIONS	Transfer from Non-Current	AS ON 31.3.2020
I. INVESTMENT IN GOVT. SECURITIES					
GOI Bonds (Cum-HY)	-	-	-	-	-
GOI Bonds (NC-HY)	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(I)	-	-	-	-	-
II. INVESTMENT IN DEBENTURES / BONDS					
HUDCO	-	-	-	-	-
REC	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(II)	-	-	-	-	-
III. OTHER CURRENT INVESTMENTS					
(A) Fixed Deposits in Banks					
Allahabad Bank	648,537	-	49,044	-	599,493
Andhra Bank	5,538,687	-	203,168	-	5,335,519
Axis Bank	88,291	6,624	-	-	94,915
Bank of Baroda	13,635,221	2,041,941	512,000	-	15,165,162
Bank of India	3,577,842	4,614,096	3,638,429	-	4,553,509
Canara Bank	233,556,066	121,241,856	289,685,188	28,395,447	93,508,181
Central Bank of India	2,069,905	2,401,822	2,473,995	-	1,997,732
Corporation Bank	76,083,974	1,783,453	77,043,359	-	824,068
Dena Bank	1,360,634	451,413	-	-	1,812,047

	HDFC Bank	1,674,742	601,035	-	-	2,275,777
	ICICI Bank	5,061,987	1,631,837	1,306,979	-	5,386,845
	IDBI Bank	2,376,583	1,635,465	2,376,583	-	1,635,465
	Indian Bank	5,319,455	2,602,884	-	-	7,922,339
	Karur Vysya Bank (KVB)	417,243	36,438	-	-	453,681
	Oriental Bank of Commerce	790,791	51,245	-	-	842,036
	Other Banks	8,419,600	2,066,223	70,000	-	10,415,823
	Punjab National Bank (PNB)	1,995,080	20,400,000	35,469,123	15,000,000	1,925,957
	Punjab & Sind Bank (P&SB)	283,168	-	-	-	283,168
	State Bank of India	22,934,206	16,364,715	76,016,798	60,000,000	23,282,123
	Syndicate Bank	1,364,146	2,035,485	-	-	3,399,631
	UCO Bank	1,364,939	147,359	-	-	1,512,298
	Union Bank of India	13,287,203	5,965,074	1,796,269	-	17,456,008
	Vijaya Bank (Bank of Baroda)	37,113,408	23,061,670	19,411,619	-	40,763,459
	SUB-TOTAL(III-A)	438,961,708	209,140,635	510,052,554	103,395,447	241,445,236
(B)	Fixed Deposits with institutions other than Banks					
	LIC HFL	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000
	PNB HFL	100,000,000	-	100,000,000	120,000,000	120,000,000
	HUDCO	-	-	-	97,400,000	97,400,000
	SUB-TOTAL(III-B)	250,000,000	-	250,000,000	367,400,000	367,400,000
(C)	Others (Specify nature)					
	SUB-TOTAL(III-C)	-	-	-		-
	SUB-TOTAL(III)	688,961,708	209,140,635	760,052,554	470,795,447	608,845,236
	TOTAL(I+II+III)	688,961,708	209,140,635	760,052,554	470,795,447	608,845,236

INVENTORIES

NOTE-10

(₹ Amount)

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Publications & Study Material	3,743,713	2,074,316
Consumables, Stores & Others	2,270,001	4,284,418
Total	6,013,714	6,358,734

SUNDRY DEBTORS

NOTE-11

(₹ Amount)

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
a) Sundry Debtors (outstanding for more than six months)		
Secured, considered good	8,150	529,758
Unsecured, considered good	15,744,280	372,524
Doubtful	3,905,329	4,249,329
	19,657,759	5,151,611

Less : Provision for Bad and Doubtful Debtors	3,450,756	3,750,756
Sub-Total (a)	16,207,003	1,400,855
b) Others Sundry Debtors		
Secured, considered good	67,295	7,473
Unsecured, considered good	27,246,246	1,170,461
Doubtful	-	-
	27,313,541	1,177,934
Less : Provision for Bad and Doubtful Debtors	-	-
Sub-Total (b)	27,313,541	1,177,934
Total (a+b)	43,520,544	2,578,789

CASH AND CASH EQUIVALENTS**NOTE-12****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Balances with Bank (including Linked Term Deposits)	290,003,815	308,010,137
Cheques / Drafts / IPO / Stamps / Franking units in hand	35,111	2,362,337
Cash in hand	971,571	554,812
Total	291,010,497	310,927,286

OTHER CURRENT ASSETS**NOTE-13****(₹ Amount)**

PARTICULARS	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
OTHER CURRENT ASSETS (specify nature)		
Accrued Interest on investments	1,410,265,447	1,232,967,351
Prepaid Expenses	19,826,598	3,439,361
Security Deposit	5,040,921	4,043,054
CENVAT/GST Credit Receivables	10,677,230	18,984,446
Income Tax Refunds due up to P/Y	29,483,288	37,619,694
Tax Deducted at Source C/Y	9,085,551	10,689,294
Inter Unit Balances	1,972,949	-
Recoverable Others	1,680,876	7,789,017
Advance to Parties	5,133,632	4,272,427
Total :	1,493,166,492	1,319,804,644

INCOME FROM ACTIVITIES**NOTE-14****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the Year ended			
	31st March 2020		31st March 2019	
Income from Members				
Annual Fees	152,509,801		131,888,856	
Other Fees	7,310,335	159,820,136	2,909,518	134,798,374
Income from Students				
Registration Fees	104,447,577		134,767,675	
Exemption Fees	33,386,560		21,832,390	
Postal Education Fees	262,917,301		313,196,832	
Examination Fees	311,863,053		353,109,281	
Oral Education Fee	50,050,320		46,110,896	
Other Fees	12,710,188	775,374,999	14,154,114	883,171,188
Sale of Publications		12,988,004		8,910,684
Programmes / Seminars				
Students	89,387,926		67,126,027	
Members	79,955,808	169,343,734	52,834,280	119,960,307
TOTAL		1,117,526,873		1,146,840,553

INCOME FROM INVESTMENTS**NOTE-15****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2020	31st March 2019
Interest on Investments and Bank Balance	528,139,469	510,811,961
Incentive on Investments	5,203,175	4,767,801
TOTAL	533,342,644	515,579,762

OTHER INCOME**NOTE-16****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2020	31st March 2019
Subscription to Journal / Bulletin /Newsletter	9,449,037	11,300,594
Interest on Staff Advance	371,711	437,009
Receipt for Investor Awareness Programmes - MCA / RD	181,162	508,326
Investor Awareness Programme / RBIDAW-Others	-	41,525
Advisory Services	50,000	1,084,000
Royalty / Commission from Publications	-	43,281

Provision for expenses no longer required, written-back	60,355,438	48,567,599
Actuarial Gain / Transfer from Earmarked Funds	33,903,641	-
Donations - General	75,312	204,177
Rent	1,083,833	1,465,582
Receipts from MCA - CRC Manesar Establishment Exps.	44,719,851	3,100,606
Amount written off - EMD / SD, etc	-	512
Receipts from ICSI-IIP against Support Services and Exps.	6,660,937	7,858,027
Receipts from ICSI-RVO against Support Services and Exps.	4,375,989	3,330,876
Interest on Income Tax Refunds	3,012,110	-
Other Miscellaneous Income/Receipts	16,493,827	5,913,101
TOTAL	180,732,848	83,855,215

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE**NOTE-17****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the year ended			
	31st Mar 2020		31st March 2019	
Salaries and Allowances		383,559,187		363,973,611
Contribution for:				
Provident Fund	41,925,356		24,253,414	
Gratuity Fund	30,194,923		8,485,560	
Leave Encashment fund	-	72,120,279	20,716,075	53,455,049
Staff Welfare		20,863,087		21,893,364
TOTAL		476,542,553		439,322,024

EXAMINATION EXPENSE**NOTE-18****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the year ended	
	31st Mar 2020	31st March 2019
Honorarium to Paper Setter/ Examiners	64,404,325	49,114,826
General Observer	6,558,124	5,867,021
Exam Centres	37,869,031	40,216,608
Despatch of Documents	7,499,036	10,500,218
Answer Books	4,862,479	6,078,875
Question Papers	9,225,000	8,500,000
Canvas Bags and Locks	858,450	222,784
Office Use Forms	-	30,349
Envelopes	766,709	988,817

Pass Certificates	201,511	353,208
Travelling	339,014	441,527
Computer based examination - Foundation	9,929,020	11,321,957
Exam Others	655,082	423,269
TOTAL	143,167,781	134,059,459

OTHER EXPENSES**NOTE-19****(₹ Amount)**

PARTICULARS		For the year ended			
		31st March 2020		31st March 2019	
Journal & Bulletins / Newsletter	19A		43,599,916		51,269,268
Legal and Professional Services	19B		13,651,179		15,572,352
Electricity and Water	19C		19,944,267		17,447,249
Communication Expense	19D				
- Telephone / Fax / E-mail / SMS		17,003,060		25,741,638	
- Courier / Postage		32,556,255	49,559,315	33,134,817	58,876,455
OTHER EXPENSES	19E				
Rent, Rates and Taxes			13,517,850		10,292,913
Stationery			9,247,415		8,384,840
Insurance			831,445		743,307
Repairs and Maintenance:-					
- Buildings		4,926,747		2,623,121	
- Computer		17,667,788		12,131,585	
- Other Assets		6,835,257		6,784,741	
- Vehicles		793,405	30,223,197	684,672	22,224,119
Office General Expenses			28,405,689		26,009,583
Newspapers and Periodicals			225,207		180,825
Meeting expenses			4,763,051		4,836,228
Computerisation (Data Processing)			4,654,060		4,920,500
Packing and Despatch			29,410		82,484
Loss/Write-off of Stocks			-		20,282
Bank Charges			7,959,359		9,547,842
Student Scholarship and Awards			379,190		453,584
Auditors Remuneration (including GST)					
- Audit Fees : Head Office		250,000		270,810	
: Other Offices		1,027,909		784,134	
- Other Services : Head Office		3,381		256,650	

: Other Offices		414,861	1,696,151	103,921	1,415,515
Internal Audit Fees			1,634,738		1,601,650
RBI Depositors Awareness Programmes			-		933,236
Investor Awareness Programmes			167,345		534,481
GST Input Reversal			488,065		-
Donation to CSBF			133,377		132,111
Miscellaneous expenses			751,774		271,167
Election Expenses (net)			-		8,740,241
Bad Debts			131,304		93,876
CRC Manesar Establishment Expenses			40,732,599		-
Provision for Bad/Doubtful Debts			-		300,000
TOTAL			145,971,226		101,718,784

CCGRT ACTIVITIES**NOTE-20****(₹ Amount)**

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2020		31st March 2019	
CCGRT				
Establishment	107,085		150,512	
Books & Periodicals	40,365		32,717	
Printing & Stationery	207,583		76,090	
Communication	182,080		289,688	
Travelling & Conveyance	47,638		24,530	
Programme & Seminar Exp	5,160,978		2,997,243	
Others	7,355,171	13,100,900	6,008,569	9,579,349
TOTAL		13,100,900		9,579,349

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA**NOTE-21 (Consolidated)****1. GENERAL INFORMATION**

The Institute of Company Secretaries of India ("the Institute or ICSI") is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of Company Secretaries in India. It is a premier national professional body, having its Head Office at New Delhi, was established on 10th December, 1980 under The Company Secretaries Act, 1980 for the purpose of regulating the profession of Company Secretaries in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute. For the purpose, the Council has constituted 4 Regional offices, one each at Mumbai, Kolkata, Chennai and New Delhi, and 72 Chapters (excluding 2 chapters named Yamunanagar and Sonapat closed during the year) across India. ICSI functions under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Institute provides high quality education to the students of Company Secretaries (CS) Course and best quality set standards to CS Members.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(A) ACCOUNTING POLICIES**1. Basis of Preparation of Financial Statements :**

The Financial Statements are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and generally accepted principle in India. All income & expenses are accounted on accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies have been consistently applied by the Institute and are consistent with those used in previous year.

2. Uses of Estimates :

The preparation of Financial Statements in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP) require management to make some estimates and assumptions which affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of Financial Statements and the reported amount of revenues and expenses during the year, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in the period in which results are known/ materialized.

3. Basis of Classification of Current and Non-Current

Assets and Liabilities in the balance sheet have been classified as Current or Non- Current.

An Asset has been classified as Current if, it is expected to be realized in, or is intended for sale in the normal operating cycle; or it is held primarily for the purpose of being traded; or it is expected to be realized within twelve months after the reporting date, or it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date.

All other Assets have been classified as Non-Current.

A Liability has been classified as Current when, it is expected to be settled in the normal operating cycle; or it is held primarily for the purpose of being traded; or it is expected to be settled within twelve months after the reporting date; or the Institute does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months.

All other Liabilities have been classified as Non-Current.

An operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash & cash equivalents.

4. Revenue Recognition

- a. The Entrance Fee is collected at the time of admission of a person as a Member and is directly credited to "Capital Reserve".
- b. Fees received from Members are accounted for on cash basis. However, fees received in advance are carried over as a liability.
- c. Fee from students is recognized on cash basis.
- d. Examination fee is recognized on the basis of conduct of examination.
- e. Revenue from sale of publications is recognized at the time of preparing the sale bill, i.e. when the property in goods as well as the significant risks and rewards of the property get transferred to the buyer.
- f. Income from Investments
 - i) Dividend on investments is recognized on receipt basis.
 - ii) Income on interest-bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rates applicable.
- g. Receipt of money for specific sponsored Programme is recognized on a systematic basis in the Income & Expenditure Account over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate. Unspent balance of such receipts, if any, are carried to next year.

5. Investments

- a. Long term investments are carried at cost including acquisition expenses and diminution in value, other than temporary, if any, is provided for.
- b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.
- c. Investments purchased at a premium are carried to the Balance sheet at face value and premium amounts amortized proportionately over the remaining tenure of investments.

6. Fixed Assets/ Depreciation and Amortization

- a. Fixed Assets excluding Land are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- b. Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment losses, if any.
- c. Land acquired on perpetual lease as well as on lease for over 99 years is treated as freehold land. Land acquired on lease for 99 years or less is treated as leasehold land
- d. Freehold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid inclusive of stamp duty and registration charges for acquiring the lease rights. The value of leasehold land is amortized over the period of lease.
- e. Depreciation is provided on the Written Down Value method at the following rates as approved by the Council, based on the useful life of the respective assets :

Item	%
Buildings	5
Furniture and Fixtures	10
Lifts/Air Conditioners/Other Equipment	15
Vehicles	20
Computers& Mobiles	40

- f. Depreciation on additions to Fixed assets is provided on monthly pro-rata basis. No depreciation is charged in the year of sale.
- g. Fixed Assets costing Rs. 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.
- h. Library books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.
- i. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.
- j. Gain or Losses arising from sale/dispose off / de-recognition of an asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of Income & Expenditure Account of the relevant year.

7. Impairment of Assets

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is an indication of impairment based on internal / external factors. The impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of asset's net selling price or value in use. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value at the weighted cost of capital.

8. Inventories

Inventories of papers, consumables, publications, study materials etc. are valued at lower of cost or net realizable value based on the physical verification done by the management at the year end. The cost is determined on FIFO basis. However inventories older than 1 year are valued at Rs. 1 only considering slow moving/non-moving/obsolete. Stock of Answer Books is charged off to the income and expenditure account in the year of purchase and valued at Nil at the end of the year.

9. Foreign Currency Transactions

- a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing as on the date of transactions.
- b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets / liabilities are translated at the year-end rates whereas non-monetary assets are carried at the rate on the date of transaction.

- c. All incomes or expenses on account of exchange rate difference are recognized in the Income and Expenditure Account.

10. Employee Benefits

Defined Contribution Plan

- a. Contributions to Provident Fund Trust maintained by the Institute are recognized as expenses.

Defined Benefit Plan

- a. Amount payable/recoverable to/from Gratuity Fund Trust are recognized as liability/assets in the balance sheet based on the valuation report received from LIC for present obligation of liability at the year end.
- b. Contribution to Pension Fund Trust are made based on actuarial valuation and recognized as an expense as per AS-15 (Revised).
- c. Provision for leave encashment is made on the basis of valuation provided by LIC and recognized as an expense as per AS-15 (Revised).

11. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the Balance Sheet comprise of cash at banks and in hand and short term deposits with an original maturity of three months or less including flexi deposit linked with bank account, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

12. Cash Flow Statement

Cash Flows are reported using Indirect Method as set out in Accounting Standard -3 “Cash Flow Statements” whereby surplus/(deficit) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flow from operating, investing and finance activities of the Institute are segregated based on the available data and information.

13. Current Assets, Loans & Advances

Current Assets, Loan & Advances are stated in the Balance sheet on the assumption that on realization in the ordinary course of activity, the value will be equal to the aggregate amount shown.

Sundry Debtors & Advances outstanding for more than three years and doubtful for recovery in the opinion of management are provided for and stated net of provisions in the books of accounts.

14. Provisions

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligations at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

15. Grants / Reimbursement of expenses and Subsidy on Sale of Publications to Regional Offices & Chapters
Annual grants, reimbursement of expenses and subsidy on sale of publications to the Regional Offices and Chapters are accounted for on cash basis.

16. Contribution/Grants to Approved Funds/Institutions/Organizations

Allocation /Contributions to ICSI Students Education Fund Trust, ICSI National Award for Corporate Governance, ICSI Employees Medical Hospitalization Trust, Company Secretaries Benevolent Fund, ICSI Employees Benevolent Fund, Performance-related Incentive Fund, Professional Development Fund and Infrastructure Fund, are made based on the amount as approved by the Council from time to time.

17. Allocations / Transfer to Reserves and Surplus and Earmarked Funds

- a. Corpus donation / donation for Building & Other Specific Fund received during the year is directly taken to General Reserve/Specific Fund.
- b. Income from investment of earmarked funds is allocated at the rate of 8%p.a. to the respective earmarked funds on the average of Opening & Closing balances and the amount utilized therefrom is debited to such funds.

18. Old outstanding amounts under the heads of “Earnest Money Deposits, Retention Money, Security Deposits and Stale Cheques”

Undisputed amount outstanding for more than three years under the head of Earnest Money Deposits, Retention Money, Security Deposits and Stale Cheques remaining unpaid at the end of financial year is being writing off and treated as Income for the year. Any subsequent claim out of the written off amount will be paid in the year of claim and will be booked as expenses for the year accordingly.

(B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

(a) Claims against the Institute not acknowledged as debts is Rs.16.90 lakh (Previous Year Rs 27.27 lakh), excluding interest which is not yet ascertained.

(b) Claims in respect of legal cases filed by the staff / labour and others against the Institute for labour and other matters, amounts not ascertainable (amount provided till 31.03.2020 is Nil (P.Y. NIL).

(c) TRACES defaults pending adjustments with Income Tax Authority amounting to Rs. 2.35 lakh (P.Y. Rs 1.69 lakh).

(d) An agreement was executed between the Institute and M/s Gurukul Online Learning Solutions Private Limited (GOLS) for e-learning for the Students of the Institute on Built, Operation and Transfer (BOT) basis. The agreement expired on 13.09.2015. GOLS failed to render accounts to the Institute from July, 2015 and also failed to transfer the portal to ICSI. Both the parties approached the Hon'ble Delhi High Court for initiating arbitration proceedings. Hon'ble High Court vide its order dated 06.03.2017 directed the parties to appear before Delhi International Arbitration Centre.

Institute has filed its statement of claim for Rs.43,24,920/- towards its dues and Rs.2,00,00,000/- towards damages. Delhi International Arbitration Centre has appointed Hon'ble Justice M L Mehta as Sole Arbitrator, Delhi Arbitration Council. GOLS has also filed its counter claim of Rs. 32 Crores approx and replied to the claim of the Institute. The matter is still pending.

Future cash flows in respect of the above matters are determined only on receipt of judgment / decision of the concerned forums/authorities.

2. Capital Commitments and Other Commitments

The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account, net of advances is Rs 883.06 lakh as on 31.3.2020 (P.Y. Rs. 953.58 lakh). Amount of other major commitments is Rs. NIL (P.Y. Rs. NIL). Further estimated amount of other commitments related to procurements of goods and services in the ordinary course of institute functioning are not disclosed to avoid excessive details

3. Management is of the opinion that except the assets written off during the year and the assets retired from active use, there is no indication w.r.t further impairment of assets as contemplated in Accounting Standard – 28.

4. **Employee Benefits :** The disclosure of 'Employee Benefits' as defined in the Accounting Standard-15 are as under:-

Defined Contribution Plan : Employer's contribution to Defined Contribution Plan such as Provident Fund is charged off during the financial year. Employee's Provident Fund is administered by 'ICSI Employee's Provident Fund Trust'.

Defined Benefit Plan

(i) **Gratuity :** The Employer's Gratuity Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a 'Defined Benefit Plan'. The present value of obligation is determined by LIC based on actuarial valuation using Projected Unit Credit (P.U.C.) method as defined in the Accounting Standard-15.

(ii) **Leave Encashment :** The Leave Encashment Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a 'Defined Benefit Plan'. The present value of obligation is determined by LIC based on actuarial valuation using Projected Unit Credit (P.U.C.) method as defined in the Accounting Standard-15.

(iii) **Pension :** 'Pension' is administered by a separate Trust named as 'ICSI Employees Pension Fund Trust' and the actuarial valuation of Pension Benefit Plan Liability has been done on 31.3.2020 by following P.U.C. method in terms of the Accounting Standard – 15.

I. Table showing changes in present value of Obligation:

Fig.: ₹ lakh

	Gratuity Funded	Pension Funded	Leave Encashment Funded with LIC & Earmarked with ICSI
Present value of obligations as at the beginning of the year	1546.49	5969.29	1600.24
Interest cost	115.99	460.94	*128.02
Past Service cost	Nil	Nil	Nil
Current service cost	104.40	81.85	141.81
Actuarial (Gain)/Loss on obligation	166.28	544.79	(409.27)
Benefits paid	(154.98)	(240.38)	(213.34)
Settlement Cost	Nil	Nil	Nil
Present Value at the year end	1778.18	6816.49	1247.46

*As per Note-2. Interest allocated on Earmarked Funds.

II. Table showing changes in fair value of Plan Assets:

Fig.: ₹ lakh

	Gratuity Funded	Pension Funded	Leave Encashment Funded with LIC & Earmarked with ICSI
Fair value of Plan Assets at beginning of the year	1520.50	5896.67	1330.82
Expected/Actual return on Plan Assets	125.69	455.33	97.22
Contributions	147.28	NIL	43.38
Benefits paid	(154.98)	(240.38)	(213.34)
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	Nil	19.41	Nil
Fund Management Charges	Nil	Nil	Nil
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1638.49	6131.03	1258.08

III. Amounts to be recognized in the Balance Sheet:

Fig.: ₹ lakh

	Gratuity Funded	Pension Funded	Leave Encashment * Funded with LIC & earmarked
Present value of Obligation at the end of the year	1778.18	6816.49	1247.46
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1638.49	6131.03	1258.08
Funded status	(139.68)	(685.46)	10.63
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(139.68)	(685.46)	10.63

IV. Expenses recognized in the Income & Expenditure Account

Fig.: ₹ lakh

	Gratuity Funded	Pension Funded	Leave Encashment Funded with LIC & earmarked
Current Service Cost	104.40	81.85	141.81
Interest Cost	115.99	460.94	*128.02
Expected return on Plan Assets	(125.69)	(455.33)	(97.22)
Past Service cost	Nil	Nil	Nil
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year	166.28	525.38	(409.27)
Expenses to be recognized	260.98	612.84	(236.66)
Less:- Allocated Return on Earmarked Funds	-	-	--
Add:- Opening excess/deficit Amount/Plan/ Funded Asset available over present obligation	-	72.62	--
Net Cost	260.98	685.46	(236.66)

*As per Note-2. Interest allocated on Earmarked Funds.

V. Funded Investment Details

Fig.: ₹ lakh

Gratuity	Pension	Leave Encashment
Insurance Policy 100% with LIC	Central and State Government Securities, PSU Bonds, Special Deposit Schemes, Fixed Deposits with Scheduled Banks.	Investments of Rs. 1258.08 lakh with LIC.

VI. Actuarial Assumptions

	Gratuity	Pension	Leave Encashment
Mortality Table	LIC(2006-08) ultimate	2012-14	2006-08
Discount Rate	7.25% p.a.	7.00% p.a.	7.25% p.a.
Future Pay Increase	10.00% p.a.	8.00% p.a.	10.00% p.a.
Return on Plan Assets	7.25% p.a.	7.50% p.a.	7.25% p.a.

5. Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information provided by the parties and collected by the Management. The Institute has sent communication to all the parties to ascertain their status however no intimation has been received from "Suppliers/Service Providers" regarding their status under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act., 2006 and hence disclosure, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable as required under the Act has been considered as NIL.

6. The Institute has issued communication to various parties/vendors for their balance confirmation at the year end. However, confirmation has not been received in most of the cases majorly due to pandemic Covid-19. Hence, balances of various parties including inter unit balances are subject to reconciliation and their confirmation.

7. The Institute operates predominantly in India and in one geographical segment as economic condition of whole India is same, further the core objective of Institute is development of profession of Company Secretary in India. Thus all its operations fall under one segment only as per the meaning of AS 17, Segment Reporting.

8. For the purpose of Current and Non Current classification in the Financial Statements, the operating cycle of the Institute has been considered as twelve months.
9. Valuation of closing inventories is done as per policy of the Institute based on the records available at the year end at HQ and Regional offices/Chapters and monthly information provided by the Regional offices/Chapters. Some of the Chapters have not provided the quantities, details of inventories as at 31-03-2020, however the same has been considered as per Headquarters stock register. Due to Covid 19 and lockdown restrictions, physical verification of closing inventory at the year end could not be carried out.
10. The break-up of Building Loan to Regional Offices and Chapters outstanding as at 31st March, 2020 are as under:

(₹ lakh)

Location	As at 31.3.2020	As at 31.3.2019	Amount due for repayment as on 31.3.2020
Mysore Chapter	2.00	2.00	2.00
Thane Chapter	Nil*	10.50	Nil
Faridabad Chapter	5.00	5.00	5.00
Total	7.50	17.50	7.50

*The same has been written off and adjusted from General Reserve as per approval of the competent authority.

11. The details of Prior Period Income /Expenditure are as under:

(₹ lakh)

Income	2019-20	2018-19
TDS	0.13	0.25
Regional Council / Chapter Reimbursement	0.50	--
Travelling/Conveyance	-	0.17
TDS rectification	-	9.67
GRKF	-	0.46
Insurance	-	42.23
Amount not claimed transferred to Income (Stale Cheques)	-	4.13
WIRO convocation	-	3.33
CRC- Receipts	45.26	-
Total	45.89	60.24
Expenditure	2019-20	2018-19
Advertisement	0.92	3.47
AMC – Office Equipments& Others	5.25	5.78
Amortization of Land at COE Kolkata	49.23	--
Audit Fee	0.05	--
Communication Expenses	0.19	--
CRC Expenses	70.21	--
DR Cloud	30.53	--
Exam Expenses	0.79	--
Full & Final Settlement of M/s Sanrachna	12.07	--
GST Liability	6.84	--
Sundry Balances w/o	4.84	--

Honorarium	0.17	--
Lease Rent	1.59	--
Legal & Professional Charges	5.47	1.26
Other Misc. Expenses	19.64	10.11
Printing & Designing Expenses	0.32	13.12
Programme & Seminars	2.31	25.14
Property Tax	10.62	9.38
44 th National Convention	12.53	-
Refund of Fee to Students	7.34	96.49
Refund to Members	0.51	--
Regional Council / Chapter Exp. Reimbursement	13.13	--
Staff welfare	1.21	--
Travelling & Conveyance	11.97	18.34
Total	267.73	183.09
Net (Income) / Expenditure	221.84	122.85

12. Income Tax

(i) The Institute of Company Secretaries of India has been registered u/s 12A of the Income Tax Act, 1961 and Income Tax returns has been filed u/s 11/12 of the Income Tax Act.

(ii) The assessment for AY 2016-17 has been completed u/s 143(3) of the Income Tax Act 1961 for the return filed under section 11/12 of the Income Tax Act accepting the returned income. For the A.Y. 2015-16, an application for rectification u/s 154 of the Income Tax Act, 1961 has been filed on 8th July, 2019 wrt receiving of less refund of Rs.14,95,916/-. Assessment for the AY 2017-18 and AY 2018-19 are under process with Income Tax Department and there is no expected extra liability in terms of the demand as per information available till date and as per past assessments. Further Income Tax Refunds as demanded in ITR filed has been received till AY 2019-20.

13. Allotment of land of Rs.2,88,56,250/- paid to Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (now Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Ltd.) towards cost of land for allotment of total area of 4918sqmt (1.215Acre) at IP-Uppal, Hyderabad out of which (i) Agreement to Sale executed and registered for 3140 sqmt in 1st phase, (ii) Agreement to sale executed for 912 sqmt in 2nd phase and (iii) execution of agreement to Sale and giving/taking possession for 866 sqmt in 3rd phase (cost of Rs. 50, 82,500/-) is yet to be done since the matter is sub judice. Request was made to Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Ltd. for execution of sale deed for 1st and 2nd phase. Writ Petition no. 31594/2014 dated 18-10-2014 has been filed in the High Court of State of Telangana and Interim stay on construction work vacated by the court vide order dated 24-08-2015 in favour of the Institute.

14. Institute has paid Rs. 80,25,000/- as part payment against the agreed total sale consideration of Rs. 3,21,00,000/- against purchase of one portion of fifth floor of multi storied building "THE GRACE" (Previous Name- NASA) in Indore at the time of execution of agreement to sell and registering the deed. Total expenditure incurred in this regard including stamp duty and registration is Rs.83,23,000/-. Occupancy Certificate has not been obtained by the seller from the competent authority and due to the same, sale deed has not yet been executed till date. Amount is kept and shown as Capital Work in Progress (CWIP) as matter is under subjudice. Details of suits filed by the Institute against the sellers of property are as under:

(i) Civil Suit- case no. 9800255 of 2016 ICSI Vs. Sirajuddin Malik & Others.in District Court, Indore dated 19-12-2016.

(ii) Contempt Suit- ICSI Vs. Sirajuddin Malik & Others.in District Court, Indore dated 05-02-2018.

(iii) Criminal Suit- Trial no. 3135 of 2017- ICSI Vs. Sirajuddin Malik & Others.in District Court, Indore dated 04-07-2017.

15. The details of Income & Expenditure in foreign currency:

a.	Earnings in Foreign Currency	Current Year	Previous Year
-	Fees from overseas members	--	---
-	Convention stalls	--	--
	Total	--	---
a.	Expenditure in foreign currency		
-	Membership fee	13.59	6.52
-	International Workshop	3.45	19.89
-	Travelling Expenses	--	--
-	Inauguration Ceremony (NPIO, Dubai)	3.60	--
-	Dubai Exam Centre	1.12	--
-	Miscellaneous Expenses	--	4.51
	Total	21.76	30.92

16. The Institute has received a show-cause notice-196/BhZU/ADG/ST/2018 dated 23rd October, 2018 from Directorate General of Goods & Service Tax Intelligence (earlier Directorate General of Central Excise Intelligence), Intelligence, Bhopal Unit for deposit of service tax (including education cess & higher education cess) on membership fee collected during the period from 01.04.2013 to 31.03.2017. The total demand for service tax was for Rs.2,78,22,787/-. The Institute has replied to the show cause notice and received an order for Rs.5,04,36,250/- (excluding interest) including penalty for non-payment of the demanded amount. In the meantime, Central Board of Indirect Taxes & Customs has launched a scheme of settlement of disputes – Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 (SVLDRS) in which the Institute has applied for its settlement. The matter was settled under the said waiver scheme and a final demand of Rs.1,39,11,394 was paid and booked as exceptional items in the Income & Expenditure Account during the year.

17. During the year, Institute, as per policy, an amount of Rs.69.94 lakh has been adjusted from its General Reserve on account of written off of some of its old outstanding balances, which were more than three years old.

18. As per the audited accounts of Southern India Regional Council (SIRC) and Western India Regional Council (WIRC), an amount of Rs. 22.73.999/- and Rs.4,54,573/- respectively has been considered as doubtful debtors/ advances. However no provision has been made as and management is hopeful that the amount will be recovered from the concerned parties and for recovery legal action has been initiated or going to be initiated.

19. Previous year's figures have been regrouped/rearranged/recast wherever considered necessary to make it comparable with the current year's classification/disclosures.

For and on behalf of the Council of the Institute

CA Sameer Gupta
Joint Secretary (F & A)

CS Ashish Mohan
Secretary

CS Nagendra D Rao
Vice President

CS Ashish Garg
President

As per our report of even date
For Bansal Sinha & Co.
Chartered Accountants
FRN 006184N

For P K Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN 006747N

(CA Hari Ubriani)
Partner
(Membership No.084437)
UDIN. 20084437AAAAAR9401

(CA Rahul Jindal)
Partner
(Membership No. 537709)
UDIN 20537709AAACJ1135

Place: New Delhi
Date: 26th September, 2020